Publisher & Owner

Archana Rajendra Ghodke

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh, Tq.Dist.Beed-431 126

(Maharashtra) Mob.09850203295

E-mail: vidyawarta@gmail.com

www.vidyawarta.com

ISSN 2319 9318

"कौशल्य विकास और रोजगार के अवसर"

MAH/MUL/03051/2012

ISSN-2319 9318

विद्यावार्ता®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी

शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन

आयोजित

"कौशल्य विकास और रोजगार के अवसर"

(विभिन्न आयामों के संदर्भ में)

Skill Development & Employment Opportunities
in the Context of Various Dimension
23 Dec. 2024

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल

डॉ. राजेंद्रकुमार यादव
समन्वयक

डॉ. एम.के. गोखले
प्राचार्य

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका
विद्यावार्ता™

शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन, (म.प्र.)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा **B++** प्रदत्त **CGPA 2.88**

Email : heggckhr@mp.gov.in

Web URL : http://gdckhargone.org

एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी

दिनांक : **23/12/2024**

– विषय –

''कौशल विकास और रोजगार के अवसर''

(विभिन्न आयामों के संदर्भ में)

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Date of Publication
December - 2024

Vidyawarta™

International Multilingual Research Journal

www.विद्यावार्ता.कॉम
YouTube Channel

Vidyawarta is peer reviewed research journal. The review committee & editorial board formed/appointed by Harshwardhan Publication scrutinizes the received research papers and articles. Then the recommended papers and articles are published. The editor or publisher doesn't claim that this is UGC CARE approved journal or recommended by any university. We publish this journal for creating awareness and aptitude regarding educational research and literary criticism.

The Views expressed in the published articles,Research Papers etc. are their writers own. This Journal dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary. Editors and publishers have the right to convert all texts published in Vidyavarta (e.g. CD / DVD / Video / Audio / Edited book / Abstract Etc. and other formats).

If any judicial matter occurs, the jurisdiction is limited up to Beed (Maharashtra) court only.

Indexed

IMPACT 9.45 iijif FACTOR

Govt. of India,
Trade Marks Registry
Regd. No. 2611690

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
Certified Quality Management System
ISO 9001:2015
International Multilingual Research Journal

http://www.printingarea.blogspot.com

मुख्य संरक्षक

श्री कर्मवीर शर्मा – जिलाधीश एवं पदेन अध्यक्ष जभास शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन

प्राचार्य एवं संरक्षक
डॉ. एम. के. गोखले

समन्वयक – शोध संगोष्ठी
डॉ. आर. के. यादव

आयोजन सचिव – शोध संगोष्ठी
डॉ. ममता गोयल

सह संयोजक – शोध संगोष्ठी
डॉ. धर्मेन्द्र भालसे, डॉ. अनुराधा ठाकुर, डॉ. मोनिका चौहान

आयोजन समिति – शोध संगोष्ठी
प्रो. प्रीति राठौर, डॉ. बी.एल. भाटे, डॉ. एम. एस. सोलंकी, डॉ. सेवन्ती डावर, प्रो. ए. जे.सोलंकी, डॉ. मनीषा चौहान, डॉ. रफिया अजीज, डॉ. एस. एच. जाफरी, श्री विनोद पटेल, डॉ. सुनील सिंह, डॉ. पवन नामदेव, डॉ. श्रद्धा महाजन, श्रीमती शर्मिला किराडे, सुश्री अनुराधा बरुड, श्री राजकुमार शिंदे, श्री प्रमोद सावनेर, श्री देवी सिंह चौहान

तकनीकी सलाहकार
प्रो. मनीष रघुवंशी, श्री अंकित चौहान, श्री हरिमेष यादव

संरक्षक एवं सलाहकार समिति
डॉ. आर. सी. दीक्षित
अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग, इंदौर

डॉ. शैल जोशी
प्राचार्य, **PMCOE** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन

प्राचार्य की कलम से........

''उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित एवं निर्देशों के परिपेक्ष्य में''

शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन मे एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया समन्वयक डॉ आर.के.यादव एवं आयोजन सचिव डॉ. ममता गोयल ने संगोष्ठी के आयोजन में महती भूमिका निभाई। शोध संगोष्ठी की आयोजन समिति के द्वारा इस संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। महाविद्यालय की सम्पूर्ण समितियों के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण करने में सभी सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा। देश के विभिन्न राज्यों से इस संगोष्ठी मे विषय से संबंधित शोध पत्र प्राप्त हुए है। महाविद्यालय की शोध समिति के संयोजक के कुशल नेतृत्व मे प्रकाशित करने हेतु सभी सदस्यों को साधुवाद। सफल आयोजन एवं सफल प्रकाशन मे सलाहकार समिति एवं संरक्षक के नेतृत्व के बगैर सफल आयोजन किया जाना संभव नहीं था। डॉ. कर्मवीर शर्मा पदेन अध्यक्ष ज. भा. स. एवं जिलाधीश खरगोन, डॉ. आर.सी. दीक्षित अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग इंदौर संभाग, डॉ. एम.एल.कोरी कुलगुरु के.टी.बी. विश्वविद्यालय खरगोन एवं डॉ. शैल जोशी प्राचार्य पी एम एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन के दिये गये सहयोग को भी हम नमन करते हैं। एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी मे शोध स्मारिका के बिना आयोजन को सफल नहीं माना जा सकता इस दिशा मे महाविद्यालय की तकनीकी टीम के वरिष्ट तकनीकी विशेषज्ञ प्रो. मनीष रघुवंशी, श्री दीपक यादव एवं श्री अंकित चौहान का रूपरेखा संग्रहण एवं संकलन करने मे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सम्पूर्ण शोध ा संगोष्ठी में इनकी भूमिका सराहनीय रही है।

पुनः कार्यक्रम समन्वयक डॉ. आर. के. यादव एवं आयोजन सचिव डॉ. ममता गोयल, विभिन्न समितियों के संयोजक, सदस्य, कार्यालयीन स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी को हार्दिक बधाई।

डॉ. एम. के. गोखले
प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन

संपादकीय .....
संपादक की कलम से......

मानव होने के नाते जब से आँखें खोली ज्ञान के अभाव मे कुछ भी समझ आना मुश्किल था। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई कुछ परिस्थितियाँ अस्पष्ट और धुंधली दिखाई देने लगी। ज्ञान के संग्रहण और संधारण के बाद धुँधलापन धीरे धीरे छटने लगा किन्तु इस हटते हुये परदों से दिमाग मे उथल पुथल मच गई। आस—पास की परिस्थितियों ने दिल—दिमाग को उद्वेलित कर दिया।

आस—पास घटने वाली घटनाएं और सामान्य जनमानस की गरीबी ने सोचने पर मजबूर कर दिया। कालांतर मे दृष्टिकोण के विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और जीवन जीने की दशाओ से निश्चित ही प्रभावित हुआ। विकसित देशों के सामान्य जन के जीवन शैली का भारतीय जनमानस की जीवन यापन शैली का तुलनात्मक अध्ययन होने लगा। प्रश्न अनेकों उत्पन्न होने लगे जिसमे मुख्यत: गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और क्रय शक्ति का काम होना महत्वपूर्ण थे। गहनता से अन्य राष्ट्रों के विकास की गति का अध्ययन किया तो पता चला कि अन्य राष्ट्रों मे स्किल डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया है और उसको ही अपने विकास का आधार बनाया है। ज्ञात आंकड़ों के आधार पर कुछ विकसित राष्ट्रों एवं पूर्वी यूरोप के देशों में कुशल जनसंख्या ८०% से ९०% तक है। एशिया में भी भारत के पड़ोसी राष्ट्रों मे भी कुशल जनसंख्या का प्रतिशत भारत से कहीं अधिक है।

भारत सरकार द्वारा इन्ही तथ्यों को ध्यान मे रखकर सन २०४७ तक भारत को विश्व मे अर्थव्यवस्था तथा अन्य विकास के पैमानों पर भी नंबर एक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान लगाया गया है कि अगर इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रही तो भारत में डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक होगी। इन तथ्यों के आधार पर ही भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। २०२० मे सम्पूर्ण भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई जिसे बहुविषयक ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बनाया गया है। इसी में शोध एवं कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है जिससे कि २०३० तक कुशल जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो सके। उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा कौशल विकास पर आधारित संगोष्ठीयां आयोजित कर भारत के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें।

डॉ. आर. के. यादव
सम्पादक
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन द्वारा एक दिवसीय कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर (विभिन्न आयामों के संदर्भ मे) विषय पर सफल राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया तथा शोध संगोष्ठी मे प्राप्त शोध पत्रों को शोध स्मारिका में प्रकाशित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इस शोध पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र निश्चित ही कौशल विकास के क्षेत्र में उपयोगी होंगे। निश्चित ही यह पत्रिका नवीन शोधार्थी एवं विद्यार्थियों हेतु बहुपयोगी होगी।

शोध संक्षेपिका के सफल प्रकाशन हेतु महाविद्यालय प्रबंधन एवं परिवार को ढ़ेर सारी शुभकामनाये।

(डॉ. आर.सी.दीक्षित)
अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर

शुभकामना संदेश

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी ''कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर (विभिन्न आयामों के संदर्भ मे)'' का सफल आयोजन किया गया जिसमें मुझे भाग लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ आयोजन एवं आयोजन तरीके को देखकर मे अत्यंत प्रसन्न एवं गदगद हूँ मेरी प्रसन्नता मे वृद्धि इस बात को लेकर भी हुई कि संगोष्ठी मे देश के विभिन्न राज्यों से शोधार्थी सम्मिलित हुए। आयोजित संगोष्ठी मे विभिन्न प्रदेशों से शोध पत्रों का वाचन एवं प्रस्तुतीकरण निश्चित ही इस संगोष्ठी को अपने मूल ध्येय की ओर ले जाएगी।

अत्यधिक खुशी तो तब और हुई कि शोधार्थीयों द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों को राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिका मे प्रकाशित किया जा रहा है, आशा है कि यह प्रयास सफल और उपयोगी सिद्ध होगा। महाविद्यालय के प्राचार्य, आयोजक, समन्वयक एवं सम्पूर्ण महाविद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

डॉ. एम. एल. कोरी
कुलगुरु
क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय,
खरगोन, (म.प्र.)

शुभकामना संदेश

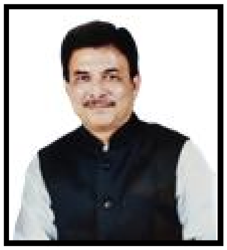

अत्यंत हर्ष का विषय है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन द्वारा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर (विभिन्न आयामों के संदर्भ मे) विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शोधार्थीयों से प्राप्त शोध का प्रकाशन शोध पत्रिका मे किया जा रहा है इस प्रकार के ज्वलंत विषय पर चर्चा एवं परिचर्चा उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े समस्त व्यक्तियों एवं शोधार्थीयों का ध्यान उन समस्याओं की ओर जाता है जो युवाओ तथा देश के भविष्य के लिए अनिवार्य होते है व्यक्तियों में कौशल विकास को उन्नत करने हेतु इस प्रकार की संगोष्ठीयों का किया जाना निश्चित ही अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है। मुझे इस संगोष्ठी में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ तथा शोध पत्र प्रकाशन में भी मुझे यह अवसर प्राप्त हो रहा है जो कि मेंरे लिये हर्ष का विषय है।

संगोष्ठी के सफल आयोजन एवं स्मारिका प्रकाशन के लिये मेरी ओर से पूरे महाविद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

डॉ. जी. एस. चौहान
कुलसचिव
क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय,
खरगोन, (म.प्र.)

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन द्वारा राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी कौशल विकास और रोजगार के अवसर (विभिन्न आयामों के संदर्भ में) का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित ही यह संगोष्ठी शिक्षाविदों, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगी।

एक शिक्षक के रूप मे हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को न केवल सफल पेशेवर बनाने के लिए, बल्कि उनके अन्दर की क्षमता को विकसित कर उन्हें एक सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करें। विकसित भारत के संकल्प एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में कौशल विकास की अहम भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आपके द्वारा जो यह आयोजन किया जा रहा है उसकी सफलता हेतु मै अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।

डॉ. शैल जोशी
प्राचार्य
प्रधानमंत्री उत्कृष्ट शासकीय स्नातकोत्तर
अग्रणी महाविद्यालय, खरगोन, (म.प्र.)

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

INDEX

01) खरगोन तहसील में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति ग्रामीण....
नितिन पाटीदार, डॉ. राजेन्द्र कुमार यादव, खरगोन, (म.प्र.) ||14

02) युवाओं में कौशल विकास हेतु आवश्यक प्रयास एवं चुनौतियों का अध्ययन
डॉ. ममता गोयल (गोनेकर), खरगोन (म.प्र.) ||18

03) कौशल विकास की रोजगार निर्माण में भूमिका
डॉ. अनुराधा ठाकुर, खरगोन, (म.प्र.) ||23

04) जनजातीय समाज में स्वरोजगार के अवसर और कौशल विकास: खरगोन....
डॉ. उषा वैद्य, विनोद कुमार पटेल, रायसेन (म.प्र.) ||26

05) महिलाओं में तकनीकी कौशल का रोजगार पर प्रभाव
अनिता मालवीया, डॉ. राजेन्द्र कुमार यादव, खरगोन, (म.प्र.) ||29

06) वर्तमान भारतीय परिपेक्ष्य में लघु एवं कुटीर उद्योग में कौशल विकास का....
डॉ. रश्मि चौहान, डॉ. राकेश ठाकुर, कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.) ||34

07) व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास
डॉ. मनोज वानखेड़े, बड़वानी ||41

08) कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर
श्रीमती करूणा नामदेव, डॉ. पवन नामदेव, खरगोन ||47

09) स्वरोजगार के अवसर एवं कौशल विकास
डॉ. श्रवण कुमार कोहरे, सनावद जिला—खरगोन ||48

10) कौशल विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका एवं चुनौतियाँ
डॉ. सावित्री भगोरे, खरगोन, (म.प्र.) ||51

11) जनजातियों में कौशल विकास : रोजगार में चुनौतीयां
डॉ. वर्षा पटेल, अर्चना नेहारे, इन्दौर (म.प्र.) ||56

12) ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को....
डॉ. दीपक गर्ग, कपिल कुमार मेहता, भोपाल ||60

13) अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक कौशल विकास
डॉ. मुकेश कुमार सावले ||64

14) कम्प्यूटर के क्षेत्र में कौशल विकास
डॉ. गायत्री चौहान, खरगोन (म.प्र.) ||68

15) कौशल विकास : आधुनिक भारत की आवश्यकता
डॉ. ललिता गोयल, किला भवन, इंदौर ||73

16) व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास का महत्व
डॉ. एस. एच. जाफरी, प्रो. ऐ. जे. सोलंकी, आनन्दनगर, खरगोन (म.प्र.) ||75

17) स्वरोजगार के अवसर और कौशल विकास में चुनौतियां
डॉ. मनीषा चौहान, खरगोन (म.प्र.) ||80

18) कौशल विकास एवं महिला उद्यमी
डॉ. मोनिका चौहान, खरगोन (म.प्र.) ||85

19) भारतीय पर्यटन उद्योग की विकास यात्रा
डॉ. रीना वसुनिया, खंडवा (म.प्र.) ||91

20) विविध क्षेत्रों में कौशल विकास....
डॉ. सेवन्ती डावर, खरग ||92

21) देश के आर्थिक विकास में कौशल विकास की भूमिका
डॉ. प्रकाश पगारे, खंडवा ||95

22) नवीन शिक्षा नीति का समाज में प्रादुभाव
डॉ. विजय सिंह मंडलोई, कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) ||97

23) भारत में कौशल विकास का सामाजिक महत्व
लेफ्टनंट डॉ. एम. आर. खोत, मालवण, सिंधुदुर्ग ||101

24) भारत में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारंपरिक और कौशल....
शम्भू, हिमांशी, शिवम, डॉ. मनोज कुमार, ज्योति नैन, डॉ. संतोष कुमार ||106

25) विविध क्षेत्रों में कौशल विकास
प्रो. गीता मेहरा, खंडवा ||108

www.vidyawarta.com/03 http://www.printingarea.blogspot.com

26) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर
डॉ. भालचन्द्र भाटे, खरगोन, (म.प्र.) ||112

27) स्वयं सहायता समूहों कि कौशल विकास एवं रोजगार निमार्ण में भूमिका
किरण नागराज (वानखेडे), सिहोर (म.प्र.) ||119

28) कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर
डॉ. गायत्री वर्मा रावल, शाजापुर (म.प्र.) ||122

29) ग्रामीण विकास में कौशल विकास की भूमिका
प्रो. माया वर्मा, डॉ. लता राठौर, भीकनगॉव ||128

30) बदलते परिदृश्य में छात्रों के व्यक्तित्व एवं व्यवसायिक विकास में मददगार....
डॉ. सुनैना चौहान, डॉ. संध्या बटवे, खरगोन ||129

31) व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास
प्रो. प्रीति राठौर (हाड़ा), खरगोन (म.प्र.) ||133

32) तकनीकी कौशल विकास और भारत की रोजगार नीति : एक राजनीतिक समीक्षा
ज्योति पटेल, महू जिला इन्दौर ||135

33) कौशल विकास और मध्य प्रदेश राज्य में स्वरोजगार योजनाओं की....
डॉ. कमलसिंह अलावा, डॉ. मोनिका चौहान, खरगोन (म.प्र.) ||139

34) Improve Personality with Effective Communication Skills
Vijaylaxmi Sathe/Sawle, khargone (M.P.) ||142

35) Career Opportunities in Solar Energy Sector in India
Dr. Dinesh Choudhary, Lalit Kumar Bhataniya, Khargone (M.P.) ||144

36) The Skill Development and Its Role in Enhancing Employability
Ranita Das, korba, Chattisgarh ||146

37) Skill Development in Personality Development
Dr. Raghavesh, Burhanpur, (M.P.) ||149

38) Leadership Ability and Troubleshooting
Dr. Smita Hajary, Burhanpur, (M.P.) ||152

www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

39) Life Skills for the Next Generation: Some Strategies
Dr. Ami Rathod, Udaipur || 155

40) Objectives of Smart Farming Using IoT Smart Sensors
Maneesh Kumar Raghuwanshi, Indore(M.P.) **||160**

41) Skill Development-Today's Necessity
Samrat Wani, Burhanpur, (M.P.) **||163**

42) Skill Development in Science and Technology in India
Dr. Dharmendra Bhalse, Dr. Rajesh Kumar, Nanauta, Saharanpur (U.P.) **||165**

43) The Skill Development in the Agriculture Sector
Dr. Prashant singh rajput, kerba, Chhattisgarh **||171**

44) उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार के बीच परस्पर संबंध
डॉ. योगासना पाराशर, इंदौर **||173**

www.vidyawarta.com/03 || http://www.printingarea.blogspot.com

01

खरगोन तहसील में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति ग्रामीण युवाओं में जागरूकता

नितिन पाटीदार
शोधार्थी (समाजशास्त्र)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

डॉ. राजेन्द्र कुमार यादव
सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन, (म.प्र)

****

सारांश

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भारत में एक प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य देश के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के बेरोजगार नवयुवको को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में भारत की लगभग ५० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। जिसमें से लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत है। जहाँ कौशल प्रशिक्षण का अभाव सदैव देखा गया है।

प्रस्तुत शोधपत्र में शोधार्थी ने खरगोन तहसील के ग्रामीण युवाओ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोधपत्र के लिये प्राथमिक समंको का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। जिसमे कुल १०० उत्तरदाताओ से प्रश्न पूछे गए है। खरगोन तहसील के विशेष संदर्भ में अध्ययन के दौरान इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में ग्रामीण युवाओं में जागरूकता का अभाव है। क्योंकि अधिकांश ग्रामीण युवाओ को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नही है।

शब्दकुंजी: रोजगार, प्रशिक्षण, ग्रामीण, बेरोजगारी, युवा, कौशल विकास, खरगोन तहसील।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारत देश में ग्रामीण युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। भारत के युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कार्यो में कुशल बनाकर देश में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमेकवीवाई) एक अनूठी पहल है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सार्थक उद्योग तथा कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे युवाओं को लाभ मिलेगा जो दसवीं व बारहवीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और उनके समक्ष रोजगार के अन्य विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। कुछ युवा गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे युवाओं के लिए यह योजना प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में सहायक सिध्द होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ताकि यह भविष्य में उनके लिए रोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके। इस तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिससे हमारा देश सुचारु रूप से प्रगति कर सके।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चार चरणों में विस्तारित है –

- प्रधानमंत्री कौशल विकास १.०
- प्रधानमंत्री कौशल विकास २.०
- प्रधानमंत्री कौशल विकास ३.०
- प्रधानमंत्री कौशल विकास ४.०

इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओ को प्रेरित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नगद मौद्रिक पुरुस्कार भी प्रदान किया जाता है। ताकि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी प्रशिक्षु अधिक से अधिक प्रेरित रह सके। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। जिसके बाद वह इस योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करके, केंद्र सरकार की सहायता से अपना खुद का बिजनेस भी स्थापित कर सकता है।

वास्तव में भारत की आधी से अधिक आबादी युवा है और लगभग ७० प्रतिशत आबादी ग्रामीण है जहां कौशल प्रशिक्षण का अभाव देखने को मिलता है। यह शोध आलेख ग्रामीण युवाओ में पीएमेकवीवाई के प्रति जागरूकता का संक्षिप्त अध्ययन है। जिसमें मुख्य रूप से यह जानने का प्रयास किया गया है कि खरगोन तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओ में इस योजना के बारे में कितनी जागरूकता व्याप्त है।

साहित्य समीक्षा

१. पांडे एवं जोशी (२०२१) ने अपने अध्ययन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति युवाओं की जागरूकता एवं रोजगार मेलों के आयोजन के बीच संबंध का अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार युवाओं के मध्य बढ़ती जागरूकता एवं रोजगार मेलों के आयोजन के मध्य एक सकारात्मक संबंध है। अपने अध्ययन में उन्होंने यह बताया की प्रशिक्षण क्षेत्र में नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

२. नेहरू (२०२२) ने अपने अध्ययन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रभाव का अध्ययन एवं योजना को बेहतर बनाने के लिए संभावित सुझावों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने अध्ययन में योजना के कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों का अध्ययन किया हैं। अपने अध्ययन में उन्होंने यह बताया की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। जिससे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को वर्तमान औद्योगिक मांगो के अनुरूप अनुकूलित किया जा सके।

३. पांडे (२०२०) ने अपने अध्ययन में प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण क्षेत्रों के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया है। अपने अध्ययन मे उन्होंने बताया है की हरियाणा के युवाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर युवाओं में काफी जागरूकता हैं। यह शोध विशेष भौगोलिक क्षेत्र (हरियाणा) के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अध्ययन करता है। अत: यह शोध नए भौगोलिक क्षेत्रों के युवाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति जागरूकता के अध्ययन की संभावनाओं को प्रशस्त करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

खरगोन तहसील में ग्रामीण युवाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जागरूकता का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र

अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की खरगोन तहसील है। खरगोन तहसील खरगोन जिले की एक प्रमुख तहसील है। खरगौन तहसील मुख्यालय कुंदा नदी के तट पर स्थित है। खरगौन जिले का यह क्षेत्र मुख्य रूप से अत्यंत प्राचीन नवग्रह मन्दिर के लिये प्रसिद्ध है। खरगौन तहसील इंदौर से १५० कि.मी. दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र कपास एवं जिनिंग कारखानों का एक प्रमुख केन्द्र है। मक्का, तुवर एवं सोयाबीन खरीफ की तथा गेहूं एवं चना रबी की प्रमुख फसलें हैं। कपास तथा मिर्च प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं। खरगौन तहसील में छोटे, मध्यम व बड़े उद्योग हैं। खरगौन तहसील मे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पोलीटेक्निक महाविद्यालय तथा कई स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर के महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। प्रस्तुत अध्ययन खरगोन तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को केंद्र में रखकर सम्पन्न किया गया है।

अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु समंको का सकंलन प्राथमिक

तथा द्वितीयक स्त्रोतों द्वारा किया गया है। इसकें अंतर्गत खरगोन तहसील` के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत १०० युवाओ से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर साक्षात्कार अनुसूची द्वारा प्राथमिक समंक एकत्र किए गए है तथा कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र — पत्रिका बुलेटिन तथा आकड़ों द्वारा द्वितीयक समंक एकत्र किए गए। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य द्वितीयक स्त्रोतों द्वारा भी समंक एकत्र किए गए है।

विश्लेषण एवं व्याख्या

एकत्र किए गए प्राथमिक समंको को सांख्यिकीय तकनीको द्वारा वर्गीकृत करके उन्हे सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हुए विश्लेषण करके परिणाम निकाला है। जिनका विश्लेषण इस प्रकार है:—

तालिका —१

क्रमांक	ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी है।	संख्या	प्रतिशत
01	हाँ	38	38 प्रतिशत
02	नहीं	62	62 प्रतिशत
कुल		**100**	**100 प्रतिशत**
क्रमांक	**चयनित ग्रामीण युवाओ में शिक्षा का स्तर।**	**संख्या**	**प्रतिशत**
01	8वीं	20	20 प्रतिशत
02	10वीं	30	30 प्रतिशत
03	12वीं	50	50 प्रतिशत
कुल		**100**	**100 प्रतिशत**
क्रमांक	**ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रो की कमी है ?**	**संख्या**	**प्रतिशत**
01	हाँ	69	69 प्रतिशत
कुल		**100**	**100 प्रतिशत**
क्रमांक	**ग्रामीण क्षेत्रो में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन सही तरीके से हो रहा है ?**	**संख्या**	**प्रतिशत**
01	हाँ	37	37 प्रतिशत
02	नहीं	63	63 प्रतिशत
कुल		**100**	**100 प्रतिशत**

स्त्रोत :— सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़े

तालिका ०१ से स्पष्ट है कि खरगोन तहसील में ३८ प्रतिशत ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी है तथा ६२ प्रतिशत युवाओ को जानकारी ही नही है। क्योकि सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण युवाओ में ५० प्रतिशत, १२वी उत्तीर्ण है ३० प्रतिशत, १० वीं उत्तीर्ण है २० प्रतिशत, ८वीं उत्तीर्ण है। इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जागरूकता का अभाव है। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के बीच इस योजना के बारे में और अधिक प्रचार—प्रसार किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

खरगोन तहसील के ६९ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियो का मानना है कि यहाँ प्रशिक्षण केन्द्रो की कमी है तथा ३१ प्रतिशत निवासियो का मानना है कि यहाँ पर्याप्त प्रशिक्षण केन्द्र है। खरगोन तहसील के ६३ प्रतिशत ग्रामीण निवासी यह मानते है कि ग्रामीण क्षेत्रो में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन सही तरीके से नही किया जा रहा है जबकि ३७ प्रतिशत निवासियो का मानना है कि योजना का संचालन सही तरीके से हो रहा है।

परिणाम

प्रस्तुत शोध—पत्र के अध्ययन के अंतर्गत प्राथमिक समंको में विश्लेषण के आधार पर निम्न परिणाम प्राप्त किए गए:—

➢ खरगोन तहसील में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जागरूकता का अभाव है।

➢ खरगोन तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में पीमकेवीवाई के प्रशिक्षण केंद्र की कमी है।

➢ खरगोन तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।

सुझाव

प्रस्तुत शोध—पत्र के अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त परिणामो के आधार पर सुझाव इस प्रकार है:—

➢ खरगोन तहसील में ग्रामीण युवाओ को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी पर्याप्त मात्रा में देने के लिए योजना का प्रचार — प्रसार करना चाहिए।

➢ खरगोन तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की

कमी को दूर करना चाहिए ताकि ग्रामीण युवा योजना का लाभ ले सके।

➢ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत सरकार देश में बेरोजगारी को समाप्त कर देश को एक निर्माता (उत्पादक) राष्ट्र के तौर पर वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है और यह तभी संभव है जब यहां पर निर्माण कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल एवं प्रतिभा मौजूद हो। सरकार ने साल २०१४ में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया था। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन किया है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत शोध– पत्र ''खरगोन तहसील में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रति ग्रामीण युवाओं में जागरूकता'' अध्ययन के दौरान इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में खरगोन तहसील के ग्रामीण युवाओं में जागरूकता का अभाव है। इस बात की पुष्टी के लिए तालिका १ से हमें यह पता चला है कि ६२ प्रतिशत ग्रामीण युवाओ को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी ही नही है तथा ३८ प्रतिशत युवाओ को जानकारी है। ६९ प्रतिशत ग्रामीण युवाओं का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रो में प्रशिक्षण केन्द्रो का अभाव है तथा ३१ प्रतिशत लोगो का मानना है कि प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रो मे पर्याप्त है। प्रस्तुत अध्ययन से इस बात की भी जानकारी प्राप्त हुई है कि खरगोन तहसील में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।

सदंर्भ

1. https://pmkvyofficial.org/

2. https://www.msde.gov.in

3. Scheme document of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana - pmkvyofficial.org. (n.d.-b). https://www.pmkvyofficial.org/pmkvy2/App_Documents/News/PMKVY_Scheme-Document_v1.1.pdf

4. Joshi, A. K., & Pandey, K. N. (2021). Awareness, perceptions and youth mobilization towards PMKVY training in Haryana. Ashwani Kumar Joshi and KN Pandey, Awareness, Perceptions and Youth Mobilization towards PMKVY Training in Haryana. International Journal of Management, 11(11), 2020.

5. Publication, I. A. E. M. E. (2020). EFFECTIVENESS OF PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJNA TRAINING. IAEME PUBLICATION. https://doi.org/10.34218/IJM.11.12.2020.259

6. Nehru, R. (2022). AN IMPACT ANALYSIS OF PRADHAN MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA (PMKVY): OPPORTUNITIES TO IMPROVE.

7. http://en.m.wikipedia.org/wiki/skill_India

8. https://www.google.com/amp/s/m.economictimes.com/topic/PMKVY/amp

9. PMKVY Guidelines (2016-2020)

10. https://khargone.nic.in/

❑❑❑

02

युवाओं में कौशल विकास हेतु आवश्यक प्रयास एवं चुनौतियों का अध्ययन

डॉ. ममता गोयल (गोनेकर)
सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग
शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

****

सारांश —

आज के वैश्वीकरण के युग में बेहतर उत्पादकता और आर्थिक विकास के लिए श्रम की शक्ति और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौशल निर्माण एक महत्वपूर्ण साधन है किसी भी देश के वित्तीय विकास और सामुदायिक विकास के पीछे ज्ञान विकास एवं कौशल वे आवश्यक शक्तियां है जो कौशल निर्माण के साथ—साथ व्यक्ति को सशक्त बनाने का काम करती है एवं उनके सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा देती है।

कौशल विकास के क्षेत्र में प्रासंगिकता देखी जाए तो आज भारत को कुशल कार्य बल की आवश्यकता है अगर हमें अपने देश के विकास को बढ़ावा देना है तो हमारालक्ष्य कौशल विकास और कुशल भारत होना चाहिए।

एकसर्वेक्षण के अनुसार लगभग ९० प्रतिशत रोजगार के अवसरों के लिए व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता होती है हमारे देश की ७० प्रतिशत साक्षरता अनुपात की तुलना में हमारे केवल २० प्रतिशत डिग्री धारकयुवाओं को ही रोजगार मिल पाता है बाकी को रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है। वैश्वीकरण के वर्तमान संदर्भ में कुशल और बहु— कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ गई है इसलिए भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास और प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध आलेख भारत में युवाओं हेतु कौशल विकास के लिए वर्तमान स्थिति और रोजगारसंबंधी आवश्यक प्रयासभविष्य तथा जीविका एवं कौशल के अवसरों को बढ़ाने में कौशल विकास की भूमिका पर केंद्रित है।

शब्द कुंजी—कौशल विकास, युवा में कौशल की आवश्यकता, आवश्यकप्रयास, रोजगार, उद्यमिता।

प्रस्तावना —

आज के तेजी से बदलते माहौल में युवाओं को एक आशाजनक भविष्य को सुरक्षित करने के मामले में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। युवाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अल्परोजगार, बेरोजगारी और संभावनाओं की कमी शामिल है। लेकिन, इन बाधाओं को पार करने का एक तरीका है: कौशल विकास।

नई प्रतिभाओं को प्राप्त करने या मौजूदा प्रतिभाओं को बढ़ाने की प्रक्रिया को कौशल विकास कहा जाता है। इसमें नौकरी पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता, औपचारिक स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण सभी शामिल हैं। कौशल विकास के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि यह न केवल लोगों को बेहतर करियर की संभावनाएं खोजने में मदद करता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाता है। इस वैश्वीकरण युग में स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल विकास एक बुनियादी आवश्यकता है। वास्तव में २१वीं सदी में किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यह समय की मांग है, आज प्रत्येक बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा के साथ—साथ कौशल विकास आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी आवश्यक है।

कौशल विकास से तात्पर्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं की योग्यताओं, क्षमताओं और ज्ञान को बढ़ाने के लिए रूपरेखातैयार कर संगठित प्रयासों से है, ताकि उन्हें अधिक रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कौशल विकास में व्यावहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी विशेषज्ञता और व्यक्तिगत विकास शामिल है, जो युवा व्यक्तियों को इस पेशेवर समय के अनुरूप समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है।

युवाओं को किसी भी देश की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जिस देश में युवाओं को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, वह देश अपनी पूरी क्षमता का उपयोग सीमित सीमा तक ही कर पाता है। इस संबंध में, एक अच्छा कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो उनकी जन्मजातरूचिऔर उन्हें अपने क्षेत्र में प्रगति करने की अनुमति देता है।

कौशल विकास की अवधारणा—

कौशल विकास नई योग्यताओं, दक्षताओं और ज्ञान को बढ़ाने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के विभिन्न कार्यो और उद्योगों में प्रदर्शन और अनुकूलन क्षमता को बेहतर बनाती है। इसमें कार्यबल की मांगों के लिए व्यक्तियों को तैयार करने के लिए लक्षित प्रशिक्षण और शिक्षा शामिल है, उन्हें व्यावहारिक, नौकरी से संबंधित कौशल के साथ—साथ संचार, टीमवर्क, समस्या—समाधान और नेतृत्व जैसे व्यापक सॉफ्ट कौशल से लैस करना।

युवाओं के लिए कौशल विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें वर्तमान नौकरी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता है, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, और समग्र व्यक्तिगत विकास में योगदान देता है। प्रभावी कौशल विकास पहल न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है बल्कि एक सक्षम, गतिशील कार्यबल का निर्माण करके आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अध्ययन के उद्देश्य

१. इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास का पता लगाना तथा युवाओंकी रोजगार क्षमता पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना करना है।

२. कौशल विकास कार्यक्रमों में युवाओं की धारणाओं और अपेक्षाओं को समझना तथा ऐसे कार्यक्रमों के प्रति उनकी संतुष्टि के स्तर का निर्धारण करना।

३. रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का सुझाव देना।

साहित्य की समीक्षा

साहित्य समीक्षा मूल रूप से जानकारी के संग्रह पर एक विश्वास है जिसे शोधकर्ता ने शोध बताते हैं कि आज के शोधों से निकाले गए निष्कर्ष पिछले शोधों में भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न लेखकों द्वारा साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि उनके पास कौशल विकास प्रथाओं, चुनौतियों, मुद्दों और संभावनाओं पर गहन पकड़ थी जो इस प्रकार हैं:

पाटिल और चरंतिमथ (२०२१) ने ''कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार योग्यता और रोजगार योग्यता कौशल के महत्व का अवलोकन'' पर एक अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य रोजगार योग्यता कौशल के महत्व को समझना और अपेक्षित कौशल और विकसित कौशल के बीच अंतर का पता लगाना था। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि उम्मीदवारों, सरकार, शैक्षिक संस्थानों और प्रशिक्षण भागीदारों जैसे हितधारकों की प्रभावी भागीदारी से रोजगार योग्यता की दर को बेहतर बनाया जा सकता है। उद्योग—संस्थान इंटरफेस के साथ बुनियादी सुविधाओं में सुधार, पाठ्यक्रम उन्नयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक—निजी भागीदारी कौशल विकास कार्यक्रमों के उचित वित्तपोषण, नियंत्रण और समीक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

संजीव और हजारिका (२०२१) ने ग्रामीण उद्यमिता के लिए कौशल विकास विषय पर एक शोध किया: राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), असम पर एक अध्ययन। इस शोध का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न कौशल—विकास संसाधनों की जांच करना है और साथ ही संस्थान द्वारा असम में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रेरक मूल्य की भी जांच करना है। कवर किया गया क्षेत्र असम था और असम के जिले से डेटा एकत्र किया गया था और विश्लेषण किया गया था और यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रगतिशील विकास हुआ क्योंकि लोग कुशल हो गए और बाद में उन्हें रोजगार मिला।

स्वैन और सुनीता (२०२०) ने ''भारत में कौशल विकास: चुनौतियां और अवसर'' पर एक शोध किया, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के साथ—साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जैसी विभिन्न

सरकारी योजनाओं को उजागर करना था या जिसे प्रधानमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए भारत सरकार की एक कौशल विकास पहल योजना है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू—जीकेवाई) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना है जो गरीब हैं और उन्हें नियमित मासिक वेतन या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहलों के समूह में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना चाहता है।

युवाओं के लिए रोजगार हेतु कौशल विकास की भूमिका :—

कौशल विकास युवाओं के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परंपरागत शिक्षा और वर्तमानमें नौकरी की आवश्यकताओं के बीच के बीच के अंतर को कम करता है, जिससे युवा व्यक्ति कार्यबल में अधिक रोजगार योग्य और प्रतिस्पर्धी बनते हैं। इस शोध में यह बताने का प्रयास किया गया है कि कौशल विकास रोजगार के लिए कितना सहायक होसकता है।

जीविका तथा बाजार की मांग को पूरा करना:

प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता मानकों के लगातार विकसित होने के साथ, नियोक्ता विशिष्ट तकनीकी कौशल और व्यावहारिक ज्ञान वाले उम्मीदवारों की तलाश करते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि युवा वर्तमान कौशल से लैस हों, जिससे वे तेजी से बदलते जीविका व्यवसाय में अधिक अनुकूलनीय और मूल्यवान बन सकें।

बेरोज़गारी कम करने में सहायक :

युवाओं को योग्यता अनुसारवाली जीविका व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करके, कौशल विकास कार्यक्रम बेरोज़गारी दरों को कम करते हैं और युवाओं को स्थायी कैरियर के अवसर प्रदान करते हैं। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ युवा बेरोज़गारी अधिक है।

उद्यमिता को बढ़ावा देना :

कौशल विकास केवल रोजगार पर ही केंद्रित नहीं है; यह युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए भी सशक्त बनाता है। वित्तीय साक्षरता, विपणन और प्रबंधन जैसे उद्यमशीलता कौशल युवाओं को अपना खुद का उद्यम शुरू करने और विकसित करने की अनुमति देते हैं, जिससे दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा होता है।

कमाई की संभावना बढ़ाना :

उच्च मांग वाले क्षेत्रों से संबंधित कौशल अक्सर बेहतर वेतन वाली नौकरियों की ओर ले जाते हैं। इन कौशलों को हासिल करके, युवा लोग अपनी कमाई की क्षमता में सुधार करते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और जीवन स्तर में सुधार होता है।

आत्मविश्वास और उत्पादकता बढ़ाना:

कौशल विकास युवाओं को कार्य कुशलता से करने में सक्षम बनाकर आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह उत्पादकता भी बढ़ाता है, क्योंकि कुशल व्यक्ति अपने संगठनों में अधिक प्रभावी और कुशलतापूर्वक योगदान दे सकते हैं।

आर्थिक विकास में योगदान: कुशल कार्यबल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। जब युवाओं को सही कौशल से लैस किया जाता है, तो वे उच्च उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देते हैं, जिससे आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा मिलता है।

कौशल विकास एवं तकनीकी प्रगति

कौशल विकास में प्रौद्योगिकी का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में नाटकीय रूप से विकसित हुआ है। ई—लर्निंग संसाधनों, दूरस्थ प्रशिक्षण और वर्चुअल प्लेसमेंट के उपयोग ने लाखों युवाओं को ऐसे कौशल हासिल करने में मदद की है जो पहले उनकी पहुँच से बाहर थे। आज अपने शुरुआती डेवलपर द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम को सीखने की दक्षता बढ़ने के लिए वीआर और यहां तक कि एआर जैसे उपकरणों को एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए।

एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विश्लेषण करने और व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है। नतीजतन, तकनीकी प्रगति ने कौशल विकास में सीखने को सार्वभौमिक बना दिया

है और ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच की खाई को कम कर दिया है। इसने ऐसे कार्यक्रमों की तैनाती को भी सक्षम किया है जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है ताकि कोई भी युवा पीछे न छूट जाए।

कौशल विकास हेतु सरकार की नीतियां एवं आवश्यक प्रयास

सरकार ने कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की नीतियां और पहल शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। युवाओं के लिए कौशल विकास पर केंद्रित सरकार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नानुसार है।

१. कौशल भारत मिशन

सन २०१५ में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य ४०० मिलियन से अधिक लोगों को नौकरी—संबंधित कौशल देना है। यह एक व्यापक पहल है जो विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों और नीतियों को जोड़ती है इस योजना के प्रमुख घटक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और औपचारिक कौशल मान्यता पर जोर देती हैं।

२. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

पीएमकेवीवाई कौशल भारत के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम है, जो नौकरियों के लिए अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित हैइसकी विशेषताए पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल), और युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने हेतु उद्योग—संरेखित प्रमाणन प्रदान करता है। यह लाखों लोगों को उच्च मांग वाले क्षेत्रों, जैसे आईटी, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण के लिए व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है, तथा शिक्षा और रोजगार के बीच के अंतर को पाटता है।

३. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू—जीकेवाई)

यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए तैयार किया गया है। इसकार्यक्रम कीविशेषताएं डीडीयू—जीकेवाई विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन में नौकरी दिलाने में सहायता के साथ नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है इसका उद्देश्य न केवल नौकरी कौशल को बढ़ाना है, बल्कि ग्रामीण युवाओं को शहरी नौकरी बाजारों से जोड़कर गरीबी उन्मूलन में भी योगदान देना है।

४. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

एनएपीएस नियोक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन के साथ प्रशिक्षुता के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है, जिससे युवाओं के लिए कार्यबल में शामिल होना आसान हो जाता है।

५. अटल इनोवेशनमिशन (एआईएम)

एआईएम युवाओं में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से स्कूलों में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से। युवा छात्रों को प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग करने और समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तथा व्यावहारिक शिक्षा और तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देता है।

ये प्रमुख कार्यक्रम संरचित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भारत के युवाओं को पारंपरिक और उभरते दोनों प्रकार के नौकरी बाजारों के लिए तैयार करना है।

कौशल विकास में शिक्षण संस्थानों की भूमिका

किसी भी कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, सरकारी निकायों और गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों पर निर्भर करती है। शिक्षण की नींव रखने में शैक्षणिक संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, उन्हें उद्योगों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अपने पाठ्यक्रम को बदलने की ज़रूरत है। उद्योग इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और ऑन—द—जॉब प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि प्रदान किए गए कौशल बाजार की मांगों के लिए

प्रासंगिक हैं, जिससे रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। गैर सरकारी संगठन और अन्य सामुदायिक संगठन कौशल विकास पहलों को अधिक समावेशी बनाने में मदद करते हैं, वंचित क्षेत्रों में युवाओं तक पहुँचते हैं और ऐसे संसाधन प्रदान करते हैं जो अन्यथा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

कौशल विकास हेतु भविष्य की संभावनाएं और सुझाव :—

बदलते परिदृश्य में युवाओं के लिए कौशल विकास का भविष्य जीवंत और संभावनाओं से भरा हुआ है, जो मुख्य रूप से तकनीकी नवाचारों, जीविकाव्यवसाय की उभरती आवश्यकताओं और सरकारी पहलों से प्रेरित है। यहाँ कुछ प्रमुख रुझान और क्षेत्र दिए गए हैं जो कौशल विकास के क्षेत्र में आवश्यक प्रयास साबित हो सकते हैं।

१. डिजिटल साक्षरता औरउभरती प्रौद्योगिकियां

जैसे—जैसे भारत अपने डिजिटल परिवर्तन को जारी रखता है, युवाओं के बीच डिजिटल साक्षरता की मांग बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कौशल महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम अधिक मुख्यधारा बनेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवा भविष्य के नौकरी बाजार के लिए तैयार हैं।

२. सॉफ्टस्किल्स को बढ़ावा देना

तकनीकी कौशल के अलावा, संचार, टीमवर्क और समस्या—समाधान जैसे सॉफ्ट स्किल्स के महत्व को भी मान्यता मिल रही है। भविष्य के कौशल विकास कार्यक्रमों में युवाओं की समग्र रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण को तेजी से एकीकृत किया जाएगा, जिससे उन्हें विभिन्न व्यावसायिक सेटिंग्स में अधिक अनुकूल बनाया जा सकेगा।

३. अपस्किलिंग और रीस्किलिंग

तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति के साथ, निरंतर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग आवश्यक हो जाएगी। आज कई नौकरियों में कर्मचारियों को लगातार नए उपकरणों और प्रक्रियाओं के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। कौशल विकास कार्यक्रम लचीले, मॉड्यूलर पाठ्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो युवा व्यक्तियों को उद्योग में होने वाले बदलावों के साथ तालमेल बिठाने और आवश्यकतानुसार बदलाव करने में सक्षम बनाते हैं।

४. प्रशिक्षण द्वारा प्रौद्योगिकी का एकीकरण

वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) जैसी तकनीकें इमर्सिव, व्यावहारिक प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करके कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना जारी रखेंगी। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म भी बढ़ेंगे, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक सुलभ सीखने के अवसर प्रदान करेंगे।

५. उद्योग क्षेत्र एवं प्रशिक्षणवशैक्षणिक संस्थान के मध्य संबंधता द्वारा

कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने में शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिक साझेदारियाँ उभरने की उम्मीद है, जहाँ उद्योग व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और अवसर प्रदान करते हैं, और शिक्षाविद आधारभूत ज्ञान के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

६. सरकारी पहल और वित्तपोषण

कौशल विकास कार्यक्रमों के संधारण और विस्तार में सरकार की भूमिका मौलिक बनी रहेगी। वित्तपोषण के स्तर को बढ़ाना, निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना और नई पहल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। सरकार के प्रयासों में समावेशिता हासिल करने के प्रयास में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना भी शामिल होगा।

७. हरित कौशल और स्थिरता

बदलती दुनिया के साथ, हरित कौशल की संख्या में उत्तरोत्तर वश्द्धि आवश्यक हो जाएगी। युवाओं को अक्षय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और कई अन्य चीजों पर कौशल से लैस होने की आवश्यकता होगी। कौशल विकास कार्यक्रम इस तरह विकसित होंगे कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों के लिए कौशल प्रशिक्षण का एकीकरण होगा।

निष्कर्ष :—

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है की

कौशल विकास युवा लोगों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह उद्यमशीलता में वृद्धि, रोजगार की अधिक संभावनाओं और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों के पास गतिशील नौकरी बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक क्षमताएं और जानकारी है, सरकारी, निजी व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों को एक साथ काम करना अति आवश्यक है ताकि हम कौशल विकास में निवेश करके अपने युवाओं और अपने देश को बेहतर भविष्य दे पाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1.https://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/49107369.cms?utm_ source=contento

2. https://msde.gov.in/en/schemes-initiatives

3.https:labor.gov.in.fleg

४. सिंह, सचिता(२०२१) ''कौशल विकास'' पश. क्र. १—१५ प्रकाशक, आत्माराम एंड सन्स

५. शर्मा ,रामचंद्र (२०१७) ''कौशल विकास'' पृ. क्र.१—३८ एप्पल बुक्स पब्लिकेशन

६. कौशल विकास नीति (२०१५)

❑❑❑

03

कौशल विकास की रोजगार निर्माण में भूमिका

डॉ. अनुराधा ठाकुर
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन

****

सारांश

रोजगार निर्माण किसी भी देश के लिए अत्यन्त महात्वपूर्ण है, विशेष कर एक विकासशील देश के लिये जहां आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। भारतकी बढ़ती जनसंख्या, भारत का युवा देश होना, रोजगार की आवश्यकता को रोजगार की मांग को और बढ़ा रहा है। इसलिए नीति निर्मताओ के लिए कौशल विकास मुख्य लक्ष्य बन चुका है।

कौशल विकास एक ऐसी अवधारणा है। जो रोजगार निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाता है और बदलती हुई नौकरी बाजार की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें तैयार करता है इस शोध पत्र में कौशल विकास की भूमिका का अध्ययन किया गया है। जो यह दर्शाता है कि कौशल आधारित प्रशिक्षण रोजगार सृजन, उत्पादकता में सुधार और सतत आर्थिक विकास में कैसे योगदान करता है यह अध्ययन विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है जो युवाओं और हाशिये पर खड़े समुदायों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर आर्थिक समावेशन और बेरोजगारी में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं।

शब्द कुंजी — कौशल विकास, रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण,युवा रोजगार आर्थिक वृद्धि

भूमिका

रोजगार निर्माण में कौशल विकास एक महात्वपूर्ण कड़ी है।

कौशल अंतर को दूर करना भारत में बेरोजगारी

के मुख्य कारणो में से एक है श्रमिकों के कौशल और नियोक्ताओं की आवश्यकताओं के बीच अंतर होना भी एक समस्या है सबहुत से नौकरी चाहने वाले शिक्षित होते हैं लेकिन उनके पास अपने क्षेत्र में व्यावसायिक कौशल नहीं होते जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न करता है उदाहरण के तौर पर कई स्नातक एसे हैं जो उद्योग, विशिष्ट कार्यो के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित ही नहीं है कौशल विकास कार्यक्रम इस अंतर को दूर करने का प्रयास करते हैं यह कार्यक्रम ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता जैसी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इस प्रकार के प्रशिक्षण से व्यक्तियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है और उनके लिए नौकरी प्राप्त करना आसान हो जाता है।

रोजगार निर्माण में केवल कौशल आधारित नौकरी पाने पर ही जोर नहीं दिया जाता बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए कौशल भी आये यानी स्वरोजगार के लिए उसे प्रशिक्षण मिले कौशल विकास कार्यक्रम जो उद्यमिता व्यवसाय प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं इससे वह अपने छोटे या बड़े व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और नए रोजगार अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।

कौशल विकास के लिए सरकारी नीतियों और योजनाएं

वर्तमान में कौशल विकास से संबन्धित अनेक योजनाएँ भारत में संचलित है जिसमें से प्रमुख है—

१. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे २०१५ में लॉन्च किया गया था भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो उन्हें रोजगार बाजार में एक पहचान और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं। इस योजना का उद्देश्य १० मिलियन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे निर्माण स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है यह योजना कौशल प्रशिक्षण के साथ—साथ मूल्यांकन और प्रमाणन पर भी ध्यान केंद्रित करती है जिससे प्रशिक्षित व्यक्तियों में की नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाती है।

२. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन —

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन एनएसएस २०१५ में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य कौशल विकास के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा बनाना है इसका उद्देश्य गुणवत्ता को बेहतर बनाना प्रशिक्षण को अधिक सुलभ बनाना कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था को अधिक समग्र और समावेशी बनाना है यह मिशन कौशल विकास एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण और प्रशिक्षक और सामग्री उद्योग की जरूरत के अनुरूप हो।

३. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना :

यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं के लिए है जो उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाती है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और और उन्हें राष्ट्रीय और स्थानिय रोजगार बाजारों से जोड़ना है ताकि वह शहरों में पलायन करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही अर्थव्यवस्था में योगदान कर सके।

४. अटल मिशन का रिज्यूमरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन :—

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन :—

यह योजना शहरी विकास पर केंद्रित है। लेकिन इसके तहत कौशल विकास के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं विशेष रूप से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और शहरी प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में इसके माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों को शहरी विकास परियोजनाओं में कार्य करने के लिए कौशल मिलता है जिससे शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।

कौशल विकास का रोजगार निर्माण पर प्रभाव :—

१. रोजगार अवसरों में वृद्धि :— कौशल विकास कार्यक्रम के प्रभाव से स्पष्ट होता है ईन

योजनाओं के माध्यम से कई युवाओं को नौकरी मिली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत लाखों लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान किया गया है उसके माध्यम से यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन में भी योगदान कर रहे हैं। नौकरी बाजार में समायोजन कौशल विकास कार्यक्रम को माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रशिक्षित व्यक्ति नौकरी बाजार की मांग के अनुसार कौशल हासिल कर सके उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग से या सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रशिक्षण प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम उद्योगों की बदलता जरूर के अनुसार अपडेट रहे. आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता कौशल विकास श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार लाता है जिससे औद्योगिक की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है और समग्र आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ता है प्रशिक्षित श्रमिक अधिक कुशल और अभिनव होते हैं जो न केवल अपने कार्य क्षमता को बढ़ते हैं बल्कि उद्योगों के लिए भी न नई सोच और कार्य शैली लेकर आते हैं।

कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में चुनौतियां :—

१. बुनियादी ढांचे की कमी —

भारत के कई दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है प्रशिक्षण क्षेत्र की प्रशिक्षण की कमी है यह है की प्रशिक्षकों की कमी और उपकरणों की अपर्याप्तता तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है इन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान महत्वपूर्ण है ताकि कौशल विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सके।

२. जागरूकता और पहुंच :—

ग्रामीण इलाकों में कौशल विकास के अवसरों के बारे में जागरूकता की कमी है इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण भी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के मुकाबले कम है इन चुनौतियों को हल करने के लिए अधिक जागरूकता अभियानों और समुदाय स्तर पर पहुंच की आवश्यकता है।

३. स्वरोजगार और नौकरी प्राप्ति में कठिनाई:—

कई बार कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण तो दे दिया जाता है लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति को नौकरी मिलने में समस्याएं आती है सुनिश्चित करने के लिए की प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिले नौकरी मिलन सेवाओं में सुधारो और उद्योग मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

कौशल विकास रोजगार निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह न केवल व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाता है बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान करता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना जैसी योजनाएं देश में कौशल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हालांकि बुनियादी ढांचे की जागरूकता और नौकरी मिलने की समस्या अभी भी मौजूद है लेकिन उन इन चुनौतियों का समाधान करके इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है कौशल विकास न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का एक माध्यम है बल्कि यह राष्ट्र विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है जो भारत के युवा कार्यबल को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाता है।

संदर्भ सूची :—

१. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय २०२३.

२. वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार।

३. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना २०२३ आधिकारिक मार्गदर्शिका और प्रभाव रिपोर्ट।

४. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन रूपरेखा और कार्यान्वयन योजना भारत सरकार।

५. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना प्रगति रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र

❑❑❑

04

जनजातीय समाज में स्वरोजगार के अवसर और कौशल विकास : खरगोन जिले (म.प्र.) के संदर्भ में

डॉ. उषा वैद्य
शोध निर्देशक, समाजशास्त्र
मानविकी एवं उदारकला संकाय रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन (म.प्र)

विनोद कुमार पटेल
शोधकर्ता
नामांकन क्रमांक AU212427
आर.डी.सी.क्रमांक R21SS5SW0014

****

१. प्रस्तावना

भारत एक विविधता वाला देश है, जहां अनेक जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली के साथ रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के ७५ वर्ष पूरे होने पर आज भी जनजातिय समुदाय के विकास की मुख्यधारा से अलग—थलग दिखाई देता है, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर विकास के लिए किये जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद उनकी स्थ्ति में विशेष सुधार न होना और उनकी अधिकांश आबादी द्वारा विकास का मुंह नही देख पाना एक बहुत बडी विडम्बना है।

जनजाति समुदायों के पास एक वैश्विक नजरिया है जो गैर—जनजाति से अलग है क्योंकि जनजाति खुद को प्रकृति के अन्य जीवों से श्रेष्ठ नहीं मानते और मानव उद्देश्यों के लिए धन के बटोरने और प्रकृति के दोहन में विश्वास नहीं करते हैं। यह वैश्विक नजरिया प्रकृति और समाज के साथ उनके संबंधों को आकार देती है और रोजी—रोटी सहित उनकी प्रथाओं को प्रभावित करती है। शहरों और गांवों में रहने वाले जनजाति समुदायों उनकी रोजी रोटी के मार्ग अलग—अलग हो सकते हैं लेकिन उन दोनों में वही वैश्विक नजरिया है।

जनजातियों का अपना एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन होता है जो विरासत के रूप में पीढी दर पीढी हस्तांतरित होता रहता है। आज का आधुनिकीकरण का युग है, जिसका प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर पड रहा है। इसके प्रभाव से जनजाति के लोग भी अछूते नहीं है। शिक्षा से जनजातियों के भौतिक व अभौतिक संस्कृतियों में परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा के प्रसार, आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि एवं आजीविका उपार्जन के लिए नवीन प्रवृत्तियों से इनके सामाजिक, आर्थिक जीवन में सुधार हुआ है या नहीं। धार्मिक कर्मकांड और सामाजिक रीति—रिवाजों एवं परंपरा से युक्त पारिवारिक और नवीन मूल्यों, आदर्शो के परिणाम स्वरूप जनजाति समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों में क्या परिवर्तन हो रहा है तथा जनजाति महिलायें बदलते सामाजिक परिवेश में सामंजस्य बिछाकर अपना विकास कर पा रही है या नहीं। आधुनिकता के इस दौर में आज भी हम जनजातियों के विकास के लिए उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर पा रहे है। इसके साथ ही यह अध्ययन जनजाति पर शिक्षा के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव एवं जनजाति समाज में उत्पन्न समस्या को हल करने तथा इनके विकास हेतु उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है।

खरगोन जिले के कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि उच्च शिक्षा के उपलब्ध होने से जनजाति समुदायों की स्थानीय समाज में गतिशीलता बढी है और उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता का बढना उनके समाज में एक बहुत बडी उपलब्धि साबित होगी।

१.१ अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान में निम्नांकित समस्यायें हैं—

१. जनजाति समुदाय दशकों से विस्थापित और बेदखल, आजादी के बाद से भी सरकारी क्रार्यक्रमों और सुविधाओं से अनदेखा, भारत में आबादी केवल आठ

प्रतिशत होने से चुनावी राजनीति में अहम न होना।

२. आदिवासी उपजीविका की दशा प्रतिवेदन २०२१ के अनुसार उनके अभाव की स्थिति के बारे में बताती है कि जनजाति सबसे अधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहते हैं और अभी भी उन संसधनों तक उनकी पहुंच और नियंत्रण नहीं है। जिस जमीन पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं, वह उद्योगपतियों और राज्य के लिए आकर्षण का केंद्र रही है।

३. उच्च शिक्षा के माध्यम से जनजाति समुदायों को सामाजिक और आर्थिक रुप से स्थिर होने के लिए मदद मिलने की संभावना है।

४. चूंकि जनजाति समुदाय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अधिक दूर जाना पड़ता है। इसलिए, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अधिक विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता अन्य अध्ययनों द्वारा खगोन जिले के संदर्भ में बताई गई है।

५. यह भी बताया गया हैं कि नई प्रौद्योगिकी, तकनीक, ज्ञान और उच्च शिक्षा के माध्यम से अवगत होने के अनुन्तर जनजाति समुदाय अपना विकास और समाज में उन्नति कर सकता है।

मध्य प्रदेश का खरगोन जिला जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहां भील, भिलाला और पटेलिया जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। इन जनजातियों का जीवन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और वनों पर निर्भर है। आधुनिक समय में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास अत्यंत आवश्यक हो गया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

२. जनजातीय समाज की स्थिति और चुनौतियाँ :

खरगोन जिले में जनजातीय समाज को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है

१. शिक्षा का अभाव :

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।

२. आर्थिक पिछड़ापन :

संसाधनों की कमी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है।

३. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी :

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव उन्हें और अधिक पिछड़ा बनाता है।

४. बाजार तक पहुँच का अभाव :

उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को सही बाजार नहीं मिल पाता, जिससे वे उचित लाभ नहीं कमा पाते।

३. स्वरोजगार के अवसर

स्वरोजगार जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी साधन है। खरगोन जिले में निम्नलिखित स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं

१. कृषि आधारित स्वरोजगार

➢ जैविक खेती और औषधीय पौधों की खेती।
➢ आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग।

२. हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग

➢ बांस, लकड़ी और मिट्टी के उत्पादों का निर्माण।
➢ परंपरागत वस्त्र और आभूषण निर्माण।

३. वन उत्पादों का व्यापार

➢ महुआ, तेंदूपत्ता, शहद और चिरौंजी का संग्रह और विपणन।
➢ वन औषधियों का प्रसंस्करण।

४. पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम

➢ जनजातीय संस्कृति आधारित पर्यटन।
➢ मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों का व्यापारिक उपयोग।

५. पशुपालन और डेयरी उद्योग

➢ डेयरी फार्मिंग।
➢ मुर्गी और बकरी पालन।

४. कौशल विकास के अवसर

जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौशल विकास किया जा सकता है

१. तकनीकी प्रशिक्षण

➢ कंप्यूटर साक्षरता।
➢ मोबाइल रिपेयरिंग और ई—कॉमर्स।

२. उद्यमिता प्रशिक्षण

➢ छोटे उद्योगों को स्थापित करने का प्रशिक्षण।
➢ वित्तीय साक्षरता।

३. सरकारी योजनाओं का लाभ

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना।

४. महिला सशक्तिकरण

- महिला स्व—सहायता समूह (SHG) का गठन।
- सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण।

५. सरकार और सामाजिक संगठनों की भूमिका

जनजातीय समाज के उत्थान में सरकार और गैर—सरकारी संगठनों (NGO) की भूमिका महत्वपूर्ण है।

१. प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।

२. स्वरोजगार योजनाओं का सही क्रियान्वयन।

३. जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार की व्यवस्था।

४. महिलाओं और युवाओं को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

६. समाधान और सुझाव

- जनजातीय क्षेत्रों में अधिक कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएँ।
- स्थानीय उत्पादों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार उपलब्ध कराया जाए।
- महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए।

७. निष्कर्ष

खरगोन जिले के जनजातीय समाज के विकास के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार की दिशा में प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से न केवल जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर सकते हैं।

जनजातीय समाज के सशक्तिकरण से न केवल उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि यह राष्ट्र के संपूर्ण विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

संदर्भ (References)

१. भारत सरकार — जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

- https://tribal-nic-in/

२. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

- https://www-pmkvyofficial-org/

३. मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Welfare Department] Madhya Pradesh)

- https://www-tribal-mp-gov-in/

४. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

- https://aajeevika-gov-in/

५. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) जनजातीय समुदायों में कौशल विकास पर रिपोर्ट

- https://www-undp-org/

६. जनजातीय क्षेत्रों में विकास : एक अध्ययन (Tribal Development Studies)

- लेखक : डॉ. रमेश चंद्र, प्रकाशन : ओरिएंट ब्लैकस्वान

७. स्थानीय अखबार और रिपोर्ट्स (Local Government Reports and News Articles)

- दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, और अन्य क्षेत्रीय समाचार पत्र।

८. शोध—पत्र और जर्नल्स (Research Papers & Journals)

- Tribal Empowerment through Skill Development* – Indian Journal of Social Work

❑❑❑

05

महिलाओं में तकनीकी कौशल का रोजगार पर प्रभाव

अनिता मालवीया
(पीएच.डी. शोधार्थी)
डॉ. बीआर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान
विश्वविद्यालय महू, इंदौर

डॉ. राजेन्द्र कुमार यादव
सह—प्राध्यापक,
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन

****

सारांश

यह शोध महिलाओं में तकनीकी कौशल के विकास और इससे उनके रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन अध्ययन करता है। शोध के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि तकनीकी कौशल महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर कैसे प्रदान करते हैं और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में किस प्रकार योगदान देते हैं। शोध के निष्कर्षों से पता चलता है कि तकनीकी कौशल महिलाओं को न केवल विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाते हैं। हालांकि, महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सामाजिक पूर्वाग्रह, शिक्षा में असमानता और कार्य—जीवन संतुलन। शोध में सुझाव दिया गया है कि महिलाओं में तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और कार्यस्थलों पर समावेशी वातावरण बनाना आवश्यक है।

प्रस्तावना

२१वीं सदी में तकनीकी क्रांति ने रोजगार के परिदृश्य को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है, जिसमें महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय समाज में, जहाँ पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ लंबे समय से प्रचलित रही हैं, तकनीकी कौशल महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन गए हैं जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करते हैं। वर्तमान डिजिटल युग में, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र महिलाओं के लिए नए और आकर्शक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इन क्षेत्रों में, तकनीकी कौशल न केवल व्यक्तिगत आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को भी बढ़ावा देते हैं। हालाँकि, इस तकनीकी परिवर्तन के बावजूद, महिलाओं को अभी भी कई संरचनात्मक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा तक सीमित पहुँच, लैंगिक पूर्वाग्रह, कार्यस्थल पर भेदभाव और सामाजिक मानदंड जैसी बाधाएँ महिलाओं की तकनीकी क्षमताओं को सीमित करती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी शिक्षा तक पहुँच की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। महिलाओं में तकनीकी कौशलों का विकास केवल व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। जब महिलाएँ तकनीकी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करती हैं, तो वे न केवल अपने लिए नए मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा भी बनती हैं। यह शोध इसी संदर्भ में महिलाओं में तकनीकी कौशलों के प्रभाव और महत्व की गहन समझ विकसित करने का प्रयास करता है।

तकनीकी कौशल का महत्व—

तकनीकी कौशल न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये कौशल न केवल व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने में मदद करते हैं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। तकनीकी कौशल वाले व्यक्ति नई तकनीकों को अपनाने में अधिक सक्षम होते हैं और वे बदलते हुए समय के साथ खुद को ढाल सकते हैं।

तकनीकी कौशल कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं।

➢ रोजगार के अवसर— तकनीकी कौशल वाले लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर होते हैं।

➢ वेतन वृद्धि— तकनीकी कौशल वाले लोग आमतौर पर अधिक वेतन प्राप्त करते हैं।

➢ आत्मनिर्भरता— तकनीकी कौशल आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं और आपको अपने करियर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

➢ नवाचार— तकनीकी कौशल आपको नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद करते हैं।

महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल का महत्व

महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल का महत्व और भी अधिक है। पारंपरिक रूप से, महिलाओं को घर के कामों तक सीमित रखा जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तकनीकी कौशल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद कर सकते हैं और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिला सकते हैं।

शोध के उद्देश्य

१. महिलाओं में तकनीकी कौशल के स्तर का आकलन करना।

२. तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसरों के बीच संबंध का विश्लेशण करना।

३. तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

४. महिलाओं में तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियॉं सुझाना।

शोध की प्रासंगिकता

यह शोध इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज के समग्र विकास से जुड़ा हुआ है। तकनीकी कौशल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं और उन्हें समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

तकनीकी कौशल का अर्थ और प्रकार—

'तकनीकी कौशल' का अर्थ है किसी विशेष तकनीक या उपकरण का उपयोग करने की क्षमता। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्रदान करता है। आज के तकनीकी युग में, तकनीकी कौशल लगभग हर क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र बन गया है।

तकनीकी कौशल के प्रकार

तकनीकी कौशल कई प्रकार के होते हैं, और ये विभिन्न क्षेत्रों में लागू होते हैं। कुछ प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं।

१. कंप्यूटर कौशल

➢ सॉफ्टवेयर कौशल— विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आदि का उपयोग करने की क्षमता।

➢ प्रोग्रामिंग विभिन्न प्रोग्रामिंग भाशाओं जैसे पाइथन, जावा, सी++ आदि का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता।

➢ डेटा विश्लेषण— डेटा को एकत्रित करने, विश्लेषण करने और उससे अर्थ निकालने की क्षमता।

२. इंजीनियरिंग कौशल

➢ डिजाइनिंग— विभिन्न उत्पादों या सिस्टम को डिजाइन करने की क्षमता।

➢ निर्माण— विभिन्न संरचनाओं या उत्पादों का निर्माण करने की क्षमता।

➢ रखरखाव— मशीनों या उपकरणों को बनाए रखने की क्षमता।

३. डिजिटल मार्केटिंग कौशल

➢ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO)— वेबसाइट को सर्च इंजन में ऊपर लाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना।

➢ सोशल मीडिया मार्केटिंग— सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करना।

➢ पेड मार्केटिंग— ऑनलाइन विज्ञापनों का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करना।

४. अन्य तकनीकी कौशल

➢ नेटवर्किंग— कंप्यूटर नेटवर्क को स्थापित करने और प्रबंधित करने की क्षमता।

➢ साइबर सुरक्षा— कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग

करना।

➢ रोबोटिक्स— रोबोट को डिजाइन करने और प्रोग्राम करने की क्षमता।

महिलाओं में तकनीकी कौशल का विकास

तकनीकी के युग में, तकनीकी कौशल न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हैं, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। महिलाओं में तकनीकी कौशल का विकास न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि समाज में समग्र विकास में भी योगदान देता है।

महिलाओं में तकनीकी कौशल विकास की आवश्यकता

➢ **रोजगार के अवसर** — तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।

➢ **आर्थिक सशक्तिकरण**— तकनीकी कौशल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाते हैं।

➢ **समाज में समानता**— तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

➢ **नवाचार**— महिलाएं तकनीकी क्षेत्र में नए नवाचार ला सकती है।

महिलाओं में तकनीकी कौशल विकास की चुनौतियाँ

➢ **सामाजिक पूर्वाग्रह** — समाज में महिलाओं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह होते हैं जो उन्हें तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकते हैं।

➢ **शिक्षा में असमानता**— कई महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नही मिल पाता है।

➢ **कार्य—जीवन संतुलन** — महिलाओं को अक्सर घर और काम दोनों को संभालना होता है, जिससे उन्हें तकनीकी कौशल सीखने के लिए कम समय मिलता है।

महिलाओं में तकनीकी कौशल विकास के लिए उपाय—

➢ **शिक्षा में सुधार**— स्कूली स्तर से ही लड़कीयों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रात्साहित किया जाना चाहिए।

➢ **प्रशिक्षण कार्यक्रम**— महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।

➢ **समाज में जागरूकता**— लोगों को महिलओं के तकनीकी क्षेत्र में योगदान के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

➢ **कार्य स्थल पर समावेशी वातावरण**— कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए एक समावेशी वातावरण बनाया जाना चाहिए।

➢ **Mentorship program-** सफल महिलाओं को मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जो अन्य महिलाओं को मार्गदर्शन दे सकें

➢ **अन्य—**

सरकारी योजनाएं— सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है।, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है।

NGOs का योगदान — कई गैर सरकारी संगठन महिलाओं को तकनीकी कौशल सिखाने के लिए काम कर रहे हैं।

ओनलाइन प्लेटफॉर्म— ब्वनतेमतंए न्कमउप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाएं मुफ्त या सस्ते में तकनीकी कौशल सीख सकते हैं।

तकनीकी कौशल का रोजगार पर प्रभाव —

आज का युग तकनीकी का युग है। हर क्षेत्र में तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा हैं, और इसी के साथ तकनीकी कौशल की मांग भी बढ़ रही है। तकनीकी कौशल न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं।

१. रोजगार के अवसरों में वृद्धि —

तकनीकी के विकास के साथ—साथ नए—नए क्षेत्रों का उदय हो रहा है, जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि। इन क्षेत्रों में तकनीकी कौशल वाले लोगों की बहुत मांग हैं। तथा तकनीकी क्षेत्र में रोजगार अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। तकनीकी लगातार बदलती रहती है, इसलिए तकनीकी कौशल वाले लोंगो को नौकरी खोने का खतरा कम होता है। एवं तकनीकी कौशल वाले लोगों को अन्य क्षेत्रों के लोगों की तुलना में अधिक वेतन

मिलता हैं।

२. करियर की प्रगति — पदोन्नति के अवसर, तकनीकी कौशल वाले लोग अपने संगठन में तेजी से पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और तकनीकी क्षेत्र में नए—नए कौशल सीखने के अवसर हमेशा बने रहते हैं। तथा तकनीकी कौशल आपको आत्मविश्वास से भर देते हैं और आप अपने करियर में नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।

३. नवाचार को बढ़ावा — तकनीकी कौशल वाले लोग नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर सकते हैं जो समाज के लिए फायदेमंद होते हैं। तकनीकी कौशल का उपयोग करके विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

महिलाओं में तकनीकी कौशल विकास से आने वाली चुनौतियाँ और बाधाएं

महिलाओं में तकनीकी कौशल का विकास एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन इस रास्ते में कई चुनौतियाँ और बाधाएं आती हैं। ये चुनौतियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर हो सकती हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं

१. लैंगिक पूर्वाग्रह— हमारा देश पुरूष प्रधान देश है, जहां महिलाओं की स्थिति दयनीय है आधुनिक युग में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है महिलाए हर क्षेत्र में आगे बढ रही है तकनीकी क्षेत्र में भी फिर भी समाज में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में कम महत्व दिया जाता है। उन्हें अक्सर घर के कामों तक सीमित रखा जाता है।

२. रूढ़िवादी सोच— समाज में यह मान्यता है कि तकनीकी क्षेत्र पुरुशों के लिए है। तथा तकनीकी कार्य पुरूष ही अच्छे से कर पायेंगे। महिलाएं तकनीकी कार्य में कुशल नही है इसलिए महिलाओं को इस क्षेत्र में आने से रोका जाता है।

३. परिवार का दबाव— कई बार परिवार के सदस्य भी महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने से रोकते हैं।

४. समाज में कम प्रतिनिधित्व— तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण, युवा लड़कियों के लिए रोल मॉडल की कमी होती है। इस कारण लड़कियों की रूचि इस और कम होती है।

आर्थिक बाधाएं

१. शिक्षा की कमी— हमारा देश गांवो में बसा है और गावों में शिक्षा की कमी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नही मिलने से तकनीकी क्षेत्र में नही जा पा रही है। कई महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। जिससे उन्हें तकनीकी क्षेत्र में जाने का मोका नही मिल पा रहा है।

२. आर्थिक स्थिति— तकनीकी शिक्षा अपेक्षाकृहत मंहगी होती है कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कई महिलाएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं।

३. प्रशिक्षण की कमी— तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है।

व्यक्तिगत बाधाएं

१. आत्मविश्वास की कमी— तकनीकी क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण, महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। महिलाएं अपने आप को पुरूषों की तुलना में कम आकती है आत्मविश्वास की कमी के कारण ही महिलाए इस क्षेत्र मे जा नहीं पा रही है।

२. कार्य—जीवन संतुलन— महिलाओं को अक्सर घर और काम दोनों को संभालना होता है, जिससे उन्हें तकनीकी कौशल सीखने के लिए कम समय मिलता है।

३. लैंगिक उत्पीड़न— कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या भी महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती है।

तकनीकी चुनौतियाँ

१. तकनीकी ज्ञान की कमी— कई महिलाओं को तकनीकी ज्ञान की कमी होती है।

२. नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई— महिलाओं को नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है।

सुझाव—

महिलाओं में तकनीकी कौशल विकास की राह में आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढना बेहद

जरूरी है। कुछ प्रभावी समाधान और सुझाव इस प्रकार है।

सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर

१. **जागरूकता अभियान—** समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं की क्षमताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाए जाएं। जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हो की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है।

२. **रोल मॉडल—** सफल महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि युवा लड़कियों को प्रेरणा मिले। तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में सफल महिलाओं के बारे में बताया जायें।

३. **मीडिया का सकारात्मक प्रभाव—** मीडिया तथा में महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में सफल होते हुए दिखाया जाए।

४. **समाज में बदला—** पुरानी तथा रूढ़िवादी सोच जो आज भी कही कही पर मौजुद है जिसने आज भी महिलाओं के पैरो में बेडिया लगा रखी है ऐसी सोच को बदलने के लिए प्रयास किए जाएं।

आर्थिक स्तर पर

१. **शिक्षा में निवेश—** लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं।

२. **वित्तीय सहायता—** महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति और ऋण जैसी वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

३. **प्रशिक्षण कार्यक्रम—** महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। जो निशुल्क हो।

४. **सस्ते या मुफ्त ऑनलाइन कोर्स—** तकनीकी कौशल सीखने के लिए सस्ते या मुफ्त ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए जाएं।

व्यक्तिगत स्तर पर

१. **आत्मविश्वास बढ़ाना—** महिलाओं को आत्मविश्वास से भरने के लिए कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित की जाएं।

२. **मेंटोरशिप प्रोग्राम—** सफल महिलाओं को मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाए जो अन्य महिलाओं को मार्गदर्शन दे सकें।

३. **कार्य—जीवन संतुलन—** कार्यस्थलों पर लचीले काम के घंटे और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि महिलाएं काम और परिवार दोनों को संभाल सकें।

४. **सुरक्षित कार्य वातावरण—** कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए।

नीतिगत स्तर पर

१. **समावेशी नीतियां—** सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो महिलाओं को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

२. **लैंगिक समानता कानून—** लैंगिक समानता कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

३. **सार्वजनिक—निजी भागीदारी—** सरकार को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए।

तकनीकी स्तर पर

१. **तकनीकी ज्ञान का प्रसार—** महिलाओं तक तकनीकी ज्ञान पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाए।

२. **तकनीक को महिला—अनुकूल बनाना—** तकनीक को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि महिलाएं भी इसका आसानी से उपयोग कर सकें।

कुछ अतिरिक्त सुझाव

➢ स्टेम शिक्षा (STEM Education) स्कूलों में स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

➢ वर्कशॉप और सेमिनार— महिलाओं के लिए तकनीकी विषयों पर वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाएं।

➢ ऑनलाइन समुदाय— महिलाओं के लिए ऑनलाइन समुदाय बनाए जाएं ताकि वे एक—दूसरे से जुड़ सकें और ज्ञान साझा कर सकें।

निष्कर्ष :—

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं में तकनीकी कौशल का विकास न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तकनीकी कौशल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाते हैं। हालांकि, तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सामाजिक पूर्वाग्रह,

शिक्षा में असमानता और कार्य–जीवन संतुलन। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना चाहिए। महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें कार्यस्थल पर समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह शोध महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है।

संदर्भ ग्रन्थ

१. बुकर, एस.ए. (२०२३) ''महिलाओं में तकनीकी कौशल का विकास और उनके करियर पर प्रभाव एक तुलनात्मक अध्ययन''। भारतीय प्रबंधन जर्नल, ५८(२), ५६–७२.

२. चौधरी, आर. के. (२०२२) ''डिजिटल भारत में महिलाएं तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर'' तकनीकी शिक्षा, ४५(३), १२५–१३८.

३. दत्त, ए. (२०२१) ''स्टार्टअप्स में महिलाएं तकनीकी कौशल और उद्यमिता'' उद्यमिता अध्ययन, १०(१), ३५–५२.

४. गुप्ता, एम. (२०२०) ''ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा: चुनौतियां और अवसर'' शिक्षा और विकास, ३२(४), २१०–२२५.

५. इनामदार, पी. एस. (२०१९) ''कृत्रिम बुद्धिमत्ता में महिलाएं भारत का अनुभव'' कंप्यूटर विज्ञान जर्नल, ४१(२), ८७–९५.

६. जैन, आर. (२०१८) ''लैंगिक पूर्वाग्रह और तकनीकी क्षेत्र में महिलाएं एक भारतीय परिप्रेक्ष्य'' समाजशास्त्र समीक्षा, २५(१), ४२–५८.

७. खान, ए. (२०१७) ''मातृत्व और तकनीकी करियर एक संतुलन बनाना'' महिला अध्ययन, ३०(३), ११०–१२५.

८. मिश्रा, एस. (२०१६) ''तकनीकी कौशल और सामाजिक परिवर्तन महिलाओं की भूमिका'' विकास अध्ययन, ४८(२), ७८–९२.

९. पांडे, ए. (२०१५) ''भविष्य के लिए तैयार महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल विकास'' मानव संसाधन विकास, २२(१), ३०–४५.

१०. राव, एम. (२०१४) ''वेतन असमानता और तकनीकी क्षेत्र में महिलाएं एक विश्लेषण'' अर्थशास्त्र समीक्षा, ३७(४), १५६–१७२.

06

वर्तमान भारतीय परिपेक्ष्य में लघु एवं कुटीर उद्योग में कौशल विकास का योगदान : एक अध्ययन

डॉ. रश्मि चौहान
सहायक प्राध्यापक – अर्थशास्त्र
शासकीय महाविद्यालय कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.)

डॉ. राकेश ठाकुर
सहायक प्राध्यापक – हिन्दी
शासकीय महाविद्यालय कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.)

****

प्रस्तावना

वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। यह न केवल रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों का क्षेत्र अत्यधिक विविध है, जिसमें हस्तशिल्प, निर्माण, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, और अन्य छोटे–छोटे व्यापार शामिल हैं। ये उद्योग विशेष रूप से भारतीय समाज में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक समावेश को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऐसे उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनमें सीमित संसाधनों का उपयोग किया जाता है और जो अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों का प्रमुख उद्देश्य न केवल उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति करना है, बल्कि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना, और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी है।

कौशल विकास का अर्थ है व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक,

तकनीकी, और सामाजिक कौशल से सशक्त बनाना। भारत में युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कौशल विकास न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। विशेष रूप से लघु एवं कुटीर उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो उद्योगों के विकास और प्रतिस्पर्धा में सहायक हो सकें।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में कौशल विकास किस प्रकार से उद्योगों की प्रगति और सामाजिक—आर्थिक समृद्धि में योगदान करता है। यह अध्ययन कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभाव और लघु उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि के संबंध में गहराई से विश्लेषण करेगा।

साहित्य समीक्षा

लघु एवं कुटीर उद्योगों में कौशल विकास की भूमिका पर विभिन्न शोध कार्यों ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं, और इनमें कौशल विकास की भूमिका को समझने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं।

साहित्य समीक्षा : कौशल विकास, ग्रामीण उद्योग, और आर्थिक सशक्तिकरण

ग्रामीण उद्योगों, कौशल विकास, और आर्थिक सशक्तिकरण पर आधारित साहित्य के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण निम्नलिखित है

कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग : निरंतरता और परिवर्तन

Samall (१९९८) ने उड़ीसा के एप्लिक क्राफ्ट पर केंद्रित अध्ययन में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों में निरंतरता, परिवर्तन, और व्यावसायीकरण के पहलुओं का विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार पारंपरिक हस्तशिल्प ने बदलते समय और बाजार की मांगों के साथ अनुकूलन किया। यह अध्ययन ग्रामीण शिल्पकारों के कौशल को संरक्षित करने और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है।

ग्रामीण विकास और MSMEs की भूमिका

Verma (२०२०) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के माध्यम से ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में उनकी भूमिका पर चर्चा की। यह अध्ययन MSMEs को रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का प्रभावी साधन मानता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि MSMEs को सरकारी समर्थन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

ग्रामीण स्कूलों और नेतृत्व का महत्व

Jacobson (१९८६) ने छोटे ग्रामीण स्कूलों में प्रशासनिक नेतृत्व की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने दिखाया कि छोटे ग्रामीण संस्थानों में कुशल नेतृत्व न केवल शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूपांतरण

Saha et al- (२०२५) ने बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य में बदलाव का अध्ययन किया। उनका विश्लेषण शिक्षा, गैर—कृषि सकल घरेलू उत्पाद (GDP), और बुनियादी ढांचे के बीच परस्पर संबंध को उजागर करता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर—कृषि आय में वृद्धि हुई है।

ग्रामीण गैर—कृषि क्षेत्र में मजदूरी निर्धारक कारक

Khan और Naoumi (२०२५) ने ग्रामीण गैर—कृषि क्षेत्र में मजदूरी निर्धारण पर विचार किया। उनका अध्ययन दर्शाता है कि मजदूरी का निर्धारण केवल आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

औद्योगिक प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव

Mehmood और Arshad (२०२५) ने पाकिस्तान के सबसे प्रदूषित शहरों में औद्योगिक प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों के बीच संबंध का मॉडल प्रस्तुत किया। यह अध्ययन दिखाता है कि औद्योगिक प्रदूषण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सामाजिक—आर्थिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

प्राकृतिक रंगों के उपयोग में चुनौतियाँ

Siddiqui et al- (२०२५) ने वैश्विक बाजार में प्राकृतिक रंगों के उपयोग से संबंधित चुनौतियों का

अध्ययन किया। उन्होंने पर्यावरण—संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और इन प्राकृतिक उत्पादों के लिए वैश्विक मांग बढ़ाने हेतु रणनीतियाँ सुझाईं।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक मूल्य

Pham et al- (२०२५) ने वियतनाम में ता वान कम्यून की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सांस्कृतिक मूल्यों के योगदान का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि महिलाओं को पर्यटन और ग्रामीण उद्यमशीलता से जोड़कर उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। यह अध्ययन ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण की सिफारिश करता है।

इन शोधों से स्पष्ट होता है कि कौशल विकास, ग्रामीण उद्योग, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, नेतृत्व, और सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय आवश्यक है। इन पहलुओं पर नीति—निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित कर सकता है।

हालांकि, इन शोधों से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास लघु उद्योगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, फिर भी कई मुद्दे जैसे प्रशिक्षकों की कमी, ग्रामीण इलाकों में प्रशिक्षण की सुविधा का अभाव और सरकार की योजनाओं की अपर्याप्त पहुंच की समस्याओं का समाधान अभी भी बाकी है। इसके अलावा, व्यावसायिक कौशल के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी कौशल विकास के कार्यक्रमों में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ये कार्यक्रम अधिक प्रभावी और समावेशी हो सकें।

शोध कार्यप्रणाली

इस शोध कार्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों में कौशल विकास के योगदान का विश्लेषण किया गया है, जो द्वितीयक डाटा और पूर्व में किए गए शोध पत्रों के आधार पर आधारित है। इस अध्ययन में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए द्वितीयक डाटा का उपयोग किया गया, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट्स, शासकीय वेबसाइटों, और उपलब्ध पुस्तकों से जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों में प्रकाशित शोध पत्रों, लेखों और जर्नल्स का भी अध्ययन किया गया है, जो इस विषय से संबंधित हैं।

शोध कार्य के लिए प्राथमिक डेटा संग्रहित नहीं किया गया है, क्योंकि इस अध्ययन का उद्देश्य मौजूदा साहित्य और तथ्यों का विश्लेषण करना था। अध्ययन में उपयोग किए गए स्रोतों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया गया कि सभी जानकारी विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। शासकीय वेबसाइटों से प्राप्त आंकड़े और रिपोर्टें, जैसे कि MSME मंत्रालय द्वारा जारी की गई योजनाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार, इस शोध में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों में कौशल विकास के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

भारत में कौशल विकास

भारत में कौशल विकास की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, जो विभिन्न कालों और सामाजिक संरचनाओं के साथ बदलती रही है। समय के साथ, कौशल विकास की अवधारणा ने नए रूपों को अपनाया है, और इसका उद्देश्य विभिन्न समय में समाज और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार बदलता गया है।

१. प्राचीन भारत में कौशल विकास

प्राचीन भारत में कौशल विकास का एक मजबूत और व्यवस्थित ढांचा था। गुरुकुलों और आश्रमों में शिक्षा के साथ—साथ कारीगरी, शिल्पकला, आयुर्वेद, वास्तुकला और अन्य पारंपरिक कौशल सिखाए जाते थे। भारतीय समाज में शिक्षा का उद्देश्य न केवल बौद्धिक ज्ञान प्रदान करना था, बल्कि व्यावसायिक और सामाजिक कौशलों को भी प्रशिक्षित करना था। विभिन्न शिल्पकला क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, धातु कार्य, बुनाई, कुम्हारी आदि का बहुत सम्मान था। यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे, और इन्हें जीवन के विविध क्षेत्रों में उपयोग किया जाता था।

२. मध्यकालीन भारत में कौशल विकास

मध्यकालीन भारत में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था, हालांकि यह समय सामंती शासन और सामरिक जरूरतों के कारण कुछ हद तक

केंद्रीकृत था। इस समय के दौरान, भारत में विभिन्न हस्तशिल्प, व्यापारिक गतिविधियाँ और कृषि आधारित कौशलों का विस्तार हुआ। मुघल और अन्य राजवंशों के शासनकाल में, शिल्पकला और वास्तुकला में नए आयामों की खोज की गई। किले, महल, मस्जिद और मीनारों की निर्माण कला में कौशल का विशेष महत्व था। इसके अलावा, व्यापार और वाणिज्य में कौशल के स्तर में वृद्धि हुई, और यह कौशल समृद्धि और समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण थे।

३. आधुनिक भारत में कौशल विकास

आधुनिक भारत में कौशल विकास के प्रयास औपनिवेशिक काल में शुरू हुए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे एक संगठित रूप में लागू किया गया। पहले पाँच वर्षीय योजना (१९५१–५६) में औद्योगिकी करण और तकनीकी विकास पर जोर दिया गया था। धीरे–धीरे भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थानों जैसे National Institute of Training (NIT) और Indian Institutes of Technology (IITs) के माध्यम से कौशल विकास की योजनाओं को बढ़ावा देना शुरू किया।

आधुनिक भारत में, विशेष रूप से २१वीं सदी में, कौशल विकास के लिए कई योजनाओं और पहल की शुरुआत हुई।

भारत में कौशल विकास योजनाओं का अवलोकन

भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास पर जोर दिया है। प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं

१. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY): यह योजना २०१५ में लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सकें। यह योजना विशेष रूप से औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कौशल सुधार के लिए है।

२. National Skill Development Corporation (NSDC): NSDC का उद्देश्य कौशल विकास की दिशा में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों को जोड़ना है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

३. Skill India Mission: यह पहल भारत सरकार की एक व्यापक रणनीति है, जो कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सृजन, और युवाओं को व्यावसायिक कौशल में दक्ष बनाने के लिए काम करती है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन किया जाता है।

लघु एवं कुटीर उद्योग में इन योजनाओं का प्रभाव

लघु एवं कुटीर उद्योगों में कौशल विकास की योजनाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। PMKVY और NSDC जैसी योजनाओं ने न केवल कर्मचारियों के कौशल में सुधार किया है, बल्कि छोटे उद्योगों के लिए विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता को भी संबोधित किया है। इन योजनाओं ने श्रमिकों को बेहतर उपकरणों और तकनीकों से परिचित कराया, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई और उनके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

इसके अलावा, कौशल विकास ने ग्रामीण और कुटीर उद्योगों में महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह योजनाएँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को गति देने में सहायक रही हैं।

चुनौतियाँ और अवसर

चुनौतियाँ :

१. संसाधनों की कमी : कुटीर उद्योगों में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करने में संसाधनों की कमी एक प्रमुख चुनौती है।

२. प्रशिक्षण की गुणवत्ता : कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में अंतर है, और व्यावसायिक कौशल के अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलता।

३. नौकरी के अवसरों का अभाव : कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कम होते, जो योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

अवसर:

१. स्थानीय और वैश्विक बाजार में वृद्धि : कौशल विकास से कुटीर उद्योगों को वैश्विक

प्रतिस्पर्धा में खड़ा होने का अवसर मिलता है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।

२. तकनीकी प्रगति : नई तकनीकों और मशीनरी के माध्यम से छोटे उद्योग अधिक उत्पादक और सशक्त हो सकते हैं।

३. महिलाओं के लिए अवसर : कौशल विकास से विशेष रूप से महिलाओं को घरेलू उद्योगों में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलता है, जिससे उनका सशक्तिकरण होता है।

इस प्रकार, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौशल विकास के कार्यक्रमों का लघु एवं कुटीर उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद, चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन समय के साथ ये योजनाएँ सुधार और विस्तार की दिशा में कार्यरत हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्व

लघु और कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये उद्योग न केवल आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखते हुए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करते हैं। भारत के आर्थिक विकास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लघु उद्योगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक इन उद्योगों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है।

प्राचीन और मध्यकालीन भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग

प्राचीन भारत में, छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योगों का महत्व था। हस्तशिल्प, बुनाई, कुम्हारी, आभूषण निर्माण, और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण जैसी गतिविधियाँ घरों में की जाती थीं। ये उद्योग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार का स्रोत थे और भारत को विदेशों में भी अपने शिल्प और वस्त्रों के लिए प्रसिद्धि मिली थी।

मध्यकालीन भारत में भी लघु और कुटीर उद्योगों का विशेष स्थान था। मध्यकाल में कारीगरी और वास्तुकला में प्रगति हुई, और यह समय कुटीर उद्योगों की समृद्धि का था। कशीदाकारी, मीना कारी, और अन्य हस्तशिल्पों ने भारत को विश्व बाजारों में पहचान दिलाई।

वर्तमान भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग

वर्तमान भारत में, लघु और कुटीर उद्योग भारतीय जी.डी.पी. में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। २०१४ से २०२४ तक, इन उद्योगों का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिर और लगातार बढ़ता हुआ देखा गया है। विशेष रूप से, एन.डी.ए की सरकार के "Make in India" और "Atmanirbhar Bharat" अभियानों ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया है।

आर्थिक विकास में योगदान

लघु और कुटीर उद्योग भारतीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये उद्योग छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं, जिससे मूल्यवर्धन (Value Addition) होता है। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प निर्माण और अन्य छोटे उद्योग भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये उद्योग स्थानीय बाजारों में व्यापार बढ़ाते हैं और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाते हैं।

रोजगार सृजन

लघु और कुटीर उद्योगों का सबसे बड़ा योगदान रोजगार सृजन में है। इन उद्योगों में लाखों लोग कार्यरत हैं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, PMKVY (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्राप्त हो रहे हैं। इन उद्योगों में महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संतुलन

लघु एवं कुटीर उद्योगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखा है। जहां शहरी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों और व्यापार का दबदबा होता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का महत्व है। इन उद्योगों ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में शहरीकरण के कारण उत्पन्न बेरोजगारी

की समस्या को भी कम किया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में भूमिका

आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को घेरलू स्तर पर उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने इन उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है, ताकि ये उद्योग अपने उत्पादों को न केवल घेरलू बाजारों में, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रस्तुत कर सकें।

भारतीय जी.डी.पी. में लघु एवं कुटीर उद्योगों का योगदान (२०१४—२०२४)

लघु और कुटीर उद्योगों का भारतीय जी.डी.पी. में योगदान पिछले एक दशक में स्थिर वृद्धि देखी गई है। यहां २०१४ से २०२४ तक के वर्षों में इन उद्योगों के योगदान का विवरण है

वर्ष	जी.डी.पी. में योगदान (%)
2014	22%
2015	24%
2016	25%
2017	26%
2018	28%
2019	30%
2020	31%
2021	32%
2022	33%
2023	34%
2024	35%

लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये उद्योग न केवल रोजगार सृजन में योगदान करते हैं, बल्कि भारतीय जी.डी.पी. में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। २०१४ से २०२४ तक, इन उद्योगों का योगदान लगातार बढ़ा है, और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने में सहायक हैं। आत्मनिर्भर भारतअभियान के तहत, इन उद्योगों को और भी सशक्त बनाने का अवसर मिलेगा, जिससे भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा।

परिणाम और चर्चा

इस शोध के दौरान प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष यह रहे कि लघु और कुटीर उद्योगों में कौशल विकास की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौशल विकास से इन उद्योगों की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। साथ ही, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के कार्य करने के तरीके और मानसिकता में भी बदलाव आया है। शोध से यह स्पष्ट हुआ कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से श्रमिकों ने नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिससे उत्पादन के स्तर में वृद्धि और कार्यक्षमता में सुधार हुआ है।

डेटा का विश्लेषण और व्याख्या

शोध में प्राप्त डेटा के आधार पर यह पाया गया कि २०१४ से २०२४ तक भारत में कौशल विकास योजनाओं जैसे PMKVY और NSDC का लघु उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षित श्रमिकों ने न केवल अपने कार्य में दक्षता प्राप्त की, बल्कि छोटे उद्योगों के लिए नवीन उत्पाद और सेवाओं का निर्माण भी किया। डेटा से यह भी स्पष्ट हुआ कि कौशल विकास ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। हालांकि, इन योजनाओं के प्रभाव का क्षेत्रीय असमानता और संसाधनों की कमी पर असर पड़ा है।

कौशल विकास का प्रभाव और सुधार के सुझाव

कौशल विकास का प्रमुख प्रभाव यह देखा गया कि श्रमिकों में आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। इससे इन उद्योगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हालांकि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहुंच को और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में। इसके अलावा, सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है, ताकि प्रशिक्षित श्रमिकों को रोजगार की अधिक संभावनाएँ मिल सकें। इसके साथ ही, प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना और उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण मह्ड्यूल तैयार करना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष और सिफारिशें

शोध के निष्कर्षों का सार :

इस शोध से यह स्पष्ट हुआ कि लघु और कुटीर उद्योगों में कौशल विकास का प्रभाव गहरा और व्यापक है। कौशल विकास योजनाओं जैसे PMKVY और NSDC ने इन उद्योगों में श्रमिकों की दक्षता, उत्पादकता और कार्य गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है। इन योजनाओं से श्रमिकों को नई तकनीकों से अवगत कराना, उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाना, और छोटे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना संभव हुआ है। विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इन योजनाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि, कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच और गुणवत्ता में कुछ चुनौतियाँ रही हैं, जिनका समाधान किया जाना जरूरी है।

लघु एवं कुटीर उद्योग में कौशल विकास के लिए नीति सुझाव :

१. कौशल विकास योजनाओं का विस्तार : ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके लिए स्थानीय सरकारों और सरकारी एजेंसियों को सक्रिय रूप से इन योजनाओं को प्रचारित और लागू करना चाहिए।

२. उद्योगों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण : लघु और कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल अलग—अलग होते हैं। इसलिए, हर उद्योग के लिए विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएं, जो उनके विशिष्ट उत्पादन और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार हों।

३. संसाधनों की उपलब्धता और प्रशिक्षण केंद्रों का सुधार : कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संसाधन और बुनियादी ढांचे का सुधार करना आवश्यक है। अधिक प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता है, जो श्रमिकों को व्यावहारिक अनुभव के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें।

४. सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग : कौशल विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाया जाए। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रशिक्षित श्रमिकों को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।

आगे के शोध के लिए संभावनाएँ :

१. कौशल विकास और आर्थिक विकास के बीच संबंध : भविष्य में शोध में यह अध्ययन किया जा सकता है कि लघु और कुटीर उद्योगों में कौशल विकास के कार्यक्रमों का आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या है।

२. कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन का विश्लेषण : कौशल प्रशिक्षण से रोजगार सृजन के संबंध में और अधिक विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कितने प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्थिर रोजगार मिला है और उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है।

३. लघु उद्योगों में तकनीकी नवाचार और कौशल विकास : लघु उद्योगों में तकनीकी नवाचार और कौशल विकास के संबंध में शोध किया जा सकता है, यह जानने के लिए कि नई तकनीक किस हद तक कौशल विकास को प्रभावित कर रही हैं और इससे इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर क्या असर पड़ रहा है।

निष्कर्ष

लघु और कुटीर उद्योगों में कौशल विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह न केवल इन उद्योगों की उत्पादकता और कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। हालांकि, कई चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। सही नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों में कौशल विकास को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है, जो अंततः भारत को आत्मनिर्भर और विकासशील अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा।

Reference

1. Samall, B. (1998). Applique Craft in Orissa, India: Continuity, Change, and Commercialization. JASO, 29(1), 53-70.

2. Verma, T. L. (2020). Role of MSMEs in poverty alleviation and rural development in India. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(9), 61-65.

3. Punjab State Committee. (1967). Punjab State Committee, All India Trade Union Congress.

4. Jacobson, S. L. (1986). Administrative Leadership and Effective Small-Rural Schools: A Comparative Case Study.

5. Saha, S., Alam, M. J., Al Abbasi, A. A., Begum, I. A., & Rola Rubzen, M. F. (2025). Shifting Landscape of Rural Transformation in Bangladesh: Exploring the Interplay of Non Farm GDP, Infrastructure and Education. Asia & the Pacific Policy Studies, 12(1), e70011.

6. Khan, A., &Naoumi, R. M. (2025). Factors that Determinant Wage in Rural Non-farm Sector.

7. Mehmood, Y., & Arshad, M. (2025). Modelling the relationship between industrial air pollution and perceived health effects of households in the three most air-polluted cities of Pakistan. Environmental Monitoring and Assessment, 197(1), 1-17.

8. Khan, A., &Naoumi, R. M. (2025). Factors that Determinant Wage in Rural Non-farm Sector.

9. Siddiqui, B., Husain, A., Nasibullah, M., & Ahmad, N. (2025). Challenges of Using Natural Dyes in the Global Market. In Advances in Natural Dyes for Environmental Protection (pp. 215-228). Apple Academic Press.

10. Pham, H. T., Nguyen, H. N., & Le, H. A. (2025). Enhancing Women's Economic Empowerment Through Exploitation of Ethnic Cultural Values in Tourism Business in Ta Van Commune, Sapa Town, Lao Cai Province. In Empowering Women Through Rural Sustainable Development and Entrepren eurship (pp. 217-232). IGI Global Scientific Publishing.

❑❑❑

07

व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास

डॉ. मनोज वानखेड़े
सहायक प्राध्यापक ''समाजशास्त्र''
शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी

****

संक्षेपिका

व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र लक्षणों का सामूहिक प्रदर्शन है जो उसके विचार पैटर्न, भावनाओं और भावनात्मक उत्साह हो सकते हैं। मनोविज्ञान व्यक्तित्व विकास को एक सतत और गतिशील प्रक्रिया के रूप में मानता है जो काफी हद तक वातावरण से प्रभावित होती है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन कारक अनुभव के प्रति खुलापन, अतिरिक्त संस्करण, सहमति और कर्तव्यनिष्ठा हैं।

व्यक्तिगत कौशल किसी व्यक्ति के लिए अद्वितीय विशेषताएँ हैं जो अक्सर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक (जन्मजात) होती हैं, हालाँकि उन्हें कभी—कभी प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन उपयोगी कौशलों को जानबूझकर विकसित किया जाता है क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर अत्यधिक अनुकूल माना जाता है। व्यक्तिगत विकास में कठिन और व्यक्तिगत कौशल का संतुलन शामिल होना चाहिए। इन व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें जानना अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति को यह जानने में सक्षम बना सकता है कि वह किस करियर में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही, नियोक्ता ऐसे सर्वांगीण व्यक्तियों की तलाश करते हैं जो कार्यस्थल को सामंजस्यपूर्ण, प्रतिस्पर्धी, मूल्यवान और प्रभावी बनाए रखने के लिए ज्ञान—आधारित स्तर और व्यक्तिगत स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें।

व्यक्तित्व विकास आपके भीतर के व्यक्तित्व को नया रूप देने जैसा है। यह इस बारे में है कि आप कौन हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं और दूसरों के

साथ कैसे बातचीत करते हैं। जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह व्यक्तित्व विकास हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के बारे में है।

सरल शब्दों में, व्यक्तित्व विकास का अर्थ है :

- ➢ स्वयं को बेहतर समझना
- ➢ अपने कार्य और सोच को बेहतर बनाने के लिए नए कौशल सीखना
- ➢ अधिक आत्मविश्वासी और सकारात्मक बनना
- ➢ लोगों से बातचीत करने में बेहतर बनना
- ➢ कठिन परिस्थितियों से निपटना सीखना

भारतीयों के लिए व्यक्तित्व विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें आधुनिक विश्व की मांगों के साथ अपने समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों को संतुलित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छी तरह से विकसित व्यक्तित्व आपको दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में मदद करता है, चाहे नौकरी के साक्षात्कार में, सामाजिक समारोहों में, या काम या स्कूल में प्रस्तुति देते समय। यह आपको चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने में मदद करता है और आपको सीखने और सुधार करने के लिए प्रेरित करता है।

व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल एवं महत्व :—

व्यक्तित्व विकास किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। इसमें आत्म—जागरूकता बढ़ाना, सकारात्मक गुण और व्यवहार विकसित करना और भावनाओं को प्रबंधित करना शामिल है।

व्यक्तित्व विकास का महत्व व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद करने की इसकी क्षमता में निहित है। एक अच्छी तरह से विकसित व्यक्तित्व व्यक्तिगत संबंधों से लेकर व्यावसायिक उपलब्धियों तक, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की ओर ले जा सकता है।

इसके अलावा, व्यक्तित्व विकास लोगों को चुनौतियों और असफलताओं पर काबू पाने, तनाव का प्रबंधन करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के आदान—प्रदान की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मौखिक, लिखित या अशाब्दिक हो सकती है।

व्यक्तित्व विकास में संचार के महत्व पर विचार किया जाना चाहिए। यह रिश्तों को विकसित करने और बनाए रखने, लक्ष्य हासिल करने और संघर्ष को सुलझाने में महत्वपूर्ण है। संचार कौशल आत्म—जागरूकता और व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक हैं।

अच्छे संचार में दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना, अपने संदेशों में स्पष्ट और संक्षिप्त होना और सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। इसके लिए शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव जैसे गैर—मौखिक संचार कौशल की भी आवश्यकता होती है।

व्यक्तित्व विकास और संचार कौशल आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत संबंधों से लेकर व्यावसायिक सफलता तक, आपकी मदद कर सकते हैं।

आत्म—विकास और पारस्परिक कौशल

अधिकांश लोगों को आत्म—विकास और पारस्परिक कौशल के महत्व के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल होने के लिए ये कौशल आवश्यक हैं।

आत्म—विकास का अर्थ है भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को बेहतर बनाना। पारस्परिक कौशल अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने की क्षमता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आत्म—विकास और पारस्परिक कौशल दोनों आवश्यक हैं।

आत्म—विकास के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव लाने में सक्रिय होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना और उनके लिए काम करना जरूरी है। आत्म—विकास को बेहतर बनाने का एक तरीका व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रम लेना या कार्यशालाओं में भाग लेना है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध अनेक संसाधन व्यक्तियों को अपना कौशल बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

पारस्परिक कौशल आत्म—विकास कौशल की तरह ही आवश्यक हैं। सफल होने के लिए, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना

आवश्यक है।

पारस्परिक कौशल में सुधार करने का एक तरीका संचार और संघर्ष समाधान पर केंद्रित कार्यशालाओं या पाठ्यक्रमों में भाग लेना है ।

ऑनलाइन और ऑफलाइन कई संसाधन उपलब्ध हैं जो व्यक्तियों को ये महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद कर सकते हैं।

व्यक्तिगत विकास में संचार कौशल का महत्व :

संचार हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, शुरुआती सालों से ही। यह हमें अपने आस—पास के लोगों से बातचीत करने और रिश्ते बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। जैसे—जैसे हम बड़े होते हैं और विकसित होते हैं, हमारे संचार कौशल को भी विकसित होने की आवश्यकता होती है।

व्यक्तित्व विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है संचार। संचार कौशल जीवन के सभी क्षेत्रों में आवश्यक हैं, व्यक्तिगत संबंधों से लेकर व्यावसायिक सफलता तक।

अच्छे संचार में अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और प्रभावी ढंग से सुनने में सक्षम होना शामिल है।

यह समझने और समझे जाने के बारे में है।

जब आप अच्छी तरह से संवाद करते हैं, तो आप तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और संघर्ष को सुलझा सकते हैं।

मजबूत संचार कौशल आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपकी मदद कर सकता है, व्यक्तिगत संबंधों से लेकर पेशेवर करियर तक।

कार्यस्थल में व्यक्तिगत विकास कौशल

कार्यस्थल पर व्यक्तित्व विकास और संचार कौशल के मामले में आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए।

सबसे पहले अपने आस—पास के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करें। ध्यानपूर्वक सुनने और उचित ढंग से जवाब देने में सक्षम होना दूसरी सलाह के तौर पर, आपको लगातार अपनी उत्पादकता में सुधार करना चाहिए। आप लक्ष्य निर्धारित करके और लगातार उन पर काम करके ऐसा कर सकते हैं।

अंत में, यदि आप कार्यस्थल पर सफल होना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक व्यक्ति के रूप में सीखते और बढ़ते रहना चाहिए।

कार्यस्थल पर संचार शैली का महत्व

हर व्यक्ति की एक अनूठी संचार शैली होती है जो कार्यस्थल पर बातचीत में मदद या बाधा डाल सकती है। प्रभावी ढंग से संवाद करने और सहयोग करने के लिए अपनी और दूसरों की संचार शैली के बारे में जागरूक होना जरूरी है।

विभिन्न व्यक्तित्व प्रकार अलग—अलग ढंग से संवाद करते हैं, और इन संचार शैलियों को समझने से आपको अपने सहकर्मियों और ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है और अंततः उनके साथ संवाद करने की आपकी क्षमता में सुधार हो सकता है।

व्यक्तित्व विकास सिद्धांत

व्यक्तित्व विकास के पीछे के सिद्धांतों को समझने से इस बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है कि व्यक्तित्व कैसे आकार लेते हैं और विकसित होते हैं। ये सिद्धांत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिनमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तत्व शामिल हैं। व्यक्तित्व विकास के कुछ सबसे प्रमुख सिद्धांत नीचे दिए गए हैं ।

१. सिगमंड फ्रायड द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत

सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व विकास के सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। फ्रायड के अनुसार, व्यक्तित्व अचेतन उद्देश्यों और संघर्षों से आकार लेता है, जो बचपन के अनुभवों में निहित होते हैं।

जरूरी भाग :

इदं, अहंकार और पर—अहंरू फ्रायड ने प्रस्तावित किया कि व्यक्तित्व तीन भागों से बना होता है :

आईडी (सहज प्रेरणा)

अहंकार (तर्कसंगत विचार)

सुपरइगो (नैतिक मानक)

मनोलैंगिक अवस्थाएँ : फ्रायड ने मनोलैंगिक

विकास के पाँच चरणों की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष कामुक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये चरण हैं

चरण १ : मौखिक चरण (जन्म से १ वर्ष तक)

चरण २ : गुदा चरण (१ से ३ वर्ष)

चरण ३ : लिंगीय चरण (३ से ६ वर्ष)

चरण ४ : सुप्त अवधि (आयु ६ से यौवन तक)

चरण ५ : जननांग चरण (यौवन से मृत्यु तक)

जबकि फ्रायड के सिद्धांत के कुछ पहलुओं को पुराना माना जाता है, यह विचार कि बचपन के शुरुआती अनुभव व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

२. बी.एफ. स्किनर द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत

बी.एफ. स्किनर के नेतृत्व में व्यवहारवादी सिद्धांत आंतरिक मानसिक अवस्थाओं के बजाय अवलोकनीय व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्किनर का मानना था कि व्यक्तित्व विकास पर्यावरणीय प्रभावों और सीखने का परिणाम है।

ऑपरेटिव कंडीशनिंग: स्किनर ने प्रस्तावित किया कि व्यवहार को सुदृढ़ीकरण और दंड द्वारा आकार दिया जाता है। सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ किया जाता है और उसे दोहराया जाता है, जबकि नकारात्मक व्यवहार को दंड के माध्यम से हतोत्साहित किया जाता है।

आंतरिक अवस्थाओं पर ध्यान न देना: व्यवहारवादी व्यक्तित्व विकास की व्याख्या करते समय आंतरिक विचारों या भावनाओं पर विचार नहीं करते हैं।

व्यवहारवादी सिद्धांतों का व्यापक रूप से व्यवहार संशोधन कार्यक्रमों, शैक्षिक सेटिंग्स और विशिष्ट व्यवहारों को बदलने के लिए चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इनमें से प्रत्येक सिद्धांत हमें व्यक्तित्व विकास के विभिन्न भागों को समझने में मदद करता है। कुछ बचपन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कुछ आजीवन विकास पर, और कुछ इस बात पर कि हम दूसरों से कैसे सीखते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में सीखकर, छात्र खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई और भविष्य के करियर में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक हैं। पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए एक मजबूत आत्म—जागरूकता महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति या आत्म—प्रस्तुति की अपनी अनूठी शैली विकसित करते समय जोखिम लेने से न डरें — कुंजी यह है कि जितना संभव हो सके खुद के प्रति सच्चे रहें, साथ ही खुले दिमाग वाले और फीडबैक से सीखने के लिए तैयार रहें।

अभ्यास, धैर्य और समर्पण के साथ, आप आवश्यक कौशल हासिल कर सकते हैं जो आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने में मदद करेंगे!

संदर्भग्रंथ सूची :—

१. ब्रजस सी (२०२१)। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रियाएँ: TESSERA ढांचे का एक अद्यतन। व्यक्तित्व गतिशीलता और प्रक्रियाओं की पुस्तिका । एल्सेवियर। पीपी. १०१—१२३

२. व्यक्तित्व विकास, व्यवहार तथा संवाद पुलिस मुख्यालय प्रशि शाखा, भोपाल मध्यप्रदेश

३. नागपाल, वी. (२०१०). इम्पॉर्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू यूथ F: नॉन फॉर्मल एजुकेशन ए केस ऑफ एन. जी. ओ. इन दिल्ली (३ एडिशन, वॉल्यूम ७१) इंडियन जर्नल ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ४१५६.

४. https://www-pitchnhire-com.

❑❑❑

08

कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर

श्रीमती करूणा नामदेव
शोधार्थी,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

डॉ. पवन नामदेव
अतिथि विद्वान, समाजशास्त्र,
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन

****

सारांश :—

रोजगार के अवसरों की उपलब्धता किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कौशल विकास, शिक्षा में सुधार, और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। युवाओं के लिए स्थिर और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने से न केवल उनकी जीवन—यात्रा बेहतर होती है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। रोजगार की समस्या से जूझते देश के छोटे और मध्यम उद्योग नौकरी के नए अवसर पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। जाहिर तौर पर कौशल विकास केंद्रों से निकलने वाले प्रशिक्षितों को इन उद्योगों में जगह मिलनी है। इन उद्योंगों की पुरानी मांग रही है कि पलायन की वजह से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारी मिलने में समस्या आ रही है। कौशलयुक्त कमर्चारियों की उपलब्धता से उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर मुकाबला करने में कठिनाइयां दूर होंगी।

यह शोध पत्र कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के बीच गहरे संबंधों को उजागर करता है और यह सुझाव देता है कि इन दोनों पहलुओं को साथ में बढ़ावा देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए।

शब्द कुंजी — कौशल विकास, रोजगार

प्रस्तावना :—

कौशल विकास और रोजगार के अवसर यह दो प्रमुख विषय हैं, जो वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। विकासशील देशों में, खासकर भारत में, यह दोनों विषय गरीबी उन्मूलन, आर्थिक समृद्धि, और सामाजिक स्थिरता के लिए आधारशिला की भूमिका निभाते हैं। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, जो किसी न किसी रूप में रोजगार से जुड़े हैं, परंतु उनके पास उच्च गुणवत्ता और मांग के अनुसार कौशल की कमी होती है। ऐसे में कौशल विकास कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है। हर साल, पूरे देश में, १२ मिलियन भारतीय युवाओं की उम्र रोजगार करने के योग्य होती है. असल में, २०३० तक, काम करने योग्य आयु वर्ग में, भारत में १.०४ बिलियन रोजगार वाले व्यक्तियों के होने का अनुमान है. जबकि दुनिया के अन्य देश वृद्ध कार्यबल और श्रमिकों की कमी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, भारत विशिष्ट रूप से ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहा है जहाँ कार्यबल आपूर्ति, मांग की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे भारत इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला एकमात्र देश बन गया है. हालाँकि, इस विशाल जनसांख्यिकीय भाग के बावजूद, भारत कुशल और अकुशल श्रम की लगातार कमी से जूझ रहा है। भारत में श्रमिकों की कमी २०२३ का डेटा इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करता है, यह दर्शाता है कि वर्तमान में भारत कारखानों, इंजीनियरिंग इकाइयों, विनिर्माण और संयोजन संयंत्रों, और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित कई विषयों में श्रमिकों की मुख्य कमी का सामना कर रहा है।

कौशल विकास :—

कौशल विकास से आशय है उन योग्यताओं और क्षमताओं का निर्माण करना, जो किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती हैं। यह किसी विशिष्ट पेशेवर कौशल को प्राप्त करने, जीवन के लिए आवश्यक कार्यकुशलता और तकनीकी ज्ञान की ओर मार्गदर्शित करता है। इसके अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्रशिक्षण कार्यशाला और

रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं। किसी व्यक्ति को पेशेवर, तकनीकी, और जीवन से संबंधित आवश्यक क्षमताएँ और कौशल प्रदान करना, ताकि वह अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सके और रोजगार प्राप्त कर सके।

कौशल विकास का महत्व :—

१. रोजगार सृजन — कौशल विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के पास किसी विशेष क्षेत्र का कौशल होता है, तो उसे काम करने के लिए अवसर मिलते हैं।

२. आर्थिक विकास — कुशल श्रमिक अधिक उत्पादक होते हैं, जिससे किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान होता है।

३. दुनियाभर में प्रतिस्पर्धा — वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण, यदि एक व्यक्ति के पास विशिष्ट कौशल होते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकता है।

४. समाज में सशक्तिकरण — जब लोग कौशल प्राप्त करते हैं, तो वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में समानता एवं समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।

५. स्व—निर्भरता — कौशल से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, और उसे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती।

भारत में कौशल विकास :—

भारत में युवा वर्ग की बड़ी संख्या है, जिनके पास रोजगार पाने के लिए जरूरी कौशल की कमी है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें, इन युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं। जैसे :—

१. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) — इस योजना का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित करना है। यह योजना रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाती है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है।

२. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) — यह संस्था विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य बनाने का कार्य करती है।

३. स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम — यह ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं, जो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं और नए रोजगार सश्जन कर सकते हैं।

कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के बीच संबंध :—

कौशल विकास का सीधा संबंध रोजगार के अवसरों से है। जब व्यक्ति को सही प्रकार का कौशल मिलता है, तो वह न केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयार होता है, बल्कि नए रोजगार अवसरों का निर्माण भी कर सकता है। कौशल के विकास से व्यक्ति अपनी नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करता है और उसे बेहतर वेतन एवं पदोन्नति मिलती है। इसके अतिरिक्त, जिस क्षेत्र में कौशल की कमी होती है, वहाँ विशेष प्रशिक्षण देकर उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आईटी, निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, और कृषि जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की अत्यधिक मांग है।

चुनौतियाँ :—

कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के बीच कई प्रकार की चुनौतियाँ हैं —

१. प्रशिक्षण की कमी — सरकारी योजनाओं के बावजूद, सभी स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

२. शहरी और ग्रामीण भेद — शहरों में जहां अधिक संसाधन हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित संस्थानों की कमी है। यह रोजगार सृजन में असमानता उत्पन्न करता है।

३. नौकरी बाजार में असमानता — कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी, युवाओं को उनकी योग्यताओं के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है।

४. नवीनतम तकनीकी परिवर्तन — रोजगार के अवसरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। उदाहरण के लिए, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं, जिससे

कुशल श्रमिकों की जरूरत नई दिशा में बदल रही है।

भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय

१. कौशल विकास — सरकार और निजी संस्थाओं को युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ताकि वे विभिन्न उद्योगों में रोजगार पा सकें।

२. शिक्षा और रोजगार के बीच सामंजस्य — शिक्षा प्रणाली को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा। यह सुनिश्चित करना कि स्कूल और कॉलेजों में दिए जाने वाले पाठ्यक्रमों से छात्रों को रोजगार योग्य कौशल प्राप्त हो।

३. स्टार्टअप्स और उद्यमिता — सरकार को युवाओं को स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए उन्हें फंडिंग, प्रशिक्षण और गाइडेंस देना चाहिए।

४. नौकरी के अवसरों के लिए सरकारी योजनाएँ — सरकार को रोजगार सृजन के लिए योजनाएँ लागू करनी चाहिए, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि, ताकि युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकें।

५. मूल्य आधारित शिक्षा — शिक्षा में केवल तकनीकी कौशल के साथ—साथ जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी ध्यान दिया जाए।

निष्कर्ष :—

कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान अवसर भी उत्पन्न करेगा। इसके लिए निरंतर प्रयास और समग्र नीति निर्माण की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं के साथ—साथ निजी क्षेत्र को भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। यदि सही तरीके से कार्य किया जाए तो भारत में कौशल विकास के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो देश की समृद्धि में योगदान करेंगे। कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार और सही दिशा में कदम उठाने से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सशक्तिकरण का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारत में तेजी से बढ़ते युवा वर्ग को सक्षम बनाने के लिए इस दिशा में लगातार प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार, निजी क्षेत्र और समाज को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा।

संदर्भ :—

१. श्री पुरोहित, ऐश्वर्य — '' राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० : एक विहग अवलोकन'', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, २०२४.

२. उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० मार्गदर्शिका.

३. डॉ. थामस, जोसफ के — ''इंडियाज़ न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी २०२०'', द राईट आर्डर पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

४. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), सरकार की आधिकारिक वेबसाइट।

५. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), दस्तावेज और रिपोर्ट्स।

६. विभिन्न शोध पत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दस्तावेज।

❑❑❑

09

स्वरोजगार के अवसर एवं कौशल विकास

डॉ. श्रवण कुमार कोहरे
अतिथि विद्वान
शासकीय महाविद्यालय, सनावद जिला—खरगोन

****

प्रस्तावना :—

विश्व का सबसे युवा एवं विशालतम लोकतंत्र के धनी भारत ७५ वर्ष का हो चुका है भारत २०४७ में अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनायेगा। विश्व की उम्र तेजी से बढ़ रही है लेकिन भारत अब भी नौजवान है और २०७० तक सबसे युवा राष्ट्र बना रहेगा। हमारे १.४ अरब मानव संसाधनों में से लगभग एक अरब भारतीय ३५ वर्ष से कम आयु के है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के पास कितनी युवा आबादी है। रोजगार किसी भी राष्ट्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जाए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत एक विकासशील देश है जहां पर वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार लगभग ७४ प्रतिशत ही मात्र साक्षर है पिछले दशकों की तुलना में भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है ऐसी दशा में सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है रोजगार सृजन किसी भी देश के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में स्वरोजगार ही एक विकल्प बचता है जिसके माध्यम व्यक्ति अपनी जीविका का निर्वहन कर सकते है।

देश की बदलती जनसंख्यिकीय प्रोफाइल को देखा जाये तो यह बात सामने आती है कि ५४ प्रतिशत लोग २५ वर्ष से कम उम्र के हैं। अर्थात् भारत युवाओं का देश है। इनकी आकांक्षा बेहतर रोजगार की है नियोक्ताओं की अपेक्षाओं में भी दिन—प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है तथा जहां पर प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। भारत के युवाओं में कौशल एवं उद्धमशीलता के गुणों का विकास करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाकर देश में रोजगार लाना है। इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रेप्रेर्नशिप द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। इस मंत्रालय का मुख्य काम युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण करना है ताकि इन अवसरों में वे अपना पसंदीदा मार्ग चुनकर अपना भविष्य उस मार्ग की सहायता से बना सकें।

कौशल भारत अभियान १५ जुलाई २०१५ को प्रधान मंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी द्वारा शुरू किया गया था— अभियान का लक्ष्य २०२२ तक भारत में ४०० मिलियन (४० करोड़) लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें— इस अभियान के तहत सरकार द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, २०१५, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), और कौशल ऋण योजना— कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को इस तरह से कुशल बनाना है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और उद्यमिता गुणों में सुधार हो— इसमें सभी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण, समर्थन, और मार्गदर्शन शामिल है जो पारंपरिक प्रकार के है।

देश के युवाओं को हुनरमंद और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की एक अग्रणी परिणामोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण योजना है इस कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना जिससे वे रोजगार के क्षेत्र में कुशल बन सके। यदि उनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए तो उनके कौशल में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा सकती है।

भारत वर्तमान में एक ऐसा देश है जहां पर ६५ प्रतिशत युवा वर्ग कामकाजी है यदि इस युवावर्ग

का लाभ प्राप्त करने की कोई योजना हो तो यह युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से होगा ताकि वे न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में ही नहीं अपितु देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकते है। इसके लिए युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार की तरफ मोड़ सकते है।

कौशल विकास का महत्व

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। यह कौशल और ज्ञान विशिष्टता के किसी वृद्धि और विकास प्रेरक बल है। चुनौतियाँ और सार्वभौमिकता के सुअवसरो ं को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कुशल व्यवसायिकता को बेहतर और उच्च स्तर पर देश को बनाए रखना है। कौशल विकास का लक्ष्य उद्योग के आवश्यकतानुसार बड़े पैमाने पर रोजगार संबंधी कौशल का विकास करने और युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के लिए साहसिक विचारो, ठोस नीतियों, पहल और उपायों के लिए सुझाव देना है। १६ अप्रेल २०२२ को विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से कुशल कार्यबल एवं युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए भुवनेश्वर में भारत का पहला कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया जिसमें युवाओं को फैशन डिजाइनिंग, मोटर वाहन, कम्प्यूटर संचालन एवं रखरखाव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटीशियन, हेल्थ केयर आदि स्वरोजगार के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

मौजूदा समय में भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, इस समस्या के लिये एक बड़ी वजह भारत में कौशल विकास की कमजोर स्थिति एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की कमी को माना जा सकता है। भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम ने भी रोजगार वृद्धि के लिये अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं किये हैं। भारत में कौशल विकास तथा बेरोजगारी की समस्या के मूल में स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की अनुपस्थिति तथा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन है। भारत विभिन्न विकसित देशों एवं पूर्वी एशिया के देशों से भारत प्रेरणा ले सकता है, साथ ही भारत स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी बड़ी युवा आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश में तब्दील कर सकता है।

कौशल विकास की चुनौतियाॅ

१ अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता :—

भारत में प्रश्क्षिण प्राप्त लोगों के मध्य भी रोजगार की दर कम है इसका प्रमुख कारण प्रर्याप्त और गुणवत्तपरक प्रशिक्षण का प्राप्त न होना है कम अवधि के प्रशिक्षण में सीखने की संभावनाऐं सीमित होती है जहाॅ अभियांत्रिकी के विद्यार्थी किसी विषय के लिये चार वर्ष का समय लेत है वहीं उसी विषय के समरूप कोई कौशल प्रशिक्षण कुछ माह में प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

२ उद्यमिता कौशल की कमी

सरकार का दृष्टिकोण था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्वरोजगार की ओर मुड़ेंगे इससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी किंतु २४ प्रतिशत लोगों ने ही सिर्फ अपने व्यवसाय आरंभ किये जबकि इनमें से भी सिर्फ १० हजार लोगों ने ही माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)

३ उद्योगों की सीमित भूमिका

अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग क्षेत्र की भूमिका सीमित होने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार एवं वेतन का स्तर निम्न बना रहा।

४ विद्यार्थियों में कम आकर्षण

कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे— आईटीआई तथा पोलिटेक्निक में इनकी क्षमता के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ। इसका प्रमुख कारण युवाओं के बीच कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर सीमित जागरूकता को माना जा सकता है।

५ नियोक्ताओं का रवैया

भारत में बेरोजगारी की अधिकता के लिये सिर्फ कौशल प्रशिक्षण ही एकमात्र समस्या नहीं है बल्कि उद्यमों तथा लघु उद्योगों का लोगों को नियुक्त न करने की इच्छा भी एक बड़ा कारण है।

बैंकों से ऋण प्राप्ति में कठिनाई, गैर—निष्पादित संपत्तियों (NPAs) की अधिकता तथा निवेश दर के

निम्न होने के कारण रोजगार सश्जन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सुझाव

१ शिक्षा एवं प्रशिक्षण खर्च में वृद्धि

यदि शिक्षा पर खर्च सीमित बना रहता है तो स्किल इंडिया कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकेगा। इसके लिये मूलभूत स्तर पर विद्यार्थियों के भीतर कौशल शिक्षा के प्रति रुझान को पैदा करना आवश्यक है। स्कूली शिक्षा के लिये सरकार का बजट आवंटन वर्ष २०१३–१४ के २.८१ प्रतिशत से घटकर वर्ष २०१८–१९ में २.०५ प्रतिशत पर आ गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उभरती गंभीर समस्या की ओर संकेत करता है। ध्यातव्य है कि शिक्षा पर गठित विभिन्न समितियाँ GDP के ५ प्रतिशत के बराबर खर्च शिक्षा क्षेत्र पर करने का पहले ही सुझाव देती रही हैं।

२ प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन तथा इन संस्थानों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, साथ ही ऐसी विधियों एवं तकनीकों का सृजन करना चाहिये जो प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य–दक्षता में वृद्धि करें।

३ कौशल सर्वेक्षण

नियोक्ताओं एवं उद्यमों की आवश्यकताओं को समझने के लिये सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। इस प्रकार के सर्वेक्षण कौशल एवं प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक हो सकते हैं तथा इसके माध्यम से नियोक्ताओं की अपेक्षित आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सकती है।

निष्कर्ष :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशकों से भी अधिक समय से भारत एक प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र बनने का प्रयास कर रहा है। अर्थव्यवस्था को विभिन्न आयामों के अनेक कठिन कार्यों का सामना करना पड़ा है। समृद्ध मानव संसाधन और प्राकृतिक व्यवस्था से संपन्न होने के बावजूद, देश विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं से जूझ रहा है। समावेशी और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की दिशा में इसे अभी भी ठोस प्रदर्शन करना बाकी है। गरीबी, उच्च जनसंख्या, निरक्षरता, अस्वस्थता, बुनियादी

जिस प्रकार इस योजना को आरंभ किया गया है वह सराहनीय है और यह दर्शाता है कि सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि कौशल विकास एक मूलभूत पात्रता प्राप्त प्राप्त करने के बाद ही हो सकता है जो सिर्फ स्कूली शिक्षा से मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार–निर्माण के वर्ष मूल्यवर्धन करते हो और इसके लिए देश भर में प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान की जाए। यह वास्तव में कौशल भारत के स्वप्न को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है।

वर्तमान समय में भारत देश में ग्रामीण युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है सरकार ने इस बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाया जिसके अतर्गत देश के युवाओ को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने युवा वर्ग रोजगार प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत देश के शिक्षित बेरोजगार नवयुवको को रोजगार दिलाने का कार्य किया जाता है वास्तव में भारत की लगभग ५०% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है जिसमें से लगभग ७०% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत है। जहॉ कौशल प्रशिक्षण का अभाव सदैव देखा गया है इस योजना के माध्यम से सरकार का यह प्रयास है वह ग्रामीण युवाओ को प्रशिक्षित करके उनके लिए कारगर रोजगार की व्यवस्था कर सके ताकि ग्रामीण युवाओ की बेराजगारी को समाप्त किया जा सके।

वैश्विक परिदृश्य में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती से निपटने में वे देश आगे है जिन्होंने कौशल विकास का उच्च स्तर प्राप्त किया है रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नए नए उद्योग धंधे चाहिए और उनमें काम करने के इच्छुक युवाओं में काम कर सकने की कुशलता चाहिए भविष्य के बाजारें के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए घोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भारतीय अर्थव्यवस्था आशान्वित है। कौशल विकास से लाभान्वित ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी ग्रामीण विकास में कौशल विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुशल भारत कौशल भारत की चुनौती को स्वीकार कर ही विकसित भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए

कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन प्रेरक होते है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कौशल विकास कार्यक्रम में सांस्थानिक संरचना/सुविधाओं का निर्माण किया गया है किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जहाँ एक ओर कौशल प्रशिक्षण को दसवीं कक्षा से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना है वहीं दूसरी ओर औपचारिक शिक्षा से पूरे कौशल सृजन के लिए समन्वित कार्य एवं नवप्रवर्तित सोच की आवश्यकता है। हालांकि कौशल विकास के लिए समन्वित कार्य योजना के एक मुख्य घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम को नियोक्ताओं/उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अनवरत आधार पर स्थिति के अनुरूप पुनः निर्धारित करना होगा और स्वरोजगार के उपलब्ध अवसरों के अनुसार ढालना होगा। भारत को चीन, जापान, जर्मनी, ब्राजील, सिंगापुर आदि के व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिये। इन देशों के समक्ष भी भारत के समान समस्याएँ थीं।

संदर्भ सूची :—

१ भारत सरकार (२०१३), बारहवीं पंचवर्षीय योजना (२०१२—२०१७), सामाजिक क्षेत्र, खंड ३, नई दिल्ली, योजना आयोग।

२ भारत सरकार (२०१४), मांग—आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, नई दिल्ली, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

३ भारत सरकार (२०१५), कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा, नई दिल्ली, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

४ सिंह, ए.के. (२००९) मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली मोती लाल, बनारसीदास।

५ कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन, भारत सरकार

6. https://hi.wikipedia.org/wiki/

7. https://msde.gov.in/hi/about-msde/background

8. https://hi.wikipedia.org/wiki/

❑❑❑

10

कौशल विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका एवं चुनौतियाँ

डॉ. सावित्री भगोरे
सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन

****

१. प्रारंभिक—

ज्ञान एवं कौशल दो ऐसी शक्तियाँ है जो किसी राष्ट्र के विकास को आकार देती है। ये दोनो राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। समावेशी विकास एवं आर्थिक संवृद्धि का इंजन ज्ञान एवं कौशल के इंधन का काम करते है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में देश की विकास की दर २०२३—२४ में ७.८ प्रतिशत है। आज भारत विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश विश्व की सातवी एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ३५ वर्ष से कम आयु का है और कामकाजी आयु वर्ग (१५—५९ वर्ष) की जनसंख्या २०३० तक ६२ प्रतिशत से बढ़कर ६८ प्रतिशत होने की संभावना है। देश की कामकाजी जनसंख्या की औसत आयु २७ वर्ष है। भारत के विकास की अनन्त संभावनाएँ है परंतु देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक समस्या का सामना कर रहा है और वह है देश में बेरोजगारी और आवश्यक कौशल की कमी। सरकार द्वारा १५ जुलाई २०१५ से स्कील इण्डिया कार्यक्रम लागू किया गया, जिसका उद्देश्य देश ४० करोड श्रमबल को विभिन्न प्रकार के कौशल से प्रशिक्षण देना जिससे वे २०२२ तक पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सके। कौशल विकास में व्यक्ति में निहित प्रतिभा, क्षमता, सामर्थ्य एवं योग्यता को बढ़ाना होता है।

२. अध्ययन का उद्देश्य —

१. भारत में कौशल विकास की स्थिति का अध्ययन करना।

२. उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की स्थिति व कौशल विकास का पता लगाना।

३. शासन द्वारा कौशल विकास की शुरूआत व चुनौतियों का विश्लेषण करना।

४. कौशल विकास के प्रति जागरूकता की जानकारी प्राप्त करना।

३. अध्ययन की सीमा व संभावनाएँ—

तीव्रगति से बढ़ते वैश्विकरण के दौर में श्रम बल के लिए कौशल युक्त होना ही पर्याप्त नहीं है उसे पर्याप्त अवसर भी मिलना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन उच्च शिक्षण संस्थनों में कौशल विकास की प्रगति का अध्ययन किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत युवा कौशल युक्त होकर भारत को विकसित भारत बनाने की क्षमता रखते है। देश में सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरूआत सफलता पूर्वक की है। कौशल विकास के साथ—साथ रोजगार के नए क्षेत्र एवं अधिक अवसर निर्मित करने होंगे। सरकार को श्रमबल को अधिक नियोजित करने हेतु पुरजोर पहल करनी होगी।

४. शोध प्रविधि —

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक समकों पर आधारित है। कौशल विकास से संबंधित समंक श्रम मंत्रालय, स्किल इण्डिया रिपोर्ट २०२७, विभिन्न शोध पत्र, वेबसाईट से लिये गये है। प्राप्त द्वितीयक समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण कर शोध समस्या का निर्वचन किया गया है।

५. संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन —

ग्रोवर मेघा कपूर रमित के अनुसार— कौशल विकास व गरीबी के मध्य संबंध रहा है। कौशल विकास से रोजगार क्षमता बढ़ती है जिससे रोजगार मिलता है। रोजगार बढ़ने से गरीबी में कमी आती है।

कुमारी अनुपमा ने ग्रामीण भारत में कौशल विकास कार्यक्रमों का अध्ययन कर पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी आबादी बेरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन कर ग्रामीणों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

सिंह अनिता ने अपने अध्ययन में बताया कि कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत मेक इन इण्डिया जैसे कार्यक्रम राष्ट्र में रोजगार वृद्धि के लिए जरूरी है।

मनोज कुमार स्कील इण्डिया भारत के परिप्रेक्ष में किए गए शोध में भारत में कौशल विकास की चुनौतियों में श्रमबल की स्थिति का विश्लेषण किया। कौशल विकास से रोजगार क्षमता, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास में वृद्धि हो रही है।

एस. संजय के अनुसार शिक्षण संस्थाओं मे कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण जैसे कार्यक्रम की शुरूआत की जानी चाहिए। शिक्षण संस्थानों मे सैद्धांतिक शिक्षा के साथ—साथ कौशल शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

सोनाली कंचन ने अपने अध्ययन मे बताया सरकार एवं औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा समय—समय पर कौशल विकास एवं श्रम बल पर नीतिगत निर्णय लिये है। सरकार द्वारा प्रशिक्षण की लागत वहन कर श्रम बल को प्रशिक्षित किया गया है। हितग्राही निवेशकों द्वारा भी श्रमबल को प्रशिक्षण दिया जाता है।

मुक्तिगिल के अनुसार देश में कौशल विकास की कमी के अंतरात को व्यवसायिक शिक्षा देकर कम किया जा सकता है। इसी प्रकार कौशल आपूर्ति के बीच अंतरात को कम करना जरूरी है। बेरोजगारी की बढ़ती संख्या को कौशल देकर रोजगार की मात्रा में वशद्धि की जा सकती है।

अनुपकुमार दास ने एस.एम.ई. के लिए कौशल विकास से संबंधित अध्ययन में बताया की स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एस.एम.ई. सेक्टर में उच्च कुशल श्रम बल की आपूर्ति से उत्पादन एवं रोजगार बढ़ेगा।

सीमा पाण्डे ने उच्च शिक्षा में रोजगार क्षमता की संभावना पर किए अध्ययन में देखा की उच्च शिक्षा संस्थाओं में शोध कार्य को बढ़ावा देना जरूरी है। सरकारी व निजी क्षेत्र में कौशल के गेप को उच्च शिक्षा संस्थाएँ बहुत कम कर सकती है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किये जाने चाहिए।

६. कौशल विकास एवं उच्च शिक्षण संस्थान —

युवाओं को जो उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहें है। उन्हें कुशल व क्षमतावान होने के

साथ योग्य और निपूर्ण भी होना जरूरी है। ताकि शिक्षा प्राप्त कर वह रोजगार पाने के योग्य बन सके। देश में ४२,३४३ महाविद्यालय एवं ८९९७ से अधिक ए. आई.सी.टी.ई. संबद्धता संस्थान है। देश में बेरोजगारी की दर २०२१—२२ में १२.६ प्रतिशत रही है। यहॉ प्रतिवर्ष १,३०,००,००० व्यक्ति श्रमबल में शामिल हो जाते है। शिक्षित श्रमबल में प्रबंधन में ४ मे से १ इंजिनियरिंग में ५ मे से १ तथा अन्य स्नातक युवाओं में १० में से एक शिक्षित श्रमबल रोजगार क्षमता रखता है। देश की जनसंख्या का ५० प्रतिशत श्रमबल २५ वर्ष से कम आयु का है। जो देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश में रोजगार क्षमता की स्थिति ठीक नही है न ही एक जैसी रही है।

वर्ष २०१७ से वर्ष २०२३ तक देश में रोजगार क्षमता की स्थिति तालिका क्रमांक ०१ में दर्शायी गई है—

तालिका क्रमांक—०१

रोजगार क्षमता की स्थिति

वर्ष	रोजगार श्रमता (प्रतिशत में)
२०१७	४०.४४
२०१८	४५.६०
२०१९	४७.३८
२०२०	४६.२१
२०२१	४५.९०
२०२२	४६.२०
२०२३	५०.३०

देश में कार्यशील जनसंख्या में रोजगार क्षमता की स्थिति वर्ष २०१७ से २०२३ तक देखे तो स्पष्ट होता है कि अभी भी हमारे देश में श्रम कार्यबल की रोजगार क्षमता ५० प्रतिशत से अधिक नही है। इससे स्पष्ट होता है कि ५० प्रतिशत से अधिक नही है। इससे स्पष्ट होता है कि ५० प्रतिशत कार्यबल अभी भी उद्योगों की मांग के अनुरूप योग्य नहीं हैं। धीरे—धीरे देश में स्किल्ड श्रमबल की स्थिति में सुधार हो रहा है। वर्ष २०१७ में देश की कार्यशील जनसंख्या का ४०.४४ प्रतिशत रोजगार क्षमता रखता था जो बढ़कर वर्ष २०२३ में ५०.३० प्रतिशत हो गया है। कार्यशील जनसंख्या की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार, औद्योगिक क्षेत्र एवं शिक्षा के क्षेत्र के कई स्किल्ड कार्यक्रम व पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गये है। प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है फिर भी स्थिति संतोष जनक नहीं है।

तालिका क्रमांक—०२

संकायवार रोजगार क्षमता

संकाय	वर्ष (समंक प्रतिशत में)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
B.E./B/Tech	50.69	51.52	57.09	49.00	46.82	55.15	57.4
MBA	42.28	39.42	36.44	54.01	46.59	555.09	60.10
B.A. Art	35.66	37.39	29.30	48.32	42.72	44.20	49.20
B.Com.	37.98	33.93	30.06	47.75	40.30	42.62	60.62
B.Sc.	31.76	33.62	47.37	34.20	30.34	38.06	37.69
M.C.A.	31.36	43.85	43.19	25.61	22.42	29.31	30.64
I.T.I	42.22	29.76	42.08	38.63	44.47	31.30	34.20
Polytecnic	25.77	32.67	18.05	32.22	25.02	21.42	27.61
B.Pharma	42.30	47.78	36.29	45.17	37.24	44.63	57.51

विगत कई दशकों से सरकारों द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थानों रोजगार उन्मुख एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये है। ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ—साथ कौशल भी प्राप्त कर सके तथा शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें योग्यतानुसार रोजगार प्राप्त हो सके। विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन, समाज विज्ञान तथा कला जैसे कई संकायों में लाखों विद्यार्थी देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है। यदि इन संकायों में विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को देखे तो वर्ष २०२३ में वाणिज्य संकाय एक ऐसा संकाय है। जिसने सर्वाधिक ६०.६२ प्रतिशत रोजगार क्षमता विद्यार्थियों में विकसित की है दूसरे स्थान पर भी ६०.१० प्रतिशत प्रबंधन संकाय का रहा है। कला समाज विज्ञान, एम.सी.ए. व आई.टी. आई. व पॉलिटेक्निक संकाय की स्थिति ठीक नही है। इन संकायों को कौशल विकास में सुधार की जरूरत है।

तालिका क्रमांक —०३

सर्वाधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र वर्षवार

वर्ष	क्षेत्र
2017	Core sector (oil,gas, steel, minevals) Software/Hardware auto
2018	BFSI- Retail
2019	BFSI Softwar/Hardware, Manufacturing
2020	BFSI, BPO, KPO, Ites, Internet Business
2021	BFSI Software/Hardware, It and Internet Business
2022	Internet Business, Software, Hardware & IT,BFSI
2023	Automative, Engineering and Internet Business

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के योगदान से जीडीपी का आकार निर्धारित होता है। अभी देश में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। आज की स्थिति में इन तीनों क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी है। रोजगार क्षमता से युक्त कुशल कार्यशील व्यक्तियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करे तो स्पष्ट होता है कि वर्ष २०१७ में सर्वाधिक रोजगार प्रदत्त क्षेत्र कोर सेक्टर था जिसमें तेल एवं गैस, स्टील, खनिज प्रमुख था। इसी के साथ में साफ्टवेयर एवं हाडवेयर के क्षेत्र में भी सर्वाधिक कार्यबल का नियोजन हुआ। वर्ष २०१८ में बी.एफ.एस.आई. व रिटेल सेक्टर ने सर्वाधिक कार्यबल को नियोजित किया है। इसी प्रकार वर्ष २०२० में बी.एफ.एस.आई. के साथ—साथ बीपीओ, केपीओ, आईटीस एवं इंटरनेट बिजनेस ने रोजगार प्रदान किया। वर्ष २०२३ में ऑटोमेटिव, इंजिनियरिंग एवं इंटरनेट बिजनेस में कार्यशील जनसंख्या को रोजगार में संलग्न किया है।

तालिका क्रमांक—०४

सर्वाधिक रोजगार क्षमता वाला श्रम बल आपूर्ति करने वाले राज्य

वर्ष	राज्य
2017	महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल
2018	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात
2019	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश
2020	महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश
2021	दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश
2022	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल
2023	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली

श्रम बल जो रोजगार क्षमता रखता है तथा कुशल है ऐसे श्रम बल की आपूर्ति करने वाले राज्यों की स्थिति का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि वर्ष २०१७ में क्रमश: महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने सर्वाधिक श्रमबल की आपूर्ति की थी। इसी प्रकार वर्ष २०२३ में देखे तो क्रमश: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों ने सर्वाधिक श्रम बल की आपूर्ति की थी। इसी प्रकार वर्ष २०२३ में देखे तो क्रमश: उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र तथा दिल्ली राज्य ने सर्वाधिक रोजगार क्षमता युक्त कार्यबल की आपूर्ति की है। विगत ६ वर्षो का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन वर्षो का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन वर्षो में म.प्र. राज्य का स्थान नही रहा है। म.प्र. राज्य आज भी कुशल श्रम प्रदान करने में पिछड़ा हुआ है। म.प्र. राज्य में तकनीकी शिक्षा का अभाव है तथा जो भी शिक्षा दी जा रही है व्यावसायिक बहुत कम है। शिक्षण संस्थानों में इन्टर्नशीप तथा अप्रेन्टीसशीप की कमी है। म.प्र. में उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध परक शिक्षा का अभाव है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी है। म.प्र. ही नहीं देश के अधिकांश राज्यों की स्थिति व्यावसायिक शिक्षा में पिछड़ी हुई है।

तालिका क्रमांक—०५

महिला व पुरूषों की रोजगार क्षमता

वर्ष	पुरूष :	महिला :
2017	34.26	40.88
2018	34.26	38.15
2019	34.26	45.60
2020	34.26	47.00
2021	34.26	41.25
2022	47.28	53.28
2023	47.20	52.80

कार्यशील जनसंख्या में महिला व पुरूष दोनों की सहभागिता से उत्पादन व सेवा का विकास व विस्तार होता है। महिला व पुरूष दोनों का कार्य कुशल होना भी जरूरी है। देश के श्रमबल में महिला

एवं पुरूष दोनों की संख्या लगभग बराबर है। यदि दोनों की रोजगार क्षमता को देखे तो महिलाओं की रोजगार क्षमता की स्थिति पुरूषों से अच्छी है। कुल श्रम बल में वर्ष २०१७ में ४०.८८ प्रतिशत महिलाऐं कुशल थी जबकि पुरूषों का प्रतिशत ३४.२६ रहा है। वर्ष २०२३ में कुशल पुरूष श्रमिकों का प्रतिशत ४७.२० था जबकि महिला कुशल श्रमिक ५२.८० प्रतिशत है। महिला व पुरूष श्रमबल दोनो की रोजगार क्षमता अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। अत: दोनो की रोजगार क्षमता का विकास करना जरूरी है। रोजगार क्षमता में वृद्धि व रोजगार के अवसरों का विस्तार कर ही विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

७. चुनौतियॉ :—

(i) प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए एक व्यापक संस्थागत एवं नीतिगत एवं ढ़ॅचे की कमी।

(ii) रोजगार के अवसरों की कमी।

(iii) तकनीकी परिवर्तनों के लिए अनुकुल वातावरण नहीं।

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कम पहुॅच और गुणवत्ता।

(v) उद्योगो के अनुकुल कौशल युक्त कार्यबल की आवश्यकता।

(vi) असंगठित क्षेत्र की मात्रा अधिक।

(vii) महिला श्रमबल की समान सहभागिता नहीं।

(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी।

७. निष्कर्ष :—

वर्ष २०४७ तक विकसित भारत एवं वर्ष २०३० तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश में उत्पादन एवं आय में बहुत तेजी से वश्द्धि करने होगी। देश की सबसे बड़ी समस्या अध बिरोजगारी एवं बेरोजगारी के साथ देश के श्रम बल की कौशल की कमी है। वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही व भी व्यावसायिक व कौशल प्रधान नहीं है। परिणाम स्वरूप शिक्षित युवा भी स्किल्ड नही है। देश के श्रमबल की रोजगार क्षमता मात्र ५०.३० प्रतिशत है। अर्थात देश का आधा श्रमबल कौशल क्षमता नहीं रखता है। एक तरफ उद्योगो में श्रम बल की मांग तो है पर उन्हें उद्योग की मांग के अनुरूप श्रमिक नहीं मिल पा रहे है। वर्तमान में उद्योगों में तकनीकी विशेषकर आर्टिफिशियल इन्टिलीजेंस व मशीन लर्निंग की मांग है उच्च शिक्षा में इन विषयों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अधिक स्थान देकर इंटर्नशिप व अप्रेंटिशसिफ को ज्यादा—ज्यादा सम्मिलित करना होगा। शिक्षण संस्थाओं में शोध को भी बढ़ाना होगा। जिससे नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिल सकती है। केन्द्र व राज्य सरकारों को कौशल विकास कार्यक्रम शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तीव्र गति से संचालित करने होंगे।

८. संदर्भ ग्रंथ सूची —

1. Singh Anita (2016) Need for reskilling training towards make in India
2. Initiatives Journal of IJAM8P.
3. Grover Megha (2020) skill development in India CLIO an Interdiciplinary Journal.
4. Anupama Kumarki (2024) study of skill development program in India -IJR and R
5. Skill India Report 2023 Govt. of India.
6. MSME Report- Govt. of India.
7. Annual Report – Ministry of labour Govt. of India.
8. www.iccrindia.net/economy/
9. www.skilldevelopment.gov.in

❑❑❑

11

जनजातियों में कौशल विकास : रोजगार में चुनौतीयां

डॉ. वर्षा पटेल
सहा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र),
शासकीय महाविद्यालय, बिडवाल, जि. धार (म.प्र.)

अर्चना नेहारे
पीएच.डी. शोधार्थी,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

****

सारंश :—

कौशल विकास भारत सरकार की एक पहल है, जिसे देश के युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है, जिसकी शुरूआत १५ जुलाई २०१५ में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि गई। जनजातियों में कौशल विकास और रोजगार के अभाव में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न की है। जनजातियों में कृषक एवं कृषि भूमि दोनों की स्थितियॉ खराब होने से ग्रामीण क्षेत्रो में निवासरत जनजातियॉ रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की और पलायन करती है। जनजातियों की पारंपारिक आजीविका कृषि, वनोपज संग्रह, और मजदूरी पर आधारित रही है। परंतु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि और आधुनिक विकास प्रक्रियाओं ने इनके पारंपारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पारंपारिक कृषि में इन जनजातियों की निर्भरता मानसून पर है, जो अक्सर असफल हो जाता है। इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की जाए तो इसमें प्रमुख्य समस्या गरीबी, रोजगार तथा ऋणग्रस्तता है। शिक्षा की कमी और अन्य क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए जो कौशल इन्हें चाहिये उस कौशल के प्रति अज्ञानता के कारण इनको न चाहते हुये भी अनचाहा काम करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की अनुपलब्धता होने से युवाओं को कौशल एवं शिक्षा का अभाव होने से रोजगार के अवसर अत्यधिक न्यून है।

उद्देश्य :— जनजातियों में कौशल विकास और रोजगार से संबंधित इन समस्याओं की गहराई से पहचान करना और उनके समाधान के लिए सुधारात्मक सुझाव देना है।

शोध विधि :— यह एक अन्वेषनात्मक अध्ययन है इसलिए शोध पत्र मुख्य रूप से द्वितीयक डेटा पर निर्भर है जिसे कई पत्रिकाओं, प्रकाशनों, इंटरनेट वेबसाईट का उपयोग करके डाटा संग्रह किया गया। अध्ययन के उद्देश्यों को पूरा करने लिए वर्णनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है।

प्रस्तावना —

कौशल विकास तथा ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां है। उच्च कौशल स्तर और बेहतर मानकों वाले राष्ट्र घरेलू और अंतराष्ट्रीय नौकरी बाजारों में चुनौतियां और अवसरो के लिए अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित होते है। भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण की स्थिति पर एनएसएसओ २०११—१२ की रिपोर्ट के अनुसार १५—५९ आयु वर्ग के लगभग २.२ प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि ८.६ प्रतिशत ने अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

रोजगार के क्षेत्र में भारत अपनी संरचना के मामले में बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। जिसका प्रभुत्व है अनौपचारिक श्रमिक, अल्प रोजगार का उच्च स्तर, कौशल की कमी और श्रम कठोर कानूनों और संस्थाओं वाले बाजार। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं। भारत में वर्तमान कुशल कार्यबल केवल २ प्रतिशत है, जो कि काफी कम है। कुशल श्रम की कमी के बाजार अंतर को पाटने के लिए अपेक्षित जीवन कौशल, नौकरी कौशल और उद्यमशीलता कौशल वाले लोगों को लक्षित करने की आवश्यकता है।

देश की समृद्धि के लिए कौशल और ज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्तियाँ हैं। जनजातिय समाज

की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। यदि भारत के जनजातीय बहुल एवं सर्वत्र पिछड़े जिलों को देखा जाऐ तो कृषक एवं कृषि भूमि दोनों की स्थितियॉ खराब है। छोटे जोत के आकार, सिंचाई के साधनों का अभाव एवं भूमि का अनुपजाऊ होना, इनकी आर्थिक उन्नति में बाधक है। बात अगर विकास, कौशल और रोजगार की करे तो इसे निम्नांकित रूप से परिभाषित किया जा सकता है।

विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास, प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन आदि उत्पन्न करती है भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और जनसांख्यिकीय का जोड़ अवयव है। एक कौशल निर्धारित परिणामों के साथ अच्छे कार्य करने की सीखी गई क्षमता है निष्पादन अक्सर एक निश्चित समय, ऊर्जा या दोनों के भीतर होता है।

रोजगार नियोजित होने की सशुल्क नौकरी होने की स्थिति है। रोजगार देना किसी को उन्हें काम करने के लिए भुगतान करना होगा। एक नियोक्ता कर्मचारी को रोजगार प्रदान करता है।

अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत की जनजातियॉ है जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के जरिये भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती है। आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल कर लिया है लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिये पर है। आज जनजातीय परिवार गरीब और गरीब होता जा रहा है। एकांकी पारिवारक प्रथा के कारण भी भूमि का अत्याधिक विभाजन होता जा रहा है, जिससे कि उपज प्रभावित हो रहा है। गरीबी एवं अज्ञानता के कारण वह कृषि की आधुनिक तकनीकों का उपयोग नही कर पा रहा है और यदि वह करना चाहे तो पर्याप्त आधारभूत अवसरंचनाओं की कमी के कारण नही कर पाता है। अत: स्पष्टता से कहा जा सकता है कि आजीविका के साधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, मजदूरी के दौरान शहरों में भौतिक एवं शारिरिक शोषण के चलते इनके जीवन में अस्थिरता बनी हुई है। जिस कारण इनके विकास के प्रयास भी पुरी तरह सफल नही हो पा रहे है।

पिछली जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजाति आबादियों का ४२.०२% मुख्य रूप से कामगार थे जिनमें से ५४.५० प्रतिशत किसान और ३२.६९ प्रतिशत कृषि श्रमिक थे। इस तरह, इन समुदायों में से करीब ८७% कामगार प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में लगे थे। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर लगभग २९.६० प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत ५२ प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की तीन—चौथाई से अधिक महिलाऐं अशिक्षित हैं। ये असमानताएं औपचारिक शिक्षा में पढ़ाई छोड़ देने की उच्च दरों से और बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में असंगत रूप से कम प्रतिनिधित्व है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसका कुल प्रभाव यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है।

कौशल विकास :— किसी कार्य को करते समय अधिक कुशल और प्रभावी होने के लिए विशिष्ट कौशल में सुधार करने की प्रक्रिया है। कौशल विकास भारत सरकार की एक पहल है जिसे देश के युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है जो उन्हें कार्य वातावरण में अधिक रोजगार योग्य और अधिक उत्पादक बनाता है। १५ जुलाई २०१५ को इसकी शुरूआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कि गई। भारत एक ऐसा देश है जहॉ ६५ प्रतिशत युवा कामकाजी आयू वर्ग में है। यदि जनसांख्यिकी लाभ को प्राप्त करने का कोई तरीका है तो वह युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से होगा ताकि वे न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देंगें।

रोजगार की चुनौतियाँ — कौशल की कमी के अलावा रोजगार प्राप्त करने में निम्नलिखित समस्याएँ आती है जैसे —

१. स्थानीय रोजगार का अभाव — स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सीमित है, जिसके कारण युवाओं को शहरों की और पलायन करना पड़ता है।

२. सांस्कृतिक बाधाएँ— जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएँ उन्हें कुछ

प्रकार के रोजगार अपनाने से रोकती है।

३. सरकारी योजनाओं का कम प्रभाव :— रोजगार गारंटी योजना जैसी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन नही हो पाता।

समस्या का व्यापक प्रभाव :— कौशल विकास और रोजगार के अभाव में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न की है। गरीबी और कुपोषण की स्थिति बढ़ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित है। जनजातीय युवाओं में निराशा और पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

कौशल विकास की स्थिति :— जनजातियों में कौशल विकास की स्थिति काफी पिछड़ी है। पारंपारिक कार्यो पर निर्भरता और शिक्षा का स्तर कम होने के कारण युवाओं को आधुनिक उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश करने में कठिनाई होती है। हालांकि, सरकार और कुछ गैर—सरकारी संगठनों द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे है, फिर भी इनका प्रभाव बहुत सीमित है। जनजातियॉ आज भी पारंपारिक आजीविका स्त्रोतों पर निर्भर है, जैसे कि कृषि, वनोपज संग्रहण और मजदूरी। इन जनजातियों का मुख्य ध्यान आजीविका के पारंपारिक साधनों पर रहता है, लेकिन बदलते समय और क्षेत्रीय विकास की दिशा में ये पारंपारिक साधन अब पर्याप्त नही है। इस समस्या का समाधान कौशल विकास के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे ये समुदाय आधुनिक कार्यो में सक्षम हो सके। महिलाओं के लिए अधिकतर कौशल विकास कार्यक्रम पारंपारिक घरेलू कार्यो तक ही सीमित होते है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प आदि।

१. सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम :—

कई सरकारी योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NRLM) ने कौशल विकास की दिशा में कुछ प्रयास किए है। लेकिन इन योजनाओं का जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन नही हो पा रहा है। जिसकी वजह है जनजातीय समुदायों को इन योजनाओं के बारे में सीमित जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव — कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी है, जिससे युवाओं को सही मार्गदर्शन नही मिल पाता है।

२. प्रशिक्षण की कमी —

अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ अनुपलब्ध है। युवाओ को रोजगार के लिए केवल पारंपारिक कौशल (जैसे खेती, कच्चे माल का संग्रहन, हस्त शिल्प) पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे वे आधुनिक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नही होते।

➢ **अवसरों की सीमितता :—** केवल कुछ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान ही है, जिनमें विशेषकर शहरों में स्थित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों का अभाव है।

➢ **कृषि आधारित कौशल —** अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि या पारंपारिक रोजगार तक ही सीमित रहते है।

३. महिलाओं का कौशल विकास —

महिलाओं के कौशल विकास में भी कई अवरोध है, जैसे पारंपारिक सामाजिक ढॉंचा और शिक्षा की कमी । यदि महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, तो ये भी रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकती है।

१. सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम :—

कौशल विकास की दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है, जिनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शामील है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हालांकि इन योजनाओं का जनजातीय क्षेत्रों में सही तरीके से क्रियान्वयन नही हो रहा है।

समस्याएँ — कम जानकारी —

अधिकांश जनजातीय समुदायों में इन योजनाओं के बारे में जानकारी नही होती।

स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन की कमी — योजनाओं का प्रभाव कार्यान्वयन नही हो पा रहा है, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों और गॉवों तक योजनाओं की पहुँच नही है।

२. प्रशिक्षण केन्द्रो का अभाव —

जिले के जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव है। जहॉ तक प्रशिक्षण की बात है, अधिकांश संस्थान शहरी इलाकों में स्थित है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केन्दों की भारी कमी है। इसके कारण जनजातीय युवा रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में असमर्थ है। इसमें प्रमुख समस्याऐं है— कृषि और पारंपारिक कौशल तक ही सीमित प्रशिक्षण — कौशल विकास कार्यक्रम कृषि या छोटे घरेलु कामकाजी क्षेत्रों में ही सीमित है और बड़े उद्योग या तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। शिक्षा की कमी भी इसमें प्रमुख समस्या बनकर उभरकर आयी है जनजातीय युवाओं में तकनीकी शिक्षा की कमी है, जिससे वे नई नौकरियों के लिए तैयार नही हो पाते।

३. पलायन की प्रवृत्ति —

जिले की जनजातियॉ रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की और पलायन करती है। लेकिन, शहरों मे भी इनका सामना अस्थिर और कम वेतन वाली नौकरियों से होता है, जिससे पलायन के बाद भी इनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नही होता है। इसमें प्रमुख समस्याएॅ— शहरी इलाकों में अस्थिर रोजगार— शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होते हुए भी उन्हें औपचारिक और स्थिर काम नही मिल पाता है। दूसरी समस्या है— जीविका की अनिश्चितता— पलायन करने वाले युवा लंबे समय तक रोजगार में स्थिरता हासिल नह कर पाते और कई बार वे वापस लौट आते है।

रोजगार की चुनौतियाँ —

जिले की जनजातियाँ न केवल पारंपारिक कार्यो पर निर्भर है, बल्कि रोजगार के अवसरों की कमी भी उनके लिए एक बड़ी समस्या है। रोजगार के लिए कई प्रकार की बाधाएें है, जो इन्हें नए अवसरों तक पहुॅचने से रोकती है।

१. स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी —

अधिकांश जनजातियॉ कृषि आधारित है, लेकिन भूमि की कमी और कृषि निवेश की कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो गए है। इसके अलावा, स्थानीय उद्योग और व्यवसायों की कमी भी रोजगार सृजन में रूकावट डालती है। इसमे प्रमुख समस्याएं है— कृषि आधारित रोजगार, क्षेत्री रोजगार का अभाव— कृषि के पैमाने पर निर्भरता और कृषि कार्यो मे कमी के कारण रोजगार के अवसर सिकुड गए है। उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्रों का अभाव होने के कारण जनजातीय समुदायों को शहरी क्षेत्रों की और पलायन करना पड़ता है।

२. सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएॅ —

जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाएं उन्हें कई प्रकार के रोजगार अपनाने में रोकती है। कई बार ये समुदाय शहरों में औद्योगिक कार्यो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक नही होते है। इनमें भी कुछ समस्याएॅ देखी गई है जैसे — परंपराएॅ और मान्यताएॅ — पारंपारिक कामकाजी ढॉचे में बदलाव करना और आधुनिक कार्यो को अपनाना कई बार इन समुदायों के लिए कठिन होता है। प्राकृतिक संसाधनों का न होना— जनजातीय समुदायों की पारंपारिक आजीविका प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है, जो अब धीरे धीरे घर रहे है।

निष्कर्ष —

कौशल विकास और रोजगार की स्थिति जनजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी दिशा में कई चुनौतियाँ भी है। बेहतर और प्रभावी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों तक पहुॅचनें का मौका और रोजगार के अवसरों तक पहुॅचनें का मौका मिल सकता है। वर्तमान समय में कौशल विकास ही वह माध्यम है, जिससे जनजातीय समुदायों को रोजगार के आधुनिक अवसर प्राप्त हो सकते है। जनजातियों के लिए कौशल विकास की संभावनाएँ सीमित है। इसका मुख्य कारण है इन लोगों मे कम जागरूकता साथ ही ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव है। बात अगर शिक्षा की जाये तो इन समुदायों में अभी भी शिक्षा का अभाव है, शिक्षित युवाओं की कमी के कारण वे तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी पाने में असमर्थ रहते है और प्रशिक्षण केन्द्रों की अनुपलब्धता, इन क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्र नही होते है। १५—५९ वर्ष के कार्यकारी आयु

समूह का अनुपात निरंतर बढेगा, अत: भारत के पास जनसांख्यिकी लाभांग का लाभ है। उपयुक्त कौशल विकास प्रयासों के माध्यम से जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करना देश के भीतर न केवल समग्रता एवं उत्पादकता प्राप्त करने हेतु अवसर उपलब्ध कराएगा बल्कि इससे वैश्विक कौशल कमियों में भी कमी होगी। अत: बडे पैमाने पर कौशल विकास अत्यधिक आवश्यक है।

संदर्भग्रंथ सूची

१. सुरेश, एस, और शिवकुमार डी, (२००२), SOCIAL WELFARE MEASURES FOR SCHEDULED TRIBES IN TAMIL NADU A STUDY. Neuro Quantology, 20(10), 6221.

२. किरणदीप, कौर,। Study on Skill development initiatives in India" (२०१५), वाल्यूम, ५ आईएसएसएन २२४९७१३७

३. Snigdha, Suhagin, (2020), "A Study on Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna(PMKVY) in Odisha" Vol. 15, ISSN N 0974-2808

4. Gandhi, M. (2022). Educational Development of Scheduled Tribe Children: Opportunities and Challenges. Politics of Education in India, 54-74.

5. Banshidhar, Naik., Snighdharani, Panda. (2023). Empowerment of Tribal Communities Through Innovation and Entrepreneurship: A Path to Sustainable Progress. International journal of research and review, doi: 10.52403/ijrr.20231140

6. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/202411/Annual%20Report%2023-24%20Eng.pdf

7. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/202309/Final%20Skill%20AR%20Eng.pdf

8. https://socialwelfare.vikaspedia.in/viewcontent/social-welfare/

❑❑❑

12

ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं कौशल विकास

(मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विकासखण्ड भीकनगांव के विशेष संदर्भ में)

डॉ. दीपक गर्ग
शोध निर्देशक
आर. एन. टी. यू, भोपाल

कपिल कुमार मेहता
पीएचडी शोधार्थी
आर. एन. टी. यू, भोपाल

****

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में, SHGs ने महिलाओं को न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है, बल्कि उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर दिया है। यह शोध पत्र स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के उद्यमिता विकास में आने वाली चुनौतियों और उनसे मिलने वाले अवसरों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में ग्रामीण विकास के लिए स्वयं सहायता समूह गतिशील उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं, जो सामूहिक कार्रवाई और सशक्तिकरण के सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं। ये जमीनी स्तर के संगठन, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएँ शामिल हैं, ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने

से लेकर सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने तक, SHGs ग्रामीण भारत के विकास परिदृश्य का अभिन्न अंग बन गए हैं। यह परिचय जमीनी स्तर पर सतत विकास और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में SHGs द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की गहन खोज के लिए मंच तैयार करता है।

स्वयं सहायता समूहों का परिचय

स्वयं सहायता समूह (SHGs) छोटे समूह होते हैं, जिनमें आमतौर पर १० से २० सदस्य होते हैं। ये सदस्य एक—दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं और बचत एवं ऋण वितरण की प्रणाली को अपनाते हैं। SHGs महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी साधन साबित हुए हैं, विशेष कर ग्रामीण इलाकों में जहाँ वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सीमित होती है। ये समूह महिलाओं को बचत करने, छोटे—मोटे व्यवसाय शुरू करने, और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करते हैं।

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना SHGs के माध्यम से महिलाओं ने न केवल अपने परिवार के लिए आर्थिक योगदान दिया है, बल्कि वे खुद के छोटे—छोटे व्यवसाय भी शुरू करने में सक्षम हुई हैं। इन में हस्तशिल्प, जनरल स्टोर्स, मछली पालन, कृषि आधारित उद्योग, सिलाई—कढ़ाई, डेयरी उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि शामिल हैं।SHGs की महिलाओं को निम्नलिखित तरीकों से स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा दिया है:—

१. **वित्तीय सहायता**:— SHGs के माध्यम से महिलाएँ आपसी बचत और छोटे ऋणों के माध्यम से व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। यह आर्थिक सहायता उन्हें बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता कम करने में मदद करती है।

२. **सामूहिक शक्ति**:— समूह में काम करने से महिलाओं को सामूहिक शक्ति का अनुभव होता है। वे एक—दूसरे की मदद से जोखिमों का सामना करने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होती हैं।

३. **विपणन और व्यापार कौशल**:—SHGs विभिन्न सरकारी और गैर—सरकारी कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को व्यापार और विपणन कौशल में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वे अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में सक्षम होती हैं।

४. **सामाजिक सशक्तिकरण**:— SHGs के माध्यम से महिलाएँ केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त होती हैं। वे परिवार और समाज में अपनी आवाज को मजबूत बनाती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। मध्यप्रदेश में SHGs का परिदृश्य मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में SHGs ने महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और महिला सशक्तिकरण योजनाओं ने SHGs को प्रोत्साहित किया है।SHGs के माध्यम से महिलाएँ छोटे व्यवसाय शुरूकर रही हैं और कृषि से संबंधित उद्यमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेर ही हैं। इन समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का एक नया मार्ग दिखाया है।

५. **सामाजिक मुद्दों के लिए सामाजिक पूंजी**:— स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक पूंजी लिंग आधारित भेदभाव, दहेज प्रथा और जातिवाद जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में एक परिसंपत्ति के रूप में कार्य करती है।

६. **सामुदायिक वकालत**:— सफल उदाहरणों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सामुदायिक मुद्दों, जैसे कि उनके गांवों में शराब की दुकानों को बंद करने, के समाधान के लिए एक साथ आने पर प्रकाश डाला गया है।

७. **समग्र योगदान**:— आर्थिक पहलुओं से परे, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास में समग्र रूप से योगदान देते हैं, तथा भारत में समुदायों के परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

महिलाओं के स्वरोजगार के अवसर में आने वाली चुनौतियाँ

हालाँकि SHGs के माध्यम से महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई चुनौतियाँ हैं जो उनके विकास में बाधक बनी हुई हैं। इनमें प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखितहैं:—

१. शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतर महिलाएँ शिक्षा

और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव में अपने व्यवसाय को सही दिशा में नहीं ले पाती हैं। व्यावसायिक कौशल और विपणन की समझ की कमी के कारण वे अपने उत्पादों को बाजार में सही ढंग से पेश नहीं कर पातीं।

२. वित्तीय संसाधनों की सीमित पहुँच

हालाँकि SHGs वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, परंतु कई बार बड़े व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक बड़े ऋणों तक पहुँच कठिन होती है। बैंकिंग प्रणाली की जटिलताओं और गारंटी की आवश्यकता के कारण महिलाएँ वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं।

३. समाजिक और पारिवारिक दबाव

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ अपनी उद्यमशीलता क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाती हैं। अक्सर उन्हें घरेलू कार्यों में उलझा दिया जाता है, जिससे उनके व्यवसायिक प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

४. बाजार तक पहुँच की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। उचित विपणन रणनीति और तकनीकी समझ के अभाव में उनके उत्पाद बाजार तक पहुँचने से पहले ही असफल हो जाते हैं।

५. प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल की कमी

डिजिटल युग में भी अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ तकनीक का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस के चलते वे अपने व्यवसाय को ऑनलाइन मंचों पर स्थापित करने में असमर्थ होती हैं, जिससे वे बाजार के आधुनिक अवसरों का लाभ नहीं उठा पातीं।

महिलाओं के उद्यमिता विकास में अवसर

चुनौतियों के बावजूद, SHGs के माध्यम से महिलाओं के उद्यमिता विकास के लिए कई अवसर भी हैं, जिनका सही उपयोग कर महिलाएँ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं:—

१. सरकारी योजनाओं का सहयोग

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, महिला उद्यमी योजना, और स्टार्टअप इंडिया, SHGs की महिलाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएँ अपने व्यवसायों को बढ़ा सकती हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकती हैं।

२. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण

सरकार और गैर—सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। महिलाएँ इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर व्यवसायिक कौशल विकसित कर सकती हैं, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें और अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से बाजार में प्रस्तुत कर सकें।

३. ई—कॉमर्स और डिजिटल मंच

ई—कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ग्रामीण महिलाएँ अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकती हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँचने ग्रामीण महिलाओं को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेट फॉर्म पर स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है।

४. सहकारी उद्यमिता

SHGs के माध्यम से महिलाएँ सामूहिक उद्यमिता की दिशा में काम कर सकती हैं। एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करना और उत्पादों की बिक्री करना उनके व्यवसाय को अधिक लाभकारी बना सकता है। सामूहिकता से वे बड़ी कंपनियों या सरकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी कर सकती हैं।

५. स्थानीय बाजारों का विकास

स्थानीय बाजारों और मेलों में SHGs द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री एक बड़ा अवसर हो सकता है। इस से महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए एक स्थायी बाजार मिल सकता है और उन की आय में वश्द्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, SHGs महिलाओं को आर्थिक और

सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि, महिलाओं को अपने व्यवसाय को सफल बनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से वे इन चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं। SHGs के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा, ताकि वे देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

सारांश

ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा महिलाओं के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से विशेष प्रयास किये जा रहें हैं। समूह की महिलाऐं भी घर की चाहर दिवारी से बहार निकल कर स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर अपने एवं अपने परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नती के लिये पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है।

कौशल की कमी के कारण समूह की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आरसेटी, नाबार्ड एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिये जाते है जैसे– सिलाई कढाई, बकरी पालन, मछली पालन, मूर्गी पालन आदि लेकर कौशल विकास को बढावा दे रही है।

संदर्भ सूची

१. म०प्र० महिला आर्थिक विकास निगम/यूनिसेफ (२०१०) ''स्वशक्ति परियोजना'' म. प्र. का उपक्रम, २४ जोन एम.पी. नगर, भोपाल पृ.क्र. ४—७।

२. महिला एवं बाल विकास इंदौर , (२००९) ''स्व सहायता समूह'' स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मार्गदर्शिका।

३. नाबार्ड व रिर्जव बैक (२०१०) ''स्व सहायता समूह'' मार्गदर्शिका, पृ.क्र. ७

४. ''स्वयं सहायता समूह (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना)'' जिला पंचायत जिला इंदौर (२०१०),।

५. ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका (२०२३)।

६. ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाऐं और कार्यक्रम की रिपोर्ट।

७. राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन की रिपोर्ट और दिशा निर्देश।

८. सिन्हा आर. के. शेख, फैमिदा, सक्सेना मनोज, मिश्रा, जी.पी.खरे एन.के. :२००६: स्व—सहायता समूह गठन प्रकिया एवं मार्गदर्शन, उधमिता विकास केन्द्र म.प्र, १६—ए, अरेरा हिल्ल, भोपाल म.प्र.।

९. २८. सिंह उपेन्द्र दिसम्बर २०१० कुरुक्षेत्र, 'ए विंग गेट नं.५ निर्माण भवन ग्रमीण वि. मंत्रालय, नई दिल्ली ११०००१।

१०. कुमार विनोद (२००९) ''स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं बनी आत्मनिर्भर'' सारथी मार्च—जून, अंक २ पृ. क्र. २३।

❑❑❑

13

अनुसूचित जाति की महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक कौशल विकास

डॉ. मुकेश कुमार सावले
(अर्थशास्त्र)

****

प्रस्तावना—

''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: ही हो जाएगा।''

—पंडित जवाहरलाल नेहरू

अर्थशास्त्र में विकास शब्द न केवल एक सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है अपितु इसका संबंध मानव मात्र के कल्याण से भी हैं। जब हम किसी अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य उसके चहुंमुखी विकास की तथा उससे संबंधित प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग के विकास से होता हैं। अर्थव्यवस्था समाज से घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा समाज परिवार का ही वृहद रूप हैं, आधारशिला है नारी जिसके बिना इस परिवार रूपी पौधे के अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस दृष्टि से चूंकि नारी अर्थव्यवस्था से आवश्यक रूप से संबंधित है, नारी का विकास किये बिना हम अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना तक नहीं कर सकते।

एक ओर जहां देश के समक्ष विकास की महान् चुनौतियां मुंह बांये खड़ी हैं जिनकी तरफ सारी दुनियां की नजर है, वहीं दूसरी ओर देश के सामने महानतम् चुनौती हैं महिलाओं के विकास की, उसकी स्थिति में सुधार की जिसे सब जानते हुए भी नजर अन्दाज करते रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी पुरूष प्रधान सभ्यता ने नारी जाति की अवहेलना की, समाज का विकास अवरूद्ध हुआ, उसका पतन हुआ, किन्तु जब नारी जाति को मान—सम्मान दिया गया उसे प्रेरणा व स्फूर्तिदायिनी जगतजननी का स्थान दिया गया, समाज उन्नति के शिखर पर पहुंच गया।

महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक—दूसरे के पूरक हैं। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं जिनसे जीवन—यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती हैं। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल—जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिशीलता पर ही निर्भर हैं। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती हैं। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी है कि जहॉ महिलाओं की उपेक्षा की गई हैं, वहॉ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ हैं। महिला की भूमिका पुरूष से कही अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती हैं। अत: स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नही हो सकता जहॉ तक भारत का संबंध है ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता''। अर्थात् जहॉ महिलाओं की पूजा होती हैं वहां देवताओं का वास होता हैं। इस आदर्श के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पश्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। भारतीय महिलाऍ किसी भी दशष्टि से पुरूषों से कम नही हैं। इतिहास के प्रारंभिक समय मे उन्हें पुरूषों से कम नहीं माना गया मध्यकाल एवं विदेशी शासनकाल में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो रही। उन्हें पूर्णत: पुरूषों पर निर्भर बना दिया गया। यहॉ तक की उन्हें दासी कहकर संबोधित किया गया तथा उनके नागरिक एवं सार्वजनिक अधिकार छीनकर उन्हें घर की चहारदीवारी में बंद कर दिया गया। **रायडन** का कथन हैं—''स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली हैं और उन्होंने ही जंगलों में मारे—मारे भटकते फिरते हुए पुरूषों का हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर जीवन या घर में बसाया हैं।'' भारतीय समाज में वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति न केवल अच्छी थी, अपितु अत्यन्त उन्नत थी। स्त्रियों को शिक्षा, विवाह, सम्पति आदि में पुरूषों के समान

अधिकार था और स्त्रियों में आत्मसम्मान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल से महिलाओं के लिए समस्यायें उत्पन्न होने लगी। धर्मसूत्रों में बाल विवाह का निर्देश दिया गया जिससे शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई और इसी काल में स्त्रियों को धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। स्मशति युग में स्त्रियों की स्थिति और भी निम्न हो गई। इसी प्रकार मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल के प्रारंभ तक स्त्रियों की बड़ी दयनीय दशा थी।

किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में उस देश का लिंगानुपात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। सामान्यत: यह देखा जाता हैं पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में कार्य करने की शारीरिक क्षमता कम होती हैं। अत: यह उत्पादन के कार्य में उतना हाथ नहीं बटा पाती हैं, जितना की उपभोग में, जिससे प्रति व्यक्ति आय इस बात पर निर्भर करती हैं कि वहाँ स्त्री जनसंख्या उत्पादन में कितना हाथ बंटाती हैं। देश में समाज अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग में विभाजित हैं। वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में १५.६ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है जिसमे खरगोन जिले १५.७ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की हैं। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने से अनुसूचित जाति के पुरूष एवं महिला दोनों कृषि संबंधी विभिन्न कार्यो से आय अर्जित कर अपनी जीविका चलाते है।

विषय का चयन—

मध्यप्रदेश पश्चिमी भाग में स्थित खरगोन जिला जो पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जिला है। इसी प्रकार वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या में १५.७ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग की है। अनुसूचित जाति में भी विभिन्न उपजातियॉ जिले में निवास करती है। प्रत्येक उपजातियों का व्यवसाय भी अलग—अलग है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति जिले में अच्छी नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य—

१. खरगोन जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से कौषल विकास का अध्ययन करना।

२. अनुसूचित जाति की महिलाओं में षिक्षा कौषल विकास के कारण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुआ है या नही स्थिति का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना—

परिकल्पना को उपकल्पना भी कहा जाता है। परिकल्पना अनुसंधान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है।

प्रो. यंग के अनुसार—''एक कार्यवाहक विचार, जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यकारी उपकल्पना के नाम से जाना जाता है।''

उपलब्ध साहित्य का अध्ययन :—

उपलब्ध साहित्य का अध्ययन एवं समीक्षा वर्तमान में किये जा रहे शोध कार्य की रूप रेखा एवं कार्य करने की नीति निर्धारण में सहायता करते हैं।

सारिका सरगरा (जुलाई २००९)—ने अपने शोध आलेख ''बाल श्रम कारण एवं प्रभाव''—एक सामाजशास्त्रीय अध्ययन में स्पष्ट किया गया हैं कि वर्तमान में सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए कई प्रकार की योजनाऐं चला रही हैं। किन्तु उनका लाभ बच्चों को नही मिल पा रहा हैं। इन योजनाओं के स्थान पर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहिए जिससें की अनिवार्य शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करें।

डॉ उमाशंकर गुरू एवं दिव्या पांण्डे (जून २०१०)—में शोध आलेख ''प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में शिक्षा गांरटी शाला गांरटी शालाओं की भूमिका'' के अध्ययन में कहा गया हैं कि शिक्षा गांरटी योजना बच्चों के शिक्षा पाने के बुनियादी अधिकार को स्पष्ट करती है इसमें सरकार और समुदाय की सहभागिता हैं। गांव के स्तर पर कई सम्भावनाए दिखाई देती हैं।

डॉ कुल श्रेष्ठ लक्ष्मी रानी (१९९८)—में महिलाओं की कार्य सहभागिता के संबंध में बताया गया हैं कि महिलाओं को गांव से लेकर मण्डल तक की विकास योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। देश के आर्थिक विकास में अपेक्षित भागीदारी के लिए महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष

ध्यान देना अनिवार्य हैं। महिलाओं को विस्तश्त प्रशिक्षण देना भी आवश्यक हैं।

तथ्यों का संकलन वर्गीकरण तथा विश्लेषण—

तथ्यो के संकलन करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय संमको का प्रयोग किया गया है। जिसमें द्वितीय संमको में अनुसूचित जाति की दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात किया गया है।

दसवर्षीय जनसंख्या वृद्धि —

खरगोन जिले में अनुसूचित जाति की दस वर्षीय विकासखण्डवार जनसंख्या वृद्धि निम्नतालिका में दर्शायी गयी

वर्ष २००१—२०११ का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका — १.१

क.	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या	दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि	अनुसचित जाति की जनसंख्या	कुल जनसंख्या से प्रतिषत
1	बड़वाह	241265 (278531)	19.68 (15.44)	42234 (49806)	19.81 (17.88)
2	महेश्वर	167321 (196278)	25.13 (17.30)	32989 (39537)	19.72 (20.16)
3	कसरावद	185823 (219959)	32.84 (18.37)	26752 (30750)	14.40 (13.98)
4	सेगांव	68967 (83487)	25.05 (21.05)	2927 (3251)	4.24 (3.89)
5	भीकनगांव	138582 (175563)	24.43 (26.68)	9819 (12032)	7.09 (6.85)
6	खरगोन	166120 (113162)	33.33 (31.87)	16912 (17302)	12.70 (15.29)
7	गोगांवा	103230 (112458)	31.27 (8.93)	11508 (12533)	11.14 (11.14)
8	भगवानपुरा	148579 (192996)	40.07 (29.89)	4771 (5551)	3.21 (2.88)
9	झिरन्या	151824 (201756)	27.93 (32.88)	5748 (6919)	3.78 (3.43)
10	जिला खरगोन	1529562 (1873046)	27.92 (22.46)	174495 (209091)	11.40 (11.16)

स्त्रोत—जिला सांख्यिकीय पुस्तिका २०१२—२०१४ जनगणना, २००१ (२०११ के ऑकड़े), पृष्ठ संख्या —२,३

उपर्युक्त तालिका में जिले में अनुसूचित जाति की दस वर्षीय विकासखण्डवार जनसंख्या वृद्धि व कुल जनसंख्या से प्रतिशत २००१—२०११ का तुलनात्मक अध्ययन किया गया कोष्ठक में २०११ के ऑकड़ों को बताया गया है। जिले में कुल दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि २००१ में २७.९२ व २०११ में २२.४६ है, जिसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत २००१ में ११.४० २०११ ११.१६ प्रतिशत रहा। इसी प्रकार विकासखण्ड भगवानपुरा में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत सबसे कम २००१ में ३.२१ २०११ में २.८८ हैं। तुलनात्मक अध्ययन में दिया गया कि २००१ से २०११ में ०.३३ प्रतिशत की कमी हुई है। बड़वाह विकासखण्ड में सबसे अधिक कुल जनसंख्या से प्रतिशत १९.८१, २००१ तथा २०११ में १७.८८ है। महेश्वर विकसखण्ड २०११ २०.१६ प्रतिशत कुल जनसंख्या से है जो सबसे अधिक है क्योकि प्रशासनिक दश्ष्टि से भी यह विकासखण्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या २००१ में १७४४९५ तथा २०११ में २०९०९१ है तुलनात्मक अध्ययन में अनुसूचति जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या सेगाव विकासखण्ड में २९२७ २००१—२०११ में हैं क्रमशः बड़वाह विकासखण्ड, भीकनगांव, कसरावद, खरगोन, गोगावा झिरन्या भगवानपुरा से तुलनात्मक अध्ययन से सेगाव विकासखण्ड से कम है।

साक्षरता—

अनुसूचित जाति की महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक कौशल विकास में शिक्षा न केवल ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ाने का साधन हैं, वरन् लोकतन्त्र में भागीदारी बढ़ाने और विस्तश्त करने का भी माध्यम है। शिक्षा से व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की कुल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होता हैं। इसीलिये सरकार ने शिक्षा के मात्रात्मक विस्तार के साथ ही गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया हैं। देश में शिक्षा विस्तार के प्रयासों से साक्षरता दर में निरन्तर सुधार हुआ हैं। इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक खरगोन जिले में साक्षरता का प्रतिशत धीरे—धीरे बढ़ता जा रहा हैं। खरगोन जिले में सन् १९७१ में साक्षरता का प्रतिशत मात्र २१.४७ था जो धीरे—धीरे बढ़कर सन् २००१ में बढ़कर यह ६३.०५ प्रतिशत था २०११ में बढ़कर यह ६४.०० प्रतिशत हो गया। प्रत्येक दशक में साक्षरता के प्रतिशत की दर वृद्धि होती जा रही है। वर्ष २००१ में कुल महिला साक्षरता का प्रतिशत ५०.६४ था, जो वर्ष २०११ में बढ़कर ५३.७ प्रतिशत हो गया।

शोध कार्य में तथ्यों के संकलन करने हेतु पूर्व से तैयार की गयी अनुसूची का प्रयोग किया गया एवं

प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं से प्रश्नो के उत्तर प्राप्त किये गये।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास की भूमिका

तालिका — १.४

कमांक	विकास हुआ	आवृति	प्रतिशत
1	हॉ	40	80
2	नही	10	20
	योग	**50**	**100.0**

स्त्रोतः— व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में ली गई ५० अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से ४० महिलाओं का विकास हुआ है तथा १० महिलाऐं अभी भी ऐसी है जिनका शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी विकास नही हुआ है। यहॉ स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ८० प्रतिशत अनुसूचित जाति महिलाओं का सामाजिक विकास में वशद्वि हुई है। २० प्रतिशत महिलाओं का विकास नही हुआ है। अनुसूचित जाति महिलाओं की परिवारिक स्थिति किस प्रकार की है। इसकी जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास अध्ययन क्षेत्र में किया गया महिला उत्तरदाताओं से यह भी प्रश्न किया गया की आपका परिवार का स्तर किस प्रकार का है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति—

अनुसूचित जाति की महिलाओं मे शिक्षा प्राप्त करने के बाद आर्थिक विकास हुआ

तालिका — १.७

कमांक	विकास हुआ	आवृति	प्रतिशत
1	हॉ	40	80
2	नही	10	20
	योग	**50**	**100.0**

स्त्रोतः— व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा प्राप्त करने के बाद ८० प्रतिशत आर्थिक विकास हुआ जबकि २० प्रतिशत महिलाऐ ऐसी है जिनका अभी भी आर्थिक विकास नही हुआ है। इनमें जागरूकता की कमी पाई गई है। स्पष्ट किया जाता है कि जागरूकता लाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा जहॉ एक ओर व्यक्ति के सामाजिक जीवन में अहम् भूमिका का निर्वहन करती है तो आर्थिक विकास में सहायक सिद्व भी होती है दोना एक दूसरे के पूरक कार्य करती है। सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि ८० प्रतिशत महिलाए आत्मनिर्भर है जबकि २० प्रतिशत महिलाऐं आज भी आत्मनिर्भर नही हैं

निष्कर्ष —

निष्कर्ष के रूप कहॉ जा सकता है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । वर्ष २००१ में कुल महिला साक्षरता का प्रतिशत ५०.६४ था, जो वर्ष २०११ में बढ़कर ५३.७ प्रतिशत हो गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ८० प्रतिशत अनुसूचित जाति महिलाओं का सामाजिक विकास में वशद्वि हुई है। २० प्रतिशत महिलाओं का विकास नही हुआ है। अनुसूचित जाति की महिलाए शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी २० प्रतिशत महिलाऐ एसी है जिनके पास स्वयं अर्जित आय के काई भी साधन नही है व ५० प्रतिशत महिलाऐ ऐसी है जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद कशषि मजदूरी निजी कार्य व घरेलू कौशल विकास का कार्य करती है तथा ३० प्रतिशत महिलाए शिक्षा कौशल प्राप्त करने के बाद शासकीय एवं अशासकीय नौकरी कर रही है। एवं अपना स्वयं का घरेलू व्यवसाय भी करती है। किसी भी राष्ट्र या समाज का सर्वागीण विकास करने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है महिलाओं के आर्थिक विकास महिलाओं से जुडी समस्याओं की पूरी जानकारी प्राप्त कर उन्हे योग्यता के अनुसार अवसर प्रदान करना ताकि कौशल विकास के माध्यम से वह अपने जीवन में गुणवत्ता ला सके।

संदर्भ सूची—

१. रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेज, प्रमुख सम्पादक प्रोफेसर ब्रजगोपाल, प्रकाशन गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा अंक xiii-I सितम्बर २०१५ पेज नं.—२०

२. रिसर्च जरनल ऑफ आर्ट्स, मैनेजमेन्ट एण्ड सोशल साइन्सेज, प्रमुख सम्पादक प्रोफेसर ब्रजगोपाल, प्रकाशन गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवा अंक xiii-I सितम्बर २०१५ पेज नं.—११

३. रानी डॉ [illegible]

कार्यक्रम, प्रकाशन,इना श्री पब्लिशर्स,जयपूर पेज नं.—११

४. रानी डॉ. आशु २०१३, महिला विकास कार्यक्रम, प्रकाशन,इना श्री पब्लिशर्स, जयपूर पेज नं. —१९

५. श्रीवास्तव डॉ. ए. पी. आर पी (२०१५)—समाजशास्त्र, प्रकाशक—राम प्रसाद एण्ड संस, हमीदिया रोड, भोपाल—पृ. सख्या, १७७—१७८

६. त्रवेदी डॉ. आर एन एवं शुक्ला डॉ. डी. पी २००४—रिसर्च मैथ्डोलाजी प्रकाशन—कालेज बुक डिपो जयपूर नयी दिल्ली पेज नं. १८१

७. कुल श्रेष्ठ ड़ॉ लक्ष्मीरानी डीन, समाज विज्ञान संकाय, नवम्बर—१९९८, कुरूक्षेत्र, दयालबाग, एज्यूकेशन इन्स्टीट्यूट दयालबाग अगरा, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या —११

८. सरगरा सारिका —जुलाइ २००९ रिसर्च लिंक Issue-64 vol- vii (5)–kala sanaj vigyan awam vanijya– प्रकाशन कार्यालय वर्द्धमान अपार्टमेन्ट ओल्ड पलासिया इन्दौर पेज नं. ७४

९. guru Dr. Uma sanker & pande divaya (june), Issue-75 vol- ix (4) -june 2010 /Research Like _ p.no.-77

10- Research Revolution-International journal of Social Science & Management –Regd office 14/2 Rajbada chowk,Indore(mp) vol- viii Issue-7 April 2015 p.no.100

11- Research Revolution-International journal of Social Science & Management –Regd office 14/2 Rajbada chowk,Indore(mp) vol- viii Issue-7 Oct. 2015 p.no.37

12- Managing Editor-Prof. Kanhaiya Ahuja –Journal Of Madhya Pradesh Economics Association vol.xxiv February 2014 p.no. -111

१३. डॉ़ जे. सी. पन्त/ड़ॉ. जे. पी. मित्रा—भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रकाशन साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, कोड—१९५७ पृष्ठ संख्या ५१

१४. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका २०१२—२०१४ जनगणना २००१—२०११ के ऑकड़े पेज नं. —२३

१५. श्रीमती प्रतीक्षा पाठक—नवीन शोध संसार volume I issue v-jan-march-2014 पेज नं.—१९७

❑❑❑

14

कम्प्यूटर के क्षेत्र में कौशल विकास

डॉ. गायत्री चौहान
सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (म. प्र.)

****

पृष्ठभूमि:

- परिचय,
- संचार कौशल,
- समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोंच,
- टीमवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क,
- कम्प्यूटर से सिकुड़ता हुआ विश्व,
- विभिन्न रोजगार के अवसर,
- शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर,
- कम्प्यूटर का व्यावसायिक क्षेत्र,
- निष्कर्ष,

परिचय

कंप्यूटर वैज्ञानिकों की सफलता में सॉफ्ट स्किल्स की अहम भूमिका होती है। प्रभावी संचार, समस्या समाधान और टीमवर्क कौशल पेशेवरों को प्रभावी ढंग से सहयोग करने, विचारों को व्यक्त करने और समग्र दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। आज के डिजिटल युग में, जहाँ तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, कंप्यूटर विज्ञान कौशल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस लेख में, हम विभिन्न कंप्यूटर विज्ञान कौशल, तकनीकी और सॉफ्ट दोनों, का पता लगाएँगे, जो इस क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक हैं। चाहे आप कंप्यूटर विज्ञान में करियर शुरू करने वाले शुरुआती हों या अपने कौशल सेट को बढ़ाने के उद्देश्य से पेशेवर हों, इन कौशलों को समझना और उन्हें कैसे हासिल करना है, यह समझना महत्वपूर्ण है। आइए कंप्यूटर विज्ञान कौशल की दुनिया में उतरें और लगातार बढ़ते तकनीकी

परिदृश्य में उनके महत्व को जानें।तकनीकी कंप्यूटर विज्ञान कौशल में विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं और उपकरणों में दक्षता शामिल है। ये कौशल पेशेवरों को सॉफ्टवेयर विकसित करने, एल्गोरिदम डिजाइन करने और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाते हैं। ठोस कंप्यूटर कौशल के साथ, आप नियमित कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, डेटा का अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं, और सहकर्मियों के साथ अधिक कुशलता से संवाद कर सकते हैं । ये कौशल आपको अधिक उत्पादक बनने, दूसरों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और अपने संगठन के भीतर पदोन्नति या नेतृत्व की स्थिति हासिल करने में मदद कर सकते हैं।

संचार कौशल

संचार मानवीय अभिप्रेति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें विचारों, विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करने की संभावना प्रदान करता है। यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संबंधों, करियर की वृद्धि और समग्र सफलता पर प्रभाव डालता है। यह हमें दूसरों को आकर्षित करने, सहयोग करने, और प्रभाव डालने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा, संचार कौशल हमारे सोशल और पेशेवर संबंधों को स्थायी और सुगम बनाने में मदद करता है। इसलिए, संचार कौशल का विकास आवश्यक है ताकि हम अपनी सोच और भावनाओं को सटीक रूप से व्यक्त कर सकें, और दूसरों के साथ मजबूत संवाद और संपर्क बना सकें। प्रौद्योगिकी के युग में, ज्ञान ही शक्ति है और सभी उम्मीदवारों को अपने आसपास होने वाली नवीनतम घटनाओं के साथ अप—टू—डेट रहना चाहिए। इन ।तजपबसमे में उद्धरण, करियर, शिक्षा और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में जानकारीपूर्ण और दिलचस्प सामग्री कैप्सूल शामिल हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी सामान्य जागरूकता में सुधार करने में आपकी सहायता करते हैं।संचार कौशल वह क्षमताएं और तकनीकें हैं जो सूचना, विचार और भावनाओं को प्रभावी ढंग से संवेदनशीलता के साथ व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसमें वाणिज्यिक और गैर—वाणिज्यिक संचार के अभिकरणों, जैसे बोली, सुनने, लिखने, शरीर की भाषा को पठन करने और उचित इशारों का उपयोग करने का समावेश होता है। ये कौशल व्यक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, दूसरों को समझने, विवादों को हल करने और स्वस्थ संबंधों का निर्माण करने में सहायता करते हैं।संचार कई स्तरों पर (एक एकल कार्रवाई के लिए भी), कई अलग अलग तरीकों से होता है और अधिकतम प्राणियों के लिए, साथ ही कुछ मशीनों के लिए भी यदि समस्त नहीं तो अधिकतम अध्ययन के क्षेत्र संचार करने के लिए ध्यान के एक हिस्से को समर्पित करते हैं, इसलिए जब संचार के बारे में बात की जाए तो यह जानना आवश्यक है कि संचार के किस पहलू के बारे में बात हो रही है। संचार की परिभाषाएँ श्रेणी व्यापक हैं, कुछ पहचानती हैं कि पशु आपस में और मनुष्यों से संवाद कर सकते हैं और कुछ सीमित हैं एवं केवल मानवों को ही मानव प्रतीकात्मक बातचीत के मापदंडों के भीतर शामिल करते हैं।

समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोंच

विश्लेषणात्मक सोच और समस्या समाधान जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण कौशल हैं, जिसमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक परिस्थितियाँ शामिल हैं। हालाँकि वे एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर हैं। विश्लेषणात्मक सोच जटिल जानकारी को छोटे, प्रबंधनीय घटकों में विभाजित करने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि किसी स्थिति को समझा जा सके और विकल्पों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन किया जा सके। दूसरी ओर, समस्या समाधान में चुनौतियों पर काबू पाने या दैनिक जीवन या कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल करने के लिए व्यावहारिक समाधान तैयार करना शामिल है। विश्लेषणात्मक सोच और समस्या—समाधान कौशल दोनों ही सुविचारित निर्णय लेने, जोखिमों का प्रबंधन करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में योगदान करते हैं। इन कौशलों के अंतर को समझकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके, व्यक्ति कार्यस्थल में अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं, जटिल परिस्थितियों को आसानी

से संभाल सकते हैं और अपने निजी जीवन में बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।विश्लेषणात्मक सोच एक मानसिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति जटिल समस्याओं या स्थितियों को व्यवस्थित रूप से छोटे, प्रबंधनीय घटकों में तोड़ता है। यह आवश्यक तत्वों और उनके संबंधों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जिससे एक प्रभावी समाधान निकलता है। विश्लेषणात्मक विचारक पैटर्न की पहचान करने, डेटा की व्याख्या करने और तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने में उत्कृष्ट होते हैं। प्रतिक्रियात्मक समस्या—समाधान के विपरीत, जो तत्काल उपचार खोजने पर केंद्रित है, विश्लेषणात्मक सोच प्रकृति में रणनीतिक है, जो किसी समस्या के मूल कारणों को संबोधित करके दीर्घकालिक समाधान की तलाश करती है।विश्लेषणात्मक सोच के मुख्य घटकों में तर्क, तथ्य—जांच और मान्यताओं पर सवाल उठाना शामिल है। यह कौशल सेट व्यक्तियों को खुले दिमाग से समस्याओं का सामना करने, सावधानीपूर्वक डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने और अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। अंततः, विश्लेषणात्मक सोच अधिक सूचित और रणनीतिक निर्णय लेने की ओर ले जाती है, जिससे पेशेवर और व्यक्तिगत प्रयासों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

टीमवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क

दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कम्प्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोडने वाली व्यवस्था को कम्प्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर/कम्प्यूटर आपस में इलेक्ट्रोनिक सूचना का आदान—प्रदान कर सकते हैं और आपस में तार या बेतार से जुडे रहते हैं। सूचना का यह आवागमन खास परिपाटी से होता है, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं और नेटवर्क के प्रत्येक कम्प्यूटर को इसका पालन करना पड़ता है। कई नेटवर्क जब एक साथ जुड़ते हैं तो इसे 'इंटरनेटवर्क' कहते हैं जिसका संक्षिप्त रूप इंटरनेट/इण्टरनेट (अंतर्जाल, अंग्रेजी में Internet) काफी प्रचलित है। अलग अलग प्रकार की सूचनाओं के कार्यकुशल आदान—प्रदान के लिये विशेष प्रोटोकॉल हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एनालॉग तथा डिजिटल विधियों का प्रयोग होता है। नेटवर्क के उपादानों में तार, हब, स्विच, राउटर आदि उपकरणों का नाम लिया जा सकता है। स्थानीय कम्प्यूटर नेटवर्किंग में बेतार नेटवर्क का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कम्प्यूटर नेटवर्क का उपयोग इलेक्ट्रानिक संचार में किया जाता है। इलेकट्रानिक की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया को दूरसंचार कहते है और एक या एक से अधिक कम्प्यूटर और विविध प्रकार के टर्मिनलों के बीच आंकड़ों को भेजना या प्राप्त करना डाटा संचार कहलाता है। टीमवर्क एक समूह का एक साझा लक्ष्य हासिल करने या किसी कार्य को प्रभावी और कुशल तरीके से पूरा करने का सहयोगात्मक प्रयास है। टीमवर्क को एक टीम के ढांचे के भीतर देखा जाता है, जो अन्योन्याश्रित व्यक्तियों का एक समूह है जो एक साझा लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं।

कम्प्यूटर से सिकुड़ता हुआ विश्व

वर्तमान समय कंप्यूटर युग होने के कारण यातायात एवं संचार में पर्याप्त सरलता है तथा समय की अपार बचत है।समय—स्थान अभिसरण समय और दूरी की धारणा में परिवर्तन है और हाल के समय में परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण भौगोलिक बाधाओं का आभासी क्षरण है। दूसरे शब्दों में, आभासी संकुचन — बेहतर परिवहन और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप दो स्थानों के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय में भौतिक कमी ने लोगों, माल, पूंजी और सूचना के तेज आवागमन को प्रोत्साहित किया है।समय और स्थान के कथित संकुचन को १९६८ में जेनेल द्वारा समय—स्थान अभिसरण के रूप में और १९९० में हार्वे द्वारा समय—स्थान संपीड़न के रूप में वर्णित किया गया है। जेनेल ने एडिनबर्ग और लंदन के बीच यात्रा के समय को प्लॉट करके समय—स्थान अभिसरण की गणना की। उन्होंने औद्योगिक क्रांति से शुरू करके डेटा एकत्र किया और पता लगाया कि कैसे समय—स्थान अभिसरण एक साथ महसूस करने के प्रभाव की धारणा को उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, एडिनबर्ग से लंदन की दो—सप्ताह की स्टेज—कोच यात्रा को अंततः दो घंटे (१९५८ में)

तक चलने वाली हवाई यात्रा ने पीछे छोड़ दिया। इसलिए, जेनेल ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों शहर २०० वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष औसतन ३० मिनट की दर से अभिसरित हुए थे। हार्वे ने जेनेल द्वारा प्रस्तुत विचारों को विकसित किया।समय—स्थान अभिसरण की अवधारणा का समर्थन करने के लिए आगे के साक्ष्य दुनिया की परिक्रमा करने में लगने वाले समय का विश्लेषण करके प्राप्त किए जा सकते हैं। १७०० के दशक में, तीन मस्तूल वाले फ्रिगेट जहाज को दुनिया की परिक्रमा करने में २ साल लगते थे, जबकि २०१५ में इसे केवल २४ घंटे लगे।

इसके अलावा, संचार प्रणालियों की प्रगति से समय और स्थान एक दूसरे से जुड़ गए हैं। उदाहरण के लिए, १९वीं सदी में बिजली के विकास से पहले, सूचना केवल अपने परिवहन माध्यम जितनी ही तेजी से आगे बढ़ सकती थी। टेलीग्राफ के विकास ने सबसे पहले इस कड़ी को तोड़ा, और वर्तमान युग में संचार तात्कालिक है — उदाहरण के लिए ई—मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक और इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए।हालांकि, समय—स्थान अभिसरण को एक रेखीय प्रक्रिया नहीं माना जा सकताय क्योंकि, सभी लोग इसे एक ही सीमा तक अनुभव नहीं करते हैं (ग्रामीण और शहरी अंतर) और कुछ स्थानों ने वैश्वीकरण से बचने का प्रयास किया है — उत्तर कोरिया में, मीडिया तक पहुंच प्रतिबंधित है और इंटरनेट का उपयोग निषिद्ध है। समय—स्थान अभिसरण के विचार की उत्पत्ति वैश्विक गांव के विचार से जुड़ी हुई है। 'वैश्विक गांव' शब्द को वैश्वीकरण के आधुनिक अग्रदूत मार्शल मैक्लुहान ने अपनी पुस्तक 'द गुटेनबर्ग गैलेक्सी: द मेकिंग ऑफ द टाइपोग्राफिक मैन (१९६२)' में लोकप्रिय बनाया था। मार्शल मैक्लुहान ने दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में देखा, जो इलेक्ट्रिक तकनीक और सूचना के तात्कालिक प्रवाह से सशक्त है। उन्होंने इंटरनेट के व्यावसायीकरण से तीस साल पहले इसे ''चेतना का विस्तार'' के रूप में भी भविष्यवाणी की थी। इसके विपरीत, टोबलर द्वारा दूरी क्षय मॉडल और दूरी के घर्षण प्रभाव को समय—स्थान अभिसरण के प्रति—सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है। दूरी क्षय मॉडल से पता चलता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी बढ़ने पर उनके बीच की अंत:क्रिया कम हो जाती है। टोबलर ने एक समान विचार प्रस्तावित किया: चूँकि निकट की चीजें दूर की चीजों की तुलना में एक—दूसरे से अधिक संबंधित होती हैं (भूगोल का पहला नियम), इसलिए छोटी दूरी पर स्थानिक अंत:क्रियाएं अधिक बार होंगी। निष्कर्ष रूप में, समय—स्थान अभिसरण का तात्पर्य परिवहन और संचार में प्रमुख प्रगति द्वारा समय और स्थान के कथित परिवर्तन और भौगोलिक बाधाओं के आभासी क्षरण से है। यह अवधारणा दुनिया भर में यात्रा करने में लगने वाले कम समय और टेलीग्राफ से स्मार्टफोन के माध्यम से तत्काल संचार की ओर प्रगति द्वारा समर्थित है।

कम्प्यूटर के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

आज के समय में हर सस्थान सरकारी हो या प्राइवेट सभी जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से इसमें रोजगार के भी अवसर तेजी से बढ़ रहे है। अगर आप रोजगार की तलाश में है या कोई स्किल या पढाई करना चाहते है तो आप कंप्यूटर के क्षेत्र में कर सकते है। आज के युग में, कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन, चिकित्सा, और रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इस बढ़ती हुई उपयोगिता के कारण, कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के रोजगार:

➢ सॉफ्टवेयर डेवलपर: सॉफ्टवेयर डेवलपर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, जैसे कि वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन, और डेस्कटॉप एप्लिकेशन बनाते हैं।

➢ वेब डेवलपर: वेब डेवलपर वेबसाइटों को डिजाइन, विकसित, और रखरखाव करते हैं।

➢ डेटा साइंटिस्ट: डेटा साइंटिस्ट बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करते हैं और उससे उपयोगी जानकारी प्राप्त करते हैं।

➢ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ: साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को सुरक्षित रखते हैं।

➢ नेटवर्क इंजीनियर: नेटवर्क इंजीनियर कंप्यूटर नेटवर्क को डिजाइन, विकसित, और रखरखाव करते हैं।

➢ आईटी सपोर्टः आईटी सपोर्ट कर्मचारी कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

➢ कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरः कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर के विभिन्न भागों को डिजाइन, विकसित, और रखरखाव करते हैं।

➢ शिक्षकः शिक्षक विद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाते हैं।

शिक्षण व्यवस्था में कम्प्यूटर

शिक्षा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग ने शिक्षकों के पढ़ाने और छात्रों के सीखने के तरीके को बदल दिया है। कंप्यूटर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया पाठ और इंटरनेट के माध्यम से असीमित शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच को सक्षम करते हैं। पाठों को अधिक रोचक बनाने के अलावा, कंप्यूटर छात्रों को उच्च शिक्षा और आधुनिक करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से लैस करते हैं। कंप्यूटर पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों को पाठ, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो को मिलाकर अत्यधिक उत्तेजक मल्टीमीडिया अनुभवों में बदल देते हैं। यह मीडिया—समृद्ध दृष्टिकोण दृश्य, श्रवण और गतिज शिक्षार्थियों को अवधारणाओं को अधिक आसानी से समझने में मदद करता है।

कम्प्यूटर का व्यावसायिक क्षेत्र

कंप्यूटर का क्षेत्र उन लोगों के लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प है जो तकनीकी रूप से कुशल हैं और समस्याओं का समाधान करने में रुचि रखते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं, और कैरियर की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। कंप्यूटर का व्यावसायिक क्षेत्र बहुत बड़ा है:

➢ कंप्यूटर का इस्तेमाल कंपनी के संचालन के हर पहलू में किया जाता है, जैसे कि उत्पाद निर्माण, विपणन, लेखा, और प्रशासन।

➢ कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले लोग कई तरह के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं. इनमें कंप्यूटर इंजीनियर, व्याख्याता, आईटी टीम लीड, डेटा वैज्ञानिक, सिस्टम मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एमएल शोधकर्ता, एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम विश्लेषक, और सिस्टम इंजीनियर जैसे पद शामिल हैं।

➢ कंप्यूटर उद्योग में कई तरह के कारोबार होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माता और खुदरा विक्रेता, सॉफ्टवेयर डेवलपर, पीसी मरम्मत और सेवा कंपनियां, कंप्यूटर प्रशिक्षण फर्म, कंप्यूटर नेटवर्किंग व्यवसाय, कंप्यूटर सलाहकार, और बहुत कुछ।

➢ कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े और छोटे दोनों तरह के कारोबारों में किया जाता है. इसका इस्तेमाल लेखांकन, दस्तावेज और प्रस्तुतियाँ, इलेक्ट्रॉनिक संचार (दूसरे शब्दों में ईमेल), और इंटरनेट एक्सेस जैसे कामों के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष

कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शैक्षिक अनुप्रयोग लगातार बढ़ रहे हैं। डिजिटल मूल निवासी कम उम्र से ही प्रौद्योगिकी में डूबे हुए हैं, इसलिए छात्र एक कंप्यूटर—समृद्ध सीखने की यात्रा की उम्मीद करते हैं जो अत्यधिक उत्तेजक, इंटरैक्टिव शैक्षणिक वातावरण के लिए उनकी भूख को संतुष्ट करती है।मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ग्रेडबुक माता—पिता को असाइनमेंट स्कोर, उपस्थिति रिकॉर्ड और उभरती हुई ताकतध्कमजोरियों को बारीकी से ट्रैक करने की अनुमति देते हैं। यह अंतर्दृष्टि सहायक हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करती है और सुधार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है। निरंतर प्रगति की दृश्यता छात्रों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देती है और शिक्षण कर्मचारियों को निर्देश को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करती है। खुला संचार छात्र उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक सहायता नेटवर्क को मजबूत करता है।ईमेल, चौट और डिजिटल मैसेजिंग ऐप, प्रशिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के बीच संवाद को तेज बनाते हैं, जबकि घर पर बैग में भरकर भेजे जाने वाले प्रिंटेड मेमो इससे ज्यादा कारगर नहीं होते। सूचना के तेज आदान—प्रदान से समन्वय को बढ़ावा मिलता है। सहयोगात्मक दस्तावेज संपादन प्लेटफॉर्म ऐसी सुविधाओं के माध्यम से टीमवर्क को बढ़ावा देते हैं, जो कई उपयोगकर्ताओं को एकीकृत संदेश के माध्यम से चौट करते हुए वास्तविक समय में प्रोजेक्ट फाइलों को संयुक्त रूप से संपादित करने में सक्षम बनाती हैं।वीडियो, स्लाइडशो, एनिमेटेड पाठ

और अन्य एध्वी सामग्री दृश्य और श्रवण सीखने वालों को आकर्षित करती हैं। वास्तविक दुनिया के प्रदर्शनों को देखने से पाठ्यपुस्तकों में चर्चा किए गए अमूर्त सिद्धांतों को पुख्ता करने में मदद मिलती है। मीडिया शिक्षकों को छात्रों का ध्यान आकर्षित करने वाली रोचक क्लिपों का संदर्भ देने में सक्षम बनाता है।

संदर्भ ग्रंथ:

- डॉ. प्रमिला कुमार, म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी १९९४
- डॉ. बी.एल. गुप्ता, सांख्यिकी, साहित्य भवन पब्लिशर्स डिस्ट्रन्यूटर्स २००५
- डॉ. डी.एन. चतुर्वेदी, डॉ. पी.सी. सिन्हा, आर्थिक शोध के तल, लोक भारती प्रकाशन १९७९
- कटरिया रस्तागी, सांख्यिकी सिद्धान्त एवं व्यवहार पब्लिकेशन मेरठ १९८८—८९
- एस.के. मिश्रा बी.के. पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस २००७
- शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मेथडोलांजी, पंचशील प्रकाशन जयपुर २००४
- आर.ए. दुबे, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिशेर्य हाउस नई दिल्ली
- जैन, डॉ. एम.के., शोध विधियाँ, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, २००६
- डॉ. चतुर्भुज मामोरिया भारत की आर्थिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूट्स २००७—०८
- डॉ. ओ.पी. शर्मा, भारत में नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण, रामप्रसाद एण्ड संस २००२—०३

❑❑❑

15

कौशल विकास : आधुनिक भारत की आवश्यकता

डॉ. ललिता गोयल
सहायक प्राध्यापक
महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर

****

सारांश

कौशल विकास आत्मनिर्भर भारत का आधारस्तंभ है। नई पीढ़ी के युवाओं का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में कौशल विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कौशल विकास के द्वारा युवाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल कार्यबल तैयार किया जा सकता है। कौशल विकास सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके साथ—साथ समाज और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्योग उद्यमशीलता मंत्रालय देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और नवाचार के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं।

आज का युग तकनीक और कौशल आधारित जीवन का युग है। इस युग में सफलता पाने के लिए सिर्फ शैक्षणिक डिग्री ही काफी नहीं है बल्कि कौशल विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कौशल विकास से आशय है — अपने ज्ञान और क्षमताओं का निरंतर उन्ननयन। दुनिया भर में बदलती आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों के कारण,सभी को अपने कौशल का उन्ननयन करने और नए कौशल को सीखने की आवश्यकता है। कौशल विकास व्यक्तियों को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। कौशल विकास के माध्यम से व्यक्ति अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं,

जिससे वे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

कौशल विकास के प्रकार

१) तकनीकी कौशल : कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर

२) पारस्परिक कौशल : संचार नेतृत्व, टीम वर्क

३) संज्ञानात्मक कौशल : सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग

भारत सरकार ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शु : की है।

१) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) : यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और उद्यमिता कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। मेक इन इंडिया के तहत बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए इस योजना की शुरुआत २०१५ में की गई थी।

२) स्किल इंडिया मिशन : इस मिशन का उद्देश्य भारत को एक कुशल राष्ट्र बनाना है, यह मिशन देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करता है।

३) डिजिटल इंडिया परियोजना : यह भारत सरकार द्वारा शु : की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, यह परियोजना तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है : डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

४) स्वच्छ भारत अभियान : यह अभियान युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान के तहत, युवाओं को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा प्रबंधन एवं स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है।

५) मेक इन इंडिया : यह भारत सरकार द्वारा शु : की गई योजना है, जिसका उद्देश्य भारत विनिर्माण को बढ़ावा देना और इसे एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र बनाना। इसे एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र बनाना निवेश को आकर्षित करना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना रोजगार के अवसर पैदा करना एवं बेरोजगारी को कम करना भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इसे एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाना।

६) कौशल विकास केंद्र : कौशल विकास केंद्र भारत सरकार द्वारा शु : की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना रोजगार के अवसर प्रदान करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना एवं उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित युवाओं को उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण उद्यमिता प्रशिक्षण एवं रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है।

७) नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) : भारत सरकार द्वारा शु : की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता प्रशिक्षण देना है, जिसके द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

कौशल विकास के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं।

१. कौशल विकास व्यक्तियों को अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है।

२. कौशल विकास व्यक्तिगत विकास में मदद करता है और व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होता है।

३. कौशल विकास उद्योगों में प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करता है।

४. आर्थिक विकास : कौशल विकास आर्थिक विकास में योगदान करता है।

५. सामाजिक विकास : कौशल विकास सामाजिक विकास में योगदान करता है। इन लाभों को देखते हुए, कौशल विकास आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्तियों को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।

निष्कर्ष : कौशल विकास आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को अपने कौशल विकास

को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यस्थल प्रशिक्षण तथा सरकारी पहलों का समर्थन किया जाना चाहिए। कौशल उन्ननयन से न केवल लोगों को रोजगार,स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी भी कम होगी।

संदर्भ

१. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय www-msde-gov-in

२. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) www-pmkvyofficial-org

३. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) www-nsdcindia-org

४. डिजिटल इंडिया परियोजना www-digitalindia-gov-in

5- Journal of Skill Development for Economic Growth in India

6- Journal of Emerging Trends in Skill Development"

7- India Skill Report

8- Twelfth Five Year Plan (2012–2017)

❑❑❑

16

व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास का महत्व

डॉ. एस एच जाफरी

प्रो. ऐ. जे. सोलंकी
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
आनन्दनगर, खरगोन (म.प्र.)

****

भूमिका

व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास आधुनिक युग में व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। दोनों ही विषय व्यक्ति के आत्मविश्वास, सामाजिक संपर्क और कार्यक्षमता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शोध पत्र व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास के बीच गहरे संबंध, इनके महत्व, और उन तरीकों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा जिनसे व्यक्तियों और समाज का समग्र विकास संभव हो सके।

व्यक्तित्व विकास की परिभाषा और महत्व

व्यक्तित्व विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार, सोचने के तरीके, और अन्य व्यक्तिगत गुणों में सुधार करता है। यह विकास व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक, और भावनात्मक क्षेत्रों में बदलाव लाने में मदद करता है। व्यक्तित्व विकास से जुडघे निम्नलिखित विशेषताएँ इसे और महत्त्वपूर्ण बनाती हैं।

१. आत्मचेतना में वृद्धि : व्यक्ति अपने लक्ष्यों, कमजोरियों और क्षमताओं को समझता है।

२. संबंध सुधार : बेहतर संवाद और संवेदनशीलता से व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है।

३. आत्मसम्मान और आत्मविश्वास : बेहतर कौशल और व्यक्तित्व के माध्यम से व्यक्ति में सकारात्मक

दृष्टिकोण का विकास होता है।

कौशल विकास : परिभाषा और महत्व

कौशल विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति की विशेष योग्यताओं और क्षमताओं को विकसित करना। इसमें सॉफ्ट स्किल्स (जैसे संवाद, टीमवर्क) और हार्ड स्किल्स (जैसे तकनीकी ज्ञान, प्रोग्रामिंग) दोनों का समावेश होता है। कौशल विकास का महत्व इस प्रकार है।

१. अर्थव्यवस्था को बढघवा : कुशल कार्यबल से उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

२. रोजगार के अवसर : कौशल युक्त व्यक्ति के लिए नौकरी पाने के अवसर बढ जाते हैं।

३. समस्याओं का समाधान : विशिष्ट कौशल के माध्यम से जटिल समस्याओं का समाधान सरलता से किया जा सकता है।

व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास का योगदान

व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास का संबंध गहरा और परस्पर पूरक है। नीचे दिए गए बिंदु इस योगदान को समझाने में सहायक हैं।

१. आत्मविश्वास में वृद्धि : नई क्षमताओं को विकसित करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। यह आत्मविश्वास व्यक्तित्व विकास का एक प्रमुख घटक है।

२. सामाजिक संपर्क सुधार : संवाद कौशल और अन्य सॉफ्ट स्किल्स का विकास व्यक्ति को सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाता है।

३. समस्या समाधान क्षमता : टेक्निकल स्किल्स और एनालिटिकल थिंकिंग का विकास व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का समाधान ढूंढने में सहायक होता है।

४. नेतृत्व क्षमता : कौशल विकास के माध्यम से व्यक्ति में निर्णय लेने और टीम को प्रेरित करने की क्षमता विकसित होती है।

कौशल विकास के प्रकार

कौशल विकास को प्रमुखतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

१. सॉफ्ट स्किल्स

- संवाद कौशल
- समय प्रबंधन
- टीमवर्क
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)
- निर्णय लेने की क्षमता

२. हार्ड स्किल्स

- प्रोग्रामिंग भाषाएँ
- वित्तीय प्रबंधन
- विदेशी भाषाएँ
- डिजिटल मार्केटिंग
- औद्योगिक तकनीकी ज्ञान

कौशल विकास के लिए प्रभावी रणनीतियाँ

कौशल विकास के लिए विभिन्न उपाय और रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। इनमें से कुछ प्रभावी उपाय निम्नलिखित हैं

१. प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ

- व्यक्तिगत और समूह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रासंगिक उद्योग विशेषज्ञों द्वारा कार्यशालाओं का संचालन।

२. ऑनलाइन शिक्षा

- कोर्स और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीकों का अधिग्रहण।
- लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे Coursera, Udemy, और Skillshare का उपयोग।

३. साक्षात्कार और फीडबैक

- विशेषज्ञों से परामर्श लेना और उनके फीडबैक को लागू करना।
- अपनी प्रगति का नियमित मूल्यांकन।

४. समूह गतिविधियाँ

- टीमवर्क और नेतृत्व कौशल को बढावा देने के लिए समूह आधारित परियोजनाएँ।
- मॉक प्रोजेक्ट्स और पियर—लर्निंग सत्र।

भारतीय संदर्भ में व्यक्तित्व और कौशल विकास

भारत में कौशल विकास को बढावा देने के लिए कई योजनाएँ और पहल की गई हैं। इनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) प्रमुख है। यह योजना युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करती है और रोजगार के अवसर बढघती है।

सरकारी पहलकदमियाँ

१. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे १५ जुलाई २०१५ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग—विशिष्ट कौशल में प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। यह योजना कौशल भारत मिशन के तहत संचालित की जाती है और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाता है।

योजना का उद्देश्य

१. कौशल प्रशिक्षण

युवाओं को उनकी रुचि और उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना।

२. रोजगार सृजन

प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना।

३. स्वरोजगार को बढावा

युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।

४. अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रशिक्षण

युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित करना ताकि वे विदेशों में भी रोजगार प्राप्त कर सकें।

५. डिजिटल और तकनीकी कौशल

उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रशिक्षण।

मुख्य विशेषताएँ

१. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (STT)

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनकी अवधि ३ महीने से १ वर्ष तक होती है।

२. रोजगार और स्वरोजगार

प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्लेसमेंट सहायता प्रदान की जाती है।

३. रोजगार लिंकेज

नौकरी प्रदाताओं और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जोडने के लिए एक मंच।

४. डिजिटल सर्टिफिकेट और आधार आधारित रिकॉर्ड

सफल प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

५. विशेष समूहों पर ध्यान

महिलाओं, दिव्यांगों और पिछडे वर्गों के युवाओं को प्राथमिकता।

६. मोबाइल और ग्रामीण केंद्र

दूर—दराज के क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण की सुविधा।

PMKVY के तहत कार्यक्रम

१. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (STT)

पहली बार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए।

२. रोजगार सृजन के लिए कौशल विकास

पहले से प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए।

३. स्व—रोजगार प्रोत्साहन

स्वरोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण।

४. विशेष परियोजनाएँ (Special Projects)

संगठनों और सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी के माध्यम से।

मुख्य उपलब्धियाँ

१. २०१५ से अब तक १.५ करोड से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

२. देशभर में ७००् प्रशिक्षण साझेदार और १२,००० से अधिक केंद्र स्थापित।

३. ३७ से अधिक सेक्टरों में प्रशिक्षण।

४. महिलाओं की भागीदारी बढघने के लिए विशेष योजनाएँ।

चुनौतियाँ और समाधान

१. प्रशिक्षण और रोजगार के बीच तालमेल का अभाव उद्योगों के साथ साझेदारी बढघना।

२. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच मोबाइल प्रशिक्षण केंद्र और जागरूकता अभियान।

३. प्लेसमेंट की दर में कमी बेहतर प्लेसमेंट लिंकेज और उद्योग सहभागिता।

४. कोर्स की गुणवत्ता में सुधार राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) का उपयोग।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बडा

कदम है। यह योजना भारत को एक कुशल कार्यबल प्रदान करने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका क्रियान्वयन और विस्तार भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खोलने में सहायक होगा।

➢ युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण।

➢ १२ मिलियन से अधिक लाभार्थी।

२. स्किल इंडिया मिशन

स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। यह मिशन १५ जुलाई २०१५ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शु : किया गया था। इसका लक्ष्य २०२२ तक ४० करोड भारतीय युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण देना है, जिससे वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य

१. युवाओं के कौशल का विकास

उद्योगों की मांग के अनुसार व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करना।

२. रोजगार के अवसर बढाना

स्वरोजगार और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

३. वैश्विक प्रतिस्पर्धा

भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

४. सामाजिक और आर्थिक विकास

गरीब और पिछडे वर्गों को प्रशिक्षण देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना।

५. डिजिटल कौशल

युवाओं को डिजिटल और तकनीकी कौशल में निपुण बनाना।

स्किल इंडिया मिशन के मुख्य घटक

१. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

➢ अल्पकालिक कौशल विकास कार्यक्रम।

➢ उद्योग आधारित पाठ्यक्रम।

➢ प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाणपत्र और रोजगार के अवसर।

२. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

➢ कौशल प्रशिक्षण के लिए निजी और सार्वजनिक साझेदारी।

➢ प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।

३. राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)

➢ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानकीकरण।

➢ कौशल और शैक्षणिक योग्यता को जोडना।

४. इंडियन स्किल्स रिपोर्ट

➢ भारत में कौशल की स्थिति और आवश्यकताओं का विश्लेषण।

५. रोजगार पोर्टल

➢ रोजगार चाहने वालों और नौकरी देने वालों को जोडने के लिए एक मंच।

६. उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी

➢ उद्योगों के साथ साझेदारी करके मांग आधारित कौशल विकास।

➢ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग।

मुख्य उपलब्धियाँ

१. १.५ करोड से अधिक युवाओं को PMKVY के तहत प्रशिक्षित किया गया।

२. देश भर में ६०० से अधिक प्रशिक्षण भागीदार और ११,००० से अधिक कौशल केंद्र स्थापित।

३. डिजिटल और तकनीकी कौशल (AI, IoT, डेटा एनालिटिक्स) के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

४. ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।

चुनौतियाँ और समाधान

१. अवसरों की कमी

➢ उद्योगों की सहभागिता बढघकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

२. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच

➢ मोबाइल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम।

३. कौशल और मांग का अंतर

➢ उद्योगों की मांग को समझकर पाठ्यक्रमों में बदलाव।

४. मानसिकता में बदलाव

➢ कौशल विकास के प्रति जागरूकता अभियान चलाना।

स्किल इंडिया मिशन भारत के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी पहल है, जो उन्हें कौशलयुक्त बनाकर आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। यह मिशन न केवल युवाओं के व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक है। इसके तहत चल रही योजनाएँ और पहलकदमियाँ भारत को एक वैश्विक कौशल शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

➢ २०२२ तक ४० करोड से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।

३. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है, जो देश में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना २००८ में सार्वजनिक—निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत की गई थी। NSDC का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य कार्यक्षेत्र और गतिविधियाँ

१. सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCs)

NSDC ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए ३९ सेक्टर स्किल काउंसिल्स की स्थापना की है। ये काउंसिल्स उद्योगों की जरूरतों को समझकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करती हैं।

२. प्रशिक्षण साझेदारी

NSDC ने ६००़ प्रशिक्षण साझेदार बनाए हैं और ११,००० से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करता है।

३. कौशल प्रमाणन

प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जो रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त होता है।

४. डिजिटल कौशल

NSDC डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल (AI, IoT, डेटा एनालिटिक्स) पर विशेष जोर देता है।

५. वित्तीय सहायता

कौशल विकास केंद्रों को स्थापित करने के लिए निजी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष

व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास के बीच एक अटूट संबंध है। कौशल विकास व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को निखारने में सहायक होता है। इसके लिए निरंतर प्रयास, शिक्षण, प्रशिक्षण, और आत्म—मूल्यांकन आवश्यक हैं। किसी भी व्यक्ति या समाज की प्रगति के लिए उक्त पहलूओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कौशल विकास के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है और समाज में अपनी उपयोगिता को बढघ सकता है।

संदर्भ

1. Government of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. “Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY).” Retrieved from https://www.msde.gov.in

2. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam Books.

3. Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Free Press.

4. UNESCO. (2012). “Youth and Skills: Putting Education to Work.”

5. National Skill Development Corporation (NSDC). “Skill Development Initiatives in India.” Retrieved from https://www.nsdcindia.org

6. Drucker, P. F. (1999). Management Challenges for the 21st Century. HarperBusiness.

7. Ministry of Labour and Employment, India. “Skill Training for Employment Promotion amongst Youth (STEP-UP).”

❑❑❑

17

स्वरोजगार के अवसर और कौशल विकास में चुनौतियां

डॉ. मनीषा चौहान
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

****

सारांश

किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल है। मुख्य रूप से कौशल विकास योजना का उद्देश्य भारत के युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना है जो कई वर्षों से अविकसित हैं। स्किल इंडिया मिशन योजना के अंतर्गत चार अन्य योजनाओं (राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना) को सम्मिलित करके शुरू की गई है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि जो प्रतिदिन परिवार के लिए रोटी कमाता है उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए एवं मौद्रिक पुरस्कार दिया जाए। इस तरह उनके कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। स्किल इंडिया की पॉलिसी में बार—बार बदलाव लाया गया है। इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सका है। कई फ्रेंचाइजी सेंटर बंद हो गए हैं। युवाओं को कम नहीं मिल रहा है। यह एक बडी चुनौती है। करोडों युवाओं को हुनरमंद बनाने करोडों रुपए की जरूरत होगी। एक अच्छा बजट भी चाहिए। स्किल इंडिया के अंतर्गत सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पहल की है। महिला बाजार के अनुकूल कौशल विकसित करने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल इंडिया प्रतिबद्ध है।

स्वरोजगार का मतलब है किसी खास नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करना जो उन्हें वेतन देता है। यह कई तरह के व्यवसाययों में आम है, लेकिन एक आम बात यह है कि स्वरोजगार वाले व्यक्ति किसी खास क्षेत्र में अत्यधिक कुशल होते हैं।

स्वरोजगार के कुछ सामान्य प्रकारों में स्वतंत्र, ठेकेदार एकल स्वामित्व और साझेदारी शामिल है।

स्वरोजगार के लाभों में उच्च स्तर की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और व्यावसायिक निर्णय पर नियंत्रण के साथ काम करने में सक्षम होना शामिल है। फिर भी नुकसानों में उच्च स्तर का रोजगार अस्थिर सभी व्यवसायिक घाटे की जिम्मेदारी लेना शामिल है।

प्रस्तावना

आज युवा जनसंख्या को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने के पैरों पर स्वयं खडे होने के लिए, उन्नत प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं कौशल विकास महत्वपूर्ण है। तथा उन्नति की गति का तीव्र बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है। सभी व्यक्तियों को अच्छे रोजगार मिले व विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो व इसके लिए उन्हें उन्नत कौशल, ज्ञान व योग्यताओं के माध्यम से सक्षम बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में बढ रही बेरोजगारी की की दरों को कम करने हेतु केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने व कौशल के विकास को बढघवा देने के उद्देश्य से समय—समय पर अनेक योजनाओं का संचालन करती रहती है। ऐसी एक योजना प्रयास के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश में दसवीं बारहवीं पास बेरोजगार नागरिक सरकार की तरह से निशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे तथा स्वयं के रोजगार की स्थापना भी कर सकेंगे।

स्वरोजगार क्या है ?

जैसा कि सर्वविदित है, कि सरकार नागरिकों को आगे बढघने के लिए कई प्रकार के प्रयास करती है। सबसे ज्यादा प्रयास युवाओं को आगे बढघने के लिए कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक योजना स्वरोजगार योजना है।

जिसमें जिसमें युवाओं को उनके खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से देश के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। इससे बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पता है। यह योजना राज्य सरकारों के द्वारा भी लागू की गई है। अक्सर यह देखा जाता है। की अधिक पढे– लिखे नहीं होने के वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता लेकिन कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए के बाद भी हमारे देश का युवा बेरोजगार है। इसके लिए सरकार बेरोजगार युवाओं को उनके खुद के रोजगार की शुरुआत करने के लिए युवा स्वरोजगार योजना के तहत कम ब्याज पर लोन प्राप्त की सुविधा प्रदान कर रही है। इससे रोजगार की तलाश कर रहे युवा बिना किसी आर्थिक समस्या के अपने स्वयं के रोजगार की शुरुआत कर सकेंगे और अपने उद्योग के लिए अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर खोल सकेंगे।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा बेरोजगारों के लिए संचालित दो महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजनाएं

स्वरोजगार योजनाएं

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, इनमें से दो अत्यधिक महत्वपूर्ण योजनाओं की निम्न अनुसार जानकारी प्रदान की जा रही है

रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति ध्जनजाति स्वरोजगार योजना

उद्देश्य:— अनुसूचित जातिध्जनजातियों के उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करना है।

लक्ष्य :— प्रतिवर्ष ५००० तथा आगामी वर्ष ५ वर्षो में २५००० अनुसूचित जातिध्जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित करना।

पात्रता:—

१. मूल निवासी — मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी

२. शैक्षणिक योग्यता — न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

३. आयु सीमा — १८ से ५० वर्ष की आयु

४. अनुसूचित जातिध जनजाति का प्रमाण पत्र धारी — (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी)

५. आयु सीमा — कोई अधिकतम वार्षिक आय सीमा निर्धारित नहीं

प्राथमिकता:—

१. राज्य शासन के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करता

२. बहुउद्देशीय इंजीनियर योजना अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति।

३. महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व।

प्रक्रिया :—

१. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में उपलब्ध निशुल्क आवेदन प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

२. आवेदकों को चयन साक्षात्कार हेतु सूचना भेजी जावेगी।

३. साक्षात्कार पूर्व मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जावेगा

४. महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गठित बैठक एवं रोजगार योजनाओं से संबंधित अधिकारियों की चयन समिति द्वारा प्रथम आओ प्रथम पांव के आधार पर चयन किया जावेगा प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित बैठक एवं रोजगार योजना से संबंधित अधिकारियों की चयन विधि द्वारा प्रथम प्रथम आओ प्रथम भाव प्रथम भाव के आधार पर चयन किया जाएगा।

५. चयनित उद्यमियों को आवश्यकता अनुसार सगन उपयोगी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मनोवैज्ञानिक, तकनीकी, विपणन कौशल एवं फील्ड वर्क को शामिल किया जाएगा।

६. प्रशिक्षण अवधि में योजना चयन कर प्रकरण बैंक से स्वीकृत कराए जावेंगे।

७. स्वीकृत ऋण के विरुद्ध योजना व्य य की अधिकतम ३३% राशि आवश्यकता अनुसार मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

८. उद्यमी चयन से लेकर उधम व्यवसाय स्थापना तक की कार्यवाही निश्चित समय सीमा में हो जावेगी।

९. उद्योग एवं सेवा के प्रकरणों में विभाग की

प्रचलित ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत ५% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

दीनदयाल रोजगार योजना

उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाइयों/गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंकों के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य है।

पात्रता :—

१. मूल निवासी — मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो

२. आयु आयु — आवेदक दिनांक को आयु १८ वर्ष से ४० वर्ष के मध्य हो

३. शैक्षणिक योग्यता —दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा आईटीआई उत्तीर्ण हो

४. आय — आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपए १.५० लाख से अधिक नहीं हो

५. रोजगार — शिक्षित बेरोजगार जिसका कार्यालय रोजगार कार्यालय में आवेदन दिनांक में पंजीयन को जीवित पंजीयन हो

सहायता

हितग्राही को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के अनुसार निम्न अनुसार मार्जिन मनी सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

उद्योग क्षेत्र:—

स्वीकृत परियोजना लागत का १०% अधिकतम रुपए ४०,०००/—स्नातक के लिए रुपए ५०,०००/—

सेवा क्षेत्र:—

स्वीकृत परियोजना लागत का ७.५% अधिकतम रुपए १५०००/— स्नातक के लिए रुपए २५,०००/—

व्यवसाय क्षेत्र:—

स्वीकृत परियोजना लागत का ५% अधिकतम रुपए ७,५००/—

पक्रिया:—

कार्यालय द्वारा निशुल्क प्रदत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, दो प्रतियो में आवश्यक सहपत्र सहित हितग्राही से प्राप्त होने पर उसकी पार्वती दी जावेगी तथा वरीयता क्रम में टास्क फोर्स समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अनुशंसा उपरांत राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेजे जाएंगे।ऋण स्वीकृत होने पर इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त आवश्यक प्रशिक्षण उपरांत संबंधित बैंक शाखा से ऋण वितरण किया जावेगा। त्रुटि वाले प्रकरणों में त्रुटि निराकरण कर पुनः प्रकरण बैंक भेजे जाते हैं ।

हितग्राहियों हेतु आवश्यक बाते

१. आवेदन पूर्व कृपया अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्टि कर ले।

२. आवेदन पत्र निशुल्क उपलब्ध है तथा यह सरल भाषा में रखा गया है। प्रत्येक बिंदु को स्वयं पढकर स्वयं की हस्तलिपि में दो प्रतियो में तैयार करें। जहां कठिनाई हो आपके सहयोग हेतु नियुक्त कार्यालय अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर ले।

३. आवेदन प्राप्त करते समय रोजगार के कार्यालय का पंजीयन कार्ड साथ में अवश्य लावे।

४. योजना हेतु सरल भाषा में प्रारूप आवेदन के साथ संलग्न हैं। इसी प्रारूप में योजना चयन एवं योजना प्रपत्र भरने हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध है। इस हेतु आवेदन वितरण दिनों में पी.एम. आर.आई.क्लिनिक संचालित की जाती है।

५. घोषणा पत्र पर स्वयं की फोटो लगाकर स्वयं प्रमाणित करें तथा दो दो फोटो आवेदन पत्र पर लगाकर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रमाणित करें।

६. संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियो पर स्वयं प्रमाणित करें।

७. वही आवेदन भरकर प्रस्तुत करें जो कि आपको कार्यालय द्वारा दिया गया है। फोटोकॉपी आदि मान्य नहीं होगी।

८. आवेदन पत्र निर्धारित काउंटरों पर ही जमा करें एवं पावती प्राप्त करें।

९. किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु आप सीधे महाप्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।

कौशल विकास में चुनौतियां

जनगणना २०११ के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या १२१ करोड है। जिसमें ६ ७.२ करोड व्यक्ति १५ से ५९ वर्ष की आयु के हैं। जिन्हें सामान्यतया कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इनमें से लगभग २५ करोड व्यक्ति १५ से २४ वर्ष की आयु के हैं। जो वर्ष २०११ की कुल जनसंख्या का २१% है। यदि इस युवा शक्ति की ऊर्जा का सदुपयोग होता तो यह भारत की विशिष्ट मानव संपदा के रूप में देश को आर्थिक विकास में मददगार होगी। साथ ही अन्य देशों में कुशल श्रम की कमी बढघ्ती आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति के कारण विदेश में भी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढघ्ेंगे। योजना आयोग के १२वीं पंचवर्षीय योजना के म सो दे के अनुसार अगले २० वर्षों में २० वर्षों में भारत में श्रम शक्ति में ३२% की वृद्धि होने की संभावना है। जबकि अन्य औद्योगिक देशों में इसमें चार प्रतिशत की कमी एवं चीन में ५% तक की कमी है हो सकती है। प्रधानमंत्री के अनुसार यदि इस युवा शक्ति को वंचित कौशलों द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया गया तो यही युवा शक्ति देश के लिए चुनौती पूर्ण हो सकती है। और बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप ले सकती है। इसलिए भारत के कौशल विकास कार्यक्रम के समक्ष निम्न चुनौतियां भी है, जिनका समाधान करके ही करके ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है।

बडा लक्ष्य

भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में वर्ष २०२२ तक लगभग ५० करोड लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। अकादमिक जगत, उद्योग, सरकार, निजी, संस्थाएं, समाज, नीति निर्धारक, रोजगार प्रदाताओं, प्रशिक्षकों, को युवाओं, अभिभावक को सभी को मिलकर कार्य करना होगा। भारत में अगले ८ से १० वर्ष तक संस्था नो की प्रशिक्षण क्षमता में वर्ष दर वर्ष चार से पांच करोड तक की वृद्धि करनी होगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी साथ में जोडा गया है। सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में ४९% हिस्सा सरकारी एवं ५१% निजी संस्थाओं के पास है। इन निजी संस्थाओं में सीआईआई, फिक्की, एसोचौम आदि शामिल है।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में ३१ लाख लोगों को प्रतिवर्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुलभ है, जिसके लिए भारत के १७ मंत्रालय व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद देश में हर साल कार्यरत जनसंख्या में नए जुडघ्ने वाले युवाओं के लगभग २०% व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सका है। शेष ८०% तक तो पहुंच ही नहीं है देश में १२०० से अधिक पॉलिटेक्निक संस्थान, १० से १२ हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अन्य निजी एवं सरकारी केंद्र, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर से जुडे संस्थान आदि इतना सब होने के बाद भी देश में कुशल प्रशिक्षित श्रम की कमी है। सरकारी, संस्थान प्रबंध को, प्रशिक्ष को विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्ति के लक्ष्य के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को चलना है,न कि सिर्फ डिप्लोमा, डिग्री पर सर्टिफिकेट लेने या देने के उद्देश्य से।

कुशल प्रशिक्षकों की कमी:—

इतने बडे लक्ष्य को संख्यात्मक दृष्टि से प्राप्त करने के दौरान सीखे गए कौशलों की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अर्थात इस लक्ष्य को मात्रात्मक के साथ गुणात्मक रूप से भी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए कुशल प्रशिक्षकों की बडघ्े स्तर पर आवश्यकता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार २०२२ तक देश में लगभग ७ लाख प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में कौशल विकास तंत्र को बदलती परिस्थितियों के अनुक्रियाशील होना पडघ्ेगा जिससे आवश्यकता पूर्ति में तालमेल बना रहे।

आधारभूत संरचना :—

भारत में तकनीकी प्रशिक्षण के संसाधन भी पर्याप्त नहीं है। भारत की तकनीकी संस्थाओं में वर्तमान में ३१ लाख लोगों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने की क्षमता है, जबकि प्रतिवर्ष एक करोड २८ लाख युवा रोजगार की तलाश में वर्ष वर्कफोर्स में जुड ते जा रहे हैं राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए आई आई टी पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना की जानी है।

असंगठित क्षेत्र : आकार एवं समस्याएं:—

असंगठित क्षेत्र के उध मो हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग के अनुसार संगठित या अनौपचारिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बडा भाग है जिसकी कुल कार्यरत जनसंख्या में ९०% व्यक्ति एवं कुल राष्ट्रीय उत्पाद में ५०% उत्पादन की भागीदारी है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आंशिक या छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित होता है। उसके पास स्थाई आजीविका का अभाव होता है। अपर्याप्त आया आय, बंधुआ, मजदूरी करना, ऋणग्रस्त ता शोषण का शिकार होना खराब कार्य की परिस्थितियों अनिश्चित ता कार्य स्थल आदि अन्य समस्याएं हैं।

शिक्षा संबंधी चुनौतियां:—

भारत की जनसंख्या में युवा शक्ति के रूप में प्राप्त जनांकिकी लाभ ही एकमात्र कारण नहीं है। जिससे कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता हुई। उच्च शिक्षा में गैर— तकनीकी क्षेत्र यथा— कला, वाणिज्य एवं विज्ञान की और अधिक ध्यान दिया गया है। भारत के ६ शहरों में एमबीए डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों पर किए गए एक अध्ययन में केवल २३% ही रोजगार योग्य पाए गए । शेष सभी आयोग्य (एम. टी. २०११) इसी प्रकार इंजीनियरिंग में स्नातकों पर किए गए एक अल्प अध्ययन में उसे ४१: व्यक्ति ही रोजगार योग्य पाए गए (ए. एम. २०११) । वैश्विक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान प्रारूप को आज के बदलते परिदृश्य में उचित नहीं माना गया है। इसके लिए वांछित कौशलों, जैसे प्रयोग गीत कौशल, सूचना एवं संचार तकनीकी का समावेश, उद्यमिता कौशल विकास आदि को महत्वपूर्ण बताया।

अभिवृत्ति कारक

समाज में कुशल श्रम से संबंधित कार्यों, जैसे— बढई गिरी इलेक्ट्रीशियन, वहान मिस्त्री, प्लंबर आदि को कम शैक्षिक उपलब्धि वाले व्यक्तियों का कार्य माना जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को या तो कला विज्ञान, वाणिज्य जैसे परंपरागत क्षेत्र में अध्ययन कराते हैं। या विधि, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, आदि क्षेत्रों में भेजते हैं। समाज में ब्लू कॉलर नौकरियों की तुलना में व्हाइट कॉलर नौकरियों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस अभिवृत्ति में बदलाव कर कौशल विकास कार्यक्रमों में समाज की भागीदारी बढानी आवश्यक है।

कौशल विकास कार्यक्रमों की दिशा:—

कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध प्रशिक्षण विकल्पों से संबंधित समस्त जानकारी का व्यापक प्रचार— प्रसार हो। विद्यालयो एवं महाविद्यालयो, सरकारी स्तर पर चल रहे रोजगार केदो द्वारा इस और कार्य किया जा सकता है यह समय—समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति उपलब्धता पंजीयन प्रक्रिया क्षमता आदि संबंधित जानकारी उपलब्ध कारण रोजगार केदो द्वारा इस और कार्य किया जा सकता है। यह समय—समय पर कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रकृति, उपलब्धता, पंजीयन प्रक्रिया, क्षमता आदि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए। रोजगार केंद्र एक निर्देशन और परामर्श केंद्र के रूप में भी विद्यार्थियों को अपनी अभिक्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम या कोर्स का चुनाव करने में उपयोगी हो सकते हैं। प्लेसमेंट की प्रक्रिया से प्रशिक्षक को संस्थाओं को भी जोडा जा सकता है गुणवत्तापूर्ण कौशल द्वारा रोजगार प्राप्ति बढाने वाले प्रशिक्षक को संस्थाओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए प्रशिक्षण को से कौशल विकास कार्यक्रमों संस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया जा सकता है कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रदान किए जाने वाले कौशलों का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं के साथ—साथ भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि युवा किसी विशेष कौशल को सीख कर निकले, उसके बाद बदलती परिस्थितियों, तकनीक, नवाचार, आदि के कारण सिखाए गए कौशल की उपयोगिता खत्म हो जाए। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिजाइन पर नीति— निर्धारकों का गहन चिंतन आवश्यक है।

निष्कर्ष —

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कौशल विकास कार्यक्रम में संस्थानिक संरचना सुविधाओं का निर्माण किया गया है। किंतु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जहां एक और कौशल प्रशिक्षण को

दसवीं कक्षा से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना है। वहीं दूसरी ओर औपचारिक शिक्षा से पूरे कौशल सृजन के लिए समन्वित कार्य एवं नव क्या करती है प्रवर्तित सोच की आवश्यकता है। हालांकि कौशल विकास के लिए समन्वित कार्य योजना के एक मुख्य घटक राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम को नियोक्ताओं/उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अनवरत आधार पर स्थिति के अनुरूप पुन: निर्धारित करना होगा और स्वरोजगार के उपलब्ध अवसरों के अनुसार डालना होगा। कौशल सूची व कौशल योजनाओं पर सूचना समयबद आधार पर उपलब्ध कराने के लिए एक संस्थाननिक व्यवस्था स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए उन क्षेत्रों पर विशेष बल देने सहित एक क्षेत्रीय अधिगत की आवश्यकता है, जहां रोजगार की संभावना है। विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा तथा आई.टी.आई. आई. टी.सी. के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण का व्यापक विस्तार एवं सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः—

1- https:// hi-Wikipedia,org-

2- scheme document of pradhan mantri kaushal Vikas yojana,pmkvyofficial,org

3- Skillindia-gov-in

४. स्वरोजगार मार्गदर्शिका उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश (सेडमैप) खरगोन।

५. संचित सिंह,२०२४ कौशल विकास दिल्लीरूअग्नि प्रकाशन।

६. सिंह.एस. २०१६ कौशल विकास दिल्ली: अग्नि प्रकाशन।

७. कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (राष्ट्रीय शहरी) आजीविका मिशन भारत सरकार।

❑❑❑

18

कौशल विकास एवं महिला उद्यमी

डॉ. मोनिका चौहान
सहायक— प्राध्यापक (गृह विज्ञान)
शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन (मध्य प्रदेश)

****

शोध सारांश

कौशल विकास महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है, बल्कि उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और तकनीकी दक्षता भी प्रदान करता है। यह शोध कौशल विकास और महिला उद्यमिता के बीच संबंध का विश्लेषण करता है और यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकारी नीतियाँ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

शब्ब्दकुंजी— कोशल विकास, महिला, उद्यमिता, चुनौतिया

परिचय

कौशल विकास और महिला उद्यमिता आधुनिक समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में, महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आवश्यक है। ताकि वे स्वतंत्र, सशक्त और समान अवसरों के साथ जीवन जी सके। कौशल विकास उन महिलाओं के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है, और जो स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य महिलाओं के लिए कौशल विकास के महत्व, महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ाना देने वाले पहलू, उनके उद्यमी बनने में आने वाली चुनौतियों और इनसे निपटने के उपाय का अध्ययन करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

१. महिला उद्यमिता का महत्व समझना : समाज और अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के योगदान का आकलन।

२. कौशल विकास का प्रभाव : कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की क्षमता को बढ़ाना।

३. चुनौतियों का विश्लेषण : महिला उद्यमिता के क्षेत्र में आने वाली प्रमुख बधाओ का अध्ययन।

४. समाधान और सिफारिशे : महिलाओं को उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए सुझाव देना।

महिलाओं के लिए कौशल विकास का महत्व

१. आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता

कौशल विकास महिलाओं को स्वरोजगार और नौकरियों के अवसर प्रदान करता है। इससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं।

१. महिला उद्यमिता को बढ़ावा

व्यावसायिक प्रशिक्षण से महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शु: करने और उसे सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम होती हैं।

इससे वे लघु एवं मध्यम उद्योगों (SMEs) में अपनी पहचान बना सकती हैं।

२. सामाजिक सशक्तिकरण और निर्णय लेने की क्षमता

जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं, तो वे परिवार और समाज में अधिक प्रभावशाली निर्णय ले सकती हैं। इससे महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ती है।

३. डिजिटल और तकनीकी साक्षरता

डिजिटल स्किल्स (ई—कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग) महिलाओं को घर से काम करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाते हैं। तकनीकी शिक्षा से महिलाएं उच्च—तकनीकी नौकरियों में प्रवेश कर सकती हैं।

४. रोजगार सृजन और महिला श्रम शक्ति में वृद्धि

कौशल विकास से महिलाएं न केवल स्वयं रोजगार पा सकती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती हैं।

इससे महिला श्रम शक्ति भागीदारी (Female Labor Force Participation) में वृद्धि होती है।

२. महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्र

१. तकनीकी और डिजिटल कौशल — कंप्यूटर, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग ।

२. व्यावसायिक और प्रबंधन कौशल — वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व कौशल।

३. स्वास्थ्य और देखभाल सेवाएं — नर्सिंग, पैरामेडिकल।

४. हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योग — बुनाई, सिलाई, खादी, जूट उद्योग।

५. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण — जैविक खेती, डेयरी उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण।

३. महिला कौशल विकास के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ

१. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) — महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना।

२. मुद्रा योजना — महिला उद्यमियों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना।

३. महिला ई—हाट — महिलाओं को ऑनलाइन व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना।

४. स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया — महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना।

महिलाओ के कौशल विकास में आने वाले चुनौतियां

१.शिक्षा और कौशल की कमी: तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक प्रबंधन का अभाव होने के कारण कई महिलाओं को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिलते।

२. आर्थिक समस्या: पूंजी की कमी और वित्तीय संस्थानों से समर्थन की कमी होने से महिलाओं के पास प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता नहीं होती।

३. सामाजिक प्रतिबंध: पारंपरिक सोच और पितृसत्तात्मक समाज होने से कुछ समुदायों में महिलाओं के लिए करियर और शिक्षा को लेकर रूढ़िवादी सोच बनी हुई है।

४. बाजार में प्रतिस्पर्धा : बड़े उद्योगों और पुरुष उद्यमियों से प्रतिस्पर्धा।

कौशल विकास और महिला उद्यमिता हेतु समाधान और सुझाव

महिला उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के अवसर मिलते हैं। इसके माध्यम से महिलाओं को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने और समाज में योगदान देने का मौका मिलता है। निम्नलिखित समाधान और सुझाव महिला उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी हो सकते हैं

१. शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार

समाधान

१. महिलाओं के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि की जाए।

२. विशेष कौशल विकास कार्यक्रम (जैसे सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल कौशल) महिलाओं के लिए पेश किए जाएं, ताकि वे स्वरोजगार के अवसरों को अधिकतम कर सकें।

सुझाव

१. सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को प्रासंगिक कौशल (जैसे कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व आदि) में प्रशिक्षित किया जाए।

२. ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जाए।

३. ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे Coursera, Udemy, आदि) के माध्यम से महिलाओं को ऑनलाइन कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

२. वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्धता

समाधान

१. महिला उद्यमियों के लिए ऋण की सुविधा को सरल और सुलभ बनाया जाए।

२. मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, और स्टैंडअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों का सक्रिय प्रचार किया जाए।

सुझाव

१. महिलाओं को छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और निवेश के अवसर प्रदान किए जाएं।

२. वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाए ताकि महिलाएं अपने व्यवसाय का प्रबंधन अच्छे से कर सकें।

३. महिला उद्यमियों के लिए विशेष माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की स्थापना की जाए जो छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान कर सकें।

३. कानूनी अधिकारों और सुरक्षा की सुरक्षा

समाधान

१. महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए, जैसे संपत्ति अधिकार, विवाह, तलाक, और घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा।

२. महिलाओं के लिए कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

सुझाव

१. महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

२. महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए अधिक सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

३. महिला हेल्पलाइन और सुरक्षित स्थल जैसे पहल दिए जाएं जहां महिलाएं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या हिंसा के खिलाफ आवाज उठा सकें।

४. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले वातावरण का निर्माण

समाधान

१. महिला उद्यमिता के लिए नेटवर्किंग, मेंटरशिप और समर्थन समूहों का निर्माण किया जाए।

२. महिलाओं के लिए कार्यशालाओं, फोरम्स और समिट्स का आयोजन किया जाए जहां वे अपने विचार साझा कर सकें और एक–दूसरे से सीख सकें।

सुझाव

१. महिला उद्यमियों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुः किए जाएं, जिसमें अनुभवी उद्यमी महिलाओं द्वारा नई उद्यमी महिलाओं को मार्गदर्शन दिया जाए।

२. नेटवर्किंग इवेंट्स आयोजित किए जाएं, ताकि महिलाएं अपने व्यवसाय के लिए संपर्क बना सकें और सहयोग प्राप्त कर सकें।

५. महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव

समाधान

१. महिलाओं के प्रति समानता की मानसिकता विकसित की जाए और लिंग भेदभाव को समाप्त किया जाए।

२. महिलाओं की सफलता को समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो सकें।

सुझाव

१. जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि समाज को यह समझ में आए कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सक्षम हैं।

२. मीडिया का उपयोग करके महिलाओं की सफलता की कहानियां साझा की जाएं और उन्हें प्रेरणा देने वाला बना जाए।

६. नीति निर्माण और सरकारी समर्थन

समाधान

१. महिलाओं के लिए विशेष नीतियाँ बनाई जाएं जो उनकी व्यवसायिक यात्रा को सशक्त बनाए।

२. सरकारी योजनाओं और संसाधनों का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि महिलाएं इनका अधिकतम उपयोग कर सकें।

सुझाव

१. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नवीन और व्यापक नीतियाँ बनानी चाहिए, जिसमें वित्तीय सहायता, कर राहत और प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हों।

२. महिलाओं के लिए उद्यमिता कार्यक्रमों और समर्थन योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू किया जाए, जिससे उन्हें तुरंत लाभ हो सके।

७. कार्यस्थल पर समान अवसर

समाधान

१. कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान वेतन और समान अवसर प्रदान किए जाएं।

२. लचीले कार्य घंटे और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि महिलाएं काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना सकें।

सुझाव

१. कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समान वेतन और समान अवसर की नीति लागू की जाए।

२. लचीले काम के घंटे और कार्यस्थल पर परिवारिक सहायता के उपाय महिलाओं के लिए पेश किए जाएं।

निष्कर्ष

महिला उद्यमिता और कौशल विकास एक दूसरे के पूरक है। कौशल विकास और महिला उद्यमिता का समन्वय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ

१. डॉ. अंशु सिंह — महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विकास, २०२१

२. डॉ. पी.एन. सिंह — भारतीय संदर्भ में कौशल विकास, २०१९

३. सरकारी रिपोर्ट: "National Policy for Skill Development & Entrepreneurship", भारत सरकार, २०१५

४. संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट (UNDP, २०२०)% "Women's Entrepreneurship and Economic Empowerment" 2020

५. डॉ. किरण देसाई — महिला उद्यमिता: संभावनाएँ और चुनौतियाँ, २०२०

६. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, भारत सरकार — National Policy for Skill Development - Entrepreneurship, 2015

७. नितिन शर्मा — डिजिटल युग में महिला उद्यमिता, २०२२

८.डॉ. सुमित्रा मिश्रा — ग्रामीण भारत में कौशल विकास और महिला रोजगार, २०१८

९. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) रिपोर्ट — Women Entrepreneurs in MSME Sector, 2021

19

भारतीय पर्यटन उद्योग की विकास यात्रा

डॉ. रीना वसुनिया
सहायक प्राध्यापक (इतिहास)
शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,
खंडवा (म. प्र.)

****

सारांश —

भारतीय पर्यटन उद्योग की विकास यात्रा ने विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ प्रगति की है। प्राचीन काल में धार्मिक तीर्थयात्राओं से लेकर, ब्रिटिश काल में व्यापारिक और सामरिक यात्रा के माध्यम से इसका विस्तार हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने पर्यटन को एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाएं शु: की। १९९० के दशक में आर्थिक उदारीकरण और डिजिटल क्रांति के बाद पर्यटन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पहचाना गया। २१वीं सदी में, भारत ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया। वर्तमान में, भारतीय पर्यटन उद्योग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और यह रोजगार, विकास और आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है।

शब्द कुंजी — पर्यटन, उद्योग, विकास, पर्यटन नीति, यात्रा

परिचय :

भारतीय पर्यटन उद्योग ने पिछले दशकों में अद्वितीय विकास यात्रा तय की है और यह भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थल, और साहसिक पर्यटन के कारण दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। पर्यटन न केवल भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विकास यात्रा का इतिहास

भारतीय पर्यटन उद्योग की विकास यात्रा काफी लंबी और विविधतापूर्ण रही है। इस उद्योग का विकास विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। यहां भारतीय पर्यटन उद्योग के प्रमुख विकास की यात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है

१. प्राचीन काल : भारतीय पर्यटन का आरंभ प्राचीन काल में धार्मिक तीर्थयात्राओं से हुआ था। हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म के अनुयायी विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाते थे। इसके अलावा, मौर्य और गुप्त काल में व्यापारिक यात्रा भी होती थी, जो एक प्रकार से पर्यटन का रूप ले चुकी थी।

२. मध्यकाल : इस काल में भारतीय शासकों द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक किलों, महलों, मस्जिदों, और अन्य संरचनाओं ने पर्यटन को प्रोत्साहित किया। पर्यटक स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे

३. प्रारंभिक स्थिति और ब्रिटिश काल (पूर्व स्वतंत्रता): भारतीय पर्यटन उद्योग की नींव ब्रिटिश काल में पड़ी, जब अंग्रेजों ने भारत में ग्रीष्मकालीन रिसॉर्ट्स का निर्माण किया और कई स्थानों को पर्यटन के लिए विकसित किया। उस समय पर्यटन मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों और विदेशी व्यापारियों के लिए था, जो भारत में आए और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस किया। भारत में धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन की जड़ें प्राचीन काल से ही मजबूत थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान, पर्यटन के रूप में यूरोपीय पर्यटकों का आगमन बढ़ा। यह समय ब्रिटिश राज के लिए व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। साथ ही, ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के लिए भारत में हिल स्टेशनों का विकास हुआ, जैसे शिमला, मसूरी, और नैनीताल।

४.स्वतंत्रता के बाद का समय (१९४७—१९८०): स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने पर्यटन के

महत्व को समझते हुए पर्यटन विभाग की स्थापना की। इस समय तक पर्यटन उद्योग धीमी गति से बढ़ रहा था, क्योंकि बुनियादी ढांचे की कमी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण की कमी थी। स्वतंत्रता के बाद (१९४७ के बाद): स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनानी शुः की। १९५० के दशक में भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) की स्थापना की गई।

५. १९९० के दशक में उदारीकरण: १९९१ में भारतीय सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारतीय पर्यटन उद्योग में तेज़ी से वृद्धि हुई। विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई, और पर्यटन को एक प्रमुख उद्योग के रूप में पहचान मिली। इसके बाद सरकार ने ष्इंडिया टूरिज्मष जैसी प्रचार योजनाओं के तहत पर्यटन को बढ़ावा दिया।

६. २१वीं सदी: २००० के दशक में डिजिटल युग और सोशल मीडिया के विकास ने पर्यटन उद्योग को और गति दी। अब, पर्यटक इंटरनेट के माध्यम से आसानी से यात्रा योजनाएं बना सकते थे और भारत के विभिन्न पर्यटन स्थल खोज सकते थे। सरकार ने 'अतुल्य भारत', 'इंडिया हैप्पेंस' जैसे प्रचार अभियानों के माध्यम से देश में पर्यटन को बढ़वा दिया।

७. वर्तमान समय: आज भारत एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, समुद्र तट, पहाड़ी क्षेत्र और वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय पर्यटन उद्योग अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है।

इस प्रकार, भारतीय पर्यटन उद्योग ने विभिन्न युगों में धीरे—धीरे अपना रूप लिया और आज यह एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र बन चुका है, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

८. आधुनिक युग में पर्यटन का विकास (१९९० के बाद): १९९१ में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारतीय पर्यटन उद्योग ने एक नई दिशा पकड़ी। विदेशी निवेश, बेहतर एयरलाइंस सेवाएं, और समृद्ध हो रहे होटल उद्योग ने पर्यटन को नई गति दी। "Incredible India" और "Atithi Devo Bhava" जैसे अभियान भारतीय पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने में सफल रहे।

भारतीय पर्यटन उद्योग का प्रमुख क्षेत्र:

१. धार्मिक पर्यटन: भारत में तीर्थ स्थलों की संख्या बहुत बड़ी है, जिनमें वाराणसी, तिरुपति, मथुरा, और अमृतसर जैसे स्थान शामिल हैं। इन स्थलों पर लाखों की संख्या में पर्यटक साल भर आते हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है।

२. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन: भारत की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थल जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, और कांची के मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन स्थलों की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व ने भारत को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बना दिया है।

३. प्राकृतिक पर्यटन: भारत में समुद्र तट, पर्वत, झीलें, और वन्य जीवन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र हैं। गोवा, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं और साहसिक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हैं।

४. साहसिक पर्यटन: ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे साहसिक खेलों के लिए भारत में उपयुक्त स्थल हैं। हिमालय क्षेत्र, उत्तर—पूर्वी राज्य और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र इन गतिविधियों के लिए आदर्श स्थल माने जाते हैं।

सरकार की पहलें

१. अतुल्य भारत अभियानये— विश्व पर्यटन मानचित्र पर भारत को एक अंतिम पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा २००२ में अतुल्य भारत अभियान शुः किया गया था। देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तर पर अतुल्य भारत अभियान चलाया गया। इसने भारतीय संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और योग का प्रदर्शन करके भारत को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में पेश किया।

२. अतिथि देवो भवः— अतिथि देवो भवः अतुल्य भारत अभियान के पूरक के लिए भारत

सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। मुख्य उद्देश्य पर्यटन के प्रभाव के बारे में जाग:कता पैदा करना और हमारे देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति, स्वच्छता और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के बारे में लोगों को जाग:क करना है।

३. विजिट इंडिया २००९—विजिट इंडिया २००९ अभियान का मुख्य उद्देश्य २००८ में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के साथ—साथ वैश्विक. आर्थिक संकट के बाद आगंतुकों और पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की घोषणा पर्यटन मंत्रालय और विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

भारतीय पर्यटन उद्योग की चुनौतियाँ:

१. आवश्यक बुनियादी ढांचा: पर्यटन की वृद्धि के साथ—साथ यातायात, आवास और अन्य सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय सरकार और निजी क्षेत्र इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता है।

२. सुरक्षा और स्वच्छता: पर्यटकों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। भारतीय पर्यटन स्थलों पर इन सुविधाओं में सुधार करना आवश्यक है।

३. पर्यावरणीय प्रभाव: पर्यटन के बढ़ते प्रभाव से पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और जैव विविधता में कमी। इसके समाधान के लिए सतत और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना ज:री है।

बाधाएँ:—भारत में पर्यटन के विकास में प्रमुख बाधा पर्याप्त हवाई सीट क्षमता, पर्यटन स्थलों तक पहुंच, आवास और पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित जनशक्ति सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता है। विशेष रूप से अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं, खराब स्वच्छता स्थितियों तथा कुछ स्थानों पर दलाली और पर्यटकों को परेशान करने की घटनाओं के कारण आगंतुकों को खराब अनुभव प्राप्त होता है।

निष्कर्ष :—

पर्यटन विकास और पर्यटन नीति निकट से संबंधित पहलू हैं। पर्यटन विकास काफी हद तक पर्यटन नीति पर निर्भर करता है। पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत्त ही महत्त्वपूर्ण खंड है। किसी भी देश का आर्थिक विकास, चाहे वह विकासशील, विकसित या अविकसित देश हो, पर्यटन क्षेत्र से काफी प्रभावित होता है। इसलिए विश्व के हर देश ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कई पर्यटन नीतियाँ तैयार की हैं। भारत सरकार ने घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए कई पहल किये हैं। पर्यटन के बुनियादी ढाँचे का विस्तार, पर्यटन स्थलों का विकास, नए पर्यटन उत्पादों का विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि कुछ उपाय हैं। स्वतंत्र काल के बाद भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कई नीतियां पेश की हैं। भारत के योजना आयोग (वर्तमान नीति आयोग) द्वारा पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी गई थी। परिणामस्वरूप पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में आगंतुकों को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है एवं बड़े पैमाने पर रोज़गार और आय अर्जित करने के अवसर पैदा कर रहा है स भारतीय पर्यटन उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में अद्वितीय विकास किया है और यह भारत की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे बुनियादी ढांचे की कमी, पर्यावरणीय प्रभाव, और सुरक्षा संबंधित समस्याएँ। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए और पर्यटन के क्षेत्र में सतत विकास को प्राथमिकता दी जाए, तो भारतीय पर्यटन उद्योग और भी अधिक समृद्ध हो सकता है।

इस प्रकार, भारतीय पर्यटन उद्योग ने विभिन्न कालखंडों में अलग—अलग चरणों में विकास किया है और यह निरंतर सुधार और विस्तार की दिशा में अग्रसर है।

संदर्भ:

१. काम्परियां डॉ, प्रकाश : मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं और चुनौतियां विदेशी पर्यटकों के संदर्भ में जनवरी — मार्च २०२२

२. व्यास, राजेश कुमार :भारत में पर्यटन, प्रभात प्रकाशन २०१७ प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली — पृष्ठ क्रमांक १५५

३. नारायण भक्त :भारत के पवित्र तीर्थ स्थल,

प्रभात प्रकाशन प्रथम संस्करण २०१९ दिल्ली १९९ — २००

४. श्रीवास्तव, डॉ.बी.के: पर्यटन का इतिहास विपणन एवं प्रबंधन, नम्या प्रकाशन, पृष्ठ १७

५. पर्यटन और हम, आर के पब्लिकेशन २०२३ पृष्ठ संख्या १२३

६. रावत डॉ. शिवचंद सिंह, उनियाल डॉ मनोज कुमार: ऐतिहासिक पर्यटन प्रतिभा प्रकाशन २०१९ पृष्ठ ५— ९

७. अग्रवाल रोहित, देश का हृदय मध्य प्रदेश पर्यटन ,ओम साइन टेक्स्ट बुक प्रथम संस्करण २०१९ पृष्ठ क्र.२०२ से २०४ ,३००

८. तिवारी धर्मेंद्र ,मिश्रा पणीता: मध्य प्रदेश इतिहास ,कला एवं संस्कृति, डच चेब,उब ळतूं ीपसस एडिशन — १ २०२२ पृष्ठ क्र.११५ — ११७

९. बरनवाल महेश कुमार तिवारी रवि शंकर यादव रूप सिंह, मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन उच चेब कास्मोस प्रकाशन,२०१९ पृष्ठ — ५—१०

10- Ministry of Tourism, Government of India- 2023- Annual Report on Tourism Statistics-

11- Sharma R- 2020- Indian Tourism A Comprehensive Overview- New Delhi Publication House-

12- Singh, P- & Jain] R- 2018- Tourism and Economic Development in India- OÛford University Press-

13- Government of India- 2022- Incredible India Campaign Impact Analysis-

❑❑❑

20

विविध क्षेत्रों में कौशल विकास
(महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में)

डॉ. सेवन्ती डावर
(सहायक प्रध्यापक) हिन्दी
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन

****

कौशल विकास

कौशल विकास देश के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़ेलिखे है, या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इस योजना में ३ महीने, ६ महीने, १ साल के लिए पंजीयन होता है। पाठ्क्रम करने के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। कौशल विकास अर्थात स्वप्रेरणा, आत्मविश्वास, निरंतर अभ्यास, सतत् प्रयास, प्रकृति के अनुरूप गतिशीलता कौशल विकास हो सकता है। अर्थात अपनी क्षमताओं का आकलन कब जब हमें नवीन कार्य करने का दायित्व का अवसर मिले। मानव के संपूर्ण विकास के लिए जीवन रफ्तार में यह दो शब्द कौशल व विकास अपने आप में परिपूर्ण अर्थ लिए हुए हैं।

कौशल — कुशलता पूर्वक कार्य करना।

विकास — कार्य को बड़ी चतुराई व दक्षता से पूर्ण कर कार्य का विस्तार करना, कार्य का विस्तार भी केवल निजी हित के लिए नहीं बल्कि सर्व प्राणी जगत के कल्याण के लिए विकास का मार्ग हो।

सशक्तिकरण से पूर्व की स्थिति

२०वीं सदीं को 'महिला जागरण काल' कहा जाता है। इस काल को संघर्ष काल कहे तो अनुचित न होगा। इस समय लोगों में फैला अंधविश्वास, कुरीतिया, शोषण दास्ताँ गरीबी से एक साथ संघर्ष करना पड़ा। पुरुष प्रधान समाज में भारतीय महिला पिछड़े वर्ग में गिनी जाती थी। इसलिए प्रत्येक समाज सुधारक आंदोलन

का केंद्र महिला बन गई। प्रारंभिक युग में भले ही नारी शिक्षा को महत्व नहीं मिला हो, परंतु आधुनिक युग में इसे पर्याप्त महत्व मिला है। शिक्षा के बल पर आज की नारी चार दिवारी के कैद से स्वतंत्र हो चुकी है। शोषण होने पर वह प्रतिकार कर रही है, उचित कदम उठाकर अपनी रक्षा कर रही हैं। आज की नारी पुरुष वर्ग के सामने खड़ी होने में समर्थ हो गई है। शिक्षा से नारियों के हृदय में साहस भरा गया है। नारी जागरण नारी शिक्षा का परिणाम है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र भारत के समस्त नागरिकों को समता का अधिकार दे दिया, इससे नारी को पुरुष के समान अवसर मिल गए हैं। आज नारी विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन गई, यद्यपि अनुपात में यह संख्या अभी नगण्य है। महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, ढहती जाने वाली आर्थिक स्थिति ने नारी को विवश कर दिया है। वह घर की चार दिवारी से बाहर आकर जीविकोपार्जन हेतु नौकरी कर रही है। इस नए जमाने की नारी दोहरी भूमिका निभा रही है। आज भी पुरुष अपने अहंकार के कारण नारी को समानता का स्थान देने के लिए तैयार नहीं है। नारी को परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु घर से बाहर या घर में व्यस्त रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके आर्थिक क्षमताओं का लाभ परिवार प्रसन्नता पूर्वक उठाता है। परंतु इस परिवार का हर एक सदस्य यह आशा रखता है, कि वह परंपरागत रूप से अपने दायित्व का निर्वहन करें।

महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण का अर्थ एक कमजोर स्थिति से मजबूत शक्तिशाली स्थिति की ओर बढना है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के अंदर निहित शक्ति को बढ़ावा देना। महिलाओं को शक्ति प्रदान करना। सशक्त बनने के लिए महिलाओं को स्वयं अपने आप और अपने अंदर निहित शक्ति व ऊर्जा पर विश्वास करना होगा। साथ ही साथ अपना आत्म बल भी पैदा करना होगा, कि कोई भी समस्या उसके मार्ग में अवरोध बनेगी, उसे वह सुगमता पूर्वक समाप्त कर लेगी, महिला सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में महिलाओं को इस योग्य बनाना है, कि वह अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सुविधाओं और अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को पहचान सके।

२००१ में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया, मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर २०१३ में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की, इस योजना का मकसद विकलांग महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। २२ जनवरी २०१५ को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। इस मकसद से बाल लिंगानुपात में गिरावट को कम करना बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना है।

महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य

महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को दूसरों से आगे निकलने और समाज में समान अधिकार, महिला सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी साक्षरता है। एक शिक्षित महिला आत्मविश्वासी मुखर और निर्णय लेने में सक्षम होती है। महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के जरिए एक माहौल का निर्माण करना, ताकि वह अपनी क्षमताओं को समझ सके, निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मापदंड है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर तरीकों को चुनौती में समान अवसर राजनीतिक, आर्थिक, नीति—निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानुन के तहत सुरक्षा प्रजनन का अधिकार आदि प्रदान करना है।

निष्कर्ष

भारतवर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए नारीवादी आंदोलन ने एक अहम भूमिका निभाई है। गांधीजी और अंबेडकर जी ने महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कई प्रयास किए। गांधी जी ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह जैसी अनेक समस्याओं के खात्मे का काम किया। वही डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने मताधिकार दिलाने, भेदभाव, समानता का अधिकार आदि बुनियादी समस्याओं को समाप्त करने की और संवैधानिक कानुन बनाए। आधुनिक भारतीय नारी में शादियों के उतार—चढ़ाव के

बाद काफी परिवर्तन आ चुका है। अपनी इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उसे अथक संघर्ष करना पड़ा। जब तक वह पुरुष के संरक्षण में रही, तब तक उसे अपने विकास के लिए अवसर प्राप्त नहीं हुआ। शिक्षा समाज सेवा मताधिकार चुनाव लड़ने का अवसर आदि इसके उदाहरण है। जब नारी ने स्वतंत्र इंसान के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहि, तो पुरुष वर्ग चौक गया। पुरुष आज तक नारी को माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में ही देखता आया था। नारी आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण यह है, कि भारतीय नारी पुरुष विरोधी नहीं है वह पुरुष के प्रति अनुदार नहीं है। वह माँ के रूप में श्रृद्धा तथा आदर की पात्रा है, पत्नी के रूप में पुरुष का स्वामित्व उसे चुभता नहीं है। भारतीय नारी ने समान अधिकार की बात करते हुए भी स्वेच्छा से पारंपरिक दायित्व को स्वीकारा है। अपने पत्नीत्व एवं मातृत्व को सफलतापूर्वक निभाना एवं पुरुषों की भांति घर से बाहर निकाल कर ऑर्थोपाजन करना शुरू किया। निसंदेह इन दोहरी दायित्व को सफलतापूर्वक निभाने की क्षमता ने नारी को समान अधिकार दिलवाने में भरपूर सहायता की है।

भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के समाज में मतत्व के बारे में सही कहा है। 'लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है, एक बार जब वह अपना कदम उठा लेती हैं, तो उनके पीछे—पीछे परिवार आगे बढ़ता है, गॉव आगे बढ़ता है, और राष्ट्र विकास की और उन्मुख होता है, आज भारत के विकास और उन्नति में नारी शक्ति का योगदान अतुल्य है'। इतिहास में भी महिलाओं ने विशिष्ट भूमिका निभाई है। जैसे कि भारतीय नारीवाद की जननी 'सावित्रीबाई फुले' जिन्होंने देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करके देश में साक्षरता का नया दीपक जलाया, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई, 'ताराबाई शिंदे' जिनकी कृति स्त्री पुरुष तुलना को पहली आधुनिक नारीवादी पाठ माना जाता है। 'पंडित रमाबाई' इन्हें ब्रिटिश राज द्वारा 'केसर—ए—हिंद' पदक से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने विशिष्ट सामाजिक सेवा से ब्रिटिश भारत के समय एक समाज सुधारक के रूप में महिलाओं की मुक्ति के लिए कार्य किया था। महिला सशक्तिकरण के लिए सावित्री बाई फुले का कथन उल्लेखित है 'स्त्रियों को न देवी मानने की जरूरत है और न पूजने की, बल्कि स्त्री का सम्मान करना और बराबरी का अधिकार देना जरूरी है।'

शब्द कुंजी : कौशल विकास, सशक्तिकरण, स्वावलंबी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति

संदर्भ सूची —

१. भारत में ग्रमीण विकास — डॉ.डी.सी.पन्त

२. उद्यमिता विकास — डॉ.यू.सी. गुप्ता, सुमन विश्वकर्मा

३. पारिवारिक संसाधन प्रबंधन — उल्पना अग्रवाल

४. महिला सशश्किरण — डॉ. हंसा व्यास, म.प्र. हिन्दी ग्रथ, अकादमी भोपाल

❑❑❑

21

देश के आर्थिक विकास में कौशल विकास की भूमिका

डॉ. प्रकाश पगारे
सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा

****

कौशल विकास एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों की कार्य क्षमता में सुधार करना और उन्हें अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बनने में मदद करना है। इस जटिल गतिविधियों या व्यवसाय से सम्बंधित कार्यों कोआसन और अनुकूलनीय रूप से करने के लिए क्षमता या क्षमता प्राप्त करने के लिए सतत और व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम को, कौशल विकास के रूप में जाना जाता है। सरल शब्दों में, कौशल अंतराल की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करना कौशल विकास के रूप में जाना जाता है।

कौशल विकास में वृद्धि के लिए अपनाये जाने वाले उपाय

१. प्रशिक्षण कार्यक्रम : कौशल विकास में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न कौशलों और ज्ञान के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके।

२. कार्यशालाएँ : कौशल विकास में वृद्धि के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न कौशलों और ज्ञान के बारे में प्रशिक्षित किया जाए।

३. ऑनलाइन पाठ्यक्रम : कौशल विकास में वृद्धि के लिए ऑनलाइन पाठ्क्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न कौशलों और ज्ञान के बारे में प्रशिक्षित किया जाता हो।

४. मेंटरशिप : कौशल विकास में वृद्धि के लिए मेंटरशिप कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें व्यक्तियों को अनुभवी पेशेवरों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता हो।

इस प्रकार के विभिन्न आयोजनों के माध्यम से व्यक्तियों को अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बनाया जा जा सकती है।

कौशल विकास का व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में महत्व

१. कार्य क्षमता में सुधार : कौशल विकास का उद्देश्य व्यक्तियों की कार्य क्षमता में सुधार करना है, ताकि वे अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकें।

२. नई प्रौद्योगिकियों का अपनाना : कौशल विकास का उद्देश्य व्यक्तियों को नई प्रौद्योगिकियों का अपनाने में मदद करना है, ताकि वे अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकें।

३. कार्य संबंधी समस्याओं का समाधान : कौशल विकास का उद्देश्य व्यक्तियों को कार्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने में मदद करना है, ताकि वे अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बन सकें।

४. व्यक्तिगत विकास : कौशल विकास का उद्देश्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास में मदद करना है, ताकि वे अपने जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट बन सकें।

कौशल विकास काउत्पत्ति के साधनों के विकास में योगदान

उत्पत्ति के साधनों में कौशल विकास का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलाती है। कौशल विकास की उत्पत्ति के साधनों के पूर्ण और कुशलतापूर्वक विदोहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है

१. उत्पादकता में वृद्धि : कौशल विकास से कर्मचारियों को अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बनने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है।

२. गुणवत्ता में सुधार : कौशल विकास से कर्मचारियों को उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है।

३. नई प्रौद्योगिकियों का अपनाना : कौशल विकास से कर्मचारियों को नई प्रौद्योगिकियों का अपनाने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होता है और उत्पादकता बढ़ती है।

४. कर्मचारियों की संतुष्टि : कौशल विकास से कर्मचारियों को अपने कार्य में अधिक प्रभावी और उत्पादक बनने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संतुष्टि में वृद्धि होती है।

५. उत्पत्ति की लागत में कमी : कौशल विकास से उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होता है, जिससे उत्पत्ति की लागत में कमी होती है।

६. उत्पत्ति की गुणवत्ता में सुधार : कौशल विकास से उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होता है, जिससे उत्पत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है।

७. नई उत्पादों का विकास : कौशल विकास से कर्मचारियों को नई उत्पादों का विकास करने में मदद मिलती है, जिससे कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है।

इन तरीकों से, कौशल विकास उत्पत्ति के साधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करता है।

व्यवसाय में कौशल विकास का महत्त्व

किसी व्यवसाय की सफलता या असफलता उसमे प्रयुक्त तकनिकी ज्ञान पर निर्भर करती है। उन्नत तकनीक, ज्ञान कौशल और प्रबंधन पर आधारित व्यवसाय सदैव उन्नति करते है।

१. प्रतिस्पर्धा में बढ़त : कौशल विकास से व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

२. उत्पादकता में वृद्धि : कौशल विकास से कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि वे अपने कार्यो को अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं।

३. ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि : कौशल विकास से कर्मचारियों को ग्राहकों की जरूरतों को समझने और पूरा करने में मदद मिलती है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है।

४. नवाचार और रचनात्मकता : कौशल विकास से कर्मचारियों को नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, जिससे व्यवसाय को नई और बेहतरीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद मिलती है।

५. कर्मचारी प्रतिधारण : कौशल विकास से कर्मचारियों को अपने कार्य में अधिक संतुष्टि और प्रतिधारण मिलती है, जिससे व्यवसाय को कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलती है।

६. व्यवसाय की वृद्धि : कौशल विकास से व्यवसाय को वृद्धि और विस्तार में मदद मिलती है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

इन कारणों से, कौशल विकास व्यवसाय में बहुत जरूरी होता है।

देश के आर्थिक विकास के लिए कौशल विकास

कौशल विकास देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह देश की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है। यहाँ कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कौशल विकास देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी होता है

१. उत्पादकता में वृद्धि : कौशल विकास से देश की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

२. प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि : कौशल विकास से देश की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

३. रोजगार के अवसरों में वृद्धि : कौशल विकास से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

४. आर्थिक विकास में योगदान : कौशल

विकास से देश के आर्थिक विकास में योगदान होता है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

५. देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि : कौशल विकास से देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

६. नवाचार और रचनात्मकता : कौशल विकास से देश में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

७. देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि : कौशल विकास से देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

विश्वपटल पर उन्ही राष्ट्रों का विकास तेज़ी से हुआ है जिन राष्ट्रों में कौशल विकास को वरीयता दी गई है। कौशल विकास की सहायता से ही राष्ट्र में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधनों को संसाधन के रूप में परिवार्तीय किया जा सकता है और इनका कुशलतापूर्वक विदोहन संभव हो पता है, जब इन संसाधनों को उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जाता है तो उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि प्राप्त होती है इन कारणों से, कौशल विकास देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है।

सन्दर्भ सूची –

१. विजय लक्ष्मी शर्मा कौशल विकास भारतीय परंपरा के नेपथ्य से भारत प्रकाशन

२. Prof-Arulsamy Dr-J Jeyadevi :& Þskill development neelkamal publication

३. Dr-B-Ramaswamy Dr-R-Sasikala Pushpa :& ÞSkill Devilopment in India Prabhat Prakashan

❑❑❑

22

नवीन शिक्षा नीति का समाज में प्रादुभाव

डॉ. विजय सिंह मंडलोई
सहायक प्राध्यापक (इतिहास)
शासकीय महाविद्यालय कसरावद,
जिला खरगोन मध्य प्रदेश

सारांश

नई शिक्षा नीति ने 'सार्वभौमिक शिक्षा' का मार्ग प्रशस्त किया है।डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एनईपी ने तकनीकी उपकरणों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि एनईपी २०२० में कई सुधारात्मक उपाय शामिल हैं, लेकिन इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी, और बजट की सीमाएँ।नई शिक्षा नीति समाज में समावेशिता, गुणवत्ता और नवीनता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति २०२० (एनईपी २०२०) भारत की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। इसे २९ जुलाई २०२० को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। यह नीति १९८६ में जारी हुई पिछली शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली में पहला बड़ा सुधार है। यह नीति, प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत–केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जो भारतीय परंपरा, संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार के साथ आधुनिक आवश्यकताओं का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य शिक्षा को समकालीन, समग्र और समावेशी बनाना है।

शिक्षा का सार्वभौमिकरण

शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी बच्चों और युवाओं को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, या भौगोलिक स्थान कुछ भी हो। यह शिक्षा को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानते हुए समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने का एक प्रयास है। भारत में, शिक्षा का सार्वभौमिकरण विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद २१। के तहत अनिवार्य शिक्षा (६—१४ वर्ष के बच्चों के लिए) का प्रावधान सुनिश्चित करता है।

मातृभाषा में शिक्षा का महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) २०२० ने मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को समझते हुए इसे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई करते हुए बेहतर समझ और सीखने की क्षमता विकसित कर सकें।किसी कक्षा में ऐसे छात्र हो सकते हैं जो एक से अधिक मूल भाषा बोलते हों, लेकिन शिक्षकों को उनकी समझ, बोलने और लिखने वाली भाषाओं के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाता। संसाधन हमेशा उन क्षेत्रीय बोलियों में उपलब्ध नहीं होते जिन्हें बच्चा समझता है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० की सिफारिशों को बनाए रखते हुए कक्षा में अपनी मातृभाषा में सीखने के लाभों को महसूस करने के लिए पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करने और लागू करने को प्राथमिकता दी है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनका विकास हो रहा है, इसलिए इस मुद्दे का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए एक ष्उच्च—स्तरीयष समिति की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की पहल — दीक्षा पोर्टल, कक्षा १—१२ के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा और ३२अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करता है। यहाँ पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण संसाधन भी उपलब्ध हैं। संसाधनों का ऐसा व्यापक पुस्तकालय उपलब्ध कराकर, DIKSHA पोर्टल शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षण वातावरण बनाना आसान बनाता है, जिससे छात्रों को अपनी मूल भाषा में सीखने का बहुमूल्य अवसर मिलता है।

मातृभाषा आधारित शिक्षा का प्रभाव (चार्ट)

मुद्दा	विवरण
मातृभाषा में सीखने के लाभ	बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने और अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता में वृद्धि।
संसाधनों की कमी	क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के लिए संसाधनों की अनुपलब्धता, जो शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है।
DIKSHA पोर्टल की भूमिका	32 भारतीय भाषाओं और भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे भाषा संबंधी अंतराल को पाटा जा सके।
समावेशी शिक्षण	विविध भाषाई पृष्ठभूमि वाले छात्रों को लाभ पहुँचाने के लिए DIKSHA पोर्टल और अन्य पहलों का उपयोग।
उच्च-स्तरीय समिति	भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें तैयार करने वाली समिति की स्थापना।
भविष्य की संभावनाएँ	क्षेत्रीय भाषाओं के लिए संसाधन विकास, बहुभाषी प्रशिक्षण, और शिक्षा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग।

तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का विस्तार

तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का प्रसार २१वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। यह पारंपरिक शिक्षण विधियों को तकनीकी उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पूरक बनाता है। डिजिटल शिक्षा ने न केवल शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और अनुकूलनीय भी बनाया है।डिजिटल शिक्षा ने भौगोलिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है। अब दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल शिक्षा छात्रों को अपनी गति और समय के अनुसार सीखने की सुविधा देती है। शिक्षा का व्यक्तिगतकरण तकनीकी उपकरण जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करते हैं। लागत प्रभावी ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल पुस्तकें पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अधिक किफायती हैं। कौशल विकास डिजिटल उपकरणों के उपयोग से छात्रों में तकनीकी कौशल विकसित होते हैं, जो भविष्य में उनके करियर में सहायक होते हैं।

प्रमुख पहल और विकास

१. DIKSHA पोर्टल

यह प्लेटफ़ॉर्म शिक्षकों और छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है।

२. ई—पाठशाला

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

(NCERT) द्वारा ई—पाठशाला ऐप के माध्यम से कक्षा १—१२ तक की सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

३. स्वयं पोर्टल

यह ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों की सामग्री उपलब्ध है।

४. उड़ान और प्रधानमंत्री ई—विद्या योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य छात्रों को मुफ्त डिजिटल सामग्री और उपकरण प्रदान करना है।

५. मोबाइल लर्निंग ऐप्स

बायजूस, अनअकादमी, कक्षा, और अन्य ऐप्स छात्रों को डिजिटल शिक्षण में नए अवसर प्रदान कर रहे हैं।

तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का विस्तार

डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एनईपी ने तकनीकी उपकरणों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोविड—१९ महामारी के दौरान यह विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ। इसके अलावा, 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा, मानव जीवन की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करने का मूल आधार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना न केवल व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी अनिवार्य है। भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास के संदर्भ में, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा वह कुंजी है, जो देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ विकास और उपयोग में सहायक बन सकती है।भारत जल्द ही दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इन युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और उन्हें उन्नत शैक्षिक अवसरों तक पहुँच उपलब्ध कराना, देश के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। एक समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि युवाओं को न केवल ज्ञान और कौशल से लैस किया जाए, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित भी किया जाए।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) ४ और भारत की प्रतिबद्धता

भारत ने २०१५ में सतत विकास एजेंडा २०३० को अपनाया। इस एजेंडे के तहत सतत विकास लक्ष्य (SDG) ४ के माध्यम से २०३० तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन भर सीखने के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है। यह शिक्षा विकास एजेंडा भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

SDG ४ के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, शिक्षा प्रणाली को

१. समर्थनकारी बनाना होगा।

२. अधिगम को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ लागू करनी होंगी।

३. सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

४. शिक्षा प्रणाली में सुधार करके इसे अधिक समावेशी और सुलभ बनाना होगा।

सतत विकास एजेंडा के लक्ष्य

२०३० तक शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार पुनर्गठित करना होगा कि सतत विकास के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इनमें शामिल हैं

➢ सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना।

➢ जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।

➢ समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देना।

➢ वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

➢ सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को संरक्षित करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीशि २०२०

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, २१वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य हमारे देश

के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बनाए रखते हुए, २१वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी ४ भी शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके संचालन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ—साथ उच्चतर स्तर की तर्कशक्ति और समस्या—समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और संस्कृति की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय संस्कृति परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा विद्यालय के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति के पूर्ण आत्म—ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व—स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा और शोध के ऊंचे मानक स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को आत्मसात किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चारक, चक्रपाणि दत्त, माधव, पाराशर, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, शंकरदेव, मैत्रेयी जैसे महान विद्वानों और विचारकों को जन्म दिया था।गागि और शठरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान शब्दद्वानों ने जन्म लिया। इन शब्दद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे गणित, खगोलशास्त्र, धातुशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और आयुर्वेद, सैन्य इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण और स्थापत्य, योग, वास्तुकला, तैराकी, शतरंज आदि में प्रमुख रूप से मौलिक योगदान किए। भारतीय संस्कृति और ज्ञान का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखना आवश्यक है। इसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा इस पर शोध कार्य होने चाहिए, इसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए—नए उपयोगों पर विचार किया जाना चाहिए।

समाज में प्रादुभाव

नवीन शिक्षा नीति के लागू होने के बाद समाज में एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। गांवों में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा, इस नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ हो रहा है।

निष्कर्ष

नवीन शिक्षा नीति २०२० भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रयास है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने का एक साधन भी है। हालांकि, इस नीति के कार्यान्वियन में चुनौतियां हैं, लेकिन यदि इसे सही दिशा में लागू किया जाए तो यह भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है।

संदर्भ सूची —

१. राणा, के. (२०२०). शिक्षा और समाज, नई दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ ४५।

२. मिश्रा, एस. (२०२१). शिक्षा का स्वरूप, मुंबई : ओरिएंट ब्लैकस्वान, पृष्ठ १२।

३. शर्मा, ए. (२०२०). भाषा और शिक्षा, पुणे : एस. चंद्रा एंड कंपनी, पृष्ठ ९२।

४. अग्रवाल, पी. (२०२१). डिजिटल शिक्षा, हैदराबाद : यूनिवर्सल पब्लिशर्स, पृष्ठ ७८।

५. गुप्ता, वी. (२०२१).भारतीय संस्कृति और शिक्षा, वाराणसी ज्ञान भारती प्रकाशन, पृष्ठ ६७।

६. जोशी, एन. (२०२१). व्यावसायिक शिक्षा, लखनऊ प्रकाशन विभाग, पृष्ठ ३४।

७. चौधरी, आर. (२०२१). शिक्षा नीति की

चुनौतियां, भोपाल : ए.बी.सी. पब्लिशिंग, पृष्ठ ८८।

८. नवीन शिक्षा नीति २०२० शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, २०२०

९. शिक्षा और समाज में बदलाव" & NCERT, २०२१, पृष्ठ ४५–६७

१०. भारत में शिक्षा की स्थिति और सुधार– शिक्षा आयोग रिपोर्ट, २०१९, पृष्ठ २३–३९

११. शिक्षा और प्रौद्योगिकी डिजिटल परिवर्तन– भारतीय विज्ञान संस्थान, २०२२, पृष्ठ ११०–१२५

१२. नवीन शिक्षा नीति २०२० पृष्ठ १५–३५

१३. शिक्षक प्रशिक्षण और विकास पृष्ठ ७८–८९

१४. समाज में शिक्षा के प्रभाव पृष्ठ १२०–१३४

१५. https : / / www-education-gov-in@nep@about&nep

१६. भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी – भारतीय विज्ञान संस्थान, २०२०

१७. भारतीय गणित और खगोलशास्त्र – NCERT, २०२१

१८. प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र – डॉ. रामचंद्र शर्मा, २०१९

१९. भारतीय स्थापत्य कला – डॉ. श्रीकृष्ण वर्मा, २०१८

२०. भारतीय धातुशास्त्र का इतिहास – डॉ. कमल कुमार, २०२०

२१. शतरंज का इतिहास और भारतीय योगदान – डॉ. रवींद्र मिश्रा, २०१७

२२. योग और आयुर्वेद : प्राचीन भारतीय ज्ञान – डॉ. विमला ठाकुर, २०२१

२३. भारतीय संस्कृति और उसका वैश्विक प्रभाव – भारतीय संस्कृति अकादमी, २०१९

२४. भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास – महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, २०१८

❑❑❑

23

भारत में कौशल विकास का सामाजिक महत्व

लेफ्टनंट डॉ. एम. आर. खोत
स.का.पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालय,
मालवण, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र

****

परिचय

भारत जैसे विकासशील देश में कौशल विकास का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत और सामाजिक समृद्धि का एक प्रमुख माध्यम है, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भारत की युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और समग्र आर्थिक प्रगति को प्रेरित किया जा सकता है। इसके साथ ही, यह सामाजिक असमानताओं को कम करने और समाज में समृद्धि फैलाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है।

तलाश पद्धतियाँ

इस शोध में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र की जाएगी, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट्स, शैक्षिक और शोध पत्र, और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों से। इसके अलावा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और विशेषज्ञों से चर्चा भी अनुसंधान का एक हिस्सा होगी।

शोध के उद्देश्य

- ➢ कौशल विकास की अवधारणा को समझना और उसकी परिभाषा स्पष्ट करना।
- ➢ भारत जैसे विकासशील देश में कौशल विकास की आवश्यकता का विश्लेषण करना
- ➢ भारत में कौशल विकास की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना,
- ➢ कौशल विकास के सामाजिक महत्व को समझना,

- रोजगार सृजन में कौशल विकास का प्रभाव का अध्ययन करना,
- आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन पर कौशल विकास का प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- कौशल विकास में आने वाली चुनौतियों को
- भारत में कौशल विकास के लिए सरकारी योजनाओं और उपायों का विश्लेषण करना
- कौशल विकास की भावी दिशाएँ का अध्ययन करना

कौशल विकास की अवधारणा

कौशल विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को कार्यक्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक ज्ञान, दक्षताएँ और तकनीकी क्षमता प्रदान की जाती है। यह एक प्रणालीबद्ध तरीका है, जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण का उपयोग करके व्यक्तियों को अपने कार्यक्षेत्र में निपुण बनाने के लिए तैयार किया जाता है। कौशल विकास का उद्देश्य न केवल किसी विशेष काम को करने की क्षमता प्राप्त करना है, बल्कि यह समाज में व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाना, आर्थिक विकास में योगदान देना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी है।

कौशल विकास की आवश्यकता

भारत में कौशल विकास की आवश्यकता विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या युवा है और रोजगार के अवसर सीमित हैं। कौशल विकास से रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होता है, और इससे व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव आता है। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, समाजिक समावेशन, महत्वपूर्ण उद्योगों की मांग, नई तकनीकी चुनौतियाइस प्रकार, भारत जैसे विकासशील देश में कौशल विकास न केवल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक समृद्धि और समावेशन के लिए भी अनिवार्य है।

भारत में कौशल विकास की स्थिति

भारत में कौशल विकास की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ और अवसर बाकी हैं। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में कई पहल की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, और विभिन्न सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम। हालांकि, यह क्षेत्र अपने पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुँच पाया है।

१, सरकारी पहल : भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और मिशनों के माध्यम से कौशल विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इनमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जनशक्ति और कौशल विकास मंत्रालय (MSDE), और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

२, निजी क्षेत्र की भूमिका : कई निजी कंपनियाँ और एनजीओ भी कौशल विकास में योगदान दे रहे हैं। कुछ प्रमुख उद्योग क्षेत्रों, जैसे आईटी, निर्माण, और स्वास्थ्य देखभाल, ने निजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। ये संस्थान युवाओं को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

३, चुनौतियाँ : भारत में कौशल विकास की प्रक्रिया में अभी भी कई अवरोध हैं, जैसे असमानता, पर्याप्त प्रशिक्षण संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की पहुंच, और उद्योगों के साथ तालमेल की कमी। इसके अलावा, कई युवा श्रमिक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में प्रशिक्षण लेते हैं, जो उन्हें वास्तविक कार्य वातावरण के लिए तैयार नहीं करता

कौशल विकास का सामाजिक महत्व

कौशल विकास केवल एक आर्थिक या पेशेवर आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक प्रभाव भी है। यह न केवल रोजगार सृजन में मदद करता है, बल्कि यह समाज में समृद्धि और समावेशन को भी बढ़ावा देता है। इसके सामाजिक महत्व के कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं

१, सामाजिक समावेशन : कौशल विकास विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच असमानताओं को कम करता है। यह विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, और सामाजिक

रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें कामकाजी अवसर प्रदान करता है।

२, शक्ति का संवर्धन : कौशल प्रशिक्षण से विशेष रूप से महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिलता है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति और परिवार में उनका योगदान बढ़ता है।

३, गरीबी उन्मूलन : कौशल विकास से युवाओं को रोजगार मिलता है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और वे गरीबी की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यह भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण साधन है।

४, समाज में बदलाव : जब लोग अपने कौशल से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं, तो वे समाज में अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इससे सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में गति आती है।

कौशल विकास में चुनौतियाँ

भारत में कौशल विकास की दिशा में कई चुनौतियाँ हैं, जो इस क्षेत्र को अपने पूर्ण क्षमता तक पहुँचने से रोकती हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं

१. प्रशिक्षण संस्थानों की कमी

भारत में कुशल प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या और गुणवत्ता में भारी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण केंद्रों की कमी है, और शहरी क्षेत्रों में भी हर व्यक्ति तक प्रशिक्षण की पहुंच नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, कई युवा कुशल कार्यबल बनने से वंचित रह जाते हैं।

२. आवश्यकता और उद्योगों के बीच अंतर

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के साथ मेल नहीं खाते। कई बार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के पास उन कौशलों की कमी होती है, जिन्हें वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता होती है। इससे नौकरी पाने में कठिनाई होती है और उद्योगों को योग्य कर्मचारियों की तलाश रहती है।

३. संस्कृति और मानसिकता की चुनौतियाँ

कई लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पारंपरिक शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और कौशल विकास को निचले दर्जे की शिक्षा समझते हैं। यह मानसिकता कौशल विकास कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रभावित करती है। इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण को लेकर समाज में पूर्वाग्रह और संकोच भी देखा जाता है।

४. वित्तीय संसाधनों की कमी

कौशल विकास के लिए उपयुक्त संसाधन, जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षक, उन्नत प्रशिक्षण सामग्री, और उचित सुविधाएं, अक्सर उपलब्ध नहीं होतीं। इसके अलावा, सरकार और निजी क्षेत्र में आवश्यक वित्तीय निवेश की कमी होती है, जो कौशल प्रशिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन में रुकावट डालती है।

५. पारदर्शिता और मानक की कमी

कई बार कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रमाणन के मानक स्पष्ट नहीं होते हैं। इससे प्रशिक्षण के परिणाम पर प्रश्न उठते हैं, और प्रशिक्षित व्यक्तियों की नौकरी की संभावनाएं प्रभावित होती हैं।

भारत में कौशल विकास के लिए सरकारी योजनाएँ और उपाय

भारत सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और उपायों को लागू किया है, जिनका उद्देश्य देशभर में युवाओं को प्रशिक्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इन योजनाओं में निम्नलिखित प्रमुख पहलें शामिल हैं

१. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग—आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। च्ड्ड्टल के अंतर्गत, उम्मीदवारों को उनके कौशल स्तर के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यह योजना प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है।

२. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)

इस मिशन का उद्देश्य कौशल विकास के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाना है। इसके तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों का सृजन किया गया है और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है।

३. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

यह निगम निजी और सार्वजनिक भागीदारों के

सहयोग से कौशल विकास के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कार्यबल तैयार करना है।

४. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन का कार्य करती है। इसके तहत, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे रोजगार के अवसरों से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

५. स्किल इंडिया मिशन:

यह मिशन कौशल विकास को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करता है और भारत में २०२२ तक ४० करोड़ प्रशिक्षित युवाओं का लक्ष्य रखता है। इसके तहत कई योजनाएँ और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जो देशभर में युवाओं को रोजगार सक्षम बनाएंगे।

६. मेक इन इंडिया और स्टार्ट—अप इंडिया:

इन पहलों के तहत, सरकार ने उद्योगों में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने और युवाओं को नए तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए योजनाएँ बनाई हैं। इसके तहत कौशल विकास को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के साथ जोड़ने पर जोर दिया जाता है।

इन योजनाओं और उपायों के माध्यम से भारत में कौशल विकास के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हालांकि, इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि कौशल विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँच सकें।

कौशल विकास की भावी दिशाएँ

भारत में कौशल विकास के क्षेत्र में भविष्य के लिए कई संभावनाएँ और दिशा—निर्देश हैं। यह क्षेत्र निरंतर बदलाव और विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और आने वाले वर्षों में इसके प्रभाव और महत्व में वृद्धि हो सकती है। कौशल विकास की भावी दिशाएँ निम्नलिखित हैं

१. प्रौद्योगिकी आधारित कौशल विकास

दुनिया भर में तकनीकी परिवर्तन की गति तेज हो रही है, और भारत में भी इसका व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। नई तकनीकों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और रोबोटिक्स, की मांग लगातार बढ़ रही है।

➢ डिजिटल कौशल : डिजिटल और तकनीकी कौशल भविष्य के लिए प्राथमिक आवश्यकता बन गए हैं। भारत में युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शु : किए गए हैं।

➢ ऑनलाइन शिक्षा : ऑनलाइन शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ है, और इससे कौशल विकास को और अधिक पहुँचनीय और सुलभ बनाया जा रहा है। आने वाले वर्षों में, अधिकतर प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यमों से होगा, जो समय और स्थान की बाधाओं को समाप्त करेगा।

२. आत्मनिर्भरता और उद्यमिता का प्रोत्साहन

भारत में युवाओं को केवल नौकरी देने वाले नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय की शुरुआत करने वाले उद्यमियों के रूप में भी तैयार करना आवश्यक है। कौशल विकास कार्यक्रमों में यह पहल और बढ़ सकती है।

➢ स्टार्ट—अप्स और उद्यमिता : सरकार द्वारा ष्स्टार्ट—अप इंडियाष जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आने वाले समय में कौशल विकास कार्यक्रमों में ज्यादा ध्यान छोटे और मझोले उद्यमों पर दिया जाएगा।

३. कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास

भारत में अधिकांश लोग कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में व्यावसायिक कौशल विकास के लिए विशेष योजनाओं की आवश्यकता है।

➢ कृषि में कौशल : कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ रहा है। किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, मशीनीकरण, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

➢ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल : ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीक, हैंडीक्राफ्ट, छोटे उद्योग, और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना होगा।

४. महिलाओं के लिए कौशल विकास

महिलाओं के लिए कौशल विकास की दिशा में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार के अवसरों में शामिल करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण : कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर अधिकार, स्वतंत्रता, और स्वावलंबन प्राप्त होगा। यह उन्हें परिवार और समाज में अपने स्थान को मजबूत करने में मदद करेगा।

५. सामाजिक समावेशन के लिए कौशल विकास

भारत में विभिन्न जाति, धर्म, और वर्गों के लोग हैं, और कौशल विकास को सामाजिक समावेशन की दिशा में भी बढ़ावा देना जरूरी है।

➢ अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल : कौशल विकास कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्तियों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

६. उद्योगों के साथ समन्वय और साझेदारी

कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय में चलाने की आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षित व्यक्तियों को बाजार की वास्तविक जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मिले।

➢ इंडस्ट्री—एजुकेशन पार्टनरशिप : उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच बेहतर साझेदारी से कौशल प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और उपयोगी हो सकता है। इससे युवा प्रशिक्षुओं को कामकाजी दुनिया में जल्दी समायोजित होने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

भारत में कौशल विकास एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है, जो न केवल आर्थिक विकास के लिए, बल्कि सामाजिक समृद्धि और समावेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह योजनाएँ और पहल अधिक प्रभावी हों। भविष्य में, तकनीकी कौशल, उद्यमिता, कृषि, और ग्रामीण विकास जैसी पहलें कौशल विकास के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएंगी। भारत में कौशल विकास को एक व्यापक दृष्टिकोण से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यह युवा शक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके और समग्र राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे सके।

संदर्भ सूची

- अहमद, म. (२०२१). “Current Status of Skill Development in India: A Review.” Asia-Pacific Journal of Skill Development, 4(2), 120-135.
- जोशी, ए. (२०२०). “Vocational Education and Skill Development: A Key to India’s Future.” Vocational Education Journal, 32(1), 45-60.
- जोशी, डी. (२०२०). “Impact of Skill Development on Economic Transformation.” Asia-Pacific Economic Review, 25(1), 35-48.
- online websides
- news papaers

❑❑❑

24

भारत में चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारंपरिक और कौशल आधारित शिक्षा का तुलनात्मक विश्लेषण

A Comparative Analysis of Conventional and Skill Based Education in the field of Medical Laboratory Technology in India-

शम्भू

हिमांशी

शिवम

एम एस सी,एम एल टी छात्र, लाइफ साइंसेज एवं हेल्थ केयर कौशल विभाग, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, पलवल, हरियाणा

डॉ. मनोज कुमार

ज्योति नैन

डॉ. संतोष कुमार

वरिष्ठ कौशल प्रशिक्षक एवं संकाय सदस्य, लाइफ साइंसेज एवं हेल्थ केयर कौशल विभाग, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल, हरियाणा

****

सारांश

परिचय और उद्देश्य : चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (एमएलटी) स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथ ही आवश्यक नैदानिक जानकारी प्रदान करते है जिससे रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम में होती है। भारत में, एमएलटी का क्षेत्र अति महत्वपूर्ण रूप में भूमिका अदा कर रहा है, इसकी शिक्षा का सञ्चालन दो अलग—अलग तरीकों से प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत पारंपरिक शिक्षा और कौशल—आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है २०१४ से पहले और अभी भी आमतौर पर मेडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के लिए तीन साल का पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रम चलाया जाता है जो कि सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने २७ फरवरी, २०१४ को कॉलेज/ विश्वविद्यालय शिक्षा के हिस्से के रूप में कौशल विकास आधारित शिक्षा के लिए एक योजना शुरू की थी, जिससे बैचलर ऑफ वोकेशन (बी. वोक.) की डिग्री प्राप्त की सके अध्ययन का उद्देश्य कौशल आधारित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और जांच करना था, जैसे प्रयोगशाला अस्पताल में इंटर्नशिप अनुभव, अभ्यास उद्योग व्यावसायिकता और पारंपरिक डिग्री कार्यक्रम के साथ तुलना करने के लिए संयुक्त शिक्षा के रूप में भविष्य के परिप्रेक्ष्य को देखा जा सके।

कार्यप्रणाली:गूगल फॉर्म प्रश्नावली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था और पूरे भारत से ४०० प्रतिभागियों को नामांकित किया गया था। जिसके अंतर्गत कौशल आधारित और पारंपरिक शिक्षा दोनों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था सर्वेक्षण २ मई से १८ दिसंबर २०२४ तक किया गया

परिणाम: देश भर से किए गए सर्वेक्षण में से अधिकांश नियमित रूप से लगभग ८६% शिक्षा के दोनों माध्यमों से सभी सैद्धांतिक और व्यावहारिक कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेते हैं।बीएससी एमएलटी के ६०% छात्र ३ साल की पारंपरिक सैद्धांतिक शिक्षा में केवल छह महीने ही प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, जहां ९०% व्यावसायिक छात्र प्रशिक्षु के रूप में कार्य अनुभव प्राप्त करने और कौशल प्राप्त करने के लिए १८ महीनों के लिए प्रशिक्षण पर जाते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से ६२% को रोजगार मिल चुका था जिनमें से १९% सरकारी क्षेत्र में थे और शेष १०% विद्यार्थियों ने मेडिकल लेबोरेटरी के क्षेत्र में स्वरोजगार निर्मित किया पारंपरिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्रों में से २१% को सरकारी नौकरी मिली और ४४% निजी क्षेत्र में कार्यरत

थे। १०% विद्यार्थियों ने मेडिकल लेबोरेटरी के क्षेत्र में स्वरोजगार निर्मित किया शेष विद्यार्थी अन्य रोजगार के तरफ अग्रसर हुए, इनमे से उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को रूचि कम रही

निष्कर्ष :

एमएलटी में पारंपरिक और कौशल—आधारित शिक्षा दोनों की अपनी—अपनी खूबियाँ और सीमाएँ हैं। जबकि पारंपरिक शिक्षा गहन सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है, कौशल—आधारित शिक्षा सैद्धांतिक के साथ —साथ अधिक उद्योग—केंद्रित है और त्वरित नौकरी की तैयारी प्रदान करती है। दोनों दृष्टिकोणों का मिश्रण — सैद्धांतिक ज्ञान और कौशल क्षमता दोनों पर जोर देना — भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र की उभरती मांगों के लिए मेडिकल लेबोरेटरी पेशेवरों को तैयार करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। अत: सैद्धांतिक ज्ञान के साथ कौशल पर अधिक ध्यान देने आवश्यकता है।

Keywords : Vocational education, Medical Lab Technology, Skill Education, Conventional Education, Healthcare

सन्दर्भ सूचि :

1. Tenover FC, Crawford JT, Huebner RE, Geiter LJ, Horsburgh CR, Jr, Good RC. The resurgence of tuberculosis: is your laboratory ready. J Clin Microbiol. 1993;31:767–70. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

2. Drobniewski FA, Caws M, Gibson A, Young D. Modern laboratory diagnosis of tuberculosis. Lancet Infect Dis. 2003;3:141–7. doi: 10.1016/S1473-3099(03)00544-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Huebner RE, Good RC, Takars JI. Current practices in mycobacteriology: results of a survey of state public health laboratories. J Clin Microbiol. 1993;31:771–5. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

4. Aziz MA, Rysweska K, Laszlo A, Blanc L. Strategic approach for the strengthening of laboratory services for tuberculosis control, 2006–2009. Geneva; WHO; 2006 (WHO/HTM/TB/2006.364). Available at: http://whqlibdoc. who.int/hq/2006/WHO_HTM_TB_2006.364 _eng.pdf

5. The Stop TB Strategy Geneva: WHO; 2006 (WHO/HTM/TB/2006.368).

6. Perkins MD, Roscigno G, Zumla A. Progress towards improved tuberculosis diagnostics for developing countries. Lancet. 2006;367:942–3.doi: 10.1016/S0140-6736(06)68386-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Petti CA, Polage CR, Quinn TC, Ronald AR, Sande MA. Laboratory medicine in Africa: a barrier to effective health care. Clin Infect Dis. 2006;42:377–82. doi: 10.1086/499363. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Centers for Disease Control and Prevention Emergence of Mycobacterium tuberculosis with extensive resistance to second-line drugs worldwide, 2000-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2006;55:301–5. [PubMed] [Google Scholar]

9. Laboratory services in tuberculosis control; part I: organization and management Geneva; WHO; 1998 (WHO/TB/98.258). Available at: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998WHO_TB_98.258_(part1).pdf

10. Hargreaves NJ, Kadzakumanja O, Whitty CJ, Salaniponi FM, Harries AD, Squire SB. Smear negative" pulmonary tuberculosis in a dots programme: poor outcomes in an area of high HIV seroprevalence. Int J Tuberc Lung Dis. 2001;5:847–54. [PubMed] [Google Scholar]

11. Hawken MP, Muhindi DW, Chakaya JM, Bhatt SM. Ng'ang'a LW, Porter JDH. Underdiagnosis of smear- positive pulmonary tuberculosis in Nairobi, Kenya. Int J Tuberc Lung Dis. 2001;5:360–3. [PubMed] [Google Scholar]

12. Munyati SS, Dhoba T, Makanza ED, Mungofa S, Wellington M, Mutsvangwa J, et al. Chronic cough in primary health care attendees, Harare, Zimbabwe: diagnosis and impact of HIV infection. Clin Infect Dis. 2005;40:1818–27. doi: 10.1086/429912. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Van Deun A, Kim SJ, Rieder HL. Will the bleach method keep its promise in sputum

smear-microscopy? Int J Tuberc Lung Dis. 2005;9:700. [PubMed] [Google Scholar]

14. Steingart KR, Henry M, Ng V, Hopewell PC, Ramsey A, Cunningham J, et al. Flourescence versus conventional sputum smear microscopy for tuberculosis: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2006;6:570–81. doi: 10.1016/S1473-3099(06)70578-3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Steingart KR, Henry M, Ng V, Hopewell PC, Ramsey A, Cunningham J, et al. Sputum processing methods to improve the sensitivity of smear microscopy for tuberculosis: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2006;6 :664–74. doi: 10.1016/S1473-3099(06)70602-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Aziz M, Ba F. Becx-Bleumink, Bretzel G, Humes R, Iademarco MF, et al. External quality assessment for AFB smear microscopy. WHO, CDC, APHL, KNCV, RIT, and IUATLD Washington: Association of Public Health Laboratories; 2002. Available at: http://www.tbrieder.org/publica tions/eqa_en.pdf

17. Aziz M, Bretzel G. Use of a standardised checklist to assess peripheral sputum smear microscopy laboratories for tuberculosis diagnosis in Uganda. Int J Tuberc Lung Dis. 2002;6:340–9. [PubMed] [Google Scholar]

18. Van Deun A, Portaels F. Limitations and requirements for quality control of sputum smear microscopy for acid-fast bacilli. Int J Tuberc Lung Dis. 1998;2:756–65. [PubMed] [Google Scholar]

19. Nguyen TN, Wells CD, Binkin NJ, Becerra JE, Pham DL, Nguyen VC. Quality control of smear microscopy for acid-fast bacilli: the case for blinded re-reading. Int J Tuberc Lung Dis. 1999;3:55–61. [PubMed] [Google Scholar]

20. Martinez A, Balandrano S, Parissi A, Zuniga A, Sanchez M, Ridderhof JC, et al. Evaluation of new external quality assessment guidelines involving random blinded rechecking of acid-fast bacili smears in a pilot project setting in Mexico. Int J Tuberc Lung Dis. 2005;9:301–5. [PubMed] [Google Scholar]

25

विविध क्षेत्रों में कौशल विकास

प्रो. गीता मेहरा
माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय, स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, खंडवा

****

प्रकृति का पुत्र मनुष्य प्रकृति में मां की ममता को तलाशता है।

किसी भी अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है, कि विद्यार्थियों में ऐसे कौशल विकसित किए जाएं जो उन्हें अपने आप सीखने में मदद करें और वह मात्र रटने में ना बंधे। इसके लिए यह जरूरी है कि पहले हम यह समझे की कौशल क्या है इनका विकास कैसे होता है।

पर्यावरण अध्ययन में विभिन्न अवधारणाओं की समझ शामिल होती है परंतु पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी आधारभूत ज्ञान के आधार पर बच्चा कुछ कार्य कर सके जिसमें कि उसमें किसी कार्य को करने की क्षमता का विकास हो सके। अर्थात् विद्यार्थी किसी कार्य को कर सकने की योग्यता को हासिल कर सके। किसी कार्य को करने के पश्चात् बच्चा जिस योग्यता को प्राप्त करता है, उसको हम कौशल कह सकते हैं।

पर्यावरण कौशल का अर्थ है पर्यावरण से जुड़े काम करने की क्षमता। पर्यावरण से जुड़े काम करने के लिए कई तरह के कौशल विकसित किये जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक सरकारी और कारोबारी नेता मिलकर काम कर रहे हैं ऐसे में सहज और कुशल पर्यावरण वैज्ञानिकों की मांग बढ़ गई है अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अगले दशक के दौरान पर्यावरण वैज्ञानिकों की मांग में ६% की वृद्धि होने की उम्मीद है २०२२ से २०३२ के बीच हर साल लगभग ५००० नए पर्यावरण वैज्ञानिक नौकरियों के

सृजन की उम्मीद है।

जबकि पर्यावरण वैज्ञानिकों की मांग लगातार बढ़ रही है इच्छुक पेशेवरों के लिए निरंतर शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सबसे अधिक मांग वाले पर्यावरण विज्ञान कौशल को पहचानने से आपको पेशेवर विकास कार्यक्रमों में निवेश करने में मदद मिल सकती है। एक समृद्ध पर्यावरण करिअर का विकास पर्यावरण वैज्ञानिकों के लिए सबसे अधिक मांग वाले कौशल में तकनीकी व्यवहारिक और सॉफ्ट कौशल शामिल है जो पेशेवरों को पर्यावरण अध्ययन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति प्रदान करते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए आप जिस भी कमी पर विचार कर रहे हैं इसके बावजूद आप निरंतर व्यवसायिक विकास में निवेश करना चाहेंगे जो आपको पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण और गतिशील परिदृश्य के लिए प्रभावी रूप से तैयार करता है। यूनिटी एनवायरमेंटल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में इकोलिटरेसी कोर्स प्रदान करते हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाले चक्र और हमारी दुनिया के हर क्षेत्र में पारिस्थितिकी विविधता का समर्थन करने वाले प्रमुख अभ्यासों पर गहराई से नजर डालता है। कौशल विकास पर विशेष रूप से लक्षण एक आधारभूत पाठ्यक्रम के रूप में या उन लोगों के लिए आदर्श प्रारंभिक बिंदु है जो पर्यावरण वैज्ञानिकों के लिए मांग में कौशल विकसित करना चाहते हैं।

मनुष्य की प्रकृति अभी भी बरकरार है। आज भी वह दौड़ते, उछलते, कूदते पानी की आवाज में सुख पाता है, डालियो और पत्तों से छनकर आती हुई किरणों की चमक उसे सुहाती है और जीव जंतुओं के सानिध्य में उसे संतोष मिलता है। यह सुख यह संतोष और सुहाने की यह भावना विज्ञान के क्षेत्र की नहीं मानविकी के क्षेत्र की बातें हैं जो हमें पर्यावरण की संस्कृति से जोड़ती है।

मनुष्य के दृष्टिकोण और उसके कार्य हमेशा भौतिक घटकों पर ही निर्भर नहीं रहते वह उनसे आगे निकलकर संस्कृति के दायरे में आ जाते हैं। मनुष्य की प्रकृति शरीर के जैविक अंगों से कुछ अलग है। दर्शन शास्त्री मैथ्यू लिपमैन का बच्चों के बारे में यह कथन कितना सटीक है प्रकृति से ही बच्चें दर्शन के तत्वों (सत्य, सुंदरता एवं व्यक्तिगत पहचान) आदि बातों में रुचि लेने वाले बनते हैं। उनमें सोचने का कौशल होता है। वे बिना किसी का सहारा लिए तर्क तक पहुंच सकते हैं। पर्यावरण और उसके संसाधन हमारी मिली जुली सांस्कृतिक संपत्ति भी है। हम पर्यावरण का संयम से रक्षण करें। इशोपनिषद् की एक ऋचा के अनुसार —यह सृष्टि उसे परम सत्ता की रचना है जिसे सबकी भलाई के लिए रचा गया है। प्रत्येक मानव को इस सृष्टि का आनंद यह सोचकर लेना है कि वह इस विराट व्यवस्था का एक अंग है। उसकी संपूर्ण जीव जगत से नजदीक का रिश्ता है तथा किसी भी जीव के लिए यह उचित नहीं है कि वह दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करें। यह विचार पारिस्थितिकी के सामंजस्य के लिए आदर्श विचार हैं।

विश्व संरक्षण रणनीति के सम्मेलन में जो संदेश दिया है वह भी उक्त विचारों से मेल खाता है उनके अनुसार पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति एवं मानव समूह को ज्ञान और चेतना का अर्जन करना चाहिए और कौशल दृष्टिकोण एवं योग्यताओं का विकास इस तरह करना चाहिए ताकि उसे पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिल सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के पक्षधर हैं और उधर प्रकृति अपने को बनाए रखने के लिए सचेष्ट। पर्यावरण कहीं गड़बड़ ना जाए यह हमारी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए जाहिर है कि आज की शिक्षा उसे दिशा में काम करेगी जो पर्यावरण के सुधार की इस चिंता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की धारा से जोड़कर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करें।

पर्यावरण का संरक्षण और मानव जाति की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक विषय हैं। इसके लिए मनुष्य का शैक्षिक विकास जरूरी है। इस विकास के मूल में तीन पक्ष हैं — मानवीय प्रकृति की समझ, सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस कार्य को एक चुनौती की तरह लेना जरूरी है। पर्यावरण का धार्मिक पक्ष तो है ही आर्थिक पक्ष उससे भी कहीं अधिक बड़ा है। आज ऊर्जा का अधिकांश भाग या तो कोयले से

प्राप्त होता है, या फिर पेट्रोलियम पदार्थों से और यह दोनों हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। आखिर यह दोनों जीवाश्म ईंधन ही तो है, वैसे भी ईंधन के लिए इंसान पेड़ों पर निर्भर रहता आया है। वनों से हमें क्या नहीं प्राप्त होता है? ईंधन, इमारती लकड़ी, जड़ी—बूटियां, औषधियाँ, गोंद, कागज, तारपीन का तेल, लाख, रेशम, शहद, फल—फूल, इत्र, सुगंध, तेंदू पत्ते, तंबाकू, दिया सलाई आदि अनेक चीज वनों से ही उपलब्ध हो सकती है। जहां जो चीज अधिकता से होती है वही उसे पूरे क्षेत्र का आर्थिक आधार बन जाती है। निर्यात के लिए ट्रकों से लेकर जहाजों तक की तस्वीरें सामने आते हैं। पर्यावरण रूठ जाए तो आदमी का जीना दूभर हो जाए, उसका अर्थतंत्र चरमरा जाए और स्वावलंबन का मेरुदंड ही टूट कर बिखर जाए। ऐसे में कल कारखानों, मिलों और धुआँ उगलने वाली चिमनियों की जीवन लीला समाप्त होने में कोई देर नहीं लगती और अगर यह बंद हो जाए तो बेकरी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है और इंसान सैकड़ो वर्ष पुराने युग में लौट जाने को मजबूर हो जाता है।

पर्यावरण के आर्थिक पक्ष की अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते, अर्थात पर्यावरण अध्ययन करते समय हमें अर्थशास्त्र के रास्ते से तो गुजरना ही पड़ता है। आज के भौतिक युग का मूलाधार है आर्थिक चेतना और आर्थिक चेतना की तह में है पर्यावरण का ठोस आधार। इतिहास में प्रकृति के लिए किया गया त्याग भी अंकित है, सन १७३० भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन। खेजड़ली गांव (जोधपुर) मैं पर्यावरण का एक नया इतिहास रचा जा रहा था, पेड़ से चिपके हुए इंसानी जिस्म अपने ऊपर कुल्हाड़ियों के वार सह रहे थे, पेड़ नहीं कटने देंगे, खुद बेशक कट जाएं। क्या गजब का त्याग था उनका कितना बड़ा उपसर्ग था वह। खेजड़ी का वृक्ष आज भी हमारे जीवन धारा के लिए संजीवनी है। इतिहास कई टेढ़े—मेढ़े रास्तों से आगे बढ़ता है, लेकिन जब कभी और जहां कहीं उसने प्रकृति से अलग हटकर सोचा तो उसकी बैलेंस शीट में दिवाला ही सामने आया। जब कभी उसने पर्यावरण के साथ संतुलन का मंत्र पढ़ा उसे आगे बढ़ने का सच्चा सुख हासिल हुआ।

समय की मांग है कि हम अपने बालकों, बालिकाओं तथा वयस्कों को पर्यावरण पाठ्यक्रम में प्रस्तावित विभिन्न विषयों के साथ एकीकृत करके पर्यावरण के प्रति सजग बनाने की भरपूर चेष्टा करें। सामाजिक फिजिशियन एवं सामाजिक अभियंता के रूप में शिक्षक उचित ढंग से समाहित पर्यावरण संबंधी विषय वस्तु द्वारा इस गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्रदान करना तथा भावी पीढ़ी को इसके बारे में जागृत करना भी भविष्य के लिए एक उत्तम निवेश ही कहा जा सकता है।

शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को विभिन्न विषयों के साथ जोड़कर बालकों में निम्न कौशलों का विकास करना वांछित है।

१. विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले तथ्यों को एकत्रित कर उन्हें समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के कौशल का विकास करना।

२. पर्यावरण का विध्वंस करने के प्रसंग में सोची गई परिकल्पनाओं को एकत्रित कर, उनका विश्लेषण कर सही परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए उसका निदान सोचने का कौशल पैदा करना।

३. विभिन्न कृत्यों से होने वाली पर्यावरणीय हानियों के संबंध में पूर्व घोषणा करने की दक्षता पैदा करना और उसका मूल्यांकन करते हुए सही स्थिति का ज्ञान करने की क्षमता का विकास करना।

४. कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता के आधार पर शुद्ध पर्यावरण के विकास में विज्ञान द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करना।

५. समाज का सदस्य होने के नाते प्रकृति के संरक्षण की भावना एवं व्यवहार का विकास करना।

पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु के बारे में विवादास्पद बिंदु यह है कि शालाओं में ज्ञान एवं कौशल के मध्य संतुलन बनाया जाए। इन दोनों विपरीत बिंदुओं के विषय में तर्कपूर्ण ढंग से सोचा जाना आवश्यक है। क्या पर्यावरण संरक्षण में कौशलों को तर्कपूर्ण तरीके से देखा जाए सूचनाओं का विश्लेषण किया जाए तथा मूल्य के आधार पर निर्णय लेकर समाज में क्रियाकलाप किए जाएं। संभवतः कोई भी

इसमें असहमत नहीं होगा कि ज्ञान और कौशल दोनों ही आवश्यक है और दोनों के मेल की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा मुख्यत: कौशल पर ही आधारित होती है। बालक का सीखना भी कौशल पर ही निर्भर होता है। बालक अपने कार्य से प्रभावित होकर ही सिखता है। वह स्वयं किसी वस्तु या क्रियाकलाप को देखता है, करता है सोचता है, असमंजस की स्थिति में आता है, अपनी कल्पनाएं स्थिर करता है और उनको सत्यापित करता है, फिर परीक्षण करता है, और निर्णय तथा परिणाम एकत्रित करता है।यही कौशल की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया में बालक गलती भी करता है, लेकिन नई सूचनाओं और परिणाम के साथ वह गलतियों को हटाता जाता है। इस प्रकार कौशल के द्वारा ज्ञान परिपक्व होता है।

यूके स्नातक में अपनी डिग्री का उपयोग ऐसे रोजगार पाने के लिए कर सकते हैं जो जरूरी नहीं कि उनकी डिग्री विषय से संबंधित हो ऐसा इसलिए है क्योंकि बालक किसी विशिष्ट विषय के बजाय अपने शैक्षणिक अध्ययन के माध्यम से कौशल विकसित करने की कोशिश कर रहा है इस विषय क्षेत्र में डिग्री प्राप्त पेशेवर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं। जिनमें शामिल है —

- सिविल या डेकोरेटरी सेवा
- परामर्श पर्यावरण
- शिक्षा पर्यावरण
- पर्यावरण नीति
- सरकारी और गैर सरकारी निकाय
- जानकारी के सिस्टम
- प्रकृति संरक्षण
- शोध।

इस विषय क्षेत्र से संबंधित रोजगार संरचना में प्रकृति संरक्षण अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र प्रबंधक और पर्यावरण जैसे नए करियर क्षेत्र उभर रहे हैं।

हम अपने पर्यावरण को संतुलित रखना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर नए संस्कारों के निर्माण की परम आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति का आधार निष्काम कर्म एवं स्थित प्रज्ञता के आदर्श स्थापित करना है। प्रदूषण फैलने का मुख्य कारण औद्योगिकरण व प्रौोगिकी नहीं, बल्कि दूषित मानसिकता ही है जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से निकली है। आज बड़े—बड़े विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों की स्थापना तो हो गई है, परंतु इनके विस्तृत भवनों के निर्माण मात्र से मस्तिष्क के भाव तो नहीं बदल जाएंगे। आज वास्तव में मानव के मस्तिष्क के भाव सिकुड़ गए हैं। भौतिक सुख पाने के लिए भीतरी चरित्र की बलि चढ़ा दी गई है। असली शिक्षा वह है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात सोचे और ऐसी शिक्षा की जड़े भारत की परिपाटी में निहित है। हमें समय—समय पर इस तथ्य पर गहरी दृष्टि रखनी चाहिए कि निर्धारित संतुलन की सुरक्षा हो पाई है या नहीं और पर्यावरण संतुलन करने हेतु निवेश किए गए धन की पुर्नप्राप्ति का अनुपात क्या रहा है। यदि इसमें कुछ और सुविधा हो रही है तो समझना चाहिए कि संरक्षण हेतु किए गए प्रयास की पूर्ति नहीं हो पाई है। अत: निर्धारित प्रक्रिया की गंभीरता से छानबीन करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ —

१. पर्यावरण शिक्षा, हरिश्चंद्र व्यास, विद्या विहार नई दिल्ली

2- https:@@www-igi&global-com@

3- https:@@anuvadasampada-azimpremjiuniversity-edu-in@

❑❑❑

26

शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

डॉ. भालचन्द्र भाटे
क्रीडा अधिकारी,
शास. कन्या महाविद्यालय, खरगोन

****

शारीरिक शिक्षा वर्तमान में व्यावसायीकता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। कुछ समय पूर्व इस व्यवसाय की ओर बड़ी गौण नजरिये से देखा जाता था, परंतु आज कई ऐसे उदाहरण समाज में है, जिनकी वजह से अब न केवल बालक–बालिका अपितु उनके पालक भी उन्हें इस क्षेत्र में जाने हेतु प्रोत्साहित करते है। इसके पूर्व, की हम इस क्षेत्र की व्यावसायिकता के बारे में चर्चा करें, हमे इस विषय को समझना जरूरी है।

क्या है शारीरिक शिक्षा –

आज की नई शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है कि एक अच्छा मनुष्य वही है जो शारीरिक दुष्टिकोण से बलवान, सक्रीय, मानसिक दृष्टिकोण से तीव्र, संवेगात्मक नजरिये से संतुलित, बौद्धिक रूप से प्रखर, सामाजिक रूप से सुव्यवस्थित हो। शिक्षा क्षेत्र का अभिनव खोज कार्य एवं उपकरणों में भी यह कई बार अनेक विश्लेषणों, नये अविष्कारों, उपकरणों के संशोधित अविष्कारों के बावजूद इस तथ्य को स्वीकार करने पर मजबुर किया है कि मानव को एक सुनियोजित खेल अथवा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम भी आवश्यक है। ओक्टीक्युफर का कथन है, कि ''शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया (शारीरिक आन्दोलन) से प्राप्त होते है।'' परंतु यहाँ मनुष्य की सामाजिक एवं शिक्षा को लेकर चिंतन नजर नही आने से विचारकों ने इस नजरिये से अपने अध्ययन को ओर स्पष्टता देने की कोशिश की तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसमें चार्ल्स बुचर द्वारा कथित परिभाषा अधिक स्पष्ट है। वे लिखते है, ''शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध को एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय, उन शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, संवोगात्मक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है।'' इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम विचार करें तो, हम यह कह सकते है कि शारीरिक शिक्षा १) शारीरिक शक्तियों, सामर्थो तथा स्वास्थ्य की पुष्टि एवं संरक्षण के सहारे मानव शरीर की वृद्धि एवं विकास को उचित दिशा और पूर्णता प्रदान करने वाला विषय है। २) अपनी गतिविधियों के आयोजन संचलन में सामुहिकता के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करने वाला विषय है तथा ३) व्यक्ति के जीवन के आर्थिक पक्ष को समृद्ध बनाने के नजरिये से कई प्रकार के कार्यक्षेत्रों को उद्घाटित करने वाला विषय है।

अब हम बात करते है खेलों की खेल एक मनोरंजनात्मक तथा शरीर को स्वस्थ रखने वाली प्रक्रिया माना जाता है। वास्तव में खेलों को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में खेल एक शारीरिक या मानसिक गतिविधि है जिसे लोग आनंद के लिये उपयोग में लेते है। जबकि खेलों में शारीरिक परिश्रम एवं कौशल का प्राथमिक महत्व होता है। खेलों में सामाजिक भागीदारी के साथ–साथ एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निहित होती है। खेलों में सामाजिक संबंध बनाने का लक्ष्य होता है जिसमें परंपरा, आनंद के साथ परिक्षेत्र का ज्ञान तथा विज्ञान का अध्ययन मनोरंजनात्मक तरीके से व्यक्ति को करवाया जाता है। इसके उपरांत खेलों के लाभ देखा जाय तो इसमें स्वास्थ्य लाभ होता है। जरूरी नही हर कदम मौद्रिक लाभ हो। इससे जीवन कौशल का विकास होता है। जो मुश्किल एवं विपरित परिस्थिति में भी जीवन को जीने की कला सिखाता है। खेल सामान्यत: अन्वेशषणात्मक, संरचनात्मक, काल्पनिक एवं नियमबद्ध प्रकार के होते है। खेलों में सांस्कृतिक विभिन्नताऐं तथा सामाजिक कौशलों का विकास भी शामिल होता है।

खेल मनोरंजन एवं शरीर को स्वस्थ रखने का

एक उत्तम माध्यम है। खेल से व्यक्ति न केवल शारीरिक अपितु बौद्धिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्राप्त करता है। वर्तमान समय में खेल बडा आर्थिक उपार्जन का विकल्प है। जो न केवल मैदान में केवल एक खिलाडी के रूप में अपितु अन्य कई विकल्पों में उपलब्ध है। आज का हमारा विषय भी ''कौशल्य विकास और रोजगार के अवसर'' दिया है, जिसमें खेल एवं शारीरिक शिक्षा भी एक आयाम हो सकता है।

किसी भी खेल में उसके कौशलों का सामान्य ज्ञान के साथ—साथ उच्च स्तरीय कौशलों का ज्ञान प्राप्त करना एक खिलाडी का कर्त्तव्य भी है और उसका अपनी क्षमता के आधार पर अधिकार भी है। खेल कौशलों में निपुणता अभ्यास से ही आ सकती है। केवल उन्हें जानकार या सुनकर या देखकर प्राप्त करना असंभव है। यदि आप कौशलों में पारंगत है तो वर्तमान समय में एक खिलाडी के रूप में भी आप रोजगार पाने के हकदार है जैसे सचिन तेंदुलकर, महेन्द्र सिंह धोनी, साईना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पुलेला गोपीचंद आदि।

हम बात करते है खेल से रोजगार की —

१. खिलाडी के रूप में कौशल के आधार पर विभिन्न संस्थाऐं बतौर खिलाडी आपका चयन करती है। १) वर्तमान में आई.पी.एल. टी—२० लीग, प्रो कबड्डी, बेडमिंटन लीग, खो—खो लीग इत्यादि। यहाँ खिलाडियों की निलामी होती है तथा उस सीजन में वह अपने प्रदर्शन को अपनी मालिकाना टीम के साथ खेलकर निलामी के पैसे प्राप्त करते है। ऐसे अनेक खिलाडी है जो वर्तमान में केवल क्रिकेट, कबड्डी, खो—खो, बेडमिंटन आदि खेलों के सहारे अपना जीवन व्यतित करते है। यह निलामी लाखे से लेकर करोड तक की होती है।

२. व्यावसायिक खिलाडी —

क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, खो—खो, कबड्डी, हॉकी, बेडमिंटन, लानटेनिस, बाक्सिंग, रेसलींग, बास्केटबॉल, बेसबॉल, मोटर स्पोर्ट्स इत्यादि खेलों की इनामी राशियों की स्पधाओं में सम्पूर्ण वर्ष खेलते रहना अन्य किसी संस्था या स्वयं के व्यवस्थापन में इसी की आमदनी को अपनी आजीविका बनाना। जैसे — विबंलडन, आस्ट्रेलियन कप, (लॉन टेनिस में) बास्केटबॉल में (लिकर्स क्लब), फुटबॉल में (रियल मेड्रिक क्लब की ओर से खेलना)।

३. विभिन्न शासकीय/अर्धशासकीय/अ—शासकीय प्रबंध भी खिलाडियों को अपने प्रतिष्ठानों में चयनित या मनोनित करते है जैसे रेलवे, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, बिजजी कंपनीया, ओ.एन.जी.सी., रियायन्स, एल.आई.सी., पुलिस, सेना इत्यादि जहाँ खिलाडियों को चयन उपरांत खेल अभ्यास करना होता है तथा उस प्रतिष्ठान के माध्यम से खेलना होना है। जहाँ उन्हें एक रेंक वेतन मिलता है तथा राष्ट्रीय — अंतर्राष्ट्रिय स्पध ाओं में सहभागिता या पदक उपरांत अच्छे प्रमोशन दिये जाते है तथा एक उम्र पश्चात् प्रतिष्ठान के उच्च पद एवं उसके आगे बतौर कर्मचारी शामिल किया जाता है।

खेलों में रोजगार के अवसर —

१. सर्विसेस — भारतीय सेना के तीनों अंगों में थलसेना, वायुसेना, जलसेना खिलाडियों की विशेष रूप से भर्ती की जाती है। यह भर्ती आमतौर पर सामान्य से अलग होती है। इस में राष्ट्रिय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाडियों को आमंत्रित किया जाता है। उम्र के १७—१८ साल की आयु में ही खिलाडी अपनी कौशल दक्षता के कारण चयनित हो जाता है। इस शार्ट टर्म कमीशन कहते है। खिलाडी पूर्ण वर्ष भर अनिवार्य परेड एवं समारोह छोड़कर अपनी सेवा के दैनिक समय में खेल अभ्यास हेतु मैदान पर रहता है तथा उसी कार्यक्रम के अनुसार उसके आहार—अध्ययन विश्राम की दिनचर्या तय होती है। वह अपनी उस शाखा के लिए खेलता है जैसे वह जिस सेना में भर्ती है उसकी सर्वोच्च स्पर्धा स्तर पर चयनित होने के पश्चात् वह सर्विसेस की टीम से भारत के सिनीयर नेशनल एवं/या नेशनल गेम्स (जो भारतीय ओलंपिक संघ के तत्वावधान में आयोजित होती है) में सहभागिता कर अपने दल को चैंपियन बनाने की कोशीश करता है तथा वहीं से राष्ट्रिय दल में स्थान पाकर भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर देश का गौरव बढ़ाता है। इस हेतु सेना में जिस पद पर उसे भर्ती किया है उस पद का मासिक

वेतन समस्त भत्तों सहित उसे प्राप्त होता है। सर्विसेस में निम्नांकित प्रकार शामिल है — थलसेना, जलसेना, वायुसेना, सी.आर.पी.एफ., एस.एस.बी. (सीमा सुरक्षा बल), बी.एस.एफ. (बोर्डर सिक्युरीटी फोर्स), स्पेशल टॉस्क फोर्स, कमांडो, पेरा ग्लाईडिंग, इण्डो तीब्बत पुलिस के अलावा समस्त राज्य पुलिस सेवाऐं भी इन्हीं का हिस्सा होती है जैसे आई.पी.एस., आर.पी.एफ., जी.आर.पी., स्टेट पुलिस बल, आपदा प्रबंधन फोर्स इत्यादि।

२. रेलवे — भारतीय रेल भी खिलाडियों के लिये एक बहुत बड़ी सेवा अवसर प्रदाता है। रेलवे भी छात्र—छात्राओं को उनके जुनियर नेशनल या राष्ट्रीय शालेय खेलों के कौशल प्रवर्धन के आधार पर अपनी सेवाओं में सीधे भर्ती करता है। रेलवे में भी खिलाडी अपने कर्त्तव्य के समय को अभ्यास समय बनाना होता है। रेलवे प्रशिक्षक आमतौर पर खिलाडियों को अभ्यास के समय कठीन एवं अधिक से अधिक अभ्यास करवते है। भारत में कई रेल डिविजनों के अपने खेल संकुल भी है। यहॉ अभ्यासरत रहकर खिलाडी अपने पद का वेतन प्रतिमाह पाता है। जब भी एसे कोई खिलाडी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करते है तो रेल संगठन उन्हें पदोन्ती प्रदान करती है। साथ ही महत्वपूर्ण विश्व चैंपियन शीप, कॉमनवेल्थ, एशियन या ओलंपिंक गेम्स में पदक पाने पर सुविधाओं भत्तों की भी प्रेरणा प्रोत्साहन प्रदान करती है। खिलाडियों को यहॉ नियमित अपने खेल कौशल को बनाये रखवाया वृद्धिगंत करना होता है।

३. बैंक, एल.आई. सी. एवं तत्सम कंपनीयाँ — बैंक भी अपने भर्ती प्रक्रिया में खिलाडियों को स्थान प्रदान करती है। परंतु बैंक व्यावसायिक सेवा प्रतिष्ठान होने से यहाँ खिलाडी को अपने खेल को खाली समय में अभ्यासरत रखना होता है या संशोधित करना होता है। उसे बैंक समय में अपने स्थान पर बैठकर बैंक कार्य करना होता है। बावजुद इसके यही बैंक की ओर से स्तरीय स्पर्धाओं के पश्चात् खिलाडी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का उच्चतम प्रदर्शन करता है एवं देश के लिए गौरव हासिल करता है तो उसे बैंक नियमों के अनुसार ही प्रमोशन, इन्क्रीमेन्ट या सुविधाऐं प्राप्त होती है।

राज्य शासन के तहत सेवाऐं —

१. क्रीडा अधिकारी — सामान्यत: खेल युवा कल्याण संचालनालय के आधीन यह पोस्ट जिला क्रीडा अधिकारी कहलाती है। खेल में उच्चतम कशतित्व के पश्चात् लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत यह पद शासन की सेवा हेतु खिलाडी को प्राप्त होता है। हालाकि उच्चतम स्तर के खिलाडी होने पर वरिष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) में बोनस अंक शासन द्वारा निर्धारित किये जाते है, जिससे अभ्यास में कमजोर छात्र भी इन सेवाओं में पात्रता हासिल कर अधिकारी बनते है।

२. अधिशिक्षक (कोच) — शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण यही कार्य है तो अधिशिक्षण यानी कोचिंग। एक अच्छे स्तरीय खिलाडी को शासकीय विभाग का किसी मान्यता प्राप्त क्लब या संगठन में अधिशिक्षक का कार्य संपादन करने का मौका मिल सकता है। इस हेतु उसमें खेल के मूलभूत (बेसिक) कौशलों के साथ—साथ उन्हें सीखाने में भी रूचि होना आवश्यक है। अधिशिक्षक बनने के लिए खिलाडी को राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला से डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक है।

इस संस्थान में प्रवेश हेतु निम्न पात्रता आवश्यक है —

१. खिलाडी को कम से कम एक या अधिक बार राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता या पदक प्राप्ति या शालेय अथवा विश्वविद्यालयीन खेलों के तहत झोन या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभाग या पदक

२. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि

३. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास. शिक्षा में स्नातक उपाधि

— वर्तमान में यह डिप्लोमा कोर्स दो वर्ष का हो गया है तथा इस के पूर्ण करने पर खिलाडी किसी भी संगठन या राज्य के खेल युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिला प्रशिक्षक पद पा सकता है।

— यदि खिलाडी को स्वयं के बल पर अकादमी

खोनी हो तब भी वह आत्मनिर्भर होकर खेल की आवश्यकता अनुसार संसाधन स्वयं से, बैंक लोन से प्राप्त कर अपनी आजीविका निर्वाह कर सकता है।

३ प्रशिक्षक(ट्रेनर) – यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु खिलाडी का अपने खेल के कौशलों का बेसिक बहुत अच्छा होना आवश्यक है, इन्हें पढ़ाने की रूचि एवं ज्ञान दोनो आवश्यक हैं। क्योंकि प्रशिक्षक को केवल कौशल बताना या सिखाना नही है अपितु उस हेतु खिलाडी की आवश्यक शारीरिक, मानसिक तैयारी भी करवानी है। उसके बौद्धिक स्तर के आधार पर उसे कौशल समझाना होगा। साथ ही उसके शारीरिक एवं शरीर क्रियात्मक व्यवहार एवं क्षमताओं के साथ उसे वह कौशल पढ़ाना होगा। यदी वह कहीं कमजोर है तो उस कमजोरी को पहचान कर योग्य व्यायाम द्वारा उसे दूर करना होगा। प्रशिक्षक बनने हेतु एक खिलाडी को किसी भी शास. शिक्षा महाविद्यालय से

– बी.पी.ई.एस. (चार वर्षीय स्नातक) उपाधी का प्रशिक्षण लेना होगा। वह इसके पश्चात्

– एम.पी.ईडी. स्नातकोत्तर उपाधी प्रशिक्षण ले सकता है। इसके सहारे वह न केवल विद्यालय अपितु महाविद्यालय तक कार्यक्षेत्र पा सकता है।

लेक्चरर /शिक्षक – इस क्षेत्र में संभावनाऐं सर्वाधिक रहती है। एक खिलाडी अपने खेलों के साथ अन्य खेलों के साथ अन्य खेलों में रूचि रखने वाला हो या अन्य खेलों के साथ नवाचार करने की यदि उसमें इच्छाशक्ति एवं उर्जा हो तो इस क्षेत्र से भी वह अपने आप को साथ ही प्रदेश को गौरवान्वित कर सकता है। इसके लिए खिलाडी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ४ वर्षीय डिग्री कोर्स यानी स्नातक उपाधी हासिल करना होगी। इससे वह अधिकाधिक शिक्षा स्तर तक शारीरिक शिक्षा शिक्षक का कार्य प्राप्त कर सकता है। यदि वह २ वर्षीय या नई शिक्षा नीति के तहत १ वर्षीय स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा की उपाधी प्राप्त करता है तो यह योग्यता उसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में लेक्चरर पद प्राप्त करने हेतु पर्याप्त है।

सामान्य पारंपरिक महाविद्यालयों में क्रीडा अधिकारी अथवा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद पाने हेतु खिलाडी को पी.एच.डी. शारीरिक शिक्षा की पात्रता हासील करना अनिवार्य है।

उपरोक्त शिक्षा के क्षेत्रों के अलावा एक खिलाडी निम्न रूप से अपना व्यावसायिक जीवन कैरियर बना सकता है –

१. अम्पायर/ निर्णायक – खिलाडी को अपने कौशलों के साथ–साथ एक लंबा अनुभव होता है। साथ ही वह हरदम अंपायरिंग यानी निर्णायकों की संगत में रहता है। खेल की सभी बारिकिया तथा कौशलों को प्रदर्शित करने की प्रशक्षिकों द्वारा दी गई सीख के साथ ही व निर्णायकों की भूमीका एवं खेल नियंत्रण अनुभवीत करता है। यदी वह एक अच्छा निर्णायक बनाना चाहे तो उस में भी रोजगार के अवसर शामिल है।

आज विभिन्न खेलों में खेलों की ख्याति एवं स्पर्धा के स्तर तथा आयोजकों को प्राप्त प्रायोजकों के आधार पर निर्णयकों को सुविधा एवं मानधन दोनो प्राप्त होता है। जैसे क्रिकेट में रणजी ट्राफी अंपायर को एक मैच हेतु लगभग ५० से ६० हजार तथा संपूर्ण सत्र के लिये लगभग ३ से ४ लाख रूपये प्राप्त होता है। साथ ही स्पर्धा स्थान (शहर में) स्तरीय आवास व्यवस्था एवं अन्य सभी सुविधाऐं प्राप्त होती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यही राशी प्रति मैच १ लाख से ५ लाख तक होती है तथा उसी स्तर की समस्त सुविधाऐं प्राप्त होती है। एक अम्पायर क्रिकेट में औसतन वर्ष भर में १० लाख से १ करोड तक की राशी बतौर मानधन प्राप्त करता है। वहीं बेडमिंटन लीग, खो–खो, इंडिया लीग, प्रो–कबड्डी, व्यावसायिक कुश्ती, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस, तथा अन्य सभी मान्यता प्रदान खेलों में भी निर्णायक रूप में कार्य करने पर अच्छा सम्मानजनक मानदेय होता है जो हमारी आय में एक आकर्षक बढोतरी करती है।

यही हम व्यावसायिक रूप से किसी खेल के निर्णायक न हो परंतु एक अच्छे खिलाडी के रूप में हम स्थानिय या राष्ट्रीय स्वैच्छिक (एमेच्युर) स्पर्धाओं में निर्णायक पद पर कार्य करते है तब भी हमें निर्णायक मानदेय एवं सम्मान प्राप्त होता है जो हमारे परंपरिक व्यवसाय या नोकरी में एक अन्य आय का स्त्रोत बन जाता है।

कॉमेंन्ट्रेटर (समालोचन) — यह भी आज के समय का एक अच्छा रोजगार है। खिलाडी होने के साथ — साथ हमें खेल के कौशल एवं तकनीकों के साथ — साथ खेल रणनीती का ज्ञान भी इसमें होना जरूरी है। इसके साथ ही हमारी जिस भाषा पर अच्छी पकड हो उसमें समालोचन करना आसान होता है। यदि हम अन्य भाषाओं का ज्ञान एवं शब्दकोश अपनी रूचि अनुसार बढ़ाते है तो हमारे कार्य हेतु हमें अनेक मंच उपलब्ध होते है। यही हम बात करें तो क्रिकेट में सबसे अच्छे कॉमेन्ट्रेटर यदि हिंदी की बात की जाये तो इन्दौर के सुशील दोषी एक विश्वविख्यात नाम है। जिन्हें न केवल भारत अपितु क्रिकेट खेलने वाले हर देश में भारतीय दल के साथ कॉमेन्ट्री (समालोचन) करने हेतु विशेष रूप से सम्मिली किया जाता था। आज यही कॉमेन्ट्री क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो—खो, कबड्डी लगभग सभी खेलों का अनिवार्य अंग बन चुकी है।

शारीरिक शिक्षा से स्वरोजगार —

शारीरिक शिक्षा विषय का अध्यापन करने पर एक खिलाडी/ विद्यार्थी अपनी सुझबुझ के आधार पर स्व—रोजगार के अवसर निकाल लेता है।

जैसे —

१. स्वयं की अकादमी — खिलाडी स्वयं की एक अकादमी आरंभ कर सकता है। इस हेतु विशिष्ट रूप से किसी खेल का ज्ञान होना आवश्यक होने के साथ—साथ यदि उसे सिखाने की पात्रता भी हासिल हो तो अधिक लाभकारी है। इस हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए बैंक से लोन भी प्राप्त हो सकता है। जैसे बाक्सिंग अकादमी, बेडमिंटन या टेबल—टेनिस अकादमी। हॉकी, फुटबॉल एवं क्रिकेट भी अब इसी क्षेत्र में शामिल है। परंतु इस में एवं जिमनास्टिक्स जैसे खेलों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने का व्यय अत्यधिक है, साथ ही सिखने के लिये बैचेस बनाकर सिखाने में यहाँ अत्यधिक खिलाडियों को तैयार किया जा सकता है। भारत में वर्तमान में कई नामी खिलाडियों ने स्वयं की अकादमी आरंभ की है जैसे —

२. पी.टी.उषा — एथलेटिक्स २. पी. गोपीचंद — बेडमिंटन ३. धनराज पिल्लई — हॉकी ४. वी.एन. आनंद — शतरंज ५. सचिन तेदुलकर — क्रिकेट आदि

२. जिम — भारत में वर्तमान में सर्वाधिक रूप से सफल व्यवसाय बन चुका है। युवाओं में ही नही सभी आयु वर्ग के पुरूष महिलाओं में इसका अजीब आकर्षण है। यह व्यवसाय बडे शहरों के साथ छोटे शहरों में भी फलफूल रहा है। शा.शिक्षा के ज्ञान के आधार पर एक खिलाडी इसे आसानी से अपनी सुझबुझ के आधार पर चला सकता है।

३. योग प्रशिक्षण — शारीरिक शिक्षा के अध्ययन का योग यह अभिन्न अंग होने से यदि आपने इस विषय में रूचि एवं अभ्यास किया है या इससे अधिक योग प्रशिक्षक डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की है तो किसी भी शहर, गांव में आप योग प्रशिक्षण की आपकी अकादमी आरंभ कर सकते है। उद्देश्य समाज में शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य बढाना होना चाहिये, आमदनी अपने आप बढती जाती है। नित्य नये उपायों, सुधारों एवं तकनीकी जानकारियों के साथ प्रशिक्षुओं को सिखाने के साथ अपनी अकादमी को व्यापक रूप देकर उसका विकास करके आप प्रतिष्ठित योग प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ कर स्वयं को एक ब्राण्ड स्थापित कर सकते हो।

४. खेल सामग्री उत्पादक — आप अच्छे अविष्कारक है या खेल सामग्री कंपनी के माध्यम से उत्पादक के स्वरूप अपने ज्ञान के आधार पर खेल कौशलों को नियमों के अन्तर्गत आसान बनाने, शरीर पर पडने वाले अतिरिक्त बोझ को हल्का करने एवं शारीरिक शक्ति का पूर्ण रूपेण फायदा प्रदान करने वाले उपकरण निर्मित करते है, कौशलों के सहायक व्यायाम हेतु उपकरण उत्पादित करते है तो खेलों को एवं खिलाडियों हेतु आप महत्वपूर्ण है। इससे आपकी आमदनी एवं खेल सेवा दोनो प्राप्त होती है।

५. खेल आयोजक — कई शारीरिक शिक्षा प्राप्त छात्र—छात्रा उपाधी के पश्चात् अपनी रूचि के आधार पर मैनजमेंट कोर्स कर उसके ज्ञान की संगत से या अपनी नैसर्गिक व्यवस्थापन ज्ञान रूचि से खेलों की स्पर्धाओं के आयोजक बनते है। वह खेल के प्रत्येक अंग का ज्ञान रखते है। अत: बतौर आयोजक, आवास

व्यवस्था, समारोह की सुसज्जता, खिलाडियों के आहार, मैदान खेल हेतु आवश्यक सतह एवं मटेरियल के साथ निर्माण, बैठक व्यवस्था, विद्युत सज्जा इत्यादी प्रत्येक इकाई का ज्ञान लेकर वह हर हिस्से से अपने आप को निखारता है एवं सफल इवेन्ट मैनेजर बनता है।

शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में — सफल व्यवसायिक बनने हेतु निजी कौशलों को हमेशा साथ बनाये रखे —

१. शा.शिक्षा में रूचि — सभी खेलों में रूचि रखकर उनके कौशल उनमें आवश्यक शारीरिक क्षमताऐं एवं मूलभूत आवश्यक कौशलों का गहराई से अध्ययन करने की रूचि एवं सिखाने में आनंद प्राप्त करने की इच्छा सदैव जागृत रखना चाहिए।

२. अच्छा व्यक्तित्व एवं अच्छा स्वास्थ्य — यदि आप शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको स्वयं को स्वस्थ रखना आवश्यक है। साथ ही अपने बोलचाल, भाषा शैली, वकृत्व इन पर भी अच्छा नियंत्रण एवं प्रभाव रखना आवश्यक है।

३. परिपक्वता — शा. शिक्षा के पेशे में व्यक्ति को हमेशा परिपक्वता के साथ अपने विचारों को रखना होता है। साथ ही किसी घटना, प्रकृति, स्वभाव या स्थिति को समझने एवं उस अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करना होता है। यानी केवल शरीर से ही नही अपितु दिमाग से भी स्वस्थ्य होना आवश्यक है।

४. अच्छा खेल प्रदर्शन — जिस खेल का अकादमी हम आरंभ करने जा रहे है उस खेल मे हमारा अनुभव हमारे व्यक्तव्य एवं कशतियों में दिखाई देना आवश्यक है। साथ ही कुछ मूलभूत, उच्च स्तरीय कौशल्य हमें हमारे प्रशिक्षण या प्रदर्शन के समय प्रदर्शित करना चाहिये जिससे सिखने वाले एवं आकर्षित छात्र दोनो विश्वास कर सके एवं आपका प्रतिवर्ष अकादमी में नये छात्र मिल सके।

५. नेतृत्व क्षमता — शारीरिक शिक्षा अध्ययन से हमारे नेतृत्व के गुणों में निखार आता है। परंतु इसका वास्तविक उपयोग हमें हमारे प्रशिक्षण संस्थान में करते आना आवश्यक है। न केवल नेतृत्व यानी आगे रहने की कला अपितु स्पर्धात्मक नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य संपादन भी इसी में शामिल होना चाहिये जिससे आपके प्रति विश्वास जागृत रहे।

६. आयोजन क्षमता — व्यक्ति को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आयोजन क्षमता बढाने का मौका मिलता है। एक प्रशिक्षक, शा. शिक्षा, अधिशिक्षक में स्पर्धा या खेल समारोह के आयोजन भी क्षमता होना आवश्यक है। खेल के मैदान एवं बारही प्रशासन तथा व्यवस्थापन के पहलूओं से वो जानकार होना चाहिये तभी आयोजन क्षमता में निखार आ सकता है।

७. समर्पण — शा. शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक, अधि. शिक्षक का खेल के समस्त पहलू के प्रति एवं समता स्तरों पर समर्पण का होना आवश्यक है, यही उसकी पहचान एवं सफलता का मंत्र है। वह व्यवहारिक हो परंतु उतना ही सभी स्तरों पर विनम्र एवं गहरी जानकारी रखने वाला होना चाहिये।

८. खिलाडी भावना — खिलाडी भावना यह मनुष्य का स्वभाव होना आवश्यक है। एक प्रशिक्षक, अधिशिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक में यह अति उच्च स्तरीय होना अनिवार्य है। यह क्षमता हर समय जैसे अनुशासन बनाये रखना, प्रामाणिकता, संघ कार्य या संगठित कार्यो के समय आत्मविश्वास, मैत्री, विश्वसनियता एवं नैतिकता के गुणों के साथ विकसित करना आवश्यक है।

९. आहार एवं शाररिक मुद्रा — शारीरिक आकार स्थिति — देह बोली का ज्ञान — इसे हम आहार एवं देह बोली का ज्ञान होना भी कह सकते है। क्योंकि यही शा.शिक्षा शिक्षक को खेल के हर क्षण पर आवश्यक शरीर स्थिति का ज्ञान नही है तो वह अपना प्रशिक्षण दे नही पायेगा और वह प्रभावी भी नही होगा।

हर समय बॉल की शुटींग एवं पिस्तोल की शुटिंग से शरीर की मुद्रा का ध्यान रखना वह सही होना अनिवार्य है अन्यथा हमारा कृतित्व (परफारमेन्स) अच्छा हो नही सकता। हमेशा खेल के कौशलों को सिखने के समय सिखाते समय शरीर की उस कौशल हेतु अवाश्यक मुद्रा का अभ्यास होना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक खेल हेतु आवश्यक आहार भी अनिवार्यता एवं नियमन दोनो का ज्ञान शिक्षक, प्रशिक्षण, उपधिशिक्षक तीनों को होना अनिवार्य है। इनकी कमी

एवं अधिकता तथा अन्य प्रभावों का भी ज्ञान होना आवश्यक है।

१०. खेल चिकित्सा एवं खेल व्यायामों का ज्ञान — खेल व्यायाम यानी सभी खेलों में अपने कौशल बढाने हेतु विशिष्ट व्यायाम वृद्धिगत किये गये है। शारीरिक क्षमता बढाने के साथ — साथ यह व्यायाम शारीरिक स्थिति — मुद्रा को भी कौशल के सम्पर्क बनाते है जिससे वह कौशल आसानी से शिघ्र एवं सही सीखाजा सके। साथ ही जहाँ खेल शारीरिक क्रियाऐं है वहॉ चोट का खतरा बना रहता है। अत: उन चोटो से उबरने या उनकी गंभीरता को समझने हेतु शिक्षक, प्रशिक्षक, अधिशिक्षक तीनों को क्रीडा चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है। यही नही प्रारंभिक अवस्था में हार्टरेट, पल्सरेट एवं ब्लड प्रेशर को परिक्षित करने का ज्ञान होना आवश्यक है। जिससे प्रशिक्षण भार को वह सही तरीके से कम या ज्यादा करने के बारे में निर्णय ले सके। साथ ही खेलों के दौरान होने वाली मोच, इत्यादी चोटों का सही प्रशिक्षण कर चिकित्सक को जानकारी दे सके। क्रीडा चिकित्सक के ज्ञान से वह अपने प्रशिक्षुओं की कुछ शारीरिक विकृतियों को भी ठीक कर सकते है जैसे नॉकनीज, बॉनीज, फ्लेट फुट आदि।

११. शरीर यंत्रणा का ज्ञान — शारीरिक शिक्षा क्षेत्र के व्यवसाय में सभी क्षेत्रों में मनुष्य की शरीर यंत्रणाओं का अभ्यास होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान खिलाडी की हलचलों से ज्ञात होता है कि उसें कहाँ क्या परेशानी है? उसे अस्थितंत्र के ज्ञान से उसकी शरीर की उपयोगिता किस खेल में ज्यादा हो सकती है यह जानकारी प्राप्त होने से वह खिलाडियों को खेल में रूचि के साथ — साथ सही खेल के चयन में मदद कर सकता है। दिसादर्शन भी एक कौशल है। जो शिक्षक,/प्रशिक्षक के पास होना चाहिये।

१२. शिक्षण संस्थाओं का ज्ञान —शारीरिक शिक्षा शिक्षक तथा खेल प्रशिक्षक/अधिशिक्षक को अपने आसपास की तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। यह उसका दुरागामी कौशल्य है। इस के उपयोग से वह खिलाडी को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के साथ — साथ भिन्न—भिन्न स्थान, परिस्थिति, वातावरण में स्वयं को ढालने एवं खेल कौशल निखारने का मौका देता है जिससे खिलाडी का आत्मविश्वास बढता है।

१३. विजेताओं से संवाद — शिक्षक, प्रशिक्षकों को अपने खिलाडियों को अन्य विजेताओं या उपलब्धि प्राप्त खिलाडियों से मिलवाना चाहिये। वे उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन करेंगे साथ ही खिलाडियों को अपनी कमजोरीयों का वह ज्ञान जो प्रशिक्षक के साथ रहते नही होता वह पूर्व से ही मिल जाता है। वहीं वह अपने आदर्श खिलाडियों के प्रोत्साहन से और अधिक रूचि एवं समर्पण बढाकर प्रशिक्षण को ग्राहित करता है।

इस तरह शारीरिक शिक्षा यह केवल अध्ययन का विषय न होकर एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम हे जिसके ज्ञान के आधार पर हम हमारे छात्र — छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ स्वयं के बल पर अपना भविष्य संवारने के लिये अग्रसर करते है।

संदर्भ सूची —

१. कमलेश एवं सांगरल, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत तथा इतिहास, टंडन पब्लिकेशन, लुधियाना (पंजाब)

२. कुंद्रा संजय टेल्स्ट — बुक ऑफ फिजिकल एज्युकेशन, (कक्षा ११ वी के लिये) सी.बी.एस.सी., एव्हरग्रीन पब्लिकेशन (इंडिया) लिमिटैड, न्युदेहली

३. वर्मा वी. पी. एण्ड वर्मा वी.के., हेल्थ एन फिजीकल एज्युकेशन (फोर क्लास १२ वीं) सरस्वती हाउस प्राइवेट लिमिटेड, न्यु देहली — ०२

४. व्यास शशि शेखर एवं व्यास राजशेखर, शारीरिक शिक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर — २

❑❑❑

27

स्वयं सहायता समूहों कि कौशल विकास एवं रोजगार निमार्ण में भूमिका

किरण नागराज (वानखेडे)
पीएच. डी. शोधार्थी, (समाजशास्त्र)
मानसरोवर ग्लोबल युनिवर्सिटी, सिहोर (म.प्र.)

****

शब्द कुंजी :— स्वरोजगार, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूह, पीएमकेवीवाई, हाउॅसजॉब

''स्वयं सहायता समूह अब राष्ट्र सहायता समूह बन चूके है। कौशल विकास एवं रोजगार निमार्ण में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।''

अपने एक उद्यभोदन में प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को ''राष्ट्र सहायता समूह'' कहकर संबोधित किया था। उसमें तनीक मात्र भी अतिस्योक्ति नहीं है। भारत के संदर्भ में विशेष तौर पर बात की जाय तो वर्तमान के हर राज्य, क्षैत्र एवं स्थान पर महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपना लौहा मनवाया है। वह ना केवल स्वयं का विकास कर रही है, बल्कि जीवन की हर कठीन घडी में सरकार की एवं अपने प्रांत की ढाल बनकर खडी है। बात चाहे कोविड—१९ की हो या भारतीय जीडीपी की यह किसी भी रूप में पीछे नहीं है। हर क्षैत्र की स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एवं उन्य आवश्यक मूद्दों पर अपना परचम लहरा रही है। माध्यम चाहे 'पीमकवीवाई' हो या शासन की अन्य रोजगार निर्माण व कौशल विकास संबंधी योजनाऐं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इनका बहुत हद तक सफल क्रियान्वयन हो रहा है। और इसी तरह देश उन्नती व प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है।

प्रस्तावना :—

पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संदर्भ में देखा जाय तो प्रतिवर्ष लगभग १३ मिलियन से भी ज्यादा लोग काम करने वाली उम्र में प्रवेश करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों जैसे— स्नातक कॉलेजों, प्रोफेशनल कॉलेजों, पौलिटेक्निक कॉलेजों, आईआईटीस एवं अन्य स्थानों से लगभग ३ मिलियन युवा प्रशिक्षित होते है। इनके प्रशिक्षण में लगभग ३ से ५ वर्ष का समय लगता है। इस गति के कौशल विकास को बढाना अपने आप में एक चुनौति भरा काम है।

उपरोक्त चुनौति को मद्देनज़र रखते हुए ही भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन भी किया। जिसने कौशल विकास को नई गति प्रदान की है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में कौशल विकास पर आधारित योग्यताओं को नई दिशा एवं रफ्तार देना था। इस कार्य में स्वय सहायता समूहों की अहम भूमिका रही है।

स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में बात की जाय तो, यह १०—१५ या इससे अधिक महिलाओं, बालिकाओं या सहायक सदस्यों का एक समूह होता है जो अपनी उन्नती और प्रगति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाऐं न केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यवसायीक रूप से सबल बनती है, बल्कि वह आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन जाती है। महिलाऐं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कौशल विकास में प्रशिक्षित महिलाऐं अपने समूहों के माध्यम से अपने ज्ञान एवं कौशल का सही समय एवं स्थान पर इस्तेमाल करके एवं स्वरोजगार के नवीन अवसरों को समाज के हर अंग तक पहूचाकर उन्नति एवं विकास की ओ निरन्तर आगे बढ रहीं है।

उद्देश्य :—

शोधार्थी के आलेख का उद्देश्य, कौशल विकास एवं स्वरोजगार निर्माण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करना है।

परिकल्पना:— शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत आलेख से पाठकों में यह रूझान बढेगा कि किस तरह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम भारत में कौशल विकास एवं स्वरोजगार निर्माण में एक गति मिल रही है और

किस तरह इस गति को और अधिक बढाया जा सकता है।

शोध प्रविधियॉः—शोधार्थी ने अपने आलेख के लिए प्राथमिक तथ्य संकलन विधि एवं द्वितीयक तथ्य संकलन विधि, इन दोनो प्रकार की प्रविधियों का इस्तेमाल किया। प्राथमिक आकडों के लिए मैने देव निदर्शन विधि के माध्यम से बडवानी जिले के कुछ स्वयं सहायता समूहों का चुनाव किया और उनसे साक्षत्कार, अवलोकन, प्रश्नावली एवं अनुसूची के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर आकडे एकत्र किए। इसके साथ ही द्वितीयक स्त्रोतों में शासकीय कार्योलयों की पत्रिकाऐं, लिखित किताबों, समाचार पत्रों, सरकारी वेबसाईट्स का पढन एवं महान विचारकों द्वारा लिखित लेखों का गहनता से अध्ययन कर तद्उपरान्त अपने आलेख की स्वयं रचना की।

आलेख का मुख्य भागः— किसी भी देश का विकास एवं प्रगति का एक प्रमुख व सशक्त माध यम वहॉ के निवासियों का कौशल और रोजगार की शैली ही होता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने १५ जुलाई २०१५ को ‘विश्व युवा कौशल दिवस‘‘ के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ‘‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना‘‘ (पीएमकेवीवाई) की शुरूवात की

१. स्वयं सहायता समूह का संक्षिप्त परिचयः— यह एक एसा समूह होता है जो अपनी विशेष आवश्यकताओं के चलते संगठीत किया जाता है। महिलाऐं विशेष तौर पर इन समूहों की सदस्य होती है। विशेष तौर पर यह ग्रामीण क्षैत्रों में देखे जाते हैं। शहरों में यह किट्टी पार्टिज़ या बीसी समूहों के नाम से जाने जाते हैं, जो अधिकांशत: आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संचालित होते हैं। जबकी ग्रामिण क्षैत्रों में यह समूह आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, राजनितिक, व्यवसायीक एवं आद्यौगिक कार्यो हेतु संचालित किए जाते हैं।

२. कौशल विकासः— वह अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति में कौशल या कार्य की दक्षताओं को बढ़ाने व सुधारने की प्रक्रिया शामिल होती है। व्यक्तिगत ज्ञान एवं व्यवसायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए किसी खास क्षैत्र में ज्ञान, क्षमता विकास, विशेषज्ञता और क्षमता हासिल करना शामिल होता है। कौशल विकास का उच्च स्तर ही व्यक्ति के विकास को सवोच्च उपलब्धि प्रदान करने में मदद करता है एवं यही देश के विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है। भारत सरकार ने कौशल विकास की प्राप्ति के लिए, ‘‘कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) का गठन किया। इस मंत्रालय का प्रमुख उदुदेश्य पूरे देश में कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर समाप्त करना एवं कौशल विकास के प्रयासों को समन्वित करना है। समाजशास्त्रीय द्रष्टिकोण से कौशल विकास प्रमुख रूप से तीन स्तरें पर काम करता है। प्रथम स्तर, तकनीकी कौशल का विकास करना। द्वितीय स्तर, सॉफ्ट कौशल का विकास और तृतीय स्तर, जनता के नेतृत्व कौशल का विकास करना।

३. स्वरोजगार से जूडी धारणाऐं :— स्वरोजगार वह अवस्था हे जहॉ व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह किसी के आधिन नोकरी या रोजगार न करते हुए अपने स्वयं के लिए स्वयं का रोज गार करने के लिए तत्पर होते हैं। एसी अवस्था में वह किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप से किसी के आधिन न रहकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी पर निर्भर अवश्य रह सकते हैं। साथ ही अगर बडा उद्यम हुआ तो वह दूसरे लोगों को रोजगार मूहैय्या करवा सकते हैं।

४. स्वयं सहायता समूह किस तरह से कौशल विकास एवं स्वरोजगार निमार्ण में सहायक हो सकते हैं ? :—उक्त विषय पर गौर किया जाय तो हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह, राष्ट्र सहायता समूहों का दर्जा ले चुके हैं। विकास से जुडे हर क्षैत्र में स्वयं सहायता समूहों ने अपना परचम लहराया है। इस अवधारणा को हम निम्न बिन्दूओं के माध्यम से समझ सकते हैं:—

१. समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो संगठन की शक्ति ही सर्वोपरी है। अत: स्वयं सहायता समूह अपने संगठनों के माध्यम से अपने कौशल और विशेषज्ञता को अन्य सदस्यों के साथ आसानी से साझा कर सकते हैं। और इसी तरह अपनी शक्ति एवं कौशल को कई गुणा अधिक इस्तेमाल करके स्वयं के एवं राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

२. भारत सरकार का उपक्रम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी) के द्वारा सन १९५५ से लघु उद्यम के विकास की सुविधा दी जा रही है। जिससें प्रत्येक वर्ष हजारों महिलाओं को अलग—अलग कौशल एवं स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कौशल को व नवीन स्वरोजगार की तकनीकों को प्रशिक्षित महिलाऐं अपने समूहों के साथ साझा कर सकती है। और इसी तरह इन चंद महिलाओं का कौशल और विशेषज्ञता हजारों, लाखों महिलाओं एवं उनके परिवारों के लिए कौशल विकास एवं स्वरोजगार निर्माण का साधन बन सकता है।

३. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं में प्राचिन समय से चली आ रही रूढीवादी सौच का उन्मूलन संभव हो सकता है। जिसका लाभ सिधे तौर पर स्वयं महिलाओं को, उनके परिवारों को एवं सम्पूर्ण समाज को मिल सकता है।

४. स्वयं सहायता समूहों से जुडी महिलाओं के परिवारों के अन्य सदस्य भी उनके द्वारा सिखे गये कौशल और स्वरोजगार की नवीन तकनीकों का सहारा लेकर स्वयं भी अपना रोजगार या जिविकोपार्जन का साधन जुटाने में काफी हद तक प्रेरित एवं लाभान्वित हो सकते हैं। इसी तरह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बेरोजगारी को कुछ हद तक कम करने में सहायता मिल सकती और इसी तरह परीवार, क्षैत्र, राज्य और देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है।

५. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भता आ जाती है। वह अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, एवं स्वयं के भविष्य से जूडे मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने लगती है। और इसी तरह काफी हद तक महिलाओं से जूडे अपराधों व निर्योग्यताओं को कम करने में सहायता मिलती हैं ।

६. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपने कौशल विकास एवं स्वरोजगार से जूडी विशषज्ञताओं को काफी हद तक अपने सम्पूर्ण क्षैत्र एवं राष्ट्र के कौशल विकास एवं स्वरोजगार निर्माण का आधार स्तंभ बनाया जा सकता है।

७. महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुडकर घर की चार दिवारी से बाहर निकलने का मौका मिलता है। इसी तरह वह अनेक संस्कृतियों व धार्मिक मान्यताओं वाले परिधान में एक साथ मिलकर कार्य करने से एक दूसरे को समझ पाने एवं किसी भी प्रकार के निर्णय में अपनी अहम भागीदारी निभा पाने में सबलता आती है। अत: इससे समाज में रूढ़ीवादिता खत्म होती है। साथ ही मानवता एवं सर्वधर्मसमभाव का उदय होता है।

८. महिलाऐं समूहों के माध्यम से छोटी—छोटी बचत प्रवृत्ति एवं स्वरोजगार के साथ हर तरह से आत्मनिर्भर बन रही है। जो महिला सशक्तिकरण के लिए एवं राष्ट्र के विकास के लिए शुभ संदेश है।

९. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाऐं जब एक—दूसरे के सम्पर्क में आकर अपने ज्ञान एवं अनुभवों को साझा करती है तो उनमें हर तरह से जागरूकता एवं सशक्तता का संचार होता है। जो राष्ट्र की उन्नति एवं विकास का आधार बन सकता है।

१०. स्वयं सहायकता समूहों के माध्यम से महिलाऐं जिवन के हर क्षैत्र में आगे बढते हुए अपने नाम का लौहा मनवा रही है। इसी तरह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में विकास की एक नवीन चेतना, व्यक्तित्व विकास एवं सशक्तिकरण की ओर सफलता का परचम लहरा रही है।

निष्कर्ष :—

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिकता की इस दौड में एवं वर्तमान समय की मॉग व आवश्यकताओं के आधार पर महिलाओं के साथ—साथ समाज के हर अंग का सशक्त होना नितान्त आवश्यक है। किसी भी देश या राष्ट्र का विकास उसके निवासियों के कौशल विकास, सबल व्यक्तित्व एवं योग्यता अनुसार काम एवं स्वस्थ्य जीवन पर निर्भर करता है। इन सब में महिला स्वयं सहायता समूह हर तरह से सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बात चाहे घर परिवार की हो या राष्ट्र के विकास की महिलाओं की भागिदारी अहम होती है। और इस बात को आज स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाऐं सत्य साबित कर चूकी है। किन्तु पूर्ण सफलता आज भी शेष है। आज भी अनेक ऐसे क्षैत्र है जहॉ महिलाऐं अपनी योग्यता, शक्ति एवं कौशल का सही अर्थ में इस्तेमाल नहीं कर पा रहीं है। इनके मार्ग मे आज भी रूढीवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव एवं संकिर्ण मानसिकता बाधक बन रही है। जिसका उन्मूलन कर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कौशल विकास एवं स्वरोजगार निर्माण के मार्ग प्रसस्त करते हुए समाज को एवं राष्ट्र को विकास

की तेज रफ्तार मिल सकती है।

सुझाव:—

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागिदारी, समाज में कौशल विकास एवं स्वरोजगार निर्माण लिए एक क्रान्तिकारी परिवर्तन का सबल आधार बने हैं। इसके अपवाद रूप में देखा जाय तो आज भी अनेक ऐसे दुरस्त क्षेत्र है जहाँ महिला स्वयं सहायता समूहों के नाम पर चुगली समूह मात्र बनकर रह गये हैं। या स्वयं सहायता समूहों को शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक आधार बनाकर कुछ असामाजिक तत्व अपना उल्लू सिधा करने में लगें है। इसी तरह की चंद बाधाओं को पहचानकर समाप्त करना होगा। स्वयं सहायता समूहों के मूल को सतही स्तर से समझकर इन समूहों के व्यक्तित्व विकास एवं कौशल निर्माण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए साथ ही इनकी विशेषज्ञताओं को तराशकर राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

अत: वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हमें स्वयं सहायता समूहों को सबल बनाने के लिए विशेष प्रयास करना होगा।

संदर्भ सूची :—

१. स्वयं सहायता समूह एवं उद्यमिता विकास, चितरंजन शर्मा, शंभू सिंह सिसोदिया, मिना सनाढ्य

२ 'राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

३ सर्वोदय की एक पुस्तिका, गांधी, विनोबा और जयप्रकाश नारायण: सर्वोदय की विजय, सुभाष मेहता द्वारा एक संकलन (पश. सं. ५५ सामाजिक संस्थाएँ)।

४ लैंगिक समानता और पितृसत्तात्मक मूल्य, किरण सक्सेना ।

५. लैंगिक हिंसा और लैंगिक समानता पर गॉधी' डॉ. अनुपमा कौशिक।

६. स्वयं—सहायता समूह उपागम और निर्धनता निवारण, डॉ. उपेन्द्र चौहान

7. https://www.bhaskar.com

8. https://www.m.timesofindia.com

9. https://www.navbharattimes.indiatimes.com

10. https://www.pmkvyofficial.org

11. https//:www.skillindiadigital.gov.in

❑❑❑

28

कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

डॉ. गायत्री वर्मा रावल

कृषि वैज्ञानिक (गृह विज्ञान विभाग) कृषि विज्ञान केन्द्र, शाजापुर (म.प्र)

****

परिचय

कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह देश के कुल कार्यबल का लगभग ४०% रोजगार प्रदान करता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती के साथ— साथ कृषि आधारित उद्यम करके अपनी आय बढ़ाते हैं। इनमें मुख्य रूप से पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, मशरूम उत्पादन इकाई, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, कृषि मशीनरी, बागवानी शामिल हैं। इसमें ग्रीनहाउस में एक बेमौसमी सब्जी इकाई स्थापित करना भी शामिल है।

देश में बढ़ती आबादी के साथ— साथ बेरोजगारी की समस्या को चुनौती देते हुए युवा इन विकल्पों के साथ रोजगार पैदा कर सकते हैं। आज भी ग्रामीण लोगों की आय मुख्य रूप से कृषि आय पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या आजादी के समय ३६ करोड़ से बढ़कर वर्ष २०२४ में लगभग १४२ करोड़ के पार हो गई है। इतनी बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा के साथ—साथ पोषण सुरक्षा के तहत उचित प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों को पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों के संदर्भ में कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

कृषि खेती हमेशा से ही भोजन और नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण रही है, लेकिन अब यह युवाओं के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। नई तकनीक और संधारणीय प्रथाओं के साथ, खेती एक रोमांचक करियर क्षेत्र बन रही है। यह परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों की

मदद कर रहा है और युवा उद्यमियों और तकनीक के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित कर रहा है। जैसे—जैसे खेती विकसित होती है, यह कई नई नौकरियाँ पैदा करती है, जिससे अगली पीढ़ी को भोजन और खेती के भविष्य को आकार देने का मौका मिलता है।

कृषि में नवाचार :

कृषि उन्नति युवाओं के लिए कई नए रास्ते खोल रही है। रोबोट, सेंसर और स्वचालित उपकरण जैसी पैटर्न—सेटिंग उन्नति की शुरूआत के साथ, विकास अधिक सक्षम और वर्तमान होता जा रहा है। इन उन्नति के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो उन्नति वृद्धि, डेटा मूल्यांकन और उपकरण आंदोलन जैसे क्षेत्रों में पदों को भरते हैं। उदाहरण के लिए, ड्रोन फसल की समृद्धि की निगरानी करते हैं और पानी या कीटनाशकों की विशिष्ट मात्रा का उपयोग करते हैं, जबकि सेंसर किसानों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए मिट्टी की स्थिति पर डेटा एकत्र करते हैं। इसके अलावा, नई व्यवहार्य विकास प्रथाएँ पारंपरिक संगठनों और नियमित विकास में अवसर पैदा कर रही हैं। युवा विकास के सामान्य प्रभावों को कम करने वाली रणनीतियों को व्यवस्थित और लागू करने के अवसर खोज रहे हैं, जैसे कि पानी का संरक्षण, पदार्थों के उपयोग को कम करना और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना।

कृषि में युवा उद्यमिता: एक बढ़ती प्रवृत्ति

युवा उद्यमशीलता एक रचनात्मक डिजाइन है, जिसमें अतिरिक्त युवा लोग अपने स्वयं के विकासशील संघों की शुरुआत करते हैं और खेती की चीजों और संगठनों का आविष्कार करते हैं। ये युवा व्यवसायी प्रांतीय क्षेत्र में क्रांतिकारी अंतर्दृष्टि और ऊर्जा ला रहे हैं, यह विकास के तरीके को बदलने के लिए किया जाता है।

कृषि में रोजगार की संभावनाएं

कृषि खेती में अत्याधुनिक व्यवसायों की स्थापना करना महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यवसाय नई प्रगति और कानूनी प्रथाओं के साथ विकसित होता है। आज का कृषि व्यवसाय केवल विकास से परे है, इसमें परिष्कृत मशीनरी और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनके लिए नई क्षमताओं और डेटा की आवश्यकता होती है। युवाओं को आधुनिक विकास विधियों का उपयोग करना सीखना चाहिए, जैसे कि सटीक कृषि व्यवसाय, जो फसल उत्पादकता, मिट्टी की स्थिति और मौसम के पैटर्न की निगरानी के लिए रोबोट, जीपीएस योजना और सेंसर जैसी प्रगति का उपयोग करता है। ये उपकरण किसानों को अतिरिक्त—सिखाए गए निर्णय लेने में मदद करते हैं, जिससे उनकी व्यवहार्यता और दक्षता बढ़ती है।

कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

पशुपालन एवं डेरी क्षेत्र में रोजगार :

पशुपालन और डेयरी उद्योग के बिना भारतीय कृषि अधूरी है। युवा अच्छी नस्ल की गाय और भैंस का चयन कर इसे एक अच्छे डेयरी व्यवसाय के रूप में स्थापित कर सकते हैं। खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि की लागत का एक हिस्सा जानवरों से उत्पादन पर निर्भर करता है। पशुओं का चारा फसलों से प्राप्त होता है। पशुओं के गोबर से प्राप्त गोबर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों जैसे दूध पाउडर, दही, छाछ, छाछ, टीज, पनीर आदि के उत्पादन और विपणन में लगी छोटे स्तर की डेयरियों, राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों के दुग्ध संघों, डेयरी विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं और चमड़ा आधारित उद्यमों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। युवा पशुपालन और डेयरी उद्योग में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सकते है।

पशुपालन एवं डेरी क्षेत्र में रोजगार

वर्मीकम्पोस्ट के साथ रोजगार :

केंचुआ खाद को वर्मीकम्पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। केंचुआ खाद जल्द तैयार होने वाली

एक उत्तम पोषक तत्व वाली खाद है। वर्मीकम्पोस्ट केंचुओं के द्वारा पशुओं से प्राप्त गोबर, वनस्पति एवं भोजन के बचे हुए कचरे के विघटन से तैयार की जाती हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर और पोटाश जैसे तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. केंचुआ खाद की एक खास विशेषता ये है की इसमें बदबू नही आती है जिस कारण वातावरण प्रदूषित नही होता हैं।

वर्मीकम्पोस्ट के साथ रोजगार

जैविक एवं प्राकृतिक खेती :

आज वर्तमान समय की महत्ती आवश्यकता के साथ—साथ भविष्य की खेती भी कहा जा सकता है। जिसमें शुद्ध रूप से तैयार जैविक फसल एवं उत्पाद का उचित दाम भी किसानों को मिल सकता है।

भेड़—बकरी पालन के साथ रोजगार :

वर्ष २०१२ में भेड़ और बकरी पालन में भेड़ और बकरियों की संख्या क्रमशः ६५.०७ और १३५.१७ मिलियन थी । यह वर्ष २०१९ में बढ़कर ७४.२६ और १४८.८८ मिलियन हो गया। सामान्य तौर पर भेड़—बकरी पालन कम लागत में शुरू किया जा सकता है। भेड़ के ऊन, चमड़े और उनके मांस की देश के साथ—साथ विदेशों में भी भारी मांग है, जो रोजगार के साथ—साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।

भेड़—बकरी पालन के साथ रोजगार

मुर्गीपालन के क्षेत्र में रोजगार :

देश की बढ़ती आबादी, रहन—सहन और खान—पान में बदलाव के कारण शाकाहारी वर्ग भी पोषण की दृष्टि से अंडे का इस्तेमाल करने लगा है। मुर्गी पालन, चिकन प्रसंस्करण को व्यावसायिक रूप से अपनाकर युवा रोजगार देश की आय में वृद्धि, देश के निर्यात और जीडीपी में प्रगति को बढ़ावा देता रहा है। सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से छूट देकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।

मुर्गीपालन के क्षेत्र में रोजगार

मधुमक्खी पालन के साथ रोजगार :

मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ५०० करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मधुमक्खी पालन, कम समय और कम लागत पर कृषि आधारित एक लाभदायक व्यवसाय है। वर्ष २०१९—२० में मधु का निर्यात ५९५३६.७४ मीट्रिक टन था। मधुमक्खी पालकों को बैंक से लोन की सुविधा भी मिलती है।

मधुमक्खी पालन के साथ रोजगार

मशरूम की खेती के साथ रोजगार :

आहार में बदलाव के कारण, मशरूम पोषण के मामले में एक बहुत ही स्वस्थ आहार है। मशरूम की खेती के लिए कम पूंजी और जमीन की जरूरत होती है। ग्रीनहाउस में तापमान को व्यवस्थित करके, आप पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मशरूम प्रोटीन, विटामिन और फाइबर

से भरपूर होता है। इसलिए लोगों के बीच इसकी काफी मांग है। मशरूम की खेती से रोजगार सृजन करती ग्रामीण महिलाए मशरूम की खेती का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, जिसे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या राष्ट्रीय मशरूम केंद्र सोलन से प्राप्त किया जा सकता हैं।

मशरूम की खेती के साथ रोजगार

वैज्ञानिक विधि से मछलीपालन :

मछली उत्पादन में भारत का तीसरा और जलीय कृषि में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के अनुसार, भारत में मत्स्य पालन १४५ मिलियन लोगों को रोजगार देता है। ३३३.४१ बिलियन टन मछली का निर्यात किया जाता है और सकल घरेलू उत्पाद में १.०७ प्रतिशत का योगदान देता है। मछली पालन में पूंजी और श्रम की कम आवश्यकता होती है। इस वजह से इसमें लागत से ज्यादा आमदनी होती है। मत्स्य पालन से संबंधित उद्योगों जैसे ग्रेडिंग, पैकिंग, सुखाने और पाउडरिंग, अचार बनाने, प्रसंस्करण में प्रशिक्षण कृषि विश्वविद्यालय, भाकृअनुप — केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान संस्थान, मुंबई और केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि से पेशेवर रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

वैज्ञानिक विधि से मछलीपालन

बागवानी एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार :

लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए फल फूल व सब्जियों की निरंतर मांग बढ़ती जा रही है। बागवानी के उत्पादों की दैनिक मांग होने के कारण कम क्षेत्रफल में भी सब्जियों एवं फलों जैसे केला, नीबू पपीता एवं पान की खेती करके अधिक लोगों को रोजगार एवं आमदनी मिल सकती है। फल, फूलों व सब्जियों की कटाई—छंटाई श्रेणीकरण, पैकिंग, मार्केटिंग, रखरखाव आदि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं होती हैं।

बागवानी एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार

औषधीय और सुगन्धित पौधों की खेती :

लहसुन, प्याज, अदरक, पुदीना और चौलाई जैसी सब्जियां पौष्टिक होने के साथ—साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। इसी कारण इनसे आयुर्वेदिक औषधियां व खाद्य उत्पाद बनाये जाते हैं। औषधीय खेती अंतर्गत अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, चियासीड इत्यादि फसलों को लगाकर फसल चक्र अपनाकर इसके साथ—साथ इनसे संबंधित रोजगार करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।

औषधीय और सुगन्धित पौधों की खेती

ग्वारपाठा प्रसंस्करण ईकाई—

ग्वारापाठा प्रसंस्करण में मुख्य कार्य पत्तियों में लसलसा ‘‘एलोइन‘‘ पदार्थ अलग करना व जैल निष्कासित करने का होता है। जैल निष्कासन हेतु विश्वविद्यालय में एक हस्त चलित व मोटर चलित मशीन विकसित की गई है जिससे साफ जैल निकाला जा सकता है।

रेशम कीटपालन—

रेशम उद्योग भी आय का उत्तम साधन है, रेशम उद्योग में शामिल कार्य जैसे—पत्तों की कटाई, सिल्कवर्म का पालन, रेशम के धागे की स्पीनिंग तथा बुनाई का कार्य महिलायें करती है। अतः यह एक उच्च आय सृजन उद्योग है। मधुमक्खीपालन एवं उससे उत्पादित शहद का संकलन एवं प्रसंस्करण द्वारा भी अच्छा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

रेशम कीटपालन

कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार :

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन भी कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में फसलों, सब्जियों, फलों, दूध, मांस, आदि से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है। कृषि से प्राप्त हुए उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण करके जैसे गन्ने से गुड़, मूंगफली से स्वादिष्ट नमकीन, फलों से जूस, कैंडी, जैम, जेली, आलू व केले से चिप्स, दूध से दूध का पाउडर, दही, छाछ मक्खन, घी, पनीर, टमाटर व आम से अचार व चटनी तैयार करके तथा मूल्य संवर्धन से रोजगार स्थापित किया जा सकता है।

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा

आज वैज्ञानिको द्वारा मंहगी एंव कृषि प्रसंस्करण इकाईयों/मशीनों की जगह सस्ती व सरल मशीनों के विकास से गॉवो में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाई लगाना आसान हो रहा है, सिर्फ आवश्यकता है जागरूक होकर लाभ कमाने की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों के लगभग ३८ केन्द्रो में कटाई उपरांत प्रौधोगिकी विषय पर अनुसंधान हो रहा है। मुख्य रूप से अनाज साफ करने की ग्रेडिंग मशीन, दाल मिल, पिसाई मिल, मक्का डिहस्कर, शैलर, छिलके निकालने की मशीन, फल व सब्जियों की ग्रेडिंग मशीन, सोयाबीन प्रसंस्करण, मशीन, फल व सब्जियों हेतु ग्रेडिंग मशीन, आलू—अदरक छीलने की मशीन, ग्वारपाठा जैल निष्कासन टमाटर एंव मिर्च बीज निष्कासान उन्नत फल—सब्जियों से नये उत्पाद बनाने की तकनीके तैयार की गई है जिनके द्वारा किसान भाई खाद्य प्रसंस्करण को अपनाकर कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण एंव मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने कृषि उत्पादो को तैयार कर लाभ कमा सकते है।

कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण :

कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण से उत्पादन लागत में कमी आएगी और इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और मशीनीकरण

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा :

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से कृषि उत्पादों का अधिक मूल्य मिलेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा

कृषि क्षेत्र में सरकारी योजनाएं :

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ और परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जलवायु सुधार योजनाएँ, आधुनिक खेती तकनीक, कौशल विकारा कार्यक्रम और ग्रामीण उद्यमिता की पहचान बना रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर स्थायी और समृद्धिशील रहें। युवाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषि उद्यम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें मशरूम उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरी पालन, मछलीपालन, वर्मीकम्पोस्टिंग, बेकरी, मधुमक्खीपालन, आधुनिक मशीनों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नाम लिया जा सकता है। युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार इकाई लगाने के लिए सब्सिडी के तहत भारी छूट दे रही है। इसके साथ ही साथ कृषि उत्पादों के विपणन में आसानी एवं फसल उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

कृषि क्षेत्र में नौकरियां : भारत में स्नातक स्तर पर १३ विषयों और स्नातकोत्तर स्तर पर ९५ से अधिक विषयों में शिक्षा की सुविधा के साथ कृषि में शिक्षा का एक बड़ा नेटवर्क है। जिनके द्वारा छात्रों की डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर और डॉक्टरेट स्तर पर कृषि शिक्षा प्रदान कर रही है। आईसीएआर से जुड़े विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियां विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत है। स्नातक डिग्री कार्यक्रम न्यूनतम ४ वर्ष की अवधि का है। कुछ कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा दो वर्षीय डिप्लोमा और लघु अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इस प्रकार संबंधित विषय में शिक्षा प्राप्त कर युवा विभिन्न विभागों में नौकरियां एवं रोजगार प्राप्त कर सकते है।

- ➢ कृषि अधिकारी
- ➢ कृषि विकास अधिकारी
- ➢ सहायक बागान प्रबंधक
- ➢ कृषि तकनीशियन
- ➢ पौधा प्रजनक
- ➢ पशु चिकित्सक
- ➢ कृषि इंजीनियर
- ➢ रेशमपालन विभाग
- ➢ खाद्य सुरक्षा अधिकारी
- ➢ फूड टेक्नोलॉजिस्ट
- ➢ अनुसंधान सहायक
- ➢ विपणन कार्यकारी
- ➢ बीज प्रमाणीकरण
- ➢ कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक
- ➢ कृषि वैज्ञानिक
- ➢ कृषि सलाहकार
- ➢ क्लिनिक और कृषि सेवा केंद्र खोल

निष्कर्ष

कृषि भूमि अगली पीढ़ी के लिए रोजगार के कई अवसर खोल रही है। प्रौद्योगिकी, संधारणीय प्रथाओं और उद्यमशीलता की पहल में प्रगति के साथ, युवा लोग खेती, कृषि व्यवसाय और संबंधित क्षेत्रों में विविध कैरियर पथ पा रहे हैं। ये अवसर न केवल बेरोजगारी को संबोधित करते हैं बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण विकास का समर्थन करते हैं और कृषि उद्योग की भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। तो ये अगली पीढ़ी में कृषि सृजन के लिए रोजगार के अवसर हैं।

कृषि व्यवसाय में युवा: ग्रामीण विकास को गति देना

'कृषि व्यवसाय में युवा'' का तात्पर्य विभिन्न ग्रामीण प्रयासों में किशोरों की अनूठी भागीदारी से है, जो पारंपरिक विकास से खाद्य प्रबंधन, कृषि–पर्यटन

और कृषि उन्नति जैसे मूल्य—वर्धित प्रथाओं में आगे बढ़ते हैं। अपनी रचनात्मक बुद्धि और दृढ़ निश्चय के प्रयोग के माध्यम से, कृषि व्यवसाय में युवाओं ने नए पद स्थापित किए हैं, नए रास्ते बनाए हैं, अपने कौशल को बढ़ाया है, और संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला में एक परिष्कृत संवेदनशीलता विकसित की है। चाहे वे अपने स्वयं के संयंत्र उद्यम शुरू करें, परिवार विकास परियोजनाओं में भाग लें, या संपन्न सहकारी समितियों और संघों के साथ सहयोग करें, कृषि व्यवसाय में युवा ताकत और सुधार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का लक्ष्य रखते हैं। उनके उपक्रम न केवल देश के जिलों की समृद्धि में योगदान करते हैं, बल्कि कृषि क्षेत्र की घटनाओं और वास्तविकता के समग्र मोड़ के बावजूद भी योगदान करते हैं।

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा और इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से कृषि उत्पादों का अधिक मूल्य मिलेगा इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

संदर्भ :—

१. धनसिंह (२०२३) ''कृषि के क्षेत्र में रोजगार'' कृषि किरण अंक १६ जुलाई—०२ दिसम्बर २०२३ पृष्ठ क्र ५४—५८

२. दिग्विजय सिंह ''आधुनिक कृषि से रोजगार के अवसर'' खेती पत्रिका नवम्बर २०२२ पृष्ठ क्र १६—१७

३. सुरेश चन्द्रा ''फसल प्रसंस्करण आज की आवश्यकता एवं महत्व'' कृषि प्रसंस्करण में उद्यमिता न्यू इण्डिया पब्लिसिंग एजेंसी २०२२ पृ.क्र. ०९—२०

४. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन आर्थिक समीक्षा २०१९—२०

५. https://vittiyasaksharta.in/gram-panchayat- ke-kshetra-mein-rojgar-ke-avsar/

❑❑❑

29

ग्रामीण विकास में कौशल विकास की भूमिका

प्रो. माया वर्मा
अतिथि विद्वान (समाजकार्य)
जननायक टंट्या मामा शासकीय महाविद्यालय, भीकनगॉव

डॉ. लता राठौर
अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र)
जननायक टंट्या मामा शासकीय महाविद्यालय, भीकनगॉव

****

शब्द कुंजी :— ग्रामीण विकास, कौशल विकास, योजना प्रशिक्षण।

सारांश :—

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की एक अग्रणी परिणामोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण योजना है इस कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना का उद्देश्य बडी संख्या मे भारतीय युवाओं की दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना तथा जुटाना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके और अपनी अजीविका का अर्जन कर सके।

प्रस्तावना :—

ग्रामीण विकास ही राष्ट्र की प्रगति का आधार हो सकता है ग्रामो की संपन्नता देश की अर्थव्यवस्था को सही मायने में सशक्त बना सकती है देश की अर्थव्यवस्था में कशषि का बडा हिस्सा है ग्रामिण विकास के लिये गॉवो में रोजगार सर्जन करने के लिए स्थानीय युवा वर्ग का रोजगार प्रदान करना आवश्यक है देश की बेरोजगारी क्षेत्रा से संबंधित है रोजगार प्राप्ति में कुशलता आवश्यकता है कौशल विकास शब्द से आशय है कि व्यक्ति में विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट योग्यता व क्षमता को विकसित करने के लिए ज्ञान व प्रशिक्षण देने कि प्रक्रिया है।

१. कौशल विकास के लिए आवश्यक

आधारभूत संरचना का निर्माण करना।

२. व्यवसायिक कुशलता तथा रोजगार अनुकुलन प्रशिक्षण देना।

उद्देश्य :—

१. भारत में कौशल विकास योजना की प्रगति का अध्ययन करना।

२. ग्रामीण विकास की सामाजिक, आर्थिक बेरोजगारो को जानना।

समस्या :—

१. कुशल मानव संसाधन का अभाव।

२. काम देने वाले और काम मॉगने वाले के बीच कडी का आभाव।

३. उचित पारिश्रमिक अभाव।

सुझाव :—

१. युवा वर्ग को कौशल विकास के आगे आने के लिए प्रोत्साहन करना होगा।

२. प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी युवो को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

३. कुशल विकास प्रशिक्षणार्थियों को सरकार द्वारा स्कालरशीप देना चाहिए।

४. कुशल व्याक्ति द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए देश भर में विकश्त की व्यवस्था निर्माण हो।

निष्कर्ष :—

युवा भारत को रोजगार निर्माण में कौशल विकासशील सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में गति लाने के साथ निजि व्यवसायिक संस्थाओं के प्रयासों की भी आवश्यकता है। कौशल विकास भारत की महत्वकाक्षी योजना है युवा वर्ग को सक्षमवान बनाने के साथ उन्हे जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करायेगा जो देश की आय वृध्दि मे प्रमुख साधन बनेगा।

संदर्भ :—

१. मौर्य अर्जून कुमार शुक्ल जयशंकर (२०२२) ''ग्रामीण विकास में कौशल की भूमिका'', संत तुलसीदास पी.जी. कॉलेज कादीपुरा, सुल्तानपुर उत्तरप्रेदश

30

बदलते परिदृश्य में छात्रों के व्यक्तित्व एवं व्यवसायिक विकास में मददगार कौशल विकास के विभिन्न आयाम

डॉ. सुनैना चौहान
सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र)
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, खरगोन

डॉ. संध्या बटवे
सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र)
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, खरगोन

****

कौशल विकास छात्रों के समग्र विकास का आधार है। शैक्षणिक उपलब्धियों से परे यह एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करता है जो आत्मविश्वास और क्षमता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। जब छात्र कौशल विकास गतिविधियों में शामिल होते हैं तो वे अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करते हैं अपनी प्रतिभा का पोषण करते हैं और अपने क्षितिज को व्यापक बनाते हैं। विकास के लिए यह समग्र दृष्टिकोण शारीरिक (भावनात्मक सामाजिक और बौद्धिक पहलुओं को शामिल करता है जिससे छात्र अधिक अनुकूलनीय और बहुमुखी व्यक्ति बन सकते हैं।

आज के प्रगतिशील युग में कौशल विकास हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को आकार देने वाले एक बुनियादी स्तंभ के रूप में खड़ा है। यह एक सतत गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए उद्योग की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। कौशल विकास का महत्व वर्तमान से परे है जो हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखने भूलने और फिर से सीखने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए,

हम न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि अवसरों के भविष्य के परिदृश्य में पनपने के लिए खुद को प्रभावी ढंग से तैयार करते हैं। अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में ऐसा सक्रिय दृष्टिकोण निस्संदेह छात्रों के भविष्य के करियर पथ या उद्यमशीलता के उपक्रमों पर पर्याप्त प्रभाव डालेगा।

पेशेवर उद्देश्यों के साथ—साथ बहुमुखी विकस को प्राप्त करने की दिशा में मार्ग को सरल बनाने में कौशल विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक करियर पथ के लिए अद्वितीय कौशल की आवश्यकता होती है, सभी में जटिलता की अलग—अलग डिग्री होती है। जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना या उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इन कौशलों में महारत हासिल करना सफलता और ठहराव के बीच अंतर करने वाला कारक हो सकता है। संक्षेप में, कौशल संवर्धन और खुद को सबसे अद्यतन और प्रासंगिक क्षमताओं से लैस करने की अथक खोज करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंच तैयार करती है, जिससे व्यक्तिगत विकास और पेशेवर सफलता दोनों का मार्ग प्रशस्त होता है।

विद्यार्थी जीवन में कौशल विकास का महत्व

१. रोजगार क्षमता में वृद्धि: जिन छात्रों के पास प्रासंगिक कौशल होते हैं, वे नियोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक होते हैं, जिससे उन्हें रोजगार बाजार में लाभ मिलता है।

२. आलोचनात्मक चिंतन: कौशल का विकास आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को स्थितियों का आकलन करने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

३. अनुकूलनशीलता: आज की निरंतर विकसित होती दुनिया में लचीलापन बहुत ज़रूरी है। कौशल विकास के सहयोग से छात्र नई तकनीक और बदलते क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं।

४. आत्मविश्वास में वृद्धि: कौशल में दक्षता प्राप्त करने से विद्यार्थियों को अधिक आत्म—विश्वास मिलता है, जो उन्हें नई कठिनाइयों का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करने के लिए प्रेरित करता है।

५. जीवन कौशल: समय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता और प्रभावी संचार जैसे आवश्यक जीवन कौशल कौशल उन्नयन के माध्यम से सिखाए जाते हैं।

६. उद्यमशीलता की भावना: क्षमताओं को बढ़ावा देने से उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा मिल सकता है और विद्यार्थियों को नवाचार करने और नई संभावनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

शिक्षा प्रणालियों में कौशल विकास

१. पाठ्यक्रम में कौशल का एकीकरण: विद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में शिक्षा के विस्तार के कौशल को शामिल करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सके।

२. पाठ्येतर गतिविधियाँ: पाठ्येतर गतिविधियाँ कौशल विकसित करने के लिए एक बेहतरीन माहौल प्रदान करती हैं। स्कूलों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ प्रदान करनी चाहिए जो सभी क्षमता स्तरों को समायोजित करती हों।

३. शिक्षकों की भूमिका: कौशल विकास के लिए शिक्षकों की भूमिका बहुत ज़रूरी है। उन्हें छात्रों को उनकी प्रतिभाओं को पहचानने में मदद करनी चाहिए, उनके प्रयासों में उनका साथ देना चाहिए और उनकी क्षमताओं को निखारने में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।

कौशल विकास की बहुमुखी प्रकृति

कौशल विकास किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है; इसमें कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो एक छात्र के समग्र विकास में योगदान देती है। इन कौशलों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं

१. तकनीकी कौशल: ये कौशल कुछ क्षेत्रों या उद्योगों के लिए विशिष्ट हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। विशेष क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए तकनीकी कौशल आवश्यक हैं।

२. सॉफ्ट स्किल्स: सॉफ्ट स्किल्स पारस्परिक और संचार कौशल हैं जो छात्रों को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाते हैं। इनमें टीमवर्क, नेतृत्व और

भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे कौशल शामिल हैं।

३. जीवन कौशल: जीवन कौशल व्यावहारिक योग्यताएँ हैं जो छात्रों को दैनिक जीवन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करती हैं। समय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, समस्या—समाधान और निर्णय लेना इस श्रेणी में आते हैं।

४. रचनात्मक कौशल: रचनात्मक कौशल में संगीत, कला, रचनात्मक लेखन और डिजाइन सहित कलात्मक और कल्पनाशील क्षमताएं शामिल हैं। ये कौशल नवाचार और आत्म—अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते हैं।

५. आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल: इन कौशलों में सूचना का विश्लेषण करने, स्थितियों का मूल्यांकन करने और प्रभावी समाधान तैयार करने की क्षमता शामिल है। ये पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अमूल्य हैं।

६. अनुकूलनशीलता और लचीलापन: अनुकूलनशीलता से तात्पर्य बदलती परिस्थितियों और वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता से है, जबकि लचीलेपन में असफलताओं और प्रतिकूलताओं से उबरना शामिल है।

७. उद्यमशीलता कौशल: उद्यमशीलता कौशल में रचनात्मकता, जोखिम उठाने की क्षमता और व्यावसायिक कौशल शामिल हैं। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो उद्यमिता या नवाचार में रुचि रखते हैं।

८. नेतृत्व कौशल: नेतृत्व कौशल छात्रों को जिम्मेदारी लेने, दूसरों को प्रेरित करने और टीमों को सामान्य लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने में सशक्त बनाता है।

९. संचार कौशल: जीवन के सभी पहलुओं में प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। छात्रों की विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने और ध्यान से सुनने की क्षमता कौशल विकास के माध्यम से बेहतर होती है।

कौशल विकास की चुनौतियाँ

➢ अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता: भारत में प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के मध्य भी रोज़गार की दर कम है, इसका प्रमुख कारण पर्याप्त और गुणवत्तापरक प्रशिक्षण का प्राप्त न होना रहा है। कम अवधि के प्रशिक्षण में सीखने की संभावनाएँ सीमित होती हैं। जहाँ अभियांत्रिकी के विद्यार्थी किसी विषय के लिये चार वर्ष का समय लेते हैं, वहीं उसी विषय के समरूप कोई कौशल प्रशिक्षण कुछ माह में प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

➢ उद्योगों की सीमित भूमिका: अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग क्षेत्र की भूमिका सीमित होने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्रशिक्षण के उपरांत रोज़गार एवं वेतन का स्तर निम्न बना रहा।

➢ विद्यार्थियों में कम आकर्षण: कौशल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे— ITI तथा पोलिटेक्निक में इनकी क्षमता के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ। इसका प्रमुख कारण युवाओं के बीच कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर सीमित जागरूकता को माना जा सकता है।

➢ नियोक्ताओं का रवैया: भारत में बेरोज़गारी की अधिकता के लिये सिर्फ कौशल प्रशिक्षण ही एकमात्र समस्या नहीं है बल्कि उद्यमों तथा लघु उद्योगों का लोगों को नियुक्त न करने की इच्छा भी एक बड़ा कारण है।

➢ बैंकों से ऋण प्राप्ति में कठिनाई, गैर—निष्पादित संपत्तियों (NPAs) की अधिकता तथा निवेश दर के निम्न होने के कारण रोज़गार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

सुझाव —

➢ शिक्षा एवं प्रशिक्षण खर्च में वृद्धि: कौशल विकास से संबधित शिक्षा और प्रशिक्षण पर आवश्यकता अनुसार नये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारभं किया जाना चाहिए ।

➢ प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन तथा इन संस्थानों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये, साथ ही ऐसी विधियों एवं तकनीकों का सृजन करना चाहिये जो प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य—दक्षता में वृद्धि करें।

➢ कौशल सर्वेक्षण: नियोक्ताओं एवं उद्यमों की आवश्यकताओं को समझने के लिये सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। इस प्रकार के सर्वेक्षण कौशल एवं प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक हो सकते हैं तथा इसके माध्यम से नियोक्ताओं की

अपेक्षित आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सकती है।

➢ भारत को चीन, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, सिंगापुर आदि के व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिये। इन देशों के समक्ष भी भारत के समान समस्याएँ थीं।

➢ कौशल विकास का सबसे मूल्यवान लाभ छात्रों की समस्या—समाधान क्षमताओं में इसका योगदान है। जैसे—जैसे छात्र नए कौशल हासिल करते हैं, वे समस्या—समाधान रणनीतियों का एक टूलकिट विकसित करते हैं जिसे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। वे परिस्थितियों का विश्लेषण करना, चुनौतियों की पहचान करना और रचनात्मक समाधान खोजना सीखते हैं। ये समस्या—समाधान कौशल हस्तांतरणीय हैं, जो छात्रों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में जटिल मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाते हैं।

सॉराशं —

निष्कर्ष रूप में, कौशल विकास व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की ओर एक छात्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह समग्र विकास, रोजगार, अनुकूलनशीलता, उद्यमशीलता, समस्या—समाधान क्षमताओं, आत्मविश्वास, जीवन कौशल और शैक्षणिक सफलता में योगदान देता है। जैसे—जैसे छात्र कौशल विकास को अपनाते हैं, वे खुद को एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में पनपने के लिए तैयार करते हैं जहाँ बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।

छात्रों को कौशल विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना उनके भविष्य में निवेश है, उन्हें उन उपकरणों से लैस करना जिनकी उन्हें संतुष्टिदायक जीवन जीने और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यकता है। तेजी से बदलती दुनिया में, सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता अपने आप में एक कौशल है, और इस क्षमता को बढ़ावा देकर, हम छात्रों को अपने भाग्य को आकार देने और अवसरों से भरे भविष्य को अपनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। कौशल विकास केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है; यह उन क्षमताओं को निखारने के बारे में है जो छात्रों को उनके जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। शिक्षकों, सलाहकारों और अभिभावकों के रूप में, कुशल, अनुकूलनीय और आत्मविश्वासी व्यक्तियों की अगली पीढ़ी को पोषित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) २०२० भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिये एक ऐतिहासिक पहल थी, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में गहन सुधार और एक प्रणालीगत बदलाव का आह्वान किया गया था। इस नवीन नीति में जीवन कौशल (Life Skills) को पाठ्यक्रम के अंग के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की गई जहाँ दृष्टिकोण यह है कि हमारी भावी पीढ़ियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिये शिक्षा को महज शैक्षणिक परिणामों तक सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि हमें इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

❑❑❑

31

व्यक्तित्व विकास में कौशल विकास

प्रो. प्रीति राठौर (हाड़ा)
सहायक प्राध्यापक—अंग्रेजी,
शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

****

यह अत्यन्त आनंद का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान परपंरा का समावेश करने की अनुशंसा की गई है।

किसी भी समस्या के निराकरण के लिए उसकी जड़ में जाना पड़ता है और उसके कारण ढूंढने पड़ते है। इसके बाद ही समाधान संभव है।

वर्तमान की अधिकतर समस्याओं पर नजर डाले तो ध्यान में आता है कि इसके कारण में हम अर्थात मनुष्य खुद है। मनुष्य के चरित्र में आयी गिरावट (क्राइसिस ऑफ केरेक्टर) जब तक मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए उचित प्रयास नहीं किये जायेंगे तब तक अधिकतर समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

''चरित्रवान नागरिकों के द्वारा ही व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व में सुख शांति एवं आनंद के वातावरण का सृजन संभव है। चरित्र निर्माण का सबसे उपर्युक्त माध्यम है — शिक्षा व्यवस्था'' डॉ.अतल कोठारी (राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय नई दिल्ली)

दूसरी महत्वपूर्ण बात है — छात्र/छात्राओं के व्यतित्व का समग्र विकास (Holistic Development of Child)। आज वैश्विक स्तर पर समग्र दृष्टि (होलस्टीक एप्रोच) की संकल्प पर काफी बाते हो रही है। इसको सही रूप से उपयोग में लाना है तब ही शिक्षा के स्तर पर छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सकता है। जो शिक्षा प्रणाली अब तक चल रही थी। उसमें इंजीनियरिंग के छात्र को प्रबंधन के बारे में मालुम नहीं होता था। विज्ञान के छात्र/छात्राओं को संगीत सिखने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन अब हमारे लिए खुशी की बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में सर्वांगीन विकास का अवसर प्रदान करती है।

जो इस प्रकार है :—

१. पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें।

२. संस्थान का वातावरण (परिवेश)।

३. सह शैक्षिक गतिविधियां।

४. पढ़ाने की पद्धतियां एवं शिक्षको के अचार—व्यवहार।

वास्तव में व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त कराना, उस असीमित क्षमता का अनुभव करवाना और उनका समग्र एवं संतुलित विकास तथा चरित्र निर्माण ही शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है।

गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बच्चे व व्यक्ति के शरीर मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान श्रेष्ठ तत्वों का प्रकटीकरण व चहुंमुखी विकास करना। पंड़ित मदन मोहन मालवीय कहते है :— चरित्र का गठन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये।

मगिनी निवेदिता कहती है ''हमें कर्मठ, उर्जावान और मानवता की सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिये। दृढ़ क्रियाशील और उत्साही चरित्र का निर्माण शिक्ष का उद्देश्य होना चाहिये। शिक्षा का लक्ष्य केवल अजीविका प्राप्त करना नहीं होता है, अपितु इसका लक्ष्य चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण होना चाहिये।

स्वामी विवेकानंद जी कहते है किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण स्वभाव अर्थात चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। शिक्षा विविध जानकारियों का ढ़ेर नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठुस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आ जन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। मेरी दृष्टि से शिक्षा का सार तथ्यों का संकलन नहीं बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है। हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिये जिससे चरित्र बने, मानसिक बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और उससे मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सकें। इसी को दूसरे रूप में कहा जाए तो ''हमें सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहिये। सम्पूर्ण शिक्षा तथा समस्त अध्ययन का एकमेव उद्देश्य है — ''व्यक्तित्व को गढ़ना''।

तैत्तिरीय उपनिष्द में व्यक्तित्व के समग्र विकास

हेतु पंचकोश की जो संकल्पना दी है वही पूर्णता की ओर ले जाती है।

व्यक्तित्व की संकल्पना :— आत्मबल का व्यक्त रूप मनुष्य है।

सम्पूर्ण जीव सृष्टि में मात्र इसी कारण से मनुष्य को ही व्यक्ति कहा गया है। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा व्यक्तित्व है। व्यक्ति के तीन अंग है एक स्थल शरीर एवं एक सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। शरीर स्थूल है, प्राण, मन, बुद्धि सुक्ष्म है और आत्मा से कारण है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना, समझना अर्थात पंत्रकोश को जानना, समझना एवं उसका समग्र विकास करना। यही शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है।

पंचकोश के अंतर्गत आता है :—

१. अन्नमय कोरा — शारीरिक विकास

२. प्राणमय कोश — प्राणों का विकास

३. मनोमय कोश — मान का विकास

४. विज्ञानमय कोश — बौद्धिक विकास

५. आनन्दमय कोश — आध्यात्मिक विकास

चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण और समग्र विकास की उपरोक्त संकल्पना को क्रियान्वित करने हेतु कुछ पद्धति से विचार करना आवश्यक है।

१. पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में समावेश।

२. सहशैक्षिक गतिविधियों से।

३. शैक्षिक संस्थानों के परिवेश, वातावरण।

४. शिक्षा अधिगम का सृजन। (पढ़ाने की पद्धतियों एवं शिक्षकों के आचरण, व्यवहार द्वारा)

ब्रह्य तत्व ने अपने में से ही समग्र सृष्टि का सश्जन किया वही सृष्टि बन गई। व्यक्ति इसी सृष्टि तत्व का विस्तार है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, शायद यही कही से आती होगी ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की अवधारणा सह अस्तिव सामाजिक एवं नागरिक बोध सर्वपंथ सम्मान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण्ज्ञं अब बात आती है व्यक्तित्व विकास के साथ—साथ कौशल विकास की कौशल आज की अनिवार्यता है और इस कौशल विकास के भी अनेक क्षेत्र है।

यहां मैं मुख्य रूप से P.M.K.V.Y 4.0 का उल्लेख करना चाहती हूँ। इस योजना को लाखों भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए डिसाईन किया गया है, जो उद्योग की मांगो के अनुरूप है। इस योजना में ए.आई. रोबोर्टिक्स आई.ओटी और ड्रोन जैसी उद्योग ४.० तकनीकों से संबंधित नए पाठ्यक्रम शामिल है, जो यह सुनिश्चित करते है, कि प्रतिभागी आधुनिक नौकरी भूमिकाओं के लिए तैयार हो इसमें २६५ से ज्यादा कोर्सेस है।

अत: आज अनेक अवसर है जिससे आप व्यक्तित्व विकास एवं कौशल विकास आसानी से कर सकते है और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते।

संदर्भ :—

१. व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, लेखक प्रो.उमेश कुमार सिंह।

२. गुगल।

❑❑❑

32

तकनीकी कौशल विकास और भारत की रोजगार नीति : एक राजनीतिक समीक्षा

ज्योति पटेल
शोधार्थी
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू जिला इन्दौर

****

सार

तकनीकी कौशल विकास और रोजगार नीति भारत की विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस शोध पत्र में ''स्किल इंडिया मिशन'', ''डिजिटल इंडिया'' जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से तकनीकी कौशल विकास के राजनीतिक प्रभाव और रोजगार सृजन का विश्लेषण किया गया है। तालिका और डेटा के माध्यम से योजनाओं की सफलता और असफलता को परखा गया है।

महत्वपूर्ण शब्द : तकनीकी कौशल, रोजगार नीति, स्कील इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, राजनीतिक समीक्षा, श्रम बाजार, सरकारी योजनाएँ।

प्रस्तावना

भारत, जिसे ''युवा राष्ट्र'' के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में अपनी जनसंख्या का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रयासरत है। देश की जनसंख्या का लगभग ६५ प्रतिशत हिस्सा ३५ वर्ष से कम आयु का है, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी प्रदान करता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को उत्पादक बनाना देश के विकास के लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि एक अनिवार्यता भी है। कौशल विकास के अभाव में बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी हुई है। इस संदर्भ में, तकनीकी कौशल विकास और रोजगार सृजन की नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

तकनीकी क्रांति और डिजिटल युग ने श्रम बाजार में नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। विश्व स्तर पर स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), और अन्य आधुनिक तकनीकों ने परंपरागत रोजगार के स्वरूप को बदल दिया है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने श्रमिकों को नए तकनीकी कौशलों से लैस करे, ताकि वे बदलते वैश्विक रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी उद्देश्य से भारतीय सरकार ने पिछले एक दशक में कई कौशल विकास योजनाएँ शुरू की हैं।

'स्किल इंडिया मिशन'', जो २०१५ में शुरू किया गया था, का उद्देश्य २०२२ तक ४० करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना था। इसी तरह, ''डिजिटल इंडिया'' कार्यक्रम, जो २०१५ में लॉन्च हुआ, का लक्ष्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल तकनीकी कौशल का विकास करना है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करना और मौजूदा बेरोजगारी की समस्या को हल करना भी है।

हालांकि, इन योजनाओं की सफलता और प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की रिपोर्ट्स के अनुसार, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा वर्ग रोजगार प्राप्त करने में सफल रहे है। दूसरी ओर, कुछ अन्य योजनाओं ने भी सफलता हासिल की है, जैसे कि डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुधार और ई—गवर्नेंस के क्षेत्र में रोजगार सृजन।

संवैधानिक दृष्टिकोण से भी तकनीकी कौशल विकास और रोजगार के अधिकार को भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुच्छेद ४१, जो कार्य, शिक्षा, और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है, और अनुच्छेद २१।, जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, कौशल विकास नीतियों के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद १६ के तहत रोजगार के अवसरों में समानता का प्रावधान है, जो कि सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार की जिम्मेदारी को दर्शाता है।

इस शोध में ''स्किल इंडिया मिशन'' और

''डिजिटल इंडिया'' जैसी नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि इन योजनाओं ने रोजगार सृजन और तकनीकी कौशल के विकास में किस हद तक योगदान दिया है। साथ ही, इन योजनाओं की राजनीतिक दिशा और कार्यान्वियन में मौजूद चुनौतियों का भी गहराई से अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र यह भी उजागर करता है कि तकनीकी कौशल विकास नीतियाँ केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। रोजगार सृजन के माध्यम से सामाजिक असमानता को कम करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर समाप्त करना, और युवाओं को सशक्त बनाना इन नीतियों के प्रमुख लक्ष्य हैं।

अत: हम कह सकते है कि, तकनीकी कौशल विकास और रोजगार नीति के बीच एक गहरा संबंध है। इन नीतियों की सफलता न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए, इस शोध पत्र में इन नीतियों के प्रभाव का राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है, ताकि यह समझा जा सके कि भारत किस हद तक अपने युवा पूँजी का लाभ उठाने में सक्षम हो पाया है।

राजनीतिक अधिकार एवं संवैधानिक प्रावधान

भारत में कौशल विकास और रोजगार का अधिकार निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा हुआ है —

- अनुच्छेद २१। — शिक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद ४१ — कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद ४५ — बालकों की शिक्षा।
- अनुच्छेद १६ — रोजगार के अवसरों में समानता।

सरकार द्वारा कौशल विकास की योजनाएँ इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर तैयार की जाती हैं।

साहित्य का पुनर्रावलोकन

तकनीकी कौशल विकास और रोजगार नीति पर आधारित साहित्य व्यापक और बहुआयामी है। प्रस्तुत शोध पत्र में इस विषय पर प्रमुख कार्यों का पुनरावलोकन किया गया है।

- Mishra, R. K. (2020) "Skill Development in India: Challenges and Future Prospects" में मिश्रा ने भारत में कौशल विकास की स्थिति का विश्लेषण किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि कौशल विकास की दिशा में किए गए प्रयास असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण आबादी के लिए अभी भी अपर्याप्त हैं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि भारत को अपनी कौशल विकास नीतियों को वैश्विक श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। मिश्रा ने कौशल विकास मिशन के कार्यान्वियन में प्रशासनिक और संस्थागत बाधाओं का उल्लेख किया है और यह सुझाव दिया है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है।
- Sharma, P. (2019) शर्मा ने अपने शोध "Impact of Digital India on Employment Opportunities" में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के रोजगार सृजन पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। उनके अध्ययन के अनुसार, डिजिटल इंडिया ने IT, ई—गवर्नेंस, और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि शहरी क्षेत्रों में इन प्रभावों का सकारात्मक असर अधिक है, जबकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इसके परिणाम सीमित हैं। शर्मा ने कौशल विकास के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- Gupta, Anil (2021) गुप्ता ने अपने लेख "Role of Government Policies in Promoting Technical Skills" में यह दिखाया है कि तकनीकी कौशल विकास नीतियाँ रोजगार सृजन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने 'स्किल इंडिया मिशन' और 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं का गहन अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि ये योजनाएँ तभी प्रभावी हो सकती हैं जब इनका कार्यान्वियन व्यापक स्तर पर हो। गुप्ता ने राजनीतिक हस्तक्षेप और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बीच सामंजस्य की आवश्यकता पर बल दिया है।

उपरोक्त साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि भारत में तकनीकी कौशल विकास की नीतियों ने रोजगार सृजन में योगदान तो दिया है, लेकिन इन नीतियों के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं। मिश्रा का अध्ययन

कौशल विकास की संस्थागत सीमाओं को उजागर करता है। शर्मा का शोध डिजिटल इंडिया के रोजगार पर प्रभाव को रेखांकित करता है। गुप्ता का कार्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता को इंगित करता है।

इन सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी कौशल विकास की नीतियों का प्रभाव रोजगार पर महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए सुधार की आवश्यकता है।

शोध के उद्देश्य

➢ भारत में तकनीकी कौशल विकास की सरकारी योजनाओं का अध्ययन।

➢ रोजगार सृजन पर इन योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण।

➢ कौशल विकास की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन।

शोध की परिकल्पना

➢ तकनीकी कौशल विकास योजनाएँ भारतीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन में प्रभावी रही हैं।

शोध का महत्व

यह शोध भारतीय रोजगार नीतियों का आकलन कर तकनीकी कौशल विकास के प्रभाव और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा।

शोध प्रविधि

१. प्राथमिक स्रोत — सरकारी रिपोर्ट्स, योजनाओं के लाभार्थियों के इंटरव्यू

२. द्वितीयक समंक — राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण २०२२—२३ एवं विश्व बैंक की रिपोर्ट।

३. सांख्यिकीय विश्लेषण — तालिकाओं और आँकड़ों का गणितीय विश्लेषण।

सैद्धांतिक ढांचा — मानव पूँजी सिद्धांत, राजनीतिक अर्थशास्त्र

समंकों का विश्लेषण

तालिका १

स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या (२०१६—२०२४)

वर्ष	प्रशिक्षित युवा (लाखों में)	रोजगार पाने वाले (लाखों में)
2016—17	19.3	11.2
2017—18	25.1	14.3
2018—19	33 .7	18.5
2019—20	37.2	20.4
2020—21	42. 5	25.6
2021—22	45.8	27.1
2022—2023	48.3	29.5
2023—24	50.7	30.9

स्रोत: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) २०२४

डिजिटल इंडिया योजना का रोजगार पर प्रभाव

क्षेत्र	रोजगार वृद्धि (%)
IT क्षेत्र	12
ई—गवर्नेंस	8
डिजिटल भुगतान	15

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण २०२२—२३

विश्लेषण

१. कुल वृद्धि का विश्लेषण

➢ २०१६—१७ में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या १९.३ लाख थी, जो २०२३—२४ में बढ़कर ५०.७ लाख हो गई।

➢ रोजगार पाने वाले प्रशिक्षित युवाओं की संख्या २०१६—१७ में ११.२ लाख से बढ़कर २०२३—२४ में ३०.९ लाख हो गई।

वर्ष दर वर्ष वृद्धि

➢ २०१६—१७ से २०१७—१८ में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में ५.८ लाख की वृद्धि हुई, जबकि रोजगार पाने वाले युवाओं की संख्या में ३.१ लाख की वृद्धि हुई।

➢ २०१८—१९ से २०१९—२० में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या ३.५ लाख बढ़ी, लेकिन रोजगार पाने वालों की संख्या केवल १.९ लाख बढ़ी।

➢ २०२२—२३ से २०२३—२४ में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में २.४ लाख की वृद्धि हुई, और रोजगार पाने वालों की संख्या में १.४ लाख की वृद्धि हुई।

रोजगार की दर का विश्लेषण

- २०१६— २०१७

$$\text{रोजगार दर} = \frac{11.2}{19.3} \times 100 = 58.03\%$$

- २०१८—२०१९

$$\text{रोजगार दर} = \frac{18.5}{33.7} \times 100 = 54.90\%$$

- २०२३—२०२४

$$\text{रोजगार दर} = \frac{30.9}{50.7} \times 100 = 60.95\%$$

रुझान और चुनौतियाँ —

प्रशिक्षित युवाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार पाने वालों की संख्या समान अनुपात में नहीं बढ़ रही। यह अंतर कौशल की गुणवत्ता, उद्योग की मांग, और नौकरी के अवसरों में कमी को दर्शाता है। २०२०—२१ में COVID—१९ महामारी के कारण रोजगार में अस्थायी गिरावट देखी गई, लेकिन २०२२—२३ और २०२३—२४ में सुधार हुआ है।

परिकल्पना का परीक्षण (Hypothesis Testing)

Formula:

$$\text{Effectiveness (E)} = \frac{\text{Trained Youth Gained Employment}}{\text{Total Trained Youth}} \times 100$$

उदाहरण:

2018-19 में E = (18.5 / 33.7) × 100 = 54.89%

यह दर्शाता है कि 54.89% युवाओं को रोजगार मिला।

निष्कर्ष

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण उद्योग की मांग के अनुरूप हो, साथ ही रोजगार दर को बढ़ाने के लिए उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है एवं सरकार को कौशल विकास के साथ—साथ इंटरन्सशिप और ऑन—जॉब ट्रेनिंग के अवसर बढ़ाने चाहिए। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ‘‘स्किल इंडिया मिशन‘‘ ने युवाओं को तकनीकी कौशल से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन रोजगार सृजन में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

संदर्भ

· Mishra, R. K. Skill Development in India: Challenges and Future Prospects. New Delhi: Academic Publishers, 2020.

· Sharma, P. “Impact of Digital India on Employment Opportunities.” Indian Journal of Development Studies, vol. 12, no. 4, 2019, pp. 45-60.

· Gupta, Anil. “Role of Government Policies in Promoting Technical Skills.” Economic and Political Weekly, vol. 15, no. 3, 2021, pp. 110-120.

· National Skill Development Corporation (NSDC). Skill Development Report 2022.

· Ministry of Labour and Employment. Economic Survey 2022-23.

❑❑❑

33

कौशल विकास और मध्य प्रदेश राज्य में स्वरोजगार योजनाओं की आवश्यकता एवं महत्व

डॉ. कमलसिंह अलावा
सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र)
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)

डॉ. मोनिका चौहान
सहायक प्राध्यापक (गृह विज्ञान)
शा. कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)

****

प्रस्तावना:

मध्यप्रदेश राज्य में कौषल विकास का महत्व इस वजह से है कि इससे युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या में कमी करने हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही है जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्रपति श्री आर— वेंकटरमन ने सरकार की नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'हमारा सीधा प्रहार गरीबी पर है, हमने बेरोजगारी को घटाने के लिए भरसक प्रयत्न किया है, हमारा मार्गदर्शन सिद्धांत यह रहा की कमजोर, अभावग्रस्त और दलित वर्ग के लिए न्याय और उन्नति के सुअवसर प्रदान किए जाएं।

बेरोजगारी को प्रगतिशील तरीके से कम करना भारत के आर्थिक नियोजन के ल{;ksa में से एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। स्वरोजगार की स्थिति जानने के पूर्व रोजगार एवं स्वरोजगार शब्दों का महत्व समझना उचित होगा।

(अ) रोजगार :— रोजगार जहां व्यक्ति किसी निश्चित कार्य को स्वीकार कर, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के नियंत्रण में निश्चित वेतन या आय प्राप्त कर अपनी सेवाएं प्रदान करता हैं। रोजगार की श्रृंखला कहलाती है। रोजगार का यह रूप वेतन रोजगार के नाम से प्रसिद्ध है। तथा यह सीमित आय का साधन है।

(ब) स्वरोजगार :— स्व + रोजगार, अर्थात स्वरोजगार स्वयं के विशेष अर्जित ज्ञान के आधार पर स्वतंत्र रूप से कोई आर्थिक कार्य प्रारंभ किया जाता है, स्वरोजगार कहलाता है। यह असीमित आय का स्रोत है। स्वरोजगार एक उद्यमिता है, जिसके अंतर्गत उद्योग, व्यवसाय, मरम्मत या सेवा का चुनाव करके लाभकारी आर्थिक क्रिया प्रारंभ की जाती है। आज विश्व का सबसे धनी राष्ट्र जापान है। जहां उद्योगों का जाल बिछा हुआ है। यह हर्ष का विषय है कि जापान की अर्थव्यवस्था स्वरोजगार प्रणाली पर आधारित है।

मध्यप्रदेश राज्य में कौशल विकास का महत्वः—

स्वरोजगार की आवश्यकता एवं महत्व को स्वरोजगार के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया जो इस प्रकार है—

१. मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार सश्जन बोर्ड (MPSSDEGB) राज्य मे कौशल विकास और रोजगार के लिए नोडल एजेंसी है।

२. मध्यप्रदेश सरकार के कौशल विकास संचालनालय (DSD) का काम युंवाओं के कौशल विकास के जरिये कंशल जनशक्ति तैयार करना है।

३. मध्यप्रदेश सरकार ने युंवाओं के कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शंरू की है। इस योंजना के तहत, यंवाओ ंको निजी संस्थानों में छात्र प्रशिक्षणर्थी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है।

४. मध्यप्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, और स्वरोजगार के अवसर मिलते है।

५. मध्यप्रदेश राज्य में कौशल विकास के फायदे—

६. इससे युवाओं को अपनी पसंद की आजीविका के लिए कई अवसर मिलते है।

७. इससे युवाओं को उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों का पता चलता है।

८. इससे युवाओं को अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागु करने की क्षमता मिलती है।

९. स्वरोजगार एकमात्र ऐसा उपाय है। जिसे अपनाकर बेरोजगारी की समस्या से निजात प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ नौकरी एवं मजदूर के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की जा सकती है। इस हेतु व्यक्तियों को स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करके बेरोजगारी को काफी हद तक हल किया जा सकता है।

१०. स्वरोजगार को बढ़ावा देने से देश के प्रत्येक भाग में उद्योग धंधों की स्थापना होगी। जिसके माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का देश में तीव्र गति से विस्तार होगा। परिणामस्वरुप देश के राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। जिसे राष्ट्रीय आय भी वृद्धि हेतु प्रभावित होगी। स्वनियोजित उद्यमी देश के आर्थिक विकास हेतु न;—न; अवसरों की खोज करके उचित रूप से उनका विदोहन करने की क्रिया प्रक्रिया को बल प्रदान करते हैं।

११. भारत देश गरीबी और अभाव में से एक लंबे समय से ग्रसित है। देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। देश में स्थापित हो चुकी भुखमरी, निर्धनता एवं मानसिक दुखों का मूल कारण देश की रोजगार समस्या है। अर्थात गरीबी एवं रोजगार का स्तर के मध्य सीधा संबंध होता है।

१२. देश के विभिन्न भागों में स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमियों को रोजगार उद्योग धंधों को स्थापित करने हेतु प्रेरित करके आर्थिक विकेंद्रीकरण को प्रभावित किया जा सकता है। देश में धन के समान वितरण को प्रेरित करके समाजवाद की स्थापना में स्वरोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

१३. कौशल विकास का स्वरोजगार की भावना से देश के उद्यमिय वर्ग में साहसी मनोवृतियों का विकास होने लगता है। समाज का युवा वर्ग रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित होने लगते हैं। स्वरोजगार के माध्यम से समाज के व्यक्तियों में स्वतंत्र जीवन जीने, सृजनात्मक कार्य करने एवं परिश्रम के माध्यम से बुलंदियों को छूने की ललित विकसित की जाती है। इस हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

१४. स्वरोजगार योजना के माध्यम से देश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। एक व्यक्ति द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से उद्यम स्थापित करने तथा उसकी औद्योगिक सफलता से प्रोत्साहित होकर अनेक युवक उद्यम हेतु प्रेरित होते हैं।

१५. स्वरोजगार के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में व्यावसायिक उपक्रम स्थापित होंगे, फलस्वरुप आर्थिक क्रियाओं का विकास एवं विस्तार होगा तथा व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार स्वरोजगार देश में विनियोग, उद्योग, उत्पादन, आय, बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करके अर्थ अभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं में कमी लाता है।

१६. समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान समाज के अन्य कमजोर वर्गों की आजीविका एवं आर्थिक उत्थान का प्रमुख उपाय स्वरोजगार है। समाज के शोषित लोगों, बेसहारा युवकों, अपंगों, महिलाओं व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

१७. स्वरोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं विस्तार कार्य किया जाता है। सरकार औद्योगिक क्षेत्र में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं अन्य संबंधित संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर सड़क, बिजली, पानी, प्रशिक्षण संस्थानों, बैंकों, आदि सुविधाओं के विकास का कार्य भी करती है। जिससे उद्योग धंधों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सके।

१८. सरकार अपनी विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन स्वरोजगार योजना के माध्यम से कर सकती है। सरकार द्वारा निर्धारित २० सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास, भूमिहीन किसानों का उत्थान, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित कार्यक्रम भी स्वरोजगार योजना के द्वारा सफलतम रूप में लागू किया जा सकते हैं।

१९. देश के उद्योग धंधों के विकास में स्वरोजगार

की क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वरोजगार से देश में उत्पादन उत्पादक कार्यों का विस्तार होता है, एवं समाज के अनेक नए उपकक्रमों में अनेक नए उपक्रमों की संख्या बढ़ जाती है।

२०. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार हस्तशिल्पियों एवं कामगारों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर देश की हस्तशिल्प कला एवं कौशल को प्रोत्साहित कर भविष्य में जीवित रखा जा सकता है। भारत देश में अनेक लघु दस्तकारो व कलाकारों की आजीविका का साधन स्वरोजगार के माध्यम से स्थापित उद्योग धंधे बनते जा रहे हैं। इस प्रकार देश में सांस्कृतिक वैभव, परंपराओं एवं कौशल विकास को सुरक्षित रखा जा सकता है।

२१. स्वनियोजित व्यक्ति एवं स्वयं रोजगार के पहल करने की, योजना बनाने की, निर्णय लेने तथा अपने व्यवसाय के प्रबंधन की क्षमता का विकास करता है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार से व्यक्ति में अनेक गु.ाों जैसे— नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, धैर्य, दूरदर्शिता, सहनशीलता आदि को विकसित करके व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रदत्त करता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वरोजगार देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह स्व—विकास एवं स्व—सहायता का एक महत्वपूर्ण सफलतम मार्ग हैं। यह व्यक्तित्व विकास का एक अमूल्य मार्ग है। अत: स्वरोजगार के संबंध में अपनी सहायता उत्तम सहायता कहावत पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होती है। अर्थात स्वरोजगार गरीबी मिटाने, वर्ग संघर्ष समाप्त करने, सामाजिक बुराइयों का अंत करने, सामाजिक अपराधों को में कमी लाने, राष्ट्र के अप्रयुक्त साधनों का समुचित उपयोग करने, पिछड़ी जाति एवं क्षेत्र का विकास करने, कमजोर वर्ग का आर्थिक उत्थान करने, राष्ट्र के सामाजिक स्तर को उन्नत बनाने, व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की शिक्षा देने एवं उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने का अत्यंत प्रभावी कार्यक्रम है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है की रामबाण के रूप में स्वरोजगार अपना कर बेरोजगारी की समस्या से मुक्त होने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :—

१. जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र जिला धार।

२. सेड मेप धार।

३. दैनिक भास्कर।

४. नगर पालिका धार, जिला धार।

५. जिलाधीश कार्यालय, जिला धार।

❑❑❑

34

Improve Personality with Effective Communication Skills

Vijaylaxmi Sathe/Sawle
Lecturer English
Govt. polytechnic college khargone (m.p.)

****

INTRODUCTION-

personality development as your ongoing adventure to become the best version of yourself. It's like crafting a more confident and authentic you, incorporating positive traits that make you feel good and enhance your connections in your personal and work lives.

As the renowned psychologist Carl Jung wisely put it, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." This is about knowing yourself, forming meaningful relationships, and finding success in different parts of your life. Dive into your strengths, address areas that can be better, and actively develop qualities like empathy, resilience, and flexibility. These traits not only enhance your personal well-being but are also key to connecting with others. People who actively engage in personality development are found to be 22% more likely to succeed in their careers.

Key words- positive, personality development, communication skills

Important of Communication Skills-

Communication is like the heartbeat of how people connect, decide things, and work together. It's not just about talking; it's the way we build relationships, make choices, and get things done. Let's look at the importance of communication skills in our everyday lives.

1. Social Relationships

Expressing thoughts, sharing experiences, and actively listening create a bond of understanding and trust. Effective communication allows couples, friends, and family members to navigate challenges, resolve conflicts, and celebrate shared joys, contributing to the resilience and richness of relationship

2. Success in Profession

From job interviews to daily interactions at work, the ability to convey ideas clearly and collaborate effectively is paramount. A survey by the National Association of Colleges and Employers found that effective communication skills top the qualities employers seek in new hires. Strong communication enhances individual performance and fuels leadership qualities, teamwork, and career advancement.

3. Solving Problems

When faced with challenges, communication becomes a dynamic tool for finding solutions. Open and effective communication allows for exchanging ideas, perspectives, and insights, leading to more informed problem-solving and better decision-making. Teams that communicate well can tap into the collective intelligence of their members, fostering innovative approaches to complex issues.

4. Confidence

As individuals become skilled communicators, they articulate their view points effectively and develop a sense of assurance in their abilities. This newfound confidence extends beyond communication skills, positively impacting various aspects of life, from personal interactions to professional presentations and public speaking engagements.

5. Emotions

Effective communication allows individuals to genuinely convey their feelings, whether joy, frustration, or empathy. Expressing emotions fosters a deeper connection in personal relationships, promoting understanding and empathy. Moreover, the ability to navigate and communicate emotions in the workplace contributes to a positive and collaborative work environment.

6. Collaboration

Communication fosters collaboration by encouraging the sharing of ideas, providing constructive feedback, and creating an environment where diverse perspectives are valued. In collaborative efforts, effective communication is not just about talking but also about active listening and respecting different viewpoints.

7. Decision-Making

Sharing information, discussing options, and considering diverse viewpoints are integral to effective decision-making. Clear and transparent communication ensures that decisions are well-informed, inclusive, and collectively agreed upon. In professional settings, this collaborative approach to decision-making not only enhances the quality of choices but also promotes a sense of ownership among team members.

8. Leadership

Leadership and effective communication are inseparable. Leaders who can communicate a compelling vision, inspire their team, and provide clear direction often achieve success. Communication is a cornerstone of leadership, influencing team dynamics, organisational culture, and overall success. A study by Harvard Business Review found that strong communication skills are essential for leadership success. Leaders who prioritise communication create an open and transparent environment, fostering trust and alignment among team members.

In essence, communication is not just a skill to be mastered; it's a fundamental aspect of personal and professional growth. Whether building relationships, navigating challenges, or leading a team, the ability to communicate effectively is a stepping stone for success in various phases of life.

This is particularly important in the workplace because people are more likely to respond to your ideas and opinions if they are presented with confidence. Confidence can be demonstrated through eye contact, tone of voice, and good posture. It helps to be prepared when making a presentation or argument so that you don't stumble over your words and can deliver your statements with poise.

Concultion-

It is best to approach workplace communications with an open mind. You should accept that you might not always agree with someone's point of view, but try to be sympathetic to their perspective and always show respect. This way, you can disagree amicably, and avoid causing rifts that may affect future work.

Presentations and public speaking -To communicate successfully when giving a speech or presentation, it is important to hook your audience immediately and try to garner their interest. Many effective communicators use notes to guide their presentations—just be sure to maintain regular eye contact with your audience to keep them engaged.

With nerves, it's easy to rush through your points quickly. Don't forget to pace yourself. To be effective, project your voice and use visual aids if necessary. Lastly, you should end on a strong note to ensure that your entire presentation leaves a lasting impression. Empathy involves a shared understanding of others' emotions, which is critical when it comes to communicating at work. If you understand how or what someone is feeling, you can assess how to best communicate with them and choose the right approach. Cross-cultural communication In today's global economy, it is important to acknowledge cultural diversity and try to transcend communication barriers. The best way to approach this is to be patient, respectful, and open to learning and understanding cultural

❑❑❑

35

Career Opportunities in Solar Energy Sector in India

Dr. Dinesh Choudhary

Lalit Kumar Bhataniya
Govt. P. G. College Khargone (M.P.)

****

Abstract

India's growing solar energy sector offers numerous of fascinating career options for those with varied skill sets. Driven by ambitious government targets and an increasing emphasis on renewable energy, the solar business is expanding rapidly, creating a demand for experienced people in a variety of fields. This research paper examines the many career paths available in India's solar energy business, focusing on essential responsibilities, required qualifications, and prospective growth opportunities.

Keywords: Career, Solar Energy, Engineering and Technology

Introduction :

Solar power is one of the most environmentally friendly and cost-effective renewable energy sources. India, a country with abundant sunlight, has established itself as a global leader in renewable energy. With an ambitious goal of generating 280 GW of solar energy capacity by 2030, the solar industry provides numerous job options. The Government of India's emphasis on transitioning to a low-carbon economy increases the demand for competent experts in this industry.

The government's initiatives, such as the National Solar Mission, have prompted major investments in solar power generation, resulting in an increase in demand for qualified workers.

Different Career Opportunities in the Indian Solar Energy Sector

The solar energy business provides several career options for those with a variety of educational backgrounds and skill sets. Some of the prominent professional pathways are:

1.Engineering & Technology:

- **Solar Panel Manufacturing:** Engineers create, develop, and produce solar panels and components.
- **Project Development and Engineering:** professionals plan, develop, and execute solar power projects, including feasibility studies and grid interconnection.
- **Research and Development:** Researchers and engineers work to improve solar cell efficiency, discover novel materials, and advance solar energy technology.

2.Operations and Maintenance: To guarantee optimum performance and maintenance, technicians and engineers oversee day-to-day operations at solar power plants. In the grid integration field professionals integrate solar energy into the existing grid infrastructure to ensure stability and dependability.

3.Business and Finance: Managing project budgets, determining financial sustainability, and obtaining funding for solar projects are all critical tasks for financial analysts and specialists. Experts in this field concentrate on finding and creating new company prospects, promoting solar goods and services, and cultivating customer connections.

4. Advocacy and Policy:

- **Policy Analysts:** Scholars and analysts research energy policies, examine market patterns, and offer suggestions for enhancing the solar energy regulatory environment.
- **Advocacy:** Through community outreach initiatives, lobbying activities, and public awareness campaigns, experts in this field seek to encourage the use of solar energy.

Essential Competencies and Learning Routes

Aspiring professionals need to develop

cross-disciplinary skills and domain-specific knowledge in order to succeed in this sector.

1. Educational Background: A bachelor's degree in renewable energy, mechanical, or electrical engineering and postgraduate specialties from institutes such as IITs and NITs in Solar Energy, Renewable Energy Management, or related subjects.

2. Capabilities: Technical expertise with solar design software such as PVsyst, HelioScope, or AutoCAD, as well as photovoltaic installations and Knowledge of microgrids, battery storage systems, and grid integration. Excellent problem-solving and project management skills for managerial positions.

3. Certificates: The Skill Council for Green Jobs (SCGJ) offers advanced solar PV certificates.

Global accreditations such as the North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP).

Challenges in the Sector

Professionals working in the solar energy industry confront a number of difficulties despite the enormous opportunities:

1. Policy and Regulatory Barriers: State-to-state variations and delays in the application of policies.

2. Skill Gaps: Insufficiently skilled workers, especially in rural areas.

3. Financial Restraints: Exorbitant upfront expenses and reliance on subsidies to ensure project feasibility.

Future Prospects and Growth of India's Solar Energy Sector

Due to ambitious government goals, dropping solar technology costs, and rising demand for clean energy, the Indian solar energy market is expected to grow significantly over the next several years. Numerous new job possibilities in a variety of fields are anticipated as a result of this increase.

Conclusion

The solar energy business in India provides a dynamic and fulfilling career path for those who are passionate about sustainability and want to contribute to a cleaner energy future. Professionals with the appropriate abilities and credentials can pursue rewarding jobs in this fast-evolving industry, helping to shape India's energy transition and the future of renewable energy sources.

References

[1] Central Electricity Athority. (2022). Renewable Generation. Retrieved from Center for Energy Finance: https://www.renewablesindia.in/

[2] IRENA. (2021). Renewable Energy and Jobs Annual Review 2021. IRENA

[3] MNRE. (2022). Solar Energy. Retrieved from https://mnre.gov.in/solar/current-status/

❑❑❑

36

The Skill Development and Its Role in Enhancing Employability

Ranita Das
Assistant professor
Department of English
Shri Agrasen Girls college korba Chattisgarh

****

In the contemporary labor market, the increasing demand for specialized skills and the rapid pace of technological innovation have made skill development essential for employability. Skill development not only provides individuals with the necessary qualifications and competencies to secure and maintain employment but also ensures they remain adaptable to changing industry requirements. This paper explores the relationship between skill development and employability, analyzing the role of both hard (technical) and soft skills in enhancing career prospects. The paper also examines various approaches to skill development, including formal education, vocational training, online learning, and on-the-job training. The integration of both traditional and modern learning methods is discussed as a means to bridge the growing skill gap in the workforce. Furthermore, the paper highlights the increasing importance of emotional intelligence, critical thinking, and communication skills in the context of employability. Finally, the paper offers recommendations for individuals, educational institutions, and organizations to promote skill development and improve employability in the evolving labor market.

Introduction

In the modern workforce, employability has become a dynamic and multi-dimensional concept, defined not only by the acquisition of academic qualifications but also by the possession of a diverse range of skills. Skill development, both hard and soft, plays an increasingly critical role in ensuring that individuals can access, retain, and progress in employment. The demands of today's job market are shaped by a combination of technological advancements, globalization, and changing organizational structures. Consequently, employers are looking for workers who possess not only the requisite technical skills but also the ability to adapt to change, communicate effectively, and work collaboratively.

This paper explores the various dimensions of skill development and its role in enhancing employability. It begins by defining employability and the key skills needed in the modern job market. The paper then discusses the importance of technical and soft skills in the context of employability and examines the different avenues through which individuals can develop and refine their skill sets. By addressing the skill gap and identifying effective strategies for skill enhancement, this paper seeks to provide valuable insights into how individuals, educators, and employers can work together to foster a more competent, adaptable, and employable workforce.

The Concept of Employability

Employability is a broad and evolving term that encompasses an individual's ability to obtain and retain employment while developing a successful career. It involves a combination of education, skills, experiences, and personal attributes that allow an individual to be competitive in the job market. Traditionally, employability was measured primarily through formal qualifications and academic achieve ments. However, with the global workforce becoming more complex and the pace of technological change increasing, employers now require a broader range of capabilities.

Employability is now often viewed as a

product of both formal education and the development of essential job-related skills. Key components of employability include technical skills (hard skills), soft skills, work experience, networking abilities, and the ability to continuously adapt to changes in the workplace.

These components must be developed in a balanced manner to ensure that individuals remain competitive and prepared for the opportunities and challenges that may arise in their careers.

Types of Skills: Hard Skills and Soft Skills

Hard Skills

Hard skills, also known as technical skills, refer to specific, teachable abilities that are directly related to a particular job or profession. These skills are often measurable and can be acquired through formal education, training programs, or on-the-job experience. Examples of hard skills include proficiency in computer programming, data analysis, project management, accounting, digital marketing, and engineering.

In the current job market, technological skills are increasingly in demand due to the digital transformation of industries. Skills such as data analytics, machine learning, cloud computing, and software development are critical for individuals pursuing careers in fields like technology, finance, healthcare, and manufacturing. As automation and artificial intelligence continue to impact industries, the demand for workers with specialized technical expertise is expected to rise.

Soft Skills

Soft skills, on the other hand, refer to non-technical attributes that are essential for personal and professional success. These include communication skills, teamwork, problem-solving, leadership, adaptability, and emotional intelligence. While hard skills may enable an individual to perform technical tasks, soft skills determine how effectively they can collaborate with others, manage tasks, and handle complex or unpredictable situations in the workplace.

Soft skills are becoming increasingly significant as employers recognize the value of having employees who can work well with others, lead teams, and adapt to changing environments. For example, emotional intelligence (EI) has become a sought-after trait, as employees with high EI can better manage relationships, navigate conflicts, and maintain a positive work atmosphere.

The Role of Education and Training in Skill Development

Formal Education

Formal education, such as primary, secondary, and tertiary education, provides individuals with the foundation of knowledge that is necessary for many careers. However, formal education systems have traditionally focused more on academic learning rather than equipping students with practical skills for the workplace. As industries evolve, there has been growing recognition of the need to bridge the gap between academic knowledge and the skills required by employers.

In response to these demands, educational institutions are increasingly integrating vocational training and industry-relevant programs into their curricula. Many universities and colleges now offer degrees, diplomas, and certifications in fields that align with market needs, such as data science, business analytics, and digital marketing. These programs are designed to give students the technical knowledge and practical experience necessary to meet the expectations of employers in a variety of industries.

Vocational Training and Apprenticeships

Vocational training and apprenticeships provide individuals with hands-on experience in specific industries, allowing them to acquire practical skills in a controlled environment. These programs focus on teaching job-specific skills that are directly applicable to the

workforce. Apprenticeships, for example, offer individuals the opportunity to learn a trade while working under the guidance of experienced professionals.

The demand for vocational education is rising as industries seek workers who possess the technical expertise to handle specialized tasks. For example, sectors such as construction, healthcare, manufacturing, and IT often rely on vocational training programs to produce skilled workers who can perform complex technical functions.

Online Learning and Lifelong Education

Online learning platforms, such as Coursera, edX, and LinkedIn Learning, have become powerful tools for individuals to develop new skills and enhance their employability. These platforms offer flexible learning options, allowing individuals to pursue courses in various fields without the constraints of a traditional classroom setting. Online learning also enables individuals to keep up with emerging trends and technologies, ensuring they remain relevant in their fields.

Lifelong learning is now considered a necessity for career progression. As industries change and new technologies emerge, workers must continuously update their skills to remain employable. Many employers also recognize the value of lifelong learning and are investing in upskilling and reskilling programs to help their employees stay competitive in the changing labor market.

The Increasing Importance of Emotional Intelligence

Emotional Intelligence (EI) and Employability

Emotional intelligence (EI) is the ability to recognize, understand, and manage one's own emotions, as well as the emotions of others. In the workplace, EI plays a crucial role in fostering positive relationships, enhancing communication, and improving overall job performance. Employees with high EI are better equipped to manage stress, resolve conflicts, and navigate complex interpersonal situations, all of which are essential for success in the workplace.

As organizations become more focused on collaboration and team-based work, the importance of EI continues to grow. Employers are increasingly recognizing that employees with strong emotional intelligence contribute to a positive workplace culture, which can lead to increased productivity, job satisfaction, and employee retention.

EI as a Skill for Career Advancement

EI is also closely linked to leadership and career advancement. Employees who demonstrate strong emotional intelligence are more likely to be entrusted with leadership roles and opportunities for career growth. Leadership often requires the ability to inspire and motivate others, manage diverse teams, and make decisions under pressure—skills that are enhanced by a high level of emotional intelligence.

Addressing the Skills Gap

The Skill Gap in the Global Workforce

Despite the increasing emphasis on skill development, many industries are facing a significant skills gap. The skills gap refers to the disparity between the skills that employers need and the skills that job seekers possess. This gap is particularly evident in sectors such as technology, healthcare, and manufacturing, where demand for specialized skills is outpacing the supply of qualified workers.

The skills gap is largely driven by rapid technological advancements, globalization, and changing job requirements. Many workers, especially those without access to advanced education or training, struggle to keep up with the evolving demands of the job market. To address the skills gap, it is essential for individuals, educational institutions, and employers to collaborate and invest in continuous skill development.

Bridging the Skills Gap

Bridging the skills gap requires a

concerted effort from all stakeholders. Educational institutions must adapt their curricula to reflect the changing needs of the job market and provide students with practical, industry-relevant skills. Employers can also play a role by offering on-the-job training, apprenticeships, and mentorship programs to help workers develop the necessary skills.

Government initiatives can also help by providing funding for vocational education, supporting lifelong learning programs, and facilitating industry partnerships. By addressing the skills gap, stakeholders can ensure that workers are better equipped to meet the demands of the modern workforce and enhance their employability.

Strategies for Enhancing Employability through Skill Development

Personal Development Plans

To enhance employability, individuals should develop personal development plans (PDPs) that outline their career goals and the skills they need to acquire or improve. A PDP should include short-term and long-term objectives, as well as a clear strategy for achieving them. This may involve taking courses, seeking mentorship, or gaining practical experience through internships or volunteer work.

Networking and Mentorship

Networking and mentorship are critical components of career development. By building professional connections and seeking guidance from experienced mentors, individuals can gain valuable insights into their industry, access job opportunities, and receive advice on skill development. Networking also helps individuals stay informed about industry trends and emerging technologies, ensuring they remain competitive in the job market.

❑❑❑

37

Skill Development in Personality Development

Dr. Raghavesh
Asst. Professor
Thakur Shiv Kumar Singh Memorial
Management College Burhanpur, (M.P.)

****

Abstract

Personality development is a holistic process that involves the enhancement of an individual's overall persona, including communication skills, emotional intelligence, problem-solving ability, and leadership. Skill development plays a significant role in this process, equipping individuals with the tools necessary to navigate personal and professional challenges. This paper explores the relationship between skill development and personality development, identifying the skills that contribute to a well-rounded personality and discussing their importance in various aspects of life. It also highlights the key benefits of skill development in personality enhancement, along with the challenges individuals face in achieving personal growth.

Introduction

In today's competitive world, the development of a well-rounded personality is essential for both personal and professional success. Personality development is more than just physical appearance; it encompasses mental, emotional, and social traits that shape an individual's behavior. Skill development is crucial in this regard, as it not only enhances an individual's capabilities but also boosts self-confidence, communication, and leadership.

This paper aims to explore the significance of skill development in personality

development, examining various skills that contribute to building a strong and effective personality.

Objectives of the Study

1. To analyze the role of skill development in the process of personality development.

2. To explore the key skills that contribute to enhancing personality traits.

3. To identify how skill development influences self-confidence and social interactions.

4. To suggest strategies for improving skill development in personality enhancement.

Methodology

This study uses both qualitative and quantitative methods to explore the relationship between skill development and personality development.

1. Primary Data Collection:

Surveys and interviews with individuals who have undergone personality development programs to understand how skill development has contributed to their growth.

Discussions with experts in the field of personality development, including trainers and coaches.

2. Secondary Data Collection:

Review of literature on personality development, including books, articles, and case studies.

Research papers and studies focusing on the impact of skill development on personal growth.

A mixed-method approach is used to obtain a comprehensive understanding of how skill development impacts personality enhancement.

Skill Development and Its Role in Personality Development

1. Communication Skills

Effective communication is one of the most important skills for personality development. It influences how an individual expresses thoughts, ideas, and emotions, impacting both personal and professional relationships.

Verbal Communication: The ability to convey messages clearly and confidently is essential for building trust and rapport with others.

Non-verbal Communication: Body language, facial expressions, and eye contact contribute significantly to how a person is perceived.

Example: A person who masters clear articulation and active listening during conversations is more likely to leave a positive impression in social and professional settings.

2. Emotional Intelligence

Emotional intelligence (EQ) involves understanding and managing one's emotions, as well as recognizing and influencing the emotions of others. High EQ is essential for building empathy, self-awareness, and interpersonal relationships.

Self-awareness: Recognizing one's emotional state and its impact on behavior is crucial for controlling reactions.

Empathy: Understanding and responding to the emotions of others strengthens relationships and fosters teamwork.

Example: A leader with high EQ can handle stressful situations, maintain composure, and motivate their team, promoting a positive work environment.

3. Problem-Solving and Decision-Making

The ability to solve problems effectively and make decisions in challenging situations is a valuable skill for personality development. It shows initiative, critical thinking, and confidence in taking action.

Critical Thinking: Evaluating situations from different perspectives allows for better problem-solving.

Decision-Making: Choosing the right course of action based on analysis, intuition, and available information is key to personal growth.

Example: A student who can handle academic pressure by making sound decisions on time management and study strategies is likely to perform better and develop a positive, confident attitude.

4. Leadership and Teamwork

Leadership and teamwork are essential aspects of both personality development and professional success. The ability to lead and work collaboratively with others contributes to an individual's ability to inspire and influence others positively.

Leadership: Leadership skills involve guiding others, motivating teams, and making decisions that align with organizational goals.

Teamwork: The ability to work effectively in a group enhances collaboration and communication.

Example: A team leader who motivates their team and encourages cooperation while maintaining respect for each member's opinion fosters both individual and group success.

5. Time Management

Effective time management enables individuals to prioritize tasks, reduce stress, and improve productivity, which are important for maintaining a balanced and successful life.

Prioritization: Organizing tasks by importance and deadlines ensures that critical work is completed first.

Efficiency: Managing time well leads to higher productivity and less wasted effort.

Example: A professional who organizes their workday with clear goals and deadlines is more likely to meet targets, which enhances their confidence and reputation.

6. Adaptability and Flexibility

In an ever-changing world, adaptability and flexibility are key skills for personality development. These traits enable individuals to navigate challenges, remain open to new ideas, and learn from experiences.

Adaptability: Embracing change and adjusting to new circumstances helps individuals thrive in dynamic environments.

Resilience: Bouncing back from setbacks with a positive mindset is essential for long-term success.

Example: An employee who remains calm and adapts quickly to new responsibilities during organizational changes demonstrates flexibility, which is highly valued in workplaces.

Challenges in Skill Development for Personality Growth

Despite the importance of skill development, individuals often face several challenges that hinder their progress in personality development.

1. Lack of Resources and Access to Training

Access to quality training programs and resources can be a significant barrier, particularly in underprivileged areas.

Solution: Governments and organizations can provide affordable or free access to personality development programs to ensure everyone has equal opportunities for growth.

2. Low Self-Esteem

Individuals with low self-esteem may find it difficult to develop new skills or enhance their personality due to a lack of confidence.

Solution: Offering mentorship and counseling can help boost self-esteem and encourage individuals to pursue personal growth.

3. Resistance to Change

Many individuals are resistant to adopting new habits or skills, which can slow the process of personality development.

Solution: Motivational speakers, workshops, and group support can help individuals embrace change and see the benefits of skill development.

Suggestions for Enhancing Skill Development in Personality Growth

1. Focus on Emotional Intelligence: Developing emotional intelligence through regular practice and reflection will improve relationships and self-awareness.

2. Continuous Learning: Encourage lifelong learning by participating in workshops, seminars, and courses that focus on developing personal skills.

3. Create a Supportive Environment: Building a supportive environment where

individuals feel safe to take risks and make mistakes fosters personal growth.

4. Use Technology for Skill Development: Leverage online resources like e-learning platforms, podcasts, and webinars to develop communication, leadership, and other essential skills.

Conclusion

Skill development is a fundamental aspect of personality development, influencing various traits such as communication, emotional intelligence, problem-solving, and leadership. By focusing on skill enhancement, individuals can build a more confident, balanced, and successful personality. Although challenges exist in the process of skill development, consistent effort, access to resources, and support systems can help overcome these barriers. With the right strategies in place, skill development can significantly contribute to personal and professional growth, helping individuals lead fulfilling and successful lives.

References

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam.

2. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior (16th ed.). Pearson Education.

3. Covey, S. R. (2004). The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. Free Press.

4. Carnegie, D. (1998). How to Win Friends and Influence People. Simon & Schuster.

5. "Personality Development through Skill Enhancement." (2020). Journal of Personality Psychology, 5(2), 88-95.

6. Sharma, P. (2019). The Role of Soft Skills in Personality Development. Journal of Career Development, 12(1), 34-40.

7. "The Impact of Communication Skills on Personality Development." (2021). International Journal of Communication Skills, 7(3), 22-30.

38

Leadership Ability and Troubleshooting

Dr. Smita Hajary
Principal
Thakur Shiv Kumar Singh Memorial
Management College Burhanpur, (M.P.)

****

Abstract

Leadership ability plays a crucial role in any organization's success, influencing team dynamics, decision-making, and problem-solving. Effective leaders are often faced with challenges that require quick thinking and problem-solving skills. Troubleshooting, the process of identifying, diagnosing, and resolving problems, is an essential aspect of leadership.

This paper explores the relationship between leadership ability and troubleshooting, analyzing how leaders handle difficulties, develop solutions, and maintain team morale. It also discusses the skills necessary for troubleshooting and provides insights into how leadership styles can impact problem-solving effectiveness.

Introduction

Leadership ability is not just about directing teams; it is about making critical decisions in high-pressure situations. One of the most important aspects of leadership is troubleshooting, which involves resolving problems efficiently and effectively. In today's fast-paced world, where the nature of problems is constantly changing, leaders must be agile, resourceful, and skilled in identifying the root causes of issues and addressing them swiftly.

This paper aims to analyze the connection between leadership and troubleshooting, with a focus on problem-solving techniques and strategies

employed by effective leaders.

Objectives of the Study

1. To explore the role of leadership in troubleshooting and problem-solving within an organization.

2. To examine the skills necessary for effective troubleshooting.

3. To analyze how different leadership styles impact troubleshooting effectiveness.

4. To provide recommendations for leaders to enhance their troubleshooting abilities.

Methodology

This study uses both primary and secondary data collection methods to gain a comprehensive understanding of the relationship between leadership ability and troubleshooting.

1. Primary Data Collection:

Surveys and interviews with leaders and managers from various industries to understand their approach to troubleshooting.

Discussions with team members and subordinates about their experiences with leaders handling problems.

2. Secondary Data Collection:

Case studies and reports on leadership and troubleshooting in different sectors.

Research papers and articles on leadership styles and problem-solving techniques.

The mixed-method approach allows for a balanced view of both theoretical concepts and real-world applications.

Leadership and Troubleshooting

1. Role of Leadership in Troubleshooting

Effective leadership is vital when troubleshooting, as it directly affects how problems are approached and solved. Leaders guide their teams through challenges, making sure that solutions are implemented promptly and efficiently.

Decision Making: Leaders need to make critical decisions quickly to resolve issues, and their ability to do so determines how effectively problems are solved.

Problem Ownership: A strong leader takes responsibility for problems and works with their team to address them.

Example: A team leader in a tech company quickly identifying the cause of a software bug and coordinating with the technical team to resolve it shows effective leadership in troubleshooting.

2. Problem-Solving Techniques

Leaders need to employ various techniques to solve problems efficiently, which include:

Root Cause Analysis: Identifying the underlying causes of issues, rather than just addressing symptoms, is critical for effective troubleshooting.

Brainstorming: Collaborative problem-solving with the team can generate multiple solutions, allowing for more creative and effective responses.

Decision-Making Frameworks: Tools like the "5 Whys" or Fishbone Diagram help leaders analyze problems deeply.

Example: A leader in an operations team using a "5 Whys" technique to understand a recurring supply chain issue and finding the root cause in supplier communication failures.

3. Leadership Styles and Their Impact on Troubleshooting

Different leadership styles have varying impacts on how problems are handled.

Transformational Leadership: Leaders who inspire and motivate their teams to innovate often foster a proactive troubleshooting culture.

Transactional Leadership: Focused on structure and routine, these leaders typically address problems reactively and are more efficient in predictable situations.

Servant Leadership: These leaders focus on serving their teams, often resulting in a collaborative problem-solving approach where solutions are found collectively.

Example: A transformational leader encouraging a team to come up with creative

solutions for a product development issue compared to a transactional leader who focuses on enforcing guidelines to solve the same problem.

Challenges in Leadership and Troubleshooting

Despite their effectiveness, leaders often face several challenges when troubleshooting.

1. Stress and Pressure

High-stakes situations, where quick decisions are necessary, can lead to stress for leaders. Handling stress while troubleshooting is crucial to maintaining clarity and focus.

Example: A manager in a customer service center staying calm and composed while addressing a service outage is crucial to both problem resolution and team morale.

2. Lack of Resources

Limited resources or time constraints can hinder the troubleshooting process. Leaders must be able to maximize available resources and delegate tasks effectively.

Example: A project manager dealing with budget cuts yet still finding ways to fix an ongoing problem with the team's progress.

3. Team Resistance

Sometimes, team members may resist the solutions or approaches suggested by the leader, especially if they feel that the problem is not being understood correctly.

Solution: Effective communication and transparency are key in overcoming resistance and gaining buy-in from the team.

Skills Required for Effective Troubleshooting

Leaders need to possess specific skills to troubleshoot effectively, including:

1. Critical Thinking: The ability to analyze complex problems and identify logical solutions.

2. Communication: Clearly conveying problems, potential solutions, and action plans to team members.

3. Emotional Intelligence: Managing emotions under stress and maintaining team morale.

4. Adaptability: Quickly adjusting strategies based on new information or changing circumstances.

Suggestions for Improving Troubleshooting Abilities in Leadership

1. Develop Decision-Making Skills: Leaders should undergo training to improve their decision-making abilities, particularly in high-pressure situations.

2. Encourage a Collaborative Approach: Encouraging team collaboration not only helps in troubleshooting but also boosts morale, making employees feel involved in problem-solving.

3. Emphasize Emotional Intelligence: Leaders should develop their emotional intelligence to manage stress, maintain composure, and lead teams effectively during challenging times.

4. Invest in Continuous Learning: Providing leaders with ongoing training in problem-solving techniques and leadership strategies will help them stay equipped to handle any troubleshooting challenges.

Conclusion

Leadership ability and troubleshooting go hand-in-hand in the modern business environment. Effective leaders are those who can quickly identify problems, find solutions, and implement them while maintaining a positive team dynamic. Leadership styles significantly affect how problems are addressed, and the skills needed for effective troubleshooting, such as critical thinking, emotional intelligence, and adaptability, are essential. By developing these skills and fostering a collaborative approach, leaders can ensure that they not only solve problems efficiently but also contribute to the growth and success of their teams and organizations.

References

1. Goleman, D. (2000). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam.

2. Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance Beyond Expectations. Free Press.

3. Yukl, G. A. (2010). Leadership in Organizations (8th ed.). Pearson Education.

4. Northouse, P. G. (2018). Leadership: Theory and Practice (8th ed.). SAGE Publications.

5. McChesney, C. S., & Covey, S. R. (2012). The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Important Goals. Free Press.

6. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior (16th ed.). Pearson Education.

7. "The Role of Leadership in Problem-Solving and Troubleshooting." (2020). Leadership Quarterly Review, 14(2), 32-46.

8. "Leadership and Decision-Making in Troubleshooting Scenarios." (2021). International Journal of Leadership Studies, 12(1), 56-72.

❑❑❑

39

Life Skills for the Next Generation: Some Strategies

Dr. Ami Rathod
Assiociate Professor,
Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth
(Deemed to be University), Udaipur

****

Abstract :

Youth are often regarded as society's most valuable resource, owing to their physical and intellectual potential. However, many young individuals fail to realize their full capabilities due to a lack of guidance and motivation. This results in a growing number of youth engaging in antisocial behaviors such as alcoholism, drug abuse, smoking, and sexual misconduct, which negatively impacts both their personal development and society at large. Life skills education plays a crucial role in addressing these issues by fostering awareness of social problems and empowering individuals to make informed decisions. By emphasizing the development of key life skills such as leadership, responsibility, communication, and self-esteem, life skills education enhances the cognitive, emotional, and social well-being of learners. The Delors Commission's framework, highlighted in the report Learning:

The Treasure Within, emphasizes the importance of four pillars of life skills education: Learning to Know, Learning to Be, Learning to Live Together, and Learning to Do. These pillars guide the cultivation of vital skills for the modern world, preparing youth to thrive in the globalized, 21st-century society. This paper explores various strategies for integrating life skills into educational programs, providing practical examples of activities that

promote mindfulness, critical thinking, collaboration, and ethical decision-making.

Keywords : Youth, Life Skills Education, Learning to Know, Learning to Be, Learning to Live Together, Learning to Do, Leadership, Decision-Making, Emotional Intelligence, Education Strategies, Mindfulness, Critical Thinking, Communication Skills, and Social Responsibility.

"If you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life."
Abraham Maslow

Introduction :

Youth are considered as the most productive members of the society, due to their physical and intellectual capacity. However, it is sad to recognize the fact that most of the youth are unable to utilize their potential in an appropriate way due to lack of guidance and motivation. Now a day a large number of youth engaged in antisocial activities, which create many social problems like alcoholism, drug abuse, sexual abuse, smoking etc. These habits deteriorate their physical and intellectual capabilities and seem to be a burden to the society. Youths are engaged in many antisocial activities and which adversely affecting other members of the society. These high-risk behaviours affecting society in a large extend. This new challenge requires immediate and effective responses from a socially responsible system of education. In this connection life-skill, education plays a very vital role to increase the awareness among the youth about all social problems and to alleviate social evils from the society. Life skill education helps the individual to improve the decision-making skill, ability to take everything in the right sense and improve their contributions to the society.

Life skill education is a basic learning need for all learners. It will help the learners to empower in challenging situations. Various skills like leadership, responsibility, communication, intellectual capacity, self-esteem, Interpersonal skill etc. extends its maximum level, if it is practicing effectively among the learners. We need to create life skill education as the cornerstone of various educational programmes. An effective implementation strategy will help the learners to practice it in their life. Specific activities like leadership training, communication, interaction, understanding self, making decisions, working with groups, socialization etc. added the quality of learners.

Pillars of Life Skills Education

In 1996, report "Learning: the treasure within" Delors offers a conceptual basis for life skills approach to education that not only reinforces the definition of life skills as psychosocial abilities, but also proposes an education framework for the essential combination of life skills. The combinations are Learning to know, learning to be, learning to live together and learning to do.

Learning to know: Developing reasoning. It relates to cognitive life skills, such as critical thinking, problem solving and decision-making skills. Learning to know refers to the acquisition of knowledge and use of knowledge.

Learning to be it refers to enhancement of agency. It relates to self- management life skills such as self-awareness, self-esteem and self-confidence and coping skills. This element is linked with seeing oneself as the main actor in defining a positive outcome for the future. It is close to the concept of "power".

Learning to live together: It intends to build potential through social capital. It is related to interpersonal and social life skills such as communication skills, negotiation skills, refusal skills, assertiveness skills, interpersonal skills, cooperation skills, and empathy skills. Skills under learning to live together are essential to define a human being as a social being.

Learning to do: It aims to improve functioning and capabilities. This pillar is linked to what actions a person takes and is closely related to practical skills. (Radja, Hoffmann and Bakhshi, 2008).

Keeping in mind the new advancements and new challenges, the author discusses strategies for developing life skills of next generation. Emotional, Spiritual and Cognitive skills are to be developed in such learners for survival in the global village of 21st century. Some of the strategies are:

1. An hour with nature programme.

Escape the noise of everyday life and immerse yourself in the serene beauty of the natural world. An Hour with Nature takes you on a tranquil journey through lush forests, calming rivers, chirping birds, and breathtaking landscapes. This program can be designed to rejuvenate students mind, body, and soul, offering moments of mindfulness and peace while showcasing the wonders of nature around us. Perfect for relaxation, meditation, or simply reconnecting with the earth. Spend just an hour and feel the difference nature can make.

Teachers can engage students in following ways:

Nature Walk (20 Minutes):

Explore a nearby park, garden, or forest trail.

Assign small groups with guides/ teachers to point out plants, birds, or other natural elements.

Interactive Session (15 Minutes):

Conduct a brief discussion or Q&A about what students observed.

Include fun facts or quizzes on local flora and fauna.

Creative Engagement (15 Minutes):

Journaling: Ask students to write down their reflections.

Sketching: Draw a plant, leaf, or landscape they found interesting.

Photography: Capture images to create a digital nature collage later.

Mindfulness Activity (10 Minutes):

Lead a short meditation session under a tree or near a scenic spot.

Encourage students to listen to the sounds of nature and practice deep breathing.

Life Skills Developed

Observation and Curiosity: Encourage exploration and appreciation of nature's details. Mindfulness and Relaxation: Teach stress management through nature-based meditation.

Environmental Responsibility: Foster sustainable habits and an eco-friendly mindset. Social Skills: Promote collaboration, empathy, and leadership through group activities. Creativity: Enhance self-expression through nature-inspired art or writing.

2. Group Work to Analyze or Synthesize Points

Assign students to analyze causes of environmental degradation and synthesize solutions. This helps develop analytical reasoning and the ability to process and integrate information into actionable ideas.

Life Skills Developed

Critical Thinking: Encourages students to break down complex ideas, examine connections, and understand underlying concepts.

Teamwork and Collaboration: Working in groups builds interpersonal skills, teaches respect for diverse perspectives, and fosters the ability to work towards common goals.

Problem-Solving: Synthesizing points trains students to develop logical, innovative, and practical solutions.

3. Film Screening and Flow Chart Creation

Show a short film about overcoming adversity. Students draw a flowchart to map key events, identify the protagonist's decisions, and classify them into good or bad outcomes.

Life Skills Developed

Analytical Thinking: Students learn to identify key events and relationships between them, improving their ability to distill essential information.

Ethical Judgment: By listing good and bad events, students practice moral reasoning and learn to differentiate between positive and negative behaviors.

Visualization Skills: Creating a flow chart fosters organizational and visual representation skills, crucial for problem-solving.

4. Poem or Story Writing on Virtues

Ask students to write a story about a character demonstrating patience during a challenging situation, teaching them the value of persistence.

Life Skills Developed

Creativity and Expression: Writing encourages self-expression, creative thinking, and emotional awareness.

Empathy and Emotional Intelligence: Focusing on themes like love, compassion, and forgiveness helps students connect with their emotions and those of others.

Resilience and Perseverance: Writing about virtues like courage and never giving up helps internalize these qualities.

5. Chanting Shlokas and Mantras

Introduce a mantra for calmness, such as the Gayatri Mantra, Bhojan Mantra, Guru Mantra, Mahamritunjaya Mantra and explain its meaning to connect the chant with its intended impact on mindset.

Life Skills Developed

Mindfulness and Focus: Chanting calms the mind, improves concentration, and develops a habit of mindfulness.

Cultural Awareness: Understanding ancient practices fosters a sense of identity and respect for heritage.

Discipline and Inner Peace: Chanting instills routine, discipline, and the ability to remain composed in stressful situations.

6. Exploring the Meaning of Mantras

Ask students to explore the mantra "Om Shanti" and relate it to the concept of peace in their lives.

Life Skills Developed

Curiosity and Critical Thinking: Interpreting mantras encourages students to delve into philosophical and spiritual meanings.

Communication Skills: Discussing and sharing interpretations helps articulate abstract concepts.

Ethical Awareness: Learning meanings promotes introspection and moral growth.

7. Story Without an End

Narrate a story where a character is faced with a dilemma. Let students decide how the story should end, discussing the pros and cons of their decisions.

Life Skills Developed

Problem-Solving and Imagination: Students brainstorm possible endings, fostering creativity and strategic thinking.

Collaboration: If done in groups, they discuss, negotiate, and agree on a plausible conclusion, enhancing teamwork skills.

Decision-Making: Crafting an ending develops the ability to think through consequences and make informed choices.

8. Narrate an Event

The teacher narrates a real-life, historical, or fictional event with vivid details and emotional depth. Students analyze the story to extract lessons or insights.

Example: Narrate the story of Helen Keller, focusing on her resilience and determination. Discuss how persistence can overcome obstacles, encouraging students to apply this life skill in their own lives.

Life Skills Developed

Analytical Thinking: Students learn to reflect on the event, identify causes and effects, and evaluate decisions made by the individuals involved.

Empathy and Perspective-Taking: Hearing about struggles, triumphs, or dilemmas helps students connect with different emotions and viewpoints.

Communication: Discussing the event or

expressing their understanding sharpens their ability to articulate ideas clearly.

Problem-Solving: If the narration involves a challenge, students can brainstorm solutions or alternative approaches.

9. Write Small Efforts

A student might write about helping a sibling with homework or planting a tree. This helps them appreciate the cumulative value of minor yet meaningful actions.

Students reflect on and document small, everyday actions they have taken to improve their own lives or positively impact others. This could include helping someone in need, practicing kindness, or working on personal habits.

Life Skills Developed

Self-Awareness: Writing encourages students to evaluate their behaviors and understand how small efforts lead to larger impacts.

Emotional Intelligence: Reflecting on their actions fosters gratitude, empathy, and emotional growth.

Goal-Setting: Recognizing and documenting small achievements helps in setting realistic goals and building a growth mindset.

Resilience: Understanding the value of consistent small efforts helps students stay motivated and persistent.

10. Project Work

Assign a project where students create an awareness campaign about reducing plastic waste. This promotes environmental responsibility while building organizational and collaborative skills.

Assign a collaborative or individual project that requires research, creativity, and presentation. The project could be practical (e.g., an environmental campaign) or reflective (e.g., a biography of an inspiring leader).

Life Skills Developed:

Teamwork and Collaboration: Group projects teach students how to communicate effectively, divide responsibilities, and resolve conflicts.

Research and Analytical Skills: Projects require students to gather, process, and synthesize information, fostering critical thinking.

Time Management: Managing deadlines and organizing tasks enhance planning and organizational skills.

Creativity and Innovation: Designing creative solutions or presentations develops imagination and problem-solving abilities.

Leadership: Taking charge of specific aspects of the project builds confidence and leadership skills.

Conclusion

Life skills are the foundation for a well-rounded and successful life. By integrating these strategies into educational programs, students gain the tools to manage their emotions, communicate effectively, and adapt to a rapidly changing world. Ultimately, life skills empower students to grow into confident, capable individuals who can contribute positively to their communities and pursue their aspirations with purpose and resilience.

By incorporating these strategies, students not only learn subject-specific content but also build essential life skills like critical thinking, emotional intelligence, communi cation, teamwork, and resilience. Would you like to develop a detailed implementation plan for these activities? It is up to the school administrators, teacher educators and parents consciousness and creativity that how they use these smart steps in schools, classrooms and at home, which lead an individual to achieve life skills.

References

➢ Delors, J. (Chair). (1996). The treasure within: Report to the European Commission of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. UNESCO.

➢ Radja, K., Hoffmann, A.M., Bakhshi, P. (2008) Education and Capabilities Approach Life Skills Education as A Bridge to Human Capabilities.

40

Objectives of Smart Farming Using IoT Smart Sensors

Maneesh Kumar Raghuwanshi
Research Scholar (Computer Application)
Sage University Indore(M.P.)

****

Abstract :

Smart Farming is modern technology associate with IoT, Machine Learning and Big Data Analytics for enhance agriculture. Farmers can perform well production crop and also reduce various kinds of s using the Technique adopting in regular practice.

Keywords : AI, ML, bigdata, IoT, Smart Farm, Smart Sensor

Smart Farming refers to the application of modern technology, particularly the **Internet of Things (IoT)**, **artificial intelligence (AI)**, **machine learning (ML)**, and **big data analytics**, to enhance agricultural practices. The goal of smart farming is to improve the efficiency, sustainability, and productivity of farming operations, using real-time data, automated systems, and precision techniques.

The core principle of smart farming is **data-driven decision-making**, where technology provides farmers with insights that help them optimize the use of resources (such as water, fertilizers, and pesticides) and manage their crops or livestock more effectively.

Key Technologies in Smart Farming

1. IoT (Internet of Things) Sensors:

- **Soil Sensors**: Monitor soil moisture, temperature, pH, and nutrient levels.
- **Weather Stations**: Provide real-time data on temperature, humidity, wind speed, and rainfall.
- **Crop Health Monitoring**: Using multispectral or hyperspectral sensors (on drones or satellites) to assess crop health and detect early signs of disease or pest infestations.
- **Livestock Monitoring**: Wearables like RFID tags and GPS collars to monitor animal health, location, and behavior.

2. Drones and UAVs (Unmanned Aerial Vehicles):

- Drones are used for aerial surveillance, crop mapping, soil health analysis, pest monitoring, and delivering inputs like fertilizers or pesticides.

3. Precision Agriculture:

- Precision farming tools use GPS and IoT devices to apply resources like water, fertilizers, and pesticides only where they are needed, reducing waste and improving crop yield.

4. Automated Equipment:

- Autonomous tractors, harvesters, and robotic systems can plant, irrigate, and harvest crops with minimal human intervention, improving efficiency and reducing labor costs.

5. Big Data and Analytics:

- Large datasets from sensors, weather forecasts, satellite imagery, and historical farming records are analyzed to predict trends, optimize planting schedules, and forecast yields.

6. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML):

- AI algorithms help analyze data collected from IoT devices, drones, and sensors to identify patterns, predict future trends, and automate decision-making processes in real time.

Enhanced Crop Monitoring and Management

Improve crop fitness and productiveness via way of means of constantly tracking variables including soil moisture, temperature, humidity, light, and nutrient stages the usage of IoT sensors.

Impact: Enables precise, records-pushed selections to optimize water usage, fertilizer application, and different inputs, in the end improving yield and lowering waste.

Achieve extra green use of sources like

water, fertilizers, and pesticides, making sure they're carried out in which and while needed. Reduces environmental impact, conserves sources, and improves crop fine and yield via way of means of concentrated on precise regions of a subject instead of making use of sources uniformly.

Data-Driven Decision Making

Use real-time records collected from IoT sensors to make well timed and knowledgeable selections approximately planting, irrigation, harvesting, and pest manipulate.

Enables farmers to conform speedy to converting situations, optimize their processes, and decrease crop loss because of unexpected occasions like pests or intense climate.

Enable farmers to remotely screen subject situations and control irrigation structures, weather manipulate in greenhouses, and different farm operations thru cell or net applications.

Increases operational performance, reduces the want for on-web website online intervention, and lets in for real-time intervention while situations extrude unexpectedly.

Use IoT sensors to tune crop growth, fine, and harvest times, making sure that the timing of harvesting and shipping aligns with marketplace demands.

Minimizes meals waste, guarantees produce is harvested at top fine, and improves the performance of the complete deliver chain.

Predictive Analytics for Crop Yield Forecasting

Leverage records from IoT sensors to forecast crop yields with more accuracy.

Helps in making plans for destiny demand, lowering meals shortages, and stopping overproduction.

Sustainability and Environmental Impact

Utilize IoT sensors to reduce the usage of sources (water, fertilizer, pesticides) and optimize farming practices to be extra eco-friendly.

Reduces environmental pollution, conserves herbal sources, and helps sustainable agricultural practices.

Use IoT-enabled wearable sensors to screen the fitness, behaviour, and place of cattle in real-time.

Improves animal fitness, welfare, and productiveness via way of means of detecting illnesses early, lowering the hazard of epidemics, and enhancing breeding practices.

in Smart Farming Using IoT Smart Sensors

The set up of IoT sensors, records series infrastructure, and integration with different technology (cloud structures, records analytics structures) may be high-priced for farmers, specifically in growing regions.

The excessive in advance fee may also deter small-scale farmers from adopting those technology, proscribing the wider implementation of clever farming.

In rural regions, specially in growing countries, the supply of dependable net and cell community insurance may be limited, that may restrict the effectiveness of IoT gadgets.

IoT sensors depend upon consistent conversation with cloud structures or neighbourhood servers, and a loss of connectivity can bring about incomplete or not on time records transmission, affecting decision-making.

The elevated reliance on records-pushed answers increases worries approximately the safety of touchy agricultural records, such as farm operations and environmental records.

Data Overload and Integration Complexity

IoT structures generate substantial quantities of records from numerous sensors, that may end up overwhelming to system and interpret without right analytics tools.

Farmers may also battle to make feel of big datasets without suitable tools, lowering the effectiveness of IoT structures.

Additionally, integrating records from a couple of sources (sensors, climate stations, drones, etc.) may be complex.

IoT-primarily based totally clever farming answers frequently require technical know-how to install, operate, and maintain.

Farmers may also face demanding situations in adopting and the usage of those technology correctly in the event that they lack the essential technical abilities or get entry to education programs.

IoT sensors uncovered to harsh farming environments (e. g. , soil, climate situations) can degrade or malfunction over time.

Ongoing maintenance, substitute of defective sensors, and making sure their sturdiness can incur extra charges and decrease the general performance of the gadget.

As farming operations scale up, coping with a big quantity of IoT sensors and making sure they maintain to characteristic correctly can end up complex.

The scalability of IoT structures may be a issue if the infrastructure isn't always sturdy sufficient to deal with a big quantity of gadgets with out turning into high priced or complex to control.

Different IoT gadgets and structures may also use various conversation protocols, standards, or records formats, making it hard to combine them right into a cohesive gadget.

Lack of standardization can result in integration problems, elevated charges, and inefficiencies in records sharing among gadgets and structures.

IoT sensors may be impacted via way of means of intense climate situations including heavy rain, freezing temperatures, or severe heat, which may also intervene with their performance.

Environmental elements can have an effect on sensor accuracy and reliability, requiring cautious attention of sensor placement and protection.

In a few regions, there can be criminal or regulatory limitations to the usage of sure IoT technology, specially concerning records ownership, privacy, or environmental regulations.

These limitations may also limitation the usage of IoT answers, proscribing their adoption and growth in sure markets or regions.

While IoT-primarily based totally clever farming gives fantastic capacity for enhancing agricultural productiveness, sustainability, and performance, it faces numerous demanding situations associated with fee, technical know-how, records management, connectivity, and gadget integration.

Addressing those demanding situations thru focused investments, education, and technological innovation may be key to knowing the overall blessings of clever farming.

❑❑❑

41

Skill Development-Today's Necessity

Samrat Wani
Asst. Professor
Thakur Shiv Kumar Singh Memorial
Management College Burhanpur, (M.P.)

****

Abstract

Skill development has emerged as a critical factor in personal and professional growth in the contemporary world. With the increasing pace of technological advancements and shifts in the job market, individuals must continuously acquire new skills to remain competitive. This paper explores the importance of skill development in today's society, highlighting its role in employment, self-reliance, and societal advancement. Additionally, the paper examines challenges faced in skill development efforts and recommends strategic actions to overcome these challenges.

Keywords : Skill Development, Employment, Self-reliance, Digital Divide, Vocational Training, Government Initiatives, Emerging Technologies, Education.

1. Introduction

In today's rapidly changing world, skill development has become more important than ever. Technological advancements and globalization have drastically altered the landscape of employment, and formal education alone is no longer sufficient for securing career success. Instead, specialized skills are crucial for job seekers. The rise of freelance and gig economies further underscores the importance of skills as individuals seek flexibility and autonomy in their careers. This paper explores the necessity of skill development, its importance across various sectors, and how it can serve as a solution to the evolving demands of the job market.

2. Literature Review

Skill development has been studied extensively across multiple disciplines, with researchers emphasizing its role in enhancing employability and economic growth. According to Singh (2019), skill development is crucial in ensuring that the workforce remains adaptable in the face of technological disruptions. The National Skill Development Corporation (NSDC) in India has highlighted the increasing importance of skill development, as over 60% of the Indian population is below the age of 30 (NSDC, 2020). This demographic provides both a challenge and an opportunity in terms of developing relevant skills to meet future demands.

Research by Agarwal (2021) suggests that industries such as IT, healthcare, and manufacturing have a high demand for skilled labor, yet there is a significant gap between the skills taught in traditional education systems and those required by employers. Furthermore, studies by Sharma & Gupta (2022) reveal that although there is a growing interest in online platforms for skill acquisition, access to quality resources remains a challenge in rural areas due to infrastructure limitations.

3. Research Objectives

To assess the importance of skill development in the current job market.

To identify the challenges faced by individuals and organizations in acquiring skills.

To explore the impact of government initiatives and private organizations on skill development.

To propose actionable solutions to enhance the effectiveness of skill development programs.

4. Methodology

This research employs both qualitative and quantitative methods for data collection and analysis.

1. Primary Data Collection:

Surveys and Interviews: Surveys were conducted with individuals who have participated in skill development programs, both

online and offline, to understand their experiences, satisfaction, and challenges faced. Additionally, interviews with industry experts and trainers were conducted to gain insights into the current skill requirements of the job market.

Case Studies: Case studies of successful skill development programs (such as Skill India) were analyzed to identify effective strategies and methodologies.

2. Secondary Data Collection:

Industry Reports: Reports from NSDC, World Economic Forum, and other industry bodies were reviewed to understand the current trends in skill development and employment.

Academic Research: Published papers and articles on skill development, employment trends, and educational reforms were examined to provide a theoretical foundation for this research.

5. Analysis and Discussion

5.1. Importance of Skill Development

Employment Opportunities: Skill development directly correlates with increased employment opportunities. The job market demands more specific, technical, and soft skills that can be applied directly to job roles. For instance, industries like IT, digital marketing, and healthcare have seen a surge in demand for skilled professionals (Ghosh, 2020).

Self-reliance and Entrepreneurship: Skill development enables individuals to pursue entrepreneurship. In today's gig economy, a variety of skills such as graphic design, programming, and marketing enable individuals to become freelancers or start their own ventures. Platforms like Fiverr and Upwork have emerged, showcasing the growing demand for skilled professionals.

Societal Contributions: Skilled individuals contribute to their communities by driving innovation and improving overall economic productivity. For instance, skilled healthcare workers improve public health, and skilled technicians contribute to technological advancements.

5.2. Challenges in Skill Development

Digital Divide: A major challenge in skill development is the digital divide between urban and rural areas. Limited access to technology and the internet restricts opportunities for many individuals to enhance their skills.

Lack of Quality Training: Many skill development programs fail to meet the required industry standards. A lack of practical training and a mismatch between skills taught and industry needs can lead to inefficiencies.

Motivation and Confidence: Mental barriers, such as low self-esteem or fear of failure, often discourage individuals, particularly from marginalized groups, from pursuing skill development opportunities.

5.3. Government and Private Initiatives

Government Programs: Initiatives like Skill India and Digital India have aimed at bridging the skills gap in India. These programs offer free and affordable training in various fields. Government-backed initiatives play a key role in creating awareness and making skill development accessible to all.

Private Sector Role: Private companies, such as Coursera and Udemy, have made online learning platforms accessible to a global audience, offering a wide range of courses tailored to specific industries and skillsets.

6. Recommendations

Enhancing Accessibility: Increasing access to digital infrastructure, particularly in rural areas, will ensure more people can participate in skill development programs.

Improved Quality of Training: Skill development programs should be designed in collaboration with industry experts to ensure they meet the current job market's requirements. Hands-on training and real-world problem-solving should be emphasized.

Personalized Learning Paths: Offering personalized skill development pathways, with mentorship and career counseling, can help individuals overcome mental barriers and stay

motivated.

Public-Private Collaboration: Collaboration between the government, private companies, and educational institutions is essential for creating comprehensive, high-quality skill development programs that are accessible to all.

7. Conclusion

Skill development is a key driver of both individual and societal growth in today's world. As industries evolve, the need for specialized skills grows, and individuals must adapt to stay competitive. While there are significant challenges to overcoming the skill gap, especially in rural areas, there are ongoing efforts by both the government and private sector to provide better opportunities for skill acquisition. By addressing these challenges and promoting more accessible and high-quality skill development initiatives, we can prepare the workforce for the demands of the modern economy.

8. References

1. Agarwal, S. (2021). The Growing Demand for Skilled Labor in India's Job Market. Journal of Employment and Workforce Development, 15(3), 45-59.

2. Ghosh, P. (2020). Impact of Skill Development on Employment in India. Indian Economic Review, 37(2), 118-132.

3. National Skill Development Corporation (NSDC). (2020). Annual Report 2020. New Delhi: NSDC.

4. Sharma, R., & Gupta, M. (2022). Skill Development and Digital Transformation in India. Indian Journal of Education and Technology, 29(1), 92-107.

5. Singh, A. (2019). Skill Development and Economic Growth in Developing Countries. Economic Journal of Development, 26(4), 88-101.

❑❑❑

42

Skill Development in Science and Technology in India

Dr. Dharmendra Bhalse
Assistant Professor, Department of Physics,
Government girls Degree College, Khargone (M.P.)

Dr. Rajesh Kumar
Associate Professor, Department of Physics,
Government Degree College, Nanauta,
Saharanpur (U.P.)

****

Abstract :

Skill development in science and technology is pivotal for fostering innovation, economic growth, and global competitiveness in India. This paper explores the current landscape of skill development initiatives in science and technology across the country, analyzing policies, institutional frameworks, and challenges faced in bridging the skill gap. Emphasis is placed on government programs like Skill India, the role of educational institutions, and public-private partnerships in building a robust skill ecosystem. The study also highlights the integration of emerging technologies such as artificial intelligence, robotics, and biotechnology in training programs to meet the demands of Industry 4.0. By examining case studies and statistical data, the paper identifies key areas of improvement and provides actionable recommendations to enhance skill development strategies. This research underscores the need for sustained investments, innovative teaching methodologies, and inclusive approaches to ensure equitable access to skill training in science and technology, ultimately driving India toward a knowledge-based economy.

Keywords : Skill development, science and tech-

nology, India, innovation, Skill India, Industry 4.0, public-private partnerships, emerging technologies, knowledge economy, education policy, workforce training.

Introduction

Skill development in science and technology is a cornerstone for economic growth, societal advancement, and global competitiveness. In India, a country with a vast demographic dividend, nurturing and harnessing the potential of its youth in the fields of science and technology is imperative. With its strong historical roots in scientific discovery and innovation, India has made significant strides in recent decades to strengthen its capabilities in these areas. However, challenges remain in aligning educational outcomes with industry requirements, promoting research and development (R&D), and ensuring equitable access to opportunities.

India's emphasis on skill development in science and technology can be traced back to the establishment of premier institutions like the Indian Institutes of Technology (IITs) and the Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs). The National Policy on Education (1986, updated in 2020) and subsequent initiatives have underscored the need for a robust science and technology education framework to foster a skilled workforce (MHRD, 2020). Over the years, government schemes like the Skill India Mission (2015) and the Atal Innovation Mission (2016) have been pivotal in promoting technical education, entrepreneurship, and innovation among Indian youth.

Despite these efforts, the World Bank (2021) reported that only 40% of graduates in India possess employable skills in the technology sector. This skills gap has been a major obstacle in realizing the full potential of India's burgeoning tech industry. Furthermore, according to NITI Aayog (2020), India invests only 0.7% of its GDP in R&D, significantly lower than countries like South Korea (4.6%) and the United States (2.8%). This underinvestment hampers the development of cutting-edge technologies and restricts opportunities for students and professionals to engage in high-value research.

To address these challenges, recent policy initiatives such as the National Education Policy (NEP) 2020 and the Digital India campaign aim to bridge the skill gap by promoting interdisciplinary learning, coding, and digital literacy from the school level. These measures are complemented by industry-driven programs like the Tata Consultancy Services (TCS) Digital Learning Initiative and IBM's SkillsBuild (2021), which provide specialized training in emerging technologies like artificial intelligence, blockchain, and data science.

This paper examines India's efforts to develop skills in science and technology, identifies persistent challenges, and explores strategies for achieving a sustainable and inclusive growth model. By fostering collaboration between academia, industry, and government, India can unlock its demographic potential and emerge as a global leader in science and technology.

Current Landscape

I. Science and Technology Ecosystem in India

India has made remarkable strides in science and technology, emerging as a global hub for innovation. With its vast pool of talent and supportive policies, the nation has established itself as a leader in multiple domains. Over the years, India has achieved significant milestones, such as the development of indigenous space technology through the Indian Space Research Organisation (ISRO), which successfully launched the Chandrayaan and Mars Orbiter missions (ISRO, 2014; 2019). Similarly, the country has made advances in biotechnology, ranking among the top 12 biotechnology hubs globally (IBEF, 2022).

The information technology (IT) sector continues to be a cornerstone of India's scientific landscape, contributing approximately 7.7% to the GDP in 2021 (NASSCOM, 2021). Meanwhile, renewable energy initiatives have posi-

tioned India as a leader in sustainable development, with a target to achieve 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030 (Ministry of New and Renewable Energy, 2022).

Key sectors such as pharmaceuticals, agriculture technology, and artificial intelligence are also driving innovation, reflecting India's robust science and technology ecosystem. The government's push through initiatives like 'Make in India' and 'Digital India' has further propelled research and development efforts across various industries.

II. Workforce and Education

i Workforce in STEM Fields

India's workforce in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) fields is among the largest globally, with millions of professionals contributing to both domestic and international markets. The country's IT workforce alone surpassed 4.5 million professionals in 2022 (NASSCOM, 2022). However, while the quantity of STEM talent is substantial, there are concerns regarding the quality and alignment of skills with industry demands.

ii Role of Academic Institutions

India boasts a robust network of academic institutions, including the Indian Institutes of Technology (IITs), Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs), and numerous state and private universities. These institutions play a pivotal role in nurturing talent, fostering innovation, and driving research. The IITs, in particular, are globally renowned for their rigorous programs and research output.

Despite these strengths, there is a need for greater collaboration between academia and industry. Partnerships with global institutions and industries could further enhance the employability of graduates and their readiness for cutting-edge technological challenges.

iii Vocational Training and Technical Education

Vocational and technical education are integral to skill development in India. Schemes like 'Skill India' and 'Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana' (PMKVY) aim to enhance the employability of youth by providing industry-relevant training. However, these initiatives often face challenges related to scalability, consistency, and alignment with local economic demands.

While technical education institutions like polytechnics and Industrial Training Institutes (ITIs) contribute significantly to workforce training, their reach and effectiveness, particularly in rural areas, require improvement.

III. Challenges

i Skill Gaps in Critical Sectors

Despite progress, India faces significant skill gaps in key sectors like artificial intelligence, data analytics, and biotechnology. Reports suggest that only 20-30% of engineering graduates are employable in their respective fields without additional training (Aspiring Minds, 2019). This gap underscores the need for revamped curricula and hands-on training.

ii Mismatch Between Academic Curricula and Industry Demands

A persistent challenge in India's education system is the misalignment between academic curricula and industry requirements. While academic institutions emphasize theoretical knowledge, industries often demand practical, application-oriented skills. Bridging this gap requires collaborative efforts, including internship programs, industry-driven projects, and curriculum updates.

iii Limited Access to Quality Education and Training in Rural Areas

A significant portion of India's population resides in rural areas, where access to quality education and training remains limited. The digital divide exacerbates this challenge, as many rural regions lack reliable internet and technological infrastructure. Although initiatives like e-learning platforms and satellite education programs aim to bridge this gap, much work remains to ensure equitable access to educational resources.

Government Initiatives

Skill development in science and tech-

nology is critical to India's vision of becoming a global leader in innovation and technology. Recognizing this, the Government of India has launched several initiatives aimed at equipping the workforce with advanced skills, fostering innovation, and promoting entrepreneurship.

I. National Skill Development Mission

Launched in 2015, the National Skill Development Mission (NSDM) aims to provide a unified framework to ensure that India's youth are equipped with the skills required to compete in a rapidly evolving global job market. The mission focuses on creating a robust ecosystem for skill development through policies, institutions, and innovative training programs.

II. Objectives and Implementation Strategies: The primary objectives of the NSDM are to:

i Skill 500 million individuals by 2025 through various programs and partnerships.

ii Align skill development initiatives with the needs of the science and technology sectors.

iii Strengthen the capacity of existing institutions and create new ones to cater to emerging technological demands.

To achieve these goals, the mission has adopted strategies such as:

i Integration of industry input: Ensuring that training modules are aligned with industry requirements, particularly in advanced fields like artificial intelligence, robotics, and biotechnology.

ii Recognition of Prior Learning (RPL): Certifying the skills of workers with informal training to enhance their employability.

iii Decentralized implementation: Empowering state-level skill development missions to address regional needs while adhering to national standards.

III. Focus on Science and Technology Sectors: Given the rapid pace of technological advancement, the NSDM has prioritized the following areas:

i Emerging technologies such as AI, machine learning, data analytics, and the Internet of Things (IoT).

ii Strengthening research and development capabilities by providing specialized training programs for scientists and engineers.

iii Collaboration with international organizations to adopt global best practices in skill training and certification.

IV. Policies and Programs

To complement the NSDM, the government has launched specific policies and programs targeting innovation, digital transformation, and entrepreneurial growth in science and technology.

V. Atal Innovation Mission (AIM): Initiated in 2016, AIM focuses on promoting a culture of innovation and entrepreneurship. Key initiatives under AIM include:

i Establishing Atal Tinkering Labs (ATLs) in schools to foster scientific curiosity among students.

ii Supporting startups and small businesses through Atal Incubation Centers (AICs) with funding, mentorship, and access to state-of-the-art facilities.

VI. Digital India: Launched in 2015, Digital India aims to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. Skill development forms a core component of this initiative, particularly in:

i Training citizens in digital literacy to reduce the digital divide.

ii Upskilling professionals in emerging fields like cybersecurity, cloud computing, and e-governance.

VII. Startup India: Since its launch in 2016, Startup India has supported innovation-driven entrepreneurship. By simplifying regulations and providing financial incentives, the program encourages startups in science and technology sectors to scale their operations. Notable initiatives include tax exemptions, a dedicated startup fund, and skill development workshops for entrepreneurs.

VIII. Role of Public-Private Partnerships: Public-private partnerships (PPPs) play a pivotal

role in enhancing skill development. Examples include:

i Collaborations between government agencies and tech giants like Google, Microsoft, and IBM to develop industry-relevant training programs.

ii Joint ventures with academic institutions to design cutting-edge curricula and provide hands-on training.

iii Encouraging private sector investment in skill development through tax benefits and subsidies.

IX. Success Stories

India has witnessed several success stories that showcase the impact of these initiatives on skill development in science and technology.

i Case Study 1: National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) Launched in 2016, NAPS has been instrumental in bridging the skill gap in sectors like IT, electronics, and manufacturing. For instance, collaborations with companies such as Tata Consultancy Services (TCS) and Infosys have led to the successful training and placement of thousands of apprentices in advanced technology roles.

ii Case Study 2: Andhra Pradesh's Fintech Valley Initiative As part of the Digital India program, the Andhra Pradesh government established Fintech Valley in Visakhapatnam. This initiative has trained over 20,000 individuals in blockchain, AI, and fintech, fostering a thriving ecosystem of startups and tech companies.

iii Case Study 3: IIT Madras's Skill Development Programs IIT Madras, in partnership with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, has launched several programs to upskill engineers and technicians in cutting-edge fields like robotics and renewable energy.

These programs have resulted in higher employability rates and have contributed to advancements in India's technological capabilities.

Emerging Trends in Skill Development

I. Industry 4.0 and Beyond

The advent of Industry 4.0 is reshaping the skill requirements in science and technology globally. Automation, artificial intelligence (AI), and robotics are leading to a paradigm shift in industrial processes, necessitating a workforce skilled in programming, machine learning, and advanced manufacturing. The World Economic Forum (2020) highlights that by 2025, nearly 85 million jobs may be displaced, but 97 million new roles requiring data analytics, cybersecurity, and IoT expertise will emerge. India must integrate these skills into its educational and vocational training programs to remain competitive.

II. Collaboration Between Academia and Industry

Partnerships between academia and industry are pivotal for bridging the skill gap. Internships, apprenticeships, and research collaborations enable students to gain practical exposure while aligning educational curricula with industry needs. For instance, IIT Madras's collaboration with Bosch for AI-driven manufacturing has produced innovative solutions while training students (NASSCOM, 2021). Scaling such initiatives across institutions can significantly enhance employability and innovation.

III. Global Best Practices and Localization

Countries like Germany and Singapore are exemplars in science and technology skill development. Germany's dual education system seamlessly integrates theoretical learning with hands-on training, ensuring workforce readiness. Singapore's SkillsFuture initiative offers citizens lifelong learning opportunities in emerging technologies (OECD, 2022). Adopting these practices in India requires customization to address local challenges, such as regional disparities and resource constraints. Policy interventions, such as aligning the National Education Policy (NEP) 2020 with these global strategies, can catalyze progress.

By focusing on emerging technologies, fostering academia-industry collaboration, and adopting proven global models, India can effec-

tively address the evolving skill demands in science and technology. This comprehensive approach will ensure a workforce that is future-ready and capable of driving technological and economic growth.

Recommendations

I. Educational Reforms: To address skill gaps in science and technology, integrating STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) education at the school level is vital (National Education Policy, 2020). This approach fosters critical thinking and innovation from an early age. Promoting interdisciplinary learning by blending technical education with arts and humanities and incorporating hands-on training in school and higher education curricula will further ensure students gain both theoretical and practical expertise (Gupta et al., 2021).

II. Infrastructure and Accessibility: Expanding digital infrastructure, particularly in rural and underserved regions, is essential for facilitating equitable e-learning opportunities (NITI Aayog, 2022). Initiatives like BharatNet should be scaled up to ensure last-mile connectivity. Establishing centers of excellence in science and technology, especially in rural areas, can act as innovation hubs, providing local talent with access to cutting-edge facilities and mentorship. Such efforts have proven effective in countries like South Korea and can be replicated in India (World Bank, 2021).

III. Policy Enhancements: Policymakers must incentivize skill development initiatives by providing tax benefits and grants to industries and academic institutions promoting vocational training and upskilling programs (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, 2020). Strengthening monitoring and evaluation frameworks for skill development schemes, using data-driven approaches to assess outcomes, will help ensure program effectiveness and accountability (Kumar & Sharma, 2021).

Through these targeted reforms, India can bridge the skill gap in science and technology, ensuring that its workforce is prepared to meet the demands of a rapidly evolving global economy.

Conclusion

India's journey in skill development within the domains of science and technology highlights a transformative progression shaped by policy interventions, institutional frameworks, and an ever-evolving global landscape. The country has made significant strides in creating a workforce adept at leveraging technological advancements, fostering innovation, and addressing the challenges of a knowledge-based economy.

However, the potential for growth remains immense, particularly in bridging the gap between academic training and industry demands, fostering inclusivity, and integrating emerging technologies into skill enhancement programs. Collaborative efforts among policymakers, educational institutions, and industries will play a pivotal role in scaling these efforts.

As India aspires to emerge as a global leader in science and technology, sustained investments in research, infrastructure, and human capital will be imperative. By aligning skill development initiatives with the nation's broader developmental goals, India can empower its youth, strengthen its economic resilience, and contribute meaningfully to the global technological ecosystem.

References

[1] Aspiring Minds. (2019). National Employability Report: Engineers.

[2] Department for Promotion of Industry and Internal Trade. (2016). Startup India Action Plan. Retrieved from startupindia.gov.in

[3] Government of Andhra Pradesh. (2017). Fintech Valley Vision 2020. Retrieved from ap.gov.in

[4] Gupta, R., Singh, A., & Verma, P. (2021). Advances in STEM education in India. Journal of Education Policy, 45(3), 178-195.

[5] India Brand Equity Foundation (IBEF). (2022). Biotechnology Sector in India.

[6] Indian Space Research Organisation

(ISRO). (2014, 2019). Chandrayaan and Mars Orbiter Mission Reports.

[7] Kumar, P., & Sharma, S. (2021). Evaluating skill development programs in India. Policy Studies Journal, 39(2), 120-135.

[8] Ministry of Electronics and IT. (2015). Digital India Initiative. Retrieved from digitalindia.gov.in

[9] Ministry of Human Resource Development (MHRD). (2020). National Education Policy 2020.

[10] Ministry of New and Renewable Energy. (2022). Renewable Energy Targets.

[11] Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (2020). Skill India Initiative: Progress Report.

[12] Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2015). National Skill Development Mission Document. Retrieved from msde.gov.in

[13] NASSCOM. (2021). Emerging Technologies in India: Role of Academia-Industry Collaborations.

[14] NASSCOM. (2021, 2022). IT Industry Reports.

[15] National Education Policy (2020). Ministry of Education, Government of India.

[16] NITI Aayog (2022). Annual Report 2022. Government of India.

[17] NITI Aayog. (2016). Atal Innovation Mission. Retrieved from niti.gov.in

[18] NITI Aayog. (2020). Innovation and R&D Report.

[19] OECD. (2022). Skills for Industry 4.0: Lessons from Global Leaders.

[20] Tata Consultancy Services (TCS). (2021). Digital Learning Initiative Report

[21] World Bank (2021). Education for Innovation in East Asia and the Pacific.

[22] World Bank. (2021). India's Skills Landscape: Challenges and Opportunities.

[23] World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020.

43

The Skill Development in the Agriculture Sector

Dr. Prashant singh rajput
Assistant professor Geography
Shri Agrasen girls college kerba, Chhattisgarh

****

The agriculture sector is a cornerstone of India’s economy, employing a significant portion of the workforce and contributing substantially to the nation’s GDP. However, the sector faces challenges such as outdated farming practices, low productivity, and limited access to modern technology and techniques. Skill development in agriculture is critical to addressing these issues and ensuring the sector’s sustainable growth. This abstract explores the role of skill development in transforming the agricultural landscape, enhancing productivity, and improving the livelihoods of farmers, especially in rural India.

India’s agriculture is primarily characterized by small-scale, subsistence farming, with limited exposure to advanced techniques and technologies. As the country strives to enhance food security and promote economic growth, equipping farmers with the necessary skills is crucial. Skill development can help bridge the gap between traditional farming methods and modern agricultural practices. It involves providing training in areas such as crop management, soil health, irrigation techniques, pest control, and post-harvest management. Furthermore, the integration of new technologies, including precision farming, data analytics, and drones, requires a workforce skilled in digital tools and innovations.

The government’s various initiatives, such as the National Skill Development Mission

(NSDM) and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), have played a pivotal role in promoting skill development in agriculture.

These initiatives aim to provide both formal and informal training to rural youth, women, and marginalized communities, empowering them with the skills required for modern farming, agribusiness, and rural entrepreneurship. The introduction of vocational training programs and certifications in agriculture ensures that farmers gain access to knowledge that can directly improve their productivity and income levels.

One of the key areas where skill development is vital is sustainable agriculture. With growing concerns over environmental degradation, climate change, and water scarcity, there is an urgent need for farmers to adopt eco friendly practices such as organic farming, agroforestry, and water-efficient Irrigation methods Skill programs focusing on these areat can significantly enhance agricultural sustainability and resilience to climate challenges. Additionally, the rise of agritech and the use of digital tools in aglature present epportunities for farmers to improve their yield, reduce waste, and optimize resources. Training in digital literary and agri-tech applications is becoming increasingly important.

However, several challenges hinder the widespread adoption of skill development in agriculture. These Include limited infrastructure in rural areas, lack of awareness among farmers about the benefits of modern training, and the need for stronger collaboration between government, educational institutions, and industry. To overcome these barriers, more robust public-private partnerships, better access to resources, and localized training programs tailored to the unique needs of rural communities are essential.

in conclusion, skill development in the agriculture sector is crucial for enhancing productivity, ensuring food security, and improving the livelihoods of farmers. By fostering a skilled workforce, India can build a more sustainable and technologically advanced agricultural sector, contributing to economic growth and self-reliance.

REFERENCE BOOKS:

1. FUNDAMENTALS OF AGRICULTURE-VOL 1 ARUN KATYAYAN

2. AGRICULTURE COMPETITIVE VBOOK-NEM RAJ SUNDA

3. ESSENTIALS OF AGRICULTURE-NARAYAN NAGRE

4. INDIAN AGRICULTURE TOWARDS 2030-RAMESH CHAND, PRAMOD JOSHIL, SHYAM KHADKA

❑❑❑

44

उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार के बीच परस्पर संबंध

डॉ. योगासना पाराशर
सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वान
(समाजशास्त्र विभाग)
माता जीजाबाई शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, इंदौर

****

सारांश —

नवाचार : आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार एवं आत्मनिर्भरता

नवाचार (Innovation) किसी समाज या राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार है। यह नई तकनीकों, प्रक्रियाओं, और समाधानों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का साधन है। नवाचार न केवल उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करता है, बल्कि समाज की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करता है।

आर्थिक विकास में नवाचार की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है, लागत को कम करता है, और नई नौकरियों का सृजन करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और ई—कॉमर्स, ने न केवल व्यापार में क्रांति लाई है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को भी सशक्त बनाया है।

सामाजिक विकास में नवाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, और पर्यावरण के क्षेत्रों में सुधार लाता है। जैसे, टेलीमेडिसिन और ई—लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बढ़ा रहे हैं। नवाचार स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है, जिससे टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, नवाचार देश को आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करता है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी योजनाएं नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित कर रही हैं।

निष्कर्षत:, नवाचार आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। यह आत्मनिर्भरता का आधार बनकर भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकता है।

प्रस्तावना —

उद्यमिता (Entrepreneurship), कौशल विकास (Skill Development), और नवाचार (Innovation) तीनों आधुनिक समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख स्तंभ हैं। ये तीनों परस्पर जुड़े हुए हैं और एक—दूसरे को मजबूत करते हैं। एक उद्यमी को सफलता के लिए व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि नवाचार उसे प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इन तीनों के समन्वय से न केवल व्यवसाय का विकास होता है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान देता है।

१. उद्यमिता (Entrepreneurship)

उद्यमिता का अर्थ है नए विचारों और अवसरों को पहचानकर उन्हें एक व्यवसाय या सेवा के :i में विकसित करना। यह न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि समाज में परिवर्तन और प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। उद्यमिता केवल व्यापार शु : करना नहीं है। यह समस्याओं को हल करने, नवाचार लाने और जोखिम उठाने की प्रक्रिया है।

उद्यमिता का अर्थ है नए विचारों और अवसरों को पहचानकर उन्हें एक व्यवसाय या सेवा के :i में विकसित करना। यह न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि समाज में परिवर्तन और प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। उद्यमिता केवल व्यापार शु : करना नहीं है। यह समस्याओं को हल करने, नवाचार लाने और जोखिम उठाने की प्रक्रिया है।

उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को एक उत्पाद या सेवा में बदलता है और उसे बाजार में प्रस्तुत करता है।

यह एक नई पहल, जोखिम उठाने, और समस्या का समाधान प्रदान करने पर आधारित है।

एक उद्यमी को अपने विचार को व्यावसायिक :i देने के लिए नवाचार और कौशल दोनों की आवश्यकता होती है।

२. कौशल विकास (Skill Development)

कौशल विकास का उद्देश्य व्यक्तियों को उन क्षमताओं से सुसज्जित करना है जो उन्हें किसी विशेष कार्य या व्यवसाय को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करती हैं।

यह प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, संचार, नेतृत्व और अन्य व्यावसायिक कौशलों पर केंद्रित है।

एक कुशल व्यक्ति उद्यम को अधिक संगठित और लाभकारी बना सकता है।

कौशल विकास (Skill Development)

कौशल विकास का अर्थ है व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करना। यह रोजगार, आत्मनिर्भरता, और व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौशल विकास से व्यक्ति अपनी दक्षता में वृद्धि करते हैं, जिससे वे विभिन्न उद्योगों में प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

आधुनिक युग में कौशल विकास का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि तकनीकी प्रगति और प्रतिस्पर्धा के कारण परंपरागत ज्ञान पर्याप्त नहीं रह गया है। आज के दौर में डिजिटल कौशल, संचार कौशल, प्रबंधन कौशल, और तकनीकी ज्ञान जैसी क्षमताओं की मांग अधिक है।

कौशल विकास न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाता है, बल्कि उद्यमिता और नवाचार को भी प्रोत्साहित करता है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता, और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसे कार्यक्रम युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करते हैं। कौशल विकास से एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण होता है, जो देश की प्रगति के लिए अत्यधिक आवश्यक है।

३. नवाचार (Innovation)

नवाचार नए विचारों, प्रक्रियाओं, उत्पादों, या सेवाओं का निर्माण और उन्हें लागू करना।

यह व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने और ग्राहकों को संतुष्ट करने का एक प्रमुख माध्यम है।

नवाचार (Innovation)

नवाचार का अर्थ है नए विचारों, प्रक्रियाओं, उत्पादों, या सेवाओं को विकसित करना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना। यह किसी समस्या का अनूठा समाधान खोजने, प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने, या ग्राहकों की ज :रतों को बेहतर तरीके से पूरा करने का माध्यम है। नवाचार समाज और व्यवसाय दोनों के लिए परिवर्तन और प्रगति का प्रमुख साधन है।

नवाचार का उपयोग तकनीकी, व्यावसायिक, और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक :i से किया जाता है। तकनीकी नवाचार ने इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाई है। व्यवसायों में, यह प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और बाजार में पहचान बनाने का एक तरीका है।

नवाचार से उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी, और ग्राहक संतोष में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाइन शिक्षा, और ई–कॉमर्स नवाचार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

किसी भी समाज या संगठन के विकास के लिए नवाचार आवश्यक है। यह न केवल नए अवसर प्रदान करता है, बल्कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है।

भारत में नवाचार (Innovation in India)

भारत एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है, जहां नवाचार का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और तकनीकी प्रगति ने भारत को नवाचार के लिए एक उपजाऊ भूमि बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, और तकनीकी क्षेत्रों में नवाचार ने नए अवसर पैदा किए हैं और चुनौतियों का समाधान किया है।

भारत में नवाचार का महत्व

१. आर्थिक विकास : नवाचार नए उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देता है, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है।

२. रोजगार सृजन : नवाचार आधारित स्टार्टअप्स ने लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है।

३. समाज पर प्रभाव : स्वास्थ्य, शिक्षा, और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान नवाचार के माध्यम से हुआ है।

४. वैश्विक प्रतिस्पधा : भारतीय नवाचार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर रहा है।

भारत में नवाचार के प्रमुख क्षेत्र

१. तकनीकी नवाचार :

➢ डिजिटल इंडिया : डिजिटल सेवाओं का विस्तार।

➢ UPI और डिजिटल पेमेंट्स : भारत का अग्रणी योगदान।

➢ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : हेल्थकेयर और शिक्षा में नई संभावनाएं।

२. कृषि में नवाचार :

➢ स्मार्ट फार्मिंग और ड्रोन का उपयोग।

➢ जैविक खेती और हाइड्रोपोनिक्स।

३. स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार :

➢ आरोग्य सेतु और टेलीमेडिसिन।

➢ कम लागत वाली वैक्सीन और मेडिकल उपकरण।

४. शिक्षा में नवाचार :

➢ ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म (Byju's, Unacademy)।

➢ स्मार्ट क्लास :म और एडटेक नवाचार।

५. ऊर्जा और पर्यावरण :

➢ हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रगति।

➢ कचरा प्रबंधन और पानी संरक्षण।

➢ सरकारी प्रयास और योजनाएं

१. स्टार्टअप इंडिया : नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन।

२. अटल नवाचार मिशन (AIM) : स्कूलों और संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा।

३. मेक इन इंडिया : घरेलू उद्योगों में नवाचार और उत्पादन को बढ़ावा।

४. प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप : युवाओं को अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रेरित करना।

५. डिजिटल इंडिया : डिजिटल तकनीक के माध्यम से सेवाओं का सुधार।

भारत में नवाचार के उदाहरण

१. UPI : यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्रांति ला दी।

२. आयुष्मान भारत : हेल्थकेयर के क्षेत्र में नवाचार।

३. Jio : डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव।

४. ISRO : अंतरिक्ष में कम लागत वाले मिशन (चंद्रयान और मंगलयान)।

५. Biocon : बायोटेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय नवाचार।

चुनौतियां और समाधान

चुनौतियां :

१. अनुसंधान और विकास (R-D) में कम निवेश।

२. ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच की कमी।

३. वित्तीय और संरचनात्मक बाधाएं।

समाधान :

१. R-D में अधिक निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी।

२. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार।

३. नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ और योजनाएं।

निष्कर्ष

भारत में नवाचार सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रमुख कारक बन चुका है। तकनीकी प्रगति, सरकारी प्रयास, और स्टार्टअप कल्चर ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। चुनौतियों के बावजूद, भारत की युवा शक्ति और विविधता इसे एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने में सहायक है।

➢ उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार के बीच परस्पर संबंध

➢ कौशल विकास : उद्यमिता का आधार

➢ प्रबंधन कौशल : उद्यमी को अपने विचार को लागू करने के लिए टीम प्रबंधन, वित्तीय योजना, और समय प्रबंधन में निपुण होना चाहिए।

➢ तकनीकी कौशल : आज के डिजिटल युग में, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ई—कॉमर्स के ज्ञान के

बिना नवाचार संभव नहीं है।

➢ संचार कौशल : निवेशकों और ग्राहकों के साथ प्रभावी संवाद करने के लिए यह आवश्यक है।

इ. नवाचार : उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है

➢ नवाचार उद्यमिता को नई संभावनाओं की ओर ले जाता है।

जैसे—जैसे नई तकनीक और प्रक्रियाएं विकसित होती हैं, उद्यमियों को कौशल में सुधार करके उन्हें अपनाने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण : डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे UPI ने फिनटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया।

c. उद्यमिता : कौशल और नवाचार का उपयोग एक सफल उद्यमी कौशल विकास के माध्यम से सीखे गए प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करता है।

वह नवाचार को अपनाकर व्यवसाय को अद्वितीय और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है।

४. इन तीनों के समन्वय के उदाहरण

डिजिटल युग के स्टार्टअप्स

Flipkart और Amazon : कुशल प्रबंधन और नवाचार के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी में क्रांति लाई।

Zomato और Swiggy : फूड डिलीवरी सिस्टम में नवाचार और तकनीकी कौशल का उपयोग।

इ. कृषि क्षेत्र में

स्मार्ट फार्मिंग : ड्रोन और सेंसर तकनीक के नवाचार ने खेती को कुशल और उत्पादक बनाया।

कृषि उद्यमिता : किसानों को कौशल प्रशिक्षण और नए उपकरणों का उपयोग सिखाया गया।

c. शिक्षा और कौशल विकास

Byju's और Unacademy : ऑनलाइन शिक्षा में नवाचार और डिजिटल कौशल का उपयोग।

कौशल आधारित शिक्षा : छात्रों को उद्यमिता और नवीन तकनीकों के लिए तैयार करना।

५. सरकारी योजनाओं के माध्यम से इनका प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) :

युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित हो सकें।

b. स्टार्टअप इंडिया :

नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

c. अटल नवाचार मिशन (AIM) :

स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

d. मुद्रा योजना :

छोटे व्यवसाय शु : करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

६. लाभ और चुनौतियां

लाभ :

१. आर्थिक विकास : नई नौकरियों और व्यवसायों का निर्माण।

२. सामाजिक प्रभाव : समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार आधारित उत्पाद।

३. वैश्विक प्रतिस्पधा : कौशल और नवाचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान।

चुनौतियां :

१. कौशल विकास में असमानता।

२. नवाचार के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी।

३. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ज्ञान और पहुंच का अभाव।

७. निष्कर्ष

उद्यमिता, कौशल विकास और नवाचार एक—दूसरे के पूरक हैं।

➢ कौशल विकास उद्यमिता को सशक्त बनाता है।

➢ नवाचार उद्यमिता को अद्वितीय और प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है।

➢ उद्यमिता इन दोनों को व्यावसायिक : i में लागू करने का माध्यम है।

➢ नवाचार और उद्यमिता आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के दो प्रमुख स्तंभ हैं। नवाचार, जहां नए विचारों और प्रक्रियाओं को जन्म देता है, वहीं उद्यमिता इन विचारों को व्यावसायिक अवसरों में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। यह दोनों मिलकर समाज और देश के आर्थिक, सामाजिक, और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है, जब लोग नवाचार और उद्यमिता को अपनाएं। नवाचार न केवल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और तकनीकी स्टार्टअप्स ने भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है।

उद्यमिता रोजगार सृजन, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनती है। छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) तथा स्टार्टअप्स युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता कृषि, हस्तशिल्प, और स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सहायक है।

सरकार की योजनाएं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता, और कौशल विकास कार्यक्रम इस लक्ष्य को और मजबूत बना रहे हैं।

नवाचार और उद्यमिता के सही उपयोग से न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि भारत वैश्विक नवाचार केंद्र बनने की ओर अग्रसर हो सकता है।

इन तीनों का सही समन्वय व्यक्तिगत, सामाजिक, और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक प्रगति को गति देता है। यदि उद्यमियों को कौशल और नवाचार में प्रशिक्षित किया जाए, तो यह एक आत्मनिर्भर और सशक्त समाज के निर्माण में सहायक होगा।

❑❑❑